हिन्दुस्तान
1936
सत्य ★ सार्थक ★ सदैव

संकट में ईरान

ईरान में मानवाधिकारों के हनन के आरोप नए नहीं हैं, मगर *ईरान इंटरनेशनल* नामक न्यूज एजेंसी ने 8 और 9 जनवरी के विरोध-प्रदर्शन के दौरान जिस बड़े पैमाने पर लोगों के कत्लेआम का दावा किया है, वह हैरतनाक है। इस एजेंसी का कहना है कि इन दो दिन के अंदर ही वहां 36,500 से अधिक लोग सरकारी दमन में मारे गए। हालांकि, ईरान के खिलाफ पश्चिमी मीडिया में दुष्प्रचार की मुहिम पुरानी है, लेकिन खुद तेहरान ने उन प्रदर्शनों के दौरान यह आरोप लगाया था कि बड़ी संख्या में बाहरी लोगों ने घुसपैठ की है और मासूम लोगों का कत्लेआम किया है। इससे इस अंदेशे को बल मिलता है कि 36,500 की संख्या अतिरंजित भले हो, मगर वहां बर्बरता से विरोध को दबाया जा रहा है। उधर अमेरिका स्थित 'ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी' ने विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 5,137 मौतों की पुष्टि की है और 12,904 अन्य की जांच का दावा किया है। कुल मिलाकर, ईरान के हालात गंभीर बने हुए हैं। खुद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने जिस तरह अवाम के गुस्से को समझने की बात कही थी, उससे भी तस्दीक होती है कि यह सिर्फ पश्चिमी दुष्प्रचार का हिस्सा नहीं है।

यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि लंबे समय से कठोर आर्थिक प्रतिबंधों और इजरायल के साथ लगातार संघर्ष के कारण ईरान की माली हालत जर्जर हो चुकी है। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां एक डॉलर की कीमत लगभग दस लाख 75 हजार रियाल (ईरानी मुद्रा) हो गई है। ईरानी लोगों की क्रय-शक्ति जवाब देने लगी है। मध्यवर्ग की खाने-पीने की चीजें व इलाज का खर्च चुकाने की क्षमता खत्म हो रही है। मौजूदा जन-उबाल के पीछे इसी तबके का गुस्सा बताया जा रहा है। सवाल उठता है कि ऐसे बर्बर दमन से क्या लोगों के आक्रोश को दबाया जा सकता है? महिलाओं के खिलाफ मजहबी पुलिस की निर्मम कार्रवाइयों ने तेहरान के प्रति दुनिया के नजरिये को पहले ही बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में, इतनी बड़ी संख्या में अपने ही देशवासियों का तथाकथित कत्लेआम से उसके प्रति रही-सही सहानुभूति भी तिरोहित हो जाएगी।

ईरान के लिए इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि वह न सिर्फ युद्ध की किसी आशंका को टाले, बल्कि घरेलू नीतियों में मानवाधिकारों का सम्मान करना सीखे।

ईरान का सबसे बड़ा संकट यह है कि उसकी सत्ता में बैठे लोग लंबे समय से अपनी सामाजिक समस्याओं का हल वैश्विक अदावत में तलाश रहे हैं। सामाजिक सुधार और आर्थिक पुनरोद्धार के कार्यक्रम चलाने के बजाय तेहरान सरकार का ज्यादातर निवेश सुरक्षा मद में होता रहा है। पश्चिम से दुश्मनी बढ़ाकर ईरानी शासक यही सोचते रहे कि राष्ट्रवादी लहर के नीचे सारी शासकीय कमियां दब जाएंगी, मगर जिस तरह रह-रहकर वहां जन-आक्रोश भड़क रहा है, इससे उसकी बाहरी सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। अमेरिका, इजरायल व पश्चिमी देशों की आंखों में उसका परमाणु कार्यक्रम खटकता रहा है। अब अमेरिका से जिस तरह तनाव बढ़ता जा रहा और वाशिंगटन विरोधी शक्तियां तेहरान को उकसाने में लगी हैं, वह एक खतरनाक रूप ले सकता है। तेहरान को यह समझना होगा कि एक छोटे अंतराल का युद्ध भी उसके खोखलेपन को उजागर कर सकता है, इसलिए धमकी की मुद्रा के बजाय उसे शांति का रुख अपनाना चाहिए। ईरान के लिए इस समय सबसे जरूरी यह है कि बातचीत के जरिये वह न सिर्फ युद्ध की किसी आशंका को टाले, बल्कि अपनी घरेलू नीतियों में मानवाधिकारों का सम्मान करना सीखे। घर ही अशांत रहा, तो बाहरी सुरक्षा कितनी कारगर होगी?

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले
26 जनवरी, 1951

द्वितीय गणराज्य-दिवस

विधि की कैसी विडम्बना है कि जिस नगर में 21 वर्ष पूर्व हमने पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली थी, वह आज भारतीय गणराज्य के प्रदेश में नहीं रहा। यदि स्वतंत्र होने के साथ भारत खंडित नहीं होता, तो आज गणराज्य-दिवस मनाने के लिए लाहौर से अधिक उपयुक्त स्थान और कोई नहीं होता। किन्तु जहां हमें लाहौर के बिछोह पर दुख है, वहां यह संतोष भी है कि वह भी एक आजाद प्रदेश की राजधानी है।

31 दिसम्बर 1929 की वह शीतकालीन रात भारतीय इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी, जबकि अर्धरात्रि के 1 जनवरी 1930 में संक्रमित होते ही भारतीय नौजवानों के दिल एक नई उमंग तथा एक नये निश्चय से प्रफुल्लित हो उठे। रावी के तट की कड़ाके की सरदी-गरमी में बदल गई। कांग्रेस-अध्यक्ष-नवयुवकों के हृदय-सम्राट- जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया कि स्वाधीनता-प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। नौजवान अपने नेता को कन्धों पर बिठाकर उस स्थान में ले गये, जहां कि शान के साथ तिरंगा झंडा फहराया गया। उल्लास तथा उमंग की उस रात में शायद ही कोई सोया होगा। जागरण की वह बेला वीरों को कर्म-क्षेत्र में आगे बढ़ने का आमंत्रण दे रही थी।
राष्ट्र का महानतम पर्वः उसके बाद कांग्रेस-कार्यसमिति ने 26 जनवरी 1930 का दिन स्वाधीनता-दिवस के रूप में निर्धारित किया। इसको नियत करने में किसी विशेष बात को ध्यान में नहीं रखा गया। उल्लेखनीय बात इतनी ही थी कि उस रोज रविवार था। स्वाधीनता-दिवस का मुख्य कार्यक्रम स्वाधीनता की प्रतिज्ञा थी, जिसे करोड़ों नर-नारियों ने दुहराया। ...गंगोत्तरी में निकली हुई जलधारा जिस प्रकार पुण्यसलिला गंगा के रूप में आगे-आगे चलने पर विशालतर व गहनतर होती जा रही है, उसी प्रकार यह प्रतिज्ञा भी अपने प्रभाव तथा अपने महत्व में विशालतर तथा गहनतर होती गई।...

यह सत्य है कि हमने स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात अनेक क्षेत्रों में अपने आपको सम्हाला है और काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। परन्तु हमारा यह आगे बढ़ना हमें देश तथा विदेश में सुख और शान्ति का राज्य स्थापन करने की ओर ले जायेगा अथवा नई-नई आपत्तियों और सर्वनाशनी अशान्ति की ओर? ... भविष्य ही मेरे इस भाव का सही उत्तर दे सकेगा।

जांच एजेंसियों का यूं टकराना ठीक नहीं

राय की राय
यहां स्कैन करें

विभूति नारायण राय | पूर्व आईपीएस अधिकारी

संघीय व्यवस्था के लिए यह स्थिति खतरे की घंटी जैसी है। क्या हम चाहेंगे कि केंद्र और राज्य की पुलिस दुश्मन देशों की सेनाओं की तरह एक-दूसरे के सामने खड़ी दिखें?

सर्वोच्च न्यायालय ने 19 जनवरी, 2026 को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पुलिस समेत राज्यों की अन्य एजेंसियों को केंद्रीय कर्मचारियों के विरुद्ध 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट' या किसी दूसरे कानून के तहत दाखिल मुकदमों में चार्जशीट लगाने के पहले सीबीआई से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

देश का संविधान संघात्मक ढांचे की परिकल्पना करता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से बंटे हुए हैं। कानून-व्यवस्था, कुछ अपवादों को छोड़कर राज्यों के अंतर्गत आती है और इसीलिए उसे लागू करने वाली एजेंसियां भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में हैं। 1967 तक जब आमतौर से केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकारें होती थीं, इस व्यवस्था से कोई बड़ी समस्या नहीं आई, पर अब जब एक दर्जन से अधिक राजनीतिक दल केंद्र और राज्यों में मिली-जुली या अकेले दम पर सरकारें चला रहे हैं, तब बार-बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है।

यह समझना दिलचस्प होगा कि ऐसी स्थिति ही क्यों पैदा हुई? इसके लिए हमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के इतिहास को खंगालना पड़ेगा। सीबीआई की पूर्वज 'दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट' की स्थापना 1946 में एक विशेष कानून के तहत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान ठेकों और आपूर्ति में बड़े पैमाने पर हुए घोटालों की जांच करना था। इसकी जांच के दायरे में मुख्य रूप से केंद्र सरकार और केंद्र शासित इलाकों के सरकारी कर्मचारी आते थे। आजादी के बाद भारतीय राज्य में अभूतपूर्व आर्थिक गतिविधियां शुरू हुईं। बड़े पैमाने पर सरकारी मशीनरी का विस्तार हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये सार्वजनिक क्षेत्रों में विशाल निवेश हुए और साथ में अरबों रुपये सरकारी खरीद-फरोख्त में खर्च किए जाने लगे। इनके अलावा सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों या इस्तेमाल में आने वाली विभिन्न इमारतों जैसी आधारभूत संरचनाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हो गया।

यह सारा विकास अपने साथ ऐसा अभिशाप लेकर आया, जिसकी शुरू में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह था भ्रष्टाचार का वह जिन्न, जो एक बार बोतल से बाहर निकला, तो फिर उसे वापस बोतल में बंद कर पाना किसी सरकार के लिए संभव न हो सका। मूंदड़ा कांड (1957-58) आजादी के बाद का पहला बड़ा वित्तीय घोटाला था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जीवन बीमा निगम लिप्त थी और जिसके चलते तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद तो लगातार बड़े घोटाले सामने आते रहे और प्रभावशाली लोगों की उनमें संदिग्ध लिप्तता आरोपित होती रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्ति से लड़ने के लिए सन् 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई और इसके गठन के लिए 'दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट' को ही आधार बनाया गया। जल्द ही इस संगठन ने अपनी विश्वसनीयता कायम कर ली और आमतौर पर सामान्य जन या अदालतें राज्य पुलिस बलों से हटकर सीबीआई से जांच कराने के आदेश देने लगीं। चूंकि कानून-व्यवस्था राज्य के अधिकार क्षेत्रों में है, अतः कानूनन यह जरूरी था कि किसी राज्य के दायित्व वाले मसलों में विवेचना करने के पहले सीबीआई राज्य सरकार की इजाजत ले। शुरू में समस्या नहीं आई। अधिकांश राज्यों ने एकमुश्त मंजूरी दे रखी थी। दिक्कत तब आनी शुरू हुई, जब अलग-अलग दलों की सरकारें केंद्र में आईं और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगने शुरू हो गए। सर्वोच्च न्यायालय को भी उसे 'तोता' कहना पड़ा। इस बीच कई राज्यों ने अपनी मंजूरी वापस ले ली, अर्थात अब सीबीआई को जांच शुरू करने के पहले संबंधित राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और इसे हासिल करना उत्तरोत्तर मुश्किल होता गया है।

इस स्थिति से उबरने के लिए केंद्र ने डीआरआई, ईडी व एनआईए जैसी दूसरी अनुसंधान एजेंसियों का उपयोग शुरू कर दिया। इन संगठनों को किसी जांच के लिए संबंधित राज्य सरकारों से पूर्वानुमति की वैधानिक आवश्यकता नहीं है। एनआईए को तो उसका ऐक्ट ऐसे अधिकार भी देता है कि वे किसी मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला बताकर उसकी तफ्तीश राज्य पुलिस से अपने हाथों में ले सकती है। इन एजेंसियों के दुरुपयोग की भी शिकायतें खूब मिलने लगी हैं। प्रायः देखा गया है कि हर चुनाव के पहले ये सक्रिय हो जाती हैं और अदालतों व मीडिया में उनके खिलाफ शिकायतों की बाढ़ सी आ जाती है।

इसी परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले को देखना पड़ेगा। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और झारखंड समेत कई प्रदेशों ने केंद्रीय एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कुछ मुकदमे कायम किए हैं, जो मुख्य रूप से इन प्रदेशों के राजनेताओं या नौकरशाहों से संबंधित विवेचनाओं में शिकायतकर्ता या गवाहों के मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हैं। पहले भी केंद्रीय एजेंसियों के छापों के दौरान राज्य पुलिस द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में आनाकानी की गई है। और तो और, उनके द्वारा मदद की गुहार लगाने पर भी उपेक्षात्मक रवैया अपनाया गया।

किसी ताकतवर नेता या नौकरशाह के परिसर पर छापों के दौरान जिस तरह पुलिस के अपने हित में दुरुपयोग की प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, उसमें पूरी आशंका है कि आने वाले दिनों में राज्य और केंद्र की एजेंसियों के बीच टकराव बढ़ेगा ही। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में अब जब भी कोई केंद्रीय एजेंसी किसी प्रदेश के ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसे संबंधित राज्य की पुलिस द्वारा अपने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना होगा।

एक संघीय व्यवस्था के लिए यह स्थिति किसी खतरे की घंटी की तरह है। क्या हम चाहेंगे कि नौबत यहां तक आए कि केंद्र और किसी राज्य की पुलिस दुश्मन देशों की सेनाओं की तरह एक-दूसरे के सामने खड़ी दिखें? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सांविधानिक रूप से तो सही हैं, पर आने वाले दिनों में इसके चलते ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिनसे निपटने के लिए संविधान में बड़े संशोधन करने पड़ेंगे। इस गंभीर संकट से बचने के लिए जरूरी है कि हमारे राजनेता ऐसे अवसरों पर ज्यादा उत्तरदायित्व पूर्ण प्रतिक्रिया दें। इसके लिए पहले इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ना होगा कि क्या वे ऐसे प्रौढ़ व्यवहार के लिए तैयार होंगे?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

विवाह से क्यों कतराने लगीं कामकाजी युवतियां

यहां स्कैन करें

क्षमा शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार

पिछले दिनों तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। हैदराबाद में एक व्यक्ति ने अदालत में अर्जी लगाई कि उसकी पत्नी नौकरीपेशा है, मगर न तो खाना बनाती है, न ही घर के कामों में उसकी मां, यानी अपनी सास की मदद करती है। उसका यह व्यवहार क्रूरता की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे तलाक का आधार माना जाए।

निचली अदालत ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। वह व्यक्ति हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने सारी दलीलें सुनने के बाद कहा कि आप एक बजे से रात 10 बजे तक काम करते हैं, जबकि आपकी पत्नी सवेरे नौ बजे से शाम छह बजे तक नौकरी करती है। इसलिए अगर वह सवेरे खाना नहीं बना पाती, तो इसे क्रूरता नहीं माना जा सकता। पति ने यह भी दलील दी कि पत्नी अक्सर अपने माता-पिता के घर रहने चली जाती है। उसके साथ नहीं रहती। इस पर भी अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकारा कि उसके वक्तव्यों में विरोधाभास है। कभी उसने कहा कि पत्नी पांच महीनों तक उसके साथ रही, दूसरी बार कहा कि 21 महीनों की शादी में पत्नी बस दो-तीन महीने ही उसके साथ रही है। गर्भपात के बाद पत्नी का अपने माता-पिता के साथ रहना भी क्रूरता नहीं माना जा सकता। अदालत ने तलाक की उसकी मांग को खारिज कर दिया।

महिला को हम त्याग की प्रतिमूर्ति बताते हैं, आखिर त्याग अपने बलिदान में ही क्यों छिपा है? नौकरीशुदा स्त्रियों का अपने वेतन पर भी अधिकार नहीं होता।

अपने देश में यह अक्सर देखने में आता है कि जो महिलाएं घर चलाती हैं और नौकरी भी करती हैं, उनका जीवन तरह-तरह की कठिनाइयों से भरा रहता है। सुबह-सवेरे उठकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, उनका नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, फिर दफ्तर की तरफ दौड़ना और वहां की आफतों को झेलना और यह भी सुनना कि महिलाएं कुछ काम नहीं करतीं, उनके लिए काफी कष्टदायी होता है।

इन दिनों ऐसे वीडियो और रील की भरमार है, जिनमें सास, ससुर, ननद, अन्य नाते-रिश्तेदार स्त्रियों को यह ज्ञान बांटते दिखते हैं कि नौकरी करो या मत करो, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। घर में साथ रहने वाले सास, ससुर, अन्य नाते-रिश्तेदार सबकी देखभाल और उचित आतिथ्य की जिम्मेदारी बहू की ही है। वह थकान, अधिक काम या दफ्तर की किसी जरूरी मीटिंग में जाने की बात नहीं कह सकती। बहू या पत्नी के मतलब एक ऐसी कर्मचारी, जो किसी रोबोट की तरह चौबीस घंटे की नौकर है। घरेलू सहायिका को तो फिर भी हफ्ते में एक दिन छुट्टी देनी पड़ती है। उसकी खुशामद करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं काम न छोड़ दे, लेकिन घर की स्त्री को यह अधिकार भी नहीं। विवाह का यह मतलब क्यों है कि कोई स्त्री बस रात-दिन काम करने, हर तरह की जिम्मेदारी उठाने और हर गलती अपने सिर लेने के लिए बनी है? बच्चे यदि कोई शरारत करें, उनसे कोई गलती हो जाए, तब भी सुनना पड़ता है कि कैसी मां है, बच्चों को कुछ नहीं सिखाया।

कर्तव्य का सारा बोझ यदि पत्नी के ही सिर है, तो उसके कुछ अधिकार भी तो होंगे। कर्तव्य और अधिकार एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। अक्सर खबरें आती हैं कि किसी देश की जीडीपी को बढ़ाने में स्त्रियों का कितना भारी योगदान है। जितने काम एक स्त्री अपने बल पर निपटाती है, यदि उन सबके लिए खर्च करना पड़े, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी रकम खर्च होगी। यदा-कदा यह बात भी होती है कि घरेलू काम के लिए स्त्रियों को बाकायदा वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि एक कामकाजी पुरुष को सप्ताह में एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी मिलती है। इसके अलावर भी छुट्टियां मिलती हैं, पर एक महिला के हिस्से इनमें से कुछ नहीं आता। उसे बिना रुके, थके, सवेरे से गए रात तक काम करना पड़ता है।

यदि महिला नौकरी करने वाली है, तो उसकी आफतें दोहरी-तिहरी हैं। ऐसी महिला को हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं। उसे त्याग की प्रतिमूर्ति बताते हैं। आखिर त्याग अपने बलिदान में ही क्यों छिपा है? कई मामलों में तो नौकरी करने वाली महिला का अपने वेतन पर भी कोई अधिकार नहीं होता। वर्षों पहले गाजियाबाद, फरीदाबाद से दिल्ली नौकरी करने आने वाली महिलाएं शाम को सब्जी खरीदकर ले जाती थीं। यात्रा के दौराने वे सब्जी काटते देखी जाती थीं। पुरानी पीढ़ी की महिलाओं को देखकर ही शायद इन दिनों बड़ी संख्या में स्त्रियां शादी नहीं करना चाहतीं। स्त्रियां बदल गई हैं, समाज नहीं बदला।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं।)

मनसा वाचा कर्मणा

भक्ति का स्थायी लक्ष्य

एक साधक ने एक बार पूछा- मनुष्य की इच्छाएं और लक्ष्य बदलते रहते हैं। आखिर मनुष्य का लक्ष्य क्या है?

जब लोग केवल शारीरिक ऊर्जा और कर्म-क्षमता के सहारे कार्य करते हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय नहीं होती, तो वे शीघ्र ही थक जाते हैं। इसके विपरीत, जब मनुष्य अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ, स्पष्ट कार्य-योजना बनाकर और किसी उच्च आदर्श को सामने रखकर कर्म करता है, तो उसके कार्य सफल होते हैं और उसका जीवन सार्थक बनता है। इसी अवस्था को भक्ति कहा गया है।

हर भौतिक क्रिया में भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति का अस्तित्व परम सत्ता, परम पुरुष पर आधारित होता है। केवल बौद्धिक गतिविधियों में संलग्न रहना या कर्म को केवल कर्म के लिए करना, दोनों ही अस्थायी परिणाम देते हैं, लेकिन जब ज्ञान और कर्म एक-दूसरे में विलीन हो जाते हैं, तो उससे भक्ति पैदा होती है। भक्ति में एक ऐसा आकर्षण होता है, जो स्थायी होता है। इसे ही प्रेरणा कहा जाता है।

मानव जीवन का लक्ष्य परम सत्ता की अनुभूति करना है। इस अनुभूति के बिना मानवीय क्रियाएं कभी स्थायी नहीं हो सकतीं। जब मनुष्य कुछ स्थायी रचना करना चाहता है या समाज में कोई मूल्य स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए आध्यात्मिक जीवन में प्रतिष्ठित होना अनिवार्य है। भक्ति और प्रेरणा के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।

साधना और निःस्वार्थ सेवा के माध्यम से मानव मन में आध्यात्मिक प्रेरणा और भक्ति का उदय होता है। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि बिना ज्ञान या कर्म के अभ्यास के भक्ति कैसे उत्पन्न हो सकती है? इसका उत्तर यह है कि यह व्यक्ति के पूर्व कर्मों की प्रतिक्रिया हो सकती है। संभव है, पूर्व जन्मों में ज्ञान और निःस्वार्थ सेवा का अभ्यास किया हो, जिसके परिणामस्वरूप इस जीवन में उसे सहज भक्ति प्राप्त हुई हो।

जो लोग यह सोचते हैं कि वे चौबीस घंटे बंद कमरे में प्राणायाम या मंत्र-जप करके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, वे असफल होंगे, क्योंकि इसमें गतिशीलता का अभाव होता है। इसी प्रकार, जो लोग केवल कर्म में लगे रहते हैं, वे भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। ज्ञान और भक्ति की तुलना गंगा और यमुना से की गई है। जब दोनों मिलते हैं, तभी जीवन की सच्ची सिद्धि होती है। इसलिए जिनके भीतर भक्ति जाग्रत हो चुकी है, उन्हें स्वयं को उपयुक्त कर्म में लगाना चाहिए।

जब ज्ञान और कर्म एक-दूसरे में विलीन हो जाते हैं, तो उससे भक्ति पैदा होती है। भक्ति में एक ऐसा आकर्षण है, जो स्थायी होता है। इसे ही प्रेरणा कहा जाता है।

भक्ति से संपन्न व्यक्ति जो भी कार्य करता है, उसमें उसे सफलता अवश्य मिलती है। कार्य में कूद पड़िए। आप पाएंगे कि आप बहुत कुछ करने में सक्षम हैं। कभी यह न सोचें कि आप कोई कार्य नहीं कर सकते।

श्रीश्री आनंदमूर्ति

ओम बिरला | लोकसभा अध्यक्ष

संविधान हमारे राष्ट्र की आत्मा है, जो विविधताओं से भरे भारत को एक सूत्र में बांधता है। इसी संविधान के मार्गदर्शन में हमने लोकतांत्रिक यात्रा में तमाम चुनौतियों का समाधान करते हुए देश का समावेशी विकास सुनिश्चित किया है।

अनुलोम-विलोम
भारतीय संविधान

राष्ट्र प्रथम को मजबूत बनाता संविधान

भारत का संविधान एक उत्कृष्ट दस्तावेज है। इसे देश का गौरव बनाने के लिए संविधान सभा ने गंभीर प्रयास किए। उसने न सिर्फ संवाद व समन्वय पर जोर दिया, बल्कि आम सहमति बनाते हुए एक शानदार दस्तावेज का निर्माण किया, जिसके माध्यम से आज हम गणतंत्र तो हैं ही, केंद्र और राज्य सरकारें भी सांविधानिक प्रावधानों के तहत अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। यह संविधान द्वारा दिखाए गए रास्ते का ही नतीजा है कि आज सरकारों में जन-कल्याण की भावना है और प्रशासनिक कामों में कठोरता भी। वे सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी जी रही हैं और धार्मिक स्वतंत्रता को भी। ये सभी बातें संविधान में निहित हैं, जिनके लिए हमारे संविधान-निर्माताओं ने गंभीर चिंतन किया।

भारतीय संविधान की कई खास बातें हैं। यह एक लिहाज से लचीला है, क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों को आसानी से बदला जा सकता है, तो कुछ मामलों में कठोर भी, क्योंकि कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसमें नागरिकों से मौलिक अधिकार के साथ-साथ मौलिक कर्तव्य की कल्पना भी की गई है। नागरिकों को जहां समता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, वहीं उनसे देश और समाज के हित में कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा भी की गई है। अच्छी बात है कि भारत का कोई राजकीय धर्म तय नहीं किया गया, यानी यह एक धर्मनिरपेक्ष देश बना, जहां सभी धर्मों को समानता हासिल है। इस तरह भारत एक खास लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए हुए है। यह महानता भारतीय संविधान की ही देन है।

सुखद है कि सांविधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से हमने एक अच्छी शासन-प्रणाली बनाई है। अब इसे और मजबूत करने की जरूरत है। हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम भारत को जल्द विकसित देशों में शुमार कर देंगे। हमें देश को सर्वोपरि रखना होगा और संविधान को भी पूर्व की तरह पर्याप्त सम्मान देना होगा। जब सभी भारतीयों के दिल में राष्ट्र प्रथम की भावना समान भाव से बहने लगेगी, तब यह देश विकसित बन जाएगा। यह संविधान की ही ताकत है कि वंचित और पिछड़े तबके के लोग भी अब ऊंचे पदों पर पहुंचने लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूरे देश में हर वयस्क नागरिक को सरकार में भागीदारी निभाने का मौका मिलता है, बिना कोई सामाजिक-आर्थिक भेदभाव किए। साफ है, भारत का संविधान महान है, जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए, ताकि देश फिर से महानता संबंधी अपने गुणों को पा सके। यह जिम्मेदारी हम सबको दिल की गहराई से निभानी चाहिए।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

इस दस्तावेज के सामने कई चुनौतियां

भारतीय संविधान राष्ट्र का कोई साधारण विधि-ग्रंथ नहीं, बल्कि एक सभ्यता की चेतना, संघर्षों की स्मृति और भविष्य के स्वप्नों का सजीव दस्तावेज है। यह केवल शासन की व्यवस्था तय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने करोड़ों भारतीयों को गरिमा, समता और स्वतंत्रता का भरोसा दिया है। विविधताओं से भरे इस देश में भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति की बहुलता को एक सूत्र में पिरोना आसान नहीं था, किंतु संविधान ने इस असंभव से दिखने वाले कार्य को भी संभव बनाया।

हालांकि, आज यह कई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। असहमति को देशद्रोह समझने की प्रवृत्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंध और संस्थाओं की स्वायत्तता पर सवाल लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। संविधान केवल किताबों में नहीं, बल्कि व्यवहार में जीवित रहना चाहिए, और इसके लिए राजनीतिक संस्कृति का सांविधानिक होना आवश्यक है।

सामाजिक न्याय आज भी अधूरा सपना है। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। संविधान ने समता का वादा किया, परंतु सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया है। महिलाओं की सुरक्षा और समान अवसर, आदिवासियों के अधिकार, और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे मुद्दे आज भी सांविधानिक आदर्शों की कसौटी पर समाज को परखते हैं।

डिजिटल युग ने भी संविधान के सामने चुनौतियां पेश की हैं। निजता का अधिकार, डाटा सुरक्षा, सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की सीमाएं और साइबर निगरानी जैसे प्रश्न आधुनिक लोकतंत्र के केंद्र में हैं। तकनीक जहां एक ओर नागरिकों को सशक्त बनाती है, वहीं दूसरी ओर राज्य की निगरानी-क्षमता को भी बढ़ाती है। ऐसे में, संविधान की व्याख्या को समय के साथ विकसित होना होगा। आर्थिक असमानता भी एक गंभीर सांविधानिक चुनौती है। संविधान ने सामाजिक और आर्थिक न्याय का सपना दिखाया, परंतु अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई इस आदर्श को कमजोर करती है। एक सशक्त लोकतंत्र के लिए आर्थिक समावेशन अनिवार्य है। यह समझना होगा कि भारतीय संविधान की अब तक की यात्रा गौरव, संघर्ष और आत्ममंथन की कहानी है। हालांकि, मौजूदा चुनौती हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम संविधान के मूल्यों को केवल स्मरण करते हैं या उन्हें जीते भी हैं? संविधान की रक्षा केवल न्यायालयों या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है।

नृपेन्द्र अभिषेक नृप, टिप्पणीकार

पहले जीवन सुधारें, फिर करें ध्यान

हमारे जीवन में बहुत अव्यवस्था है। उसे ठीक किए बिना ध्यान का कुछ भी अर्थ नहीं। यदि आप यह सोचकर ध्यान में बैठ जाएं कि इससे व्यवस्था आ जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले अपने दैनिक जीवन में सुव्यवस्था स्थापित करें, तब ध्यान की गहराइयों में उतरने का लाभ होगा।

अध्यात्म

जे. कृष्णमूर्ति

हम सब युद्ध की तैयारियों में लगे हुए हैं। इन तैयारियों से विश्व में कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी प्रकार का विस्फोट अवश्य होगा। हम एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्वक कभी भी नहीं रह पाए हैं। शांति के बारे में हम बातें खूब करते हैं। सारे धर्मों ने शांति का ही संदेश दिया है, लेकिन इस धरती पर शांति कभी भी संभव नहीं हो पाई है। यह धरती, जिस पर हम सब रहते हैं, किसी एक देश की नहीं है। यह हम सबकी और हमारी धरती है।

दूर करें हृदय से हिंसा

इस नफरत का संभवतः एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे हृदय हिंसा से भरे हैं। हम कभी भी शत्रुता के भाव से, प्रतिशोध के भाव से मुक्त नहीं रहे। कभी भी अपने भय, दुख, घावों और प्रतिदिन के जीवन की पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाए। हमें कभी शांति नहीं मिली। हम हमेशा परेशानियों में घिरे रहते हैं। यह सब हमारे जीवन का हिस्सा हैं। हमारे प्रतिदिन के दुखभोग का हिस्सा है।

इस प्रेम विरहित दुखभोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य ने कई रास्ते आजमाए हैं। उसने इसका दमन करके देख लिया। किसी श्रेष्ठतर तत्व से अपना तादात्म्य करके देख लिया। किसी आदर्श के लिए, किसी विश्वास के लिए, किसी आस्था के लिए अपने आपको समर्पित कर के देख लिया। फिर भी यह दुख कभी समाप्त नहीं होता। हम इसके अभ्यस्त हो चुके हैं। हम अपने से कभी यह नहीं पूछते कि क्या इस दुख का समापन संभव है।

दुख से मुक्ति का करें प्रयत्न

पहली बात तो यह है कि क्या हम सचमुच दुख से मुक्त होना चाहते हैं? क्या हम कभी दुख से वस्तुतः मुक्त हुए हैं। इसकी छानबीन की है? इसका सामना किया है? इसकी समस्त गतिविधि को, इसके निहितार्थों को समझा है? हमारा तकनीकी क्षेत्र में तो असाधारण चातुर्य है, फिर हम दुख की इस समस्या का निराकरण क्यों नहीं कर पाए हैं? इस प्रश्न पर साथ-साथ चर्चा करना, स्वयं इस बात का पता लगाना कि क्या दुख का वास्तव में अंत हो सकता है, बहुत जरूरी है।

हम कई तरह से दुखी होते हैं। किसी के मर जाने का दुख। गरीबी का दुख, जिसे पूरब के लोग बेहतर जानते हैं। फिर अज्ञान का घना दुख है- किताबी ज्ञान के अभाव के अर्थ में 'अज्ञान' नहीं, बल्कि पूरी तरह अपने आपको स्व की समस्त जटिल क्रियाशीलता को न जानने के अर्थ में अज्ञान।

यदि हम इसे बहुत गहराई से नहीं समझ लेते, तो उस अज्ञान का दुख बना रहता है। यद्यपि तकनीकी तथा अन्य दुनियावी मामलों में सफल होने की निपुणता हममें अवश्य है,

तथापि कुछ भी कभी मौलिक रूप से गहराई से न समझ पाने का दुख भी है।

बाहर से या भीतर से सुंदर न होने का निजी दुख भी है। फिर आसक्ति तथा उसके साथ जुड़े हुए भय और विकृति का दुख है। प्रेम न पाने का तथा प्रेम के लिए तरसने का भी एक दुख होता है। जो विचार से परे है, शाश्वत है, उसका बोध कभी न हो पाने का दुख है और अंततः मृत्यु का दुख तो है ही।

प्रेम इच्छा है या फिर कुछ और...

जब तक दुख का अंत नहीं होता, तब तक प्रेम कैसे संभव है? आश्चर्य की बात है कि हमने प्रेम और दुख को संबंधित किया हुआ है। मैं अपने बेटे से प्रेम करता हूं और जब वह मर जाता है, तो मैं दुख से भर उठता हूं। इस प्रकार दुख को हम प्रेम के साथ जोड़ देते हैं।

अब हम पूछ रहे हैं, जब तक व्यथा मौजूद है, दुख मौजूद है, तब तक क्या प्रेम का अस्तित्व संभव भी है? प्रेम क्या कोई इच्छा है? प्रेम क्या सुख है कि उस कामना, उस सुख की पूर्ति न होने पर दुख छा जाए? हम कहते हैं कि ईर्ष्या, आसक्ति, स्वामित्व आदि रूपों में दुख प्रेम का ही एक भाग है। ऐसी हमारी संस्कारबद्धता है। हम इसी प्रकार शिक्षित हुए हैं। यह हमारी विरासत का, हमारी परंपरा का हिस्सा है।

प्रेम और दुख साथ नहीं रह सकते

प्रेम और दुख दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। क्या दुख के साथ प्रेम का वजूद मुमकिन है? या फिर प्रेम कोई बिल्कुल अलग ही बात है?

हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि किसी व्यक्ति के प्रति, किसी प्रतीक के प्रति, अपने परिवार के प्रति अनुरक्ति को, निष्ठा को प्रेम नहीं कहा जा सकता। यदि मैं विभिन्न कारणों से आपके प्रति श्रद्धा रखता हूं, तो उस श्रद्धा के पीछे कोई हेतु होता है और प्रेम का कोई हेतु, कोई प्रयोजन नहीं होता। यदि कोई हेतु है, तो प्रेम है ही नहीं, यह बिल्कुल स्पष्ट है।

पहले अपने को सुधारें

जहां महत्वाकांक्षा है, क्या वहां प्रेम रह सकता है? वह महत्वाकांक्षा भौतिक संसार में हो या मानसिक संसार में, क्या वहां प्रेम रह सकता है? बिल्कुल नहीं। हम मानते हैं कि वहां प्रेम नहीं रह सकता। फिर भी हम अपने उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं। जब हम ऐसे दांव-पेच खेलते हैं, तब हमारे मस्तिष्क पर क्या गुजरती है, जरा देखिए। मैं बड़ा महत्वाकांक्षी हूं। आध्यात्मिकता में मेरा स्थान भगवान की बिल्कुल बगल में होना चाहिए। हो सके तो भगवान की दाहिनी ओर। मैं संबोधि हासिल करना चाहता हूं। आपको पता ही है कि वह सारा छलावा है। संबोधि कोई हासिल करने की चीज नहीं है। जो समय के परे है, उसे आप उपलब्ध नहीं कर सकते।

बाहरी विश्व में क्या चल रहा है, उस पर जरा दृष्टि डालिए। विभिन्न राष्ट्रों के बीच प्रतिद्वंद्विता है। राजनेता एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में जुटे हैं। हम अपना सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। यह सब हम इसलिए चलने देते हैं, क्योंकि हम स्वयं भी भीतर प्रतिस्पर्धा में लगे हैं।

यह सब विचार-विमर्श हम इसलिए कर रहे हैं, ताकि हमारे जीवन में व्यवस्था आ सके। हमारे अस्त-व्यस्त 'घर' में व्यवस्था आ सके। हमारे जीवन में बहुत ही अव्यवस्था है, और समग्र, समन्वित व्यवस्था स्थापित किए बिना ध्यान का कुछ भी अर्थ नहीं है। यदि आपके 'घर' में व्यवस्था नहीं है, तो आप ध्यान की मुद्रा में बैठ तो जाएंगे यह उम्मीद करते हुए कि इस प्रकार ध्यान करने के परिणामस्वरूप वह व्यवस्था आ जाएगी? पहले अपने दैनिक जीवन में सुव्यवस्था स्थापित करें, तब कहीं वह ध्यान की गहराइयों का, उसकी सुंदरता व अर्थवत्ता का, उसकी महत्ता का, उसके मूल्य का अनुसंधान कर सकेगा।

सप्ताह के व्रत-त्योहार

27 जनवरी से 02 फरवरी 2026

27 जनवरी (मंगलवार) : माघ शुक्ल नवमी तिथि सायं 07.06 मिनट तक पश्चात दशमी तिथि। गुप्त नवरात्र समाप्त।

28 जनवरी (बुधवार) : माघ शुक्ल दशमी तिथि सायं 04.37 मिनट तक पश्चात एकादशी तिथि। भद्रा रात्रि 03.17 मिनट से।

29 जनवरी (गुरुवार) : माघ शुक्ल एकादशी तिथि दोपहर 01.56 मिनट तक। जया एकादशी व्रत। भीष्म द्वादशी।

30 जनवरी (शुक्रवार) : माघ शुक्ल द्वादशी तिथि प्रातः 11.10 मिनट तक। प्रदोष व्रत। तिल द्वादशी।

31 जनवरी (शनिवार) : माघ शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रातः 08.26 मिनट तक पश्चात चतुर्दशी रात्रि 05.34 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक तदनंतर पूर्णिमा तिथि। चतुर्दशी तिथि का क्षय। शुक्र उदय।

01 फरवरी (रविवार) : माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथि रात्रि 03.39 मिनट तक। माघ पूर्णिमा। माघ स्नान समाप्त। श्री गुरु रविदास जयंती। फरवरी मास प्रारंभ। गंडमूल रात्रि 11.58 मिनट से।

02 फरवरी (सोमवार) : फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा तिथि रात्रि 01.53 मिनट तक। फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रारंभ। गंडमूल विचार।

-पं. ऋभुकांत गोस्वामी

आस्था-अनास्था

श्री व्यथितहृदय

ब्रह्म को जानने वाला ही सर्वश्रेष्ठ

दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कौन है?

-संकल्प जोशी, नैनीताल

मिथिला के राजा जनक ने एक बार वृहत् यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने यज्ञ में बड़े-बड़े ऋषियों और महर्षियों को आमंत्रित किया। उनमें उद्दालक, पुलस्त्य, गार्गी और याज्ञवल्क्य मुख्य थे।

जब यज्ञ समाप्त हो गया, तो जनक ने एक हजार पुष्ट सींगों और थनों वाली गायें खड़ी करके कहा, 'हे ऋषियों, आप में जो सर्वश्रेष्ठ हो, वह इन गायों को हांककर ले जाए।'

यज्ञ में एकत्र ऋषि एक-दूसरे की ओर देखने लगे। किसी में अपने-आपको सर्वश्रेष्ठ समझने का साहस नहीं हो रहा था। जब गायों को हांककर ले जाने के लिए कोई नहीं उठा, तो याज्ञवल्क्य ने शिष्य सोमश्रवा से कहा, 'सोमश्रवा, तू इन गायों को हांककर आश्रम में ले चल।'

जब सोमश्रवा गायों को ले जाने के लिए उठा, तो वहां एकत्र ऋषि क्रोधावेश में आ गए। बोले, 'ऐसा नहीं हो सकता। गायों को ले जाने से पहले याज्ञवल्क्य को अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करनी होगी।'

याज्ञवल्क्य बोले, 'ऋषियो, मैंने कब कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मुझे गायों की आवश्यकता है, इसलिए मैं गायें ले जा रहा हूं।'

ऋषियों ने याज्ञवल्क्य की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, 'झूठ है। आप गायों को ले जाकर अपने-आपको श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता।'

जब ऋषियों में वाद-विवाद होने लगा, तो गार्गी ने उठकर, 'ऋषियो, आप घबराएं नहीं। मैं याज्ञवल्क्य से दो प्रश्न करूंगी। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही याज्ञवल्क्य गायों को ले जा सकेंगे।' याज्ञवल्क्य बोले, 'अच्छी बात है, गार्गी, करो प्रश्न, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं।'

गार्गी ने पहला प्रश्न किया, 'महर्षि, आकाश को अनंत कहा जाता है, बताइए आकाश में कौन व्याप्त है?'

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 'आकाश में ब्रह्म व्याप्त है, क्योंकि ब्रह्म भी अनंत और सीमा रहित है।'

गार्गी बोली, 'सत्य है। अब आप मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, 'सूर्य, चंद्रमा, तारों और अग्नि में किसका तेज समाहित है?'

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 'ब्रह्म का तेज समाहित है, क्योंकि ब्रह्म से बढ़कर कोई भी तेजवान नहीं है।'

गार्गी ने प्रसन्न होकर कहा, 'ऋषियों, हम सब में याज्ञवल्क्य ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे ब्रह्म को जानते हैं। जो ब्रह्म को जानता है, वही श्रेष्ठ होता है। इन्हें गायों को ले जाने का पूर्ण अधिकार है।'

वहां एकत्र ऋषि याज्ञवल्क्य के सामने झुक गए और याज्ञवल्क्य गायों को लेकर अपने आश्रम में चले गए।

(साभार : 'वृहदारण्यक उपनिषद्', उपनिषदों की श्रेष्ठ कहानियां, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली)

विचार

अहिंसक होना कायरता नहीं

कुछ लोग सोचते हैं कि अहिंसा ने समाज को कायर बनाया है, फिर सामाजिक स्तर पर उसके उपयोग का आग्रह क्यों? मुझे लगता है कि यह सोचना नितांत भ्रांतिपूर्ण है। अहिंसा और कायरता में कोई संबंध नहीं है। भीरु आदमी अहिंसक नहीं हो सकता। जो आदमी मौत से डरता है, वह अहिंसक नहीं हो सकता। डरपोक आदमी अविश्वसनीय भी होता है। वह अपनी अविश्वसनीयता को अहिंसा के चोले से छिपाने की कोशिश में ही लगा रहता है। और, जब उसे अवसर मिलता है, तो वह किसी भी हद तक जाकर हिंसावादी हो जाता है।

आचार्य तुलसी

अहिंसक वह होता है, जो अभय है और जिसे मौत का भय नहीं सताता। फिर यह कैसे माना जाए कि अहिंसा व्यक्ति या समाज को कायर बनाती है। यह भ्रम इसलिए उत्पन्न हुआ कि सही अर्थ में अहिंसा में विश्वास नहीं करने वाले धार्मिकों ने अपनी दुर्बलता को अहिंसा की ओट में पाला-पोसा। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उग्र हिंसावादी अहिंसा की अनुपयोगिता प्रमाणित करने के लिए यह प्रचारित करते हैं कि अहिंसा समाज को कायर बनाती है।

भारत के इतिहास में मौर्य और गुप्तकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है। उस युग में सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक जैसे व्यक्तियों ने अहिंसा को वह प्रतिष्ठा दी, जो कि साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। अहिंसा को प्रतिष्ठा शक्तिशाली व्यक्ति ही दे सकता है।

हम इस ऐतिहासिक तथ्य को भुला देते हैं कि भारत पारस्परिक घृणा और जातीय संघर्ष से कायर बना।

पारस्परिक फूट और पारस्परिक आक्रमण से कायर बना और इन्हीं कारणों से वह परतंत्र बना। कहां वह मौर्य युग का वृहत्तर भारत और कहां विक्रम की दसवीं शताब्दी के बाद का परतंत्र भारत। भारत की परतंत्रता कायरता से आई और वह कायरता सामाजिक शक्ति के विघटन से आई।

अहिंसा का प्रारंभ चित्त की शुद्धि से होता है। यह जीवन का संयम है। उसकी पृष्ठभूमि है- चित्त की निर्मलता। जिसका चित्त कषाय (क्रोध, काम, माया और लोभ) से कलुषित होता है, उसके जीवन में अहिंसा का विकास नहीं हो पाता। हम वस्तु को सर्वांगीण दृष्टि से देखना सीखें और सापेक्ष दृष्टि से उसका प्रतिपादन करें। यह दूसरों के विचारों के प्रति न्याय होगा, अपने प्रति न्याय होगा तथा सत्य और अहिंसा के प्रति न्याय होगा।

चिंतन

ईश्वर की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति विशेष

सृष्टिकर्ता की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट और अद्वितीय है। उस विशेष प्राणी के समान कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अनमोल है और सृष्टिकर्ता के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है। परमेश्वर की नजर में प्रत्येक व्यक्ति कुछ विशेष है। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। किसी भी स्थान पर और किसी भी समय पर ईश्वर की रचना में आप जो भूमिका निभाते हैं, उसमें कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। आप उस विशेष परिस्थिति के लिए, उस विशेष समय, स्थान, संदर्भ में सबसे आवश्यक और अपरिहार्य हैं। और, इसलिए आप आनंदित होइए और प्रभु के प्रति आभारी रहिए कि उसने आपको निभाने के लिए एक भूमिका दी है।

स्वामी चिदानंद

आप अपनी भूमिका पूरी तरह से और सार्थक तरीके से निभाते हैं या नहीं, यह अप्रासंगिक है। भगवान हर किसी से अपेक्षा करता है कि वह किसी भी समय वह कार्य करे, जो वह करने में सक्षम है। भगवान यह उम्मीद नहीं करते कि चींटी जंगल में हाथी की तरह बड़ी लकड़ी खींच ले। न ही भगवान यह उम्मीद करते हैं कि हाथी अबाबील और कबूतर की तरह हवा में शान से उड़ सके। वह उम्मीद करते हैं कि पक्षी उड़ें और वे जो करते हैं, उसके लिए वह उनसे प्यार करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि हाथी अपनी भूमिका निभाएंगे, जंगल को सम्मान देंगे और ताकत के अविश्वसनीय काम करेंगे। वह मनुष्य से अपेक्षा करते हैं कि वह मनुष्य की तरह जिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर, अपने क्षेत्र में एक कार्य पूरा कर सकता है, निर्माता के दिल को खुश कर सकता है और पृथ्वी पर उसकी योजना में कुछ योगदान दे सकता है।

यही सच्चाई है। सत्य से अवगत होना ही चिंता मुक्त होना है। सत्य से अवगत होना भगवान के प्रति आभारी होना है। आपने मुझे अद्वितीय बनाया है। आपने मुझे एक भूमिका दी है। आपने

मुझे प्रेरित किया है। मेरी भूमिका को पूरा करने और मेरी भूमिका निभाने के लिए सभी सहायक कारक मेरे पास लाए हैं। इसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद देता हूं। इसके लिए मैं आपका सदा-सदा के लिए आभारी रहूंगा।

कोई भी त्यागने योग्य नहीं है। कोई भी बेकार नहीं है। ईश्वर की नजर में या उन लोगों की नजर में कोई भी कम नहीं है, जो मानवीय निर्णय और आलोचना के मानवीय मानकों से बचने की कोशिश करते हैं। जो ईश्वर की रचना को वैसे ही स्वीकार करते हैं, जैसी वह है, क्योंकि ईश्वर ने इसे बनाया है। उनके लिए, जो कुछ भी ईश्वर ने बनाना उचित समझा, किसी भी तरीके से, वह उत्तम है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उनके लिए यह स्वीकार्य है, जो कुछ भी ईश्वर से निकलता है। वह उसकी दिव्यता और पूर्णता का हिस्सा है। आप इसलिए ईश्वर की अपनी योजना में और ईश्वर के अपने तरीके से पूरी तरह से पूर्ण हैं।

व्यक्ति को आत्मा की शांति का आनंद लेना चाहिए। मैं आ गया हूं, मैं घर पर हूं, मैं भगवान की उपस्थिति में हूं और मुझे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है।

भेजें अपने सवाल

स्वर्ग-नरक की कल्पना का आधार क्या है?

पाप क्या है, पुण्य क्या है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? ईश्वर की आराधना कैसे करें? ऐसे सवाल अकसर हमारे मन में उठते हैं, पर इनका जवाब हमारे पास नहीं होता। मन-मस्तिष्क में आने वाले ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे पैनल में शामिल धर्माचार्य आपको देंगे।

अपने सवाल हमें इस पते पर भेजें :
धर्मक्षेत्रे, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301 (उत्तर प्रदेश)

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन प्रसन्न रहेगा। माता का सान्निध्य मिलेगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। कारोबार के लिए विदेश यात्रा लाभप्रद रहेगी।

वृष : धार्मिक संगीत में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार के लिए पिता से धन मिल सकता है। मित्रों के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी।

मिथुन : मन प्रसन्न तो रहेगा, परंतु आत्मविश्वास में कमी भी हो सकती है। दांपत्य सुख में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। माता की सेहत का ध्यान रखें।

कर्क : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं।

सिंह : मन परेशान रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

कन्या : मन परेशान हो सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। परिवार का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी।

तुला : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। नौकरी में अफसरों से सद्भाव बनाकर रखें। तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी।

वृश्चिक : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी।

धनु : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में लाभ में वृद्धि हो सकती है। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है।

मकर : मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। परिवार का साथ मिलेगा। भवन सुख में वृद्धि हो सकती है। परिवार में धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं।

कुंभ : शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों में मन लगेगा। लेखन आदि कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा।

मीन : वाणी में मधुरता रहेगी। कारोबार का विस्तार हो सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। किसी संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं। वस्त्र उपहार में मिल सकते हैं।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

27 जनवरी, मंगलवार, **शक संवत्**: 07 माघ (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग**: 14 माघ मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम**: 07 शब्बान, 1447, **विक्रमी संवत्**: माघ शुक्ल नवमी तिथि सायं 07.06 मिनट तक पश्चात दशमी तिथि, भरणी नक्षत्र प्रातः 11.09 मिनट तक पश्चात कृतिका नक्षत्र, शुक्ल योग रात्रि 03.13 मिनट तक पश्चात ब्रह्म योग, बालव करण। चंद्रमा मेष राशि में सायं 04.45 मिनट तक उपरांत वृष राशि में। **सूर्य उत्तरायण**। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। गुप्त नवरात्र समाप्त।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया यह बताएं कि सूर्य को जल अर्पित करते समय हम अपनी विभिन्न समस्याओं के लिए क्या उपाय करें। -कुमार मार्तण्ड, अयोध्या

■ यदि आपको जीवन में उचित मान-सम्मान नहीं मिल रहा है या फिर ऑफिस में स्थान नहीं बना पा रहे हैं, तो आप सूर्य को जल देते समय इस मंत्र का जाप करें- ऊं घृणि सूर्याय नमः। यदि आपको धन की समस्या निरंतर बनी हुई है या फिर कर्जा है, तो आप इस मंत्र का जाप सूर्य को जल देते हुए करें- ऊं सूर्याय नमः। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, तो सूर्य को जल देते समय सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें- मंत्र (पहला रूप) : ऊं भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि। तन्नो सूर्य प्रचोदयात॥

वर्ग पहेली : 8222

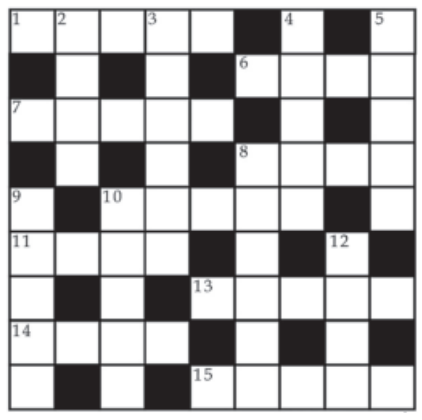

ऊपर से नीचे

2. सन्नद्धता; दक्षता; चतुराई (4)
3. नामकृत करना; नाम लिखना; मनोनीत करना (3,3)
4. सिर पर हाथ मारकर दुख या शोक करते रहना (2,3)
5. पराजय स्वीकार करना; हारना (2,3)
8. इधर से उधर तक जाना; एक छोर से जा कर दूसरे छोर से निकलना (2,2,2)
9. अपनत्व; आत्मीयता; स्वजन भावना (5)
10. क्रोध करना; दबदबा दिखाना (5)
12. ईश्वर; विधाता; ब्रह्मा; कर्ता; गृहपति (4)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली

(उत्तर अगले अंक में)

बाएं से दाएं

1. खौफनाक; डरावना; भयंकर; मारक; खतरे वाला; जोखिमपूर्ण; संकटात्मक (5)
6. कथा लिखने वाला; कहानीकार (4)
7. कम-से-कम घना; अत्यंत दुर्लभ; 'सघनतम' का विलोम; सबसे पतला (5)
8. वैभव; शान; ठसक; प्रतिष्ठा; मर्यादा (2,2)
10. गीला करना; भिगोना; सिंचित करना; शीतल करना; स्निग्ध करना (2,3)
11. धारण करना; ओढ़ना; काछना; डालना (4)
13. अपने लिए जगह निकालना; घर बनाना; बसना; रहना (2,3)
14. किसी अधिकारी के पद का सूचक (4)
15. अपराध में सम्मिलित करना; दाग लगाना; दोषी बनाना (2,3)

वर्ग पहेली : 8221

सुडोकू : 8204

* मध्यम

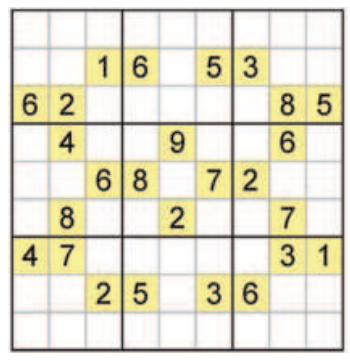

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8203

3	1	9	8	6	7	2	4	5
8	6	4	3	2	5	1	9	7
2	5	7	9	4	1	6	3	8
5	3	6	2	8	4	9	7	1
7	4	1	5	3	9	8	6	2
9	8	2	1	7	6	4	5	3
1	2	5	6	9	3	7	8	4
4	9	8	7	5	2	3	1	6
6	7	3	4	1	8	5	2	9

समझौता: भारत को ईयू के 45 करोड़ ग्राहकों तक पहुंच मिलेगी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। करीब 20 साल के लंबे इंतजार के बाद आज भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते से भारत को करीब 45 करोड़ ग्राहकों का विशाल बाजार उपलब्ध हो जाएगा।

यूरोपीय संघ 27 विकसित देशों का एक समूह है, जिसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, ग्रीस, हंगरी और आयरलैंड जैसे आदि प्रमुख देश शामिल है।

करीब 45 करोड़ की आबादी वाले इन देशों की कुल सकल घरेलू उत्पाद 20 से 22.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है। उधर,140 करोड़ की आबादी के हिसाब से युवा शक्ति के लिहाज से बड़े बाजार वाला देश है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच समझौता व्यापार को एक नई दिशा देगा।

लंबी वार्ता के बाद हो रही समझौते को दोनों पक्षों ने मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया है। इस समझौते के बाद भारत में यूरोप की लग्जरी कारें, चॉकलेट, शराब, वाइन, रफ डायमंड व इलेक्ट्रॉनिक्स सामान सस्ते होंगे। वहीं, भारत के कपड़े, चमड़ा, दवाइयां, इंजीनियरिंग सामान, रक्षा, आईटी और सेवा क्षेत्र को यूरोप का बड़ा बाजार मिलेगा।

मंगलवार को दिल्ली में भारत-ईयू शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा शामिल होंगे।

सम्मेलन में सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े समझौते भी होंगे लेकिन सबसे अहम व्यापार से जुड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। इस समझौते के बाद भारत के 95 से 99 फीसदी सामान की यूरोपीय बाजार में पहुंच शून्य या बेहतर कम आयात शुल्क के साथ होगी।

इसी तरह से यूरोप से आने वाले अधिकांश सामान सस्ते हो जाएंगे क्योंकि समझौते के तहत भारत भी यूरोपीय सामान को शुल्क मुक्त या फिर सीमित शुल्क के साथ पहुंच की इजाजत देगा।

रोजगार के लिहाज से भी भारत को बड़ा लाभ

इस समझौते के जरिए रोजगार के लिहाज से भी भारत को बड़ा लाभ होगा क्योंकि भारतीय चिकित्सक, इंजीनियर, बैंक कर्मचारी व अन्य संस्थानों में काम करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं के लिए यूरोप में नौकरियों के अवसर खुलेंगे। कुल मिलाकर 27 देशों में युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। उधर, समझौते के बाद यूरोपीय संघ में शामिल देश भारत में निवेश करेंगे। निवेश के जरिए भारत में नए उद्योग और दफ्तर खुलेंगे।

समझौते के बाद लग्जरी कारें होंगी सस्ती

एफटीए के तहत टैरिफ रेट कोटा के तहत समझौता होगा, जिसमें सालाना आधार पर लग्जरी गाड़ियों के यूरोप से भारत आयात करने का कोटा निर्धारित किया जाएगा। इन गाड़ियों को कम आयात शुल्क के साथ आयात करने की इजाजत होगी। सूत्रों का कहना है कि पहले चरण में 15 हजार यूरो यानी करीब 16.3 लाख से अधिक मूल्य वाली कारों को कम आयात शुल्क साथ सीमित संख्या में आयात करने की अनुमति होगी।

इन प्रमुख शहरों को मिलेगा लाभ

1. कपड़ा
तिरुपुर, सूरत, लुधियाना, पानीपत, मुंबई, जयपुर।

2. चमड़ा व उत्पाद
कानपुर, आगरा, कोलकाता व अन्य शहर।

3. दवाइयां
अहमदाबाद, मुंबई-ठाणे, हैदराबाद, इंदौर व अन्य शहरों से।

4. इंजीनियरिंग सामान
पुणे, अहमदाबाद,वडोदरा, मुंबई, झारसुगुडा, कानपुर जैसे अन्य औद्योगिक शहर।

भविष्य की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए विमानन क्षेत्र को लेकर घोषणाओं की उम्मीद

नए हवाई अड्डों के लिए धनराशि का ऐलान कर सकती है सरकार

बजट उम्मीदें

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत में बीते कुछ वर्षों के दौरान विमानन क्षेत्र में तेजी से यात्रियों की संख्या बढ़ी है, जिसके भविष्य में तेजी से बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सरकार नए हवाई अड्डों के विस्तार से लेकर बेड़े में शामिल होने वाले विमानों और उनके लिए समुचित ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रही है।

भविष्य की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए विमानन क्षेत्र को लेकर आगामी आम बजट में कुछ अहम ऐलान किए जा सकते हैं। भारत में वर्ष 2025 में हवाई यात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई, जो 25 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जिससे भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक बन गया है।

मौजूदा समय में संचालित हवाई अड्डों की संख्या 164 से अधिक है, जिसमें घरेलू, अंतरराष्ट्रीय, हवाई पट्टियां और नागरिक एन्क्लेव भी शामिल हैं। तेजी से बढ़ती यात्रियों की संख्या और बेहतर हवाई कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर अगले पांच वर्षों में देश 50 से अधिक नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाना है। इसी जरूरत को देखते हुए भारत ने 1700 नए यात्री विमानों को ऑर्डर दिया है, जो अगले पांच से 10 वर्षों में बेड़े में शामिल होंगे। ऐसे में हवाई यातायात की जरूरतों को ध्यान में रखकर केंद्रीय बजट में बड़े ऐलान होने की संभावना है। खासकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर केंद्र सरकार को बीते कुछ वर्षों में विशेष ध्यान रहा है। इसके लिए पहले से उड़ान योजना संचालित है, जो क्षेत्रीय संपर्क योजना है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना है।

बड़े शहरों के लिए नए एयरपोर्ट बनाने की योजना

बड़े शहरों में एक से अधिक हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। मुंबई में नवी मुंबई बनाया गया है जो संचालित हो चुका है। वहीं, दिल्ली और एनसीआर में आने वाले यात्रियों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए जेवर (गौतमबुद्धनगर) में नया हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जो अगले कुछ महीनों में संचालित होगा। ऐसे में बाकी बड़े शहरों के लिए भी नया हवाई अड्डा बनाने का ऐलान हो सकता है। बीते दिनों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक कार्यक्रम में कहा था कि देश भर में हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार 150 किलोमीटर के दायरे में दो हवाई अड्डों पर प्रतिबंध लगाने वाली नीति की समीक्षा करेगी।

2016 में यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसके तहत रियायती दरों पर उड़ानें और बेहतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है।

भारत में कलपुर्जे तैयार करने पर रहेगा जोर

अब सरकार हवाई जहाजों की मरम्मत और भारत में ही हवाई जहाज और उनके कलपुर्जे तैयार हों, इस पर भी ध्यान दे रही है। बजट में विमानों के स्पेयर पार्ट्स और छोटे विमानों के निर्माण के लिए पीएलआई योजना को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो भारत को एक वैश्विक उड्डयन केंद्र बनाने की दिशा में एक कदम है।

बैंक कर्मियों की हड़ताल का कामकाज पर असर संभव

नई दिल्ली, एजेंसी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) द्वारा पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल पर जाने के फैसले से मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कामकाज प्रभावित होने की आशंका है।

अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नौ संगठनों के संयुक्त निकाय यूएफबीयू द्वारा हड़ताल का यह आह्वान 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सुलह बैठक के विफल होने के बाद आया है।

चूंकि 25 जनवरी (रविवार) और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को बैंक बंद रहे हैं, इसलिए मंगलवार की हड़ताल के कारण लगातार तीन दिनों तक शाखा स्तर की सेवाएं बाधित रहेंगी। यूएफबीयू के घटक अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने बताया, सुलह कार्यवाही के दौरान विस्तृत चर्चा के बावजूद हमारी मांग पर कोई आश्वासन नहीं मिला। इसलिए, हम हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं।

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी) के महासचिव रूपम रॉय ने कहा कि मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) और यूएफबीयू के बीच सभी शनिवारों को छुट्टी घोषित करने पर सहमति बनी थी।

उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार हमारी वाजिब मांग पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इससे काम के घंटों का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करने पर सहमत हुए हैं।

'पांच-दिवसीय बैंकिंग कोई विलासिता नहीं'

यूएफबीयू के एक अन्य घटक नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज के महासचिव एल चंद्रशेखर ने कहा, यह आंदोलन ग्राहकों के खिलाफ नहीं, बल्कि एक टिकाऊ और मानवीय बैंकिंग प्रणाली के लिए है। पांच-दिवसीय बैंकिंग कोई विलासिता नहीं, बल्कि आर्थिक और मानवीय आवश्यकता है। एसबीआई, पंजाब पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में नकद जमा, निकासी, चेक निपटान और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने की आशंका है।

बाजार 30s

भारत में शुरू होगा रियल एस्टेट पाठ्यक्रम

नई दिल्ली। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी पीई एनालिटिक्स लिमिटेड और कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के भू-अर्थव्यवस्था विभाग ने भारत में रियल एस्टेट से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। गुरुग्राम स्थित पीई एनालिटिक्स रियल एस्टेट डेटा विश्लेषण मंच प्रॉपइक्विटी का संचालन करती है। पीई एनालिटिक्स ने बताया कि कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ इस साझेदारी से भारत में एक रियल एस्टेट स्कूल स्थापित करने में मदद मिलेगी।

भारत में ड्रीमलाइनर के ऑर्डर मिलेंगे: बोइंग

नई दिल्ली। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भारतीय बाजार में उसके ड्रीमलाइनर विमानों के लिए और अधिक ऑर्डर मिलेंगे। भारतीय विमानन बाजार आने वाले समय में बड़ी वृद्धि के लिए तैयार है। बोइंग भारत और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष सलिल गुप्ते ने भारतीय एयरोस्पेस के औद्योगीकरण के लक्ष्य पर जोर दिया।

एक्सिस बैंक को तीसरी तिमाही में मुनाफा हुआ

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े ऋणदाता एक्सिस बैंक ने सोमवार को दिसंबर तिमाही के लिए 7,010.65 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ घोषित किया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के 6,742.99 करोड़ रुपये के मुकाबले चार प्रतिशत अधिक है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए उसका शुद्ध लाभ पिछले साल के 6,303.77 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,489.57 करोड़ रुपये हो गया।

अदाणी को हाइब्रिड बिजली आपूर्ति का जिम्मा

नई दिल्ली। असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ हाइब्रिड बिजली आपूर्ति और ऊर्जा प्रबंधन समझौता किया है। एईएसएल का वाणिज्यिक और औद्योगिक विभाग हरियाणा (बावल), उत्तराखंड (रुड़की) और गुजरात (पाटन) स्थित विनिर्माण संयंत्रों की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 15.50 करोड़ यूनिट हाइब्रिड बिजली आपूर्ति का प्रबंधन करेगा।

पीवीआर आईनॉक्स ने ब्रांड मारिको को बेचा

नई दिल्ली। प्रमुख मल्टीप्लेक्स संचालक पीवीआर आईनॉक्स ने सोमवार को कहा कि उसने प्रीमियम अल्पाहार क्षेत्र में सक्रिय अपने बीसी ब्रांड को घरेलू एफएमसीजी दिग्गज मारिको को 226.8 करोड़ रुपये के नकद सौदे में बेच दिया है। बिजली परिवार द्वारा प्रवर्तित पीवीआर आईनॉक्स के बोर्ड ने जिया मेज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी 93.27 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी।

रेनो भारतीय बाजार को लेकर बेहद गंभीर

चेन्नई। फ्रांसीसी कार विनिर्माता रेनो ने सोमवार को भारतीय बाजार में अपने पुराने लोकप्रिय एसयूवी 'डस्टर' को दोबारा पेश करने के साथ ही अपनी पुरजोर मौजूदगी दर्ज कराने की प्रतिबद्धता जताई। रेनो ग्रुप के मुख्य वृद्धि अधिकारी फेब्रिस कैम्बोलिव ने नई डस्टर की पेशकश के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि कंपनी भारत को अपने पांच प्रमुख संभावनाशील बाजारों में एक मानती है।

पीआईडीएफ पर चिंता को अपरिपक्व बताया

नई दिल्ली। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज ने वन 97 कम्युनिकेशंस (पेटीएम) पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) प्रोत्साहन की स्थिति को लेकर जताई जा रही चिंताएं बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई हैं और समय से पहले हैं। एक निजी कंपनी द्वारा हाल ही में दाखिल किए गए आईपीओ के मसौदा पत्र में यह उल्लेख किए जाने के बाद पेटीएम के शेयरों में एक ही दिन में भारी गिरावट दर्ज की गई।

एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर्स में हिस्सा लेगी वारी

नई दिल्ली। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज (डब्ल्यूआरटीएल) ने सोमवार को कहा कि उसके बोर्ड ने एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर्स में 1,225 करोड़ रुपये में 55 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। कंपनी के एक बयान के अनुसार यह सौदा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण), ऊर्जा दक्षता और सहायक बुनियादी ढांचे को मिलाकर एक एकीकृत मंच बनाने की वारी की दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप है।

सीमा शुल्क और टीडीएस सरलीकरण की संभावना

बजट उम्मीदें 2

नई दिल्ली, एजेंसी। इस बार बजट से उम्मीद की जा रही है कि वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सीमा शुल्क ढांचे में जीएसटी की तर्ज पर बड़े बदलाव और कई अन्य सुधार देखने को मिल सकते हैं।

बजट में कर्ज और जीडीपी के अनुपात को कम करने पर भी ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि अब भारत का राजकोषीय प्रबंधन केवल घाटे को संभालने के बजाय कर्ज के बोझ को कम करने की दिशा में बढ़ रहा है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए, जिन्हें पिछले साल 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट और बाद में जीएसटी दरों में कटौती से बड़ी राहत मिली थी, इस बार मानक कटौती में और बढ़ोतरी की उम्मीद है।

उद्योग जगत को उम्मीद है कि एक अप्रैल से लागू होने वाले नए और सरल आयकर अधिनियम 2025 के बारे में बजट में स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए कुछ नए प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं, ताकि अधिक लोग पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई व्यवस्था को अपनाएं। इसके साथ ही टीडीएस की विभिन्न श्रेणियों और दरों को कम करके उन्हें और सरल बनाया जा सकता है।

सीमा शुल्क व्यवस्था में सुधार के तहत दरों को कम करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया जा सकता है। साथ ही विवादों में फंसे लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये को सुलझाने के लिए एक माफी योजना भी लाई जा सकती है।

रक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन के तहत केंद्र और राज्यों की भागीदारी वाली एक नई योजना के लिए भी बजट का प्रावधान किया जा सकता है।

वेतन आयोग लागू करने की घोषणा पर नजरें

सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद है, जिसे एक जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। राज्यों को मिलने वाले करों के हिस्से में भी 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ोतरी हो सकती है। एमएसएमई क्षेत्र और रत्न-आभूषण तथा चमड़ा जैसे उद्योगों के लिए विशेष रियायतों की उम्मीद है। इसके अलावा लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के लिए भी बजट में फंड दिया जा सकता है।

सिएटल में कारोबारी बैठक का आयोजन

सिएटल, एजेंसी। वाशिंगटन राज्य से अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा से पहले, सिएटल में आयोजित एक कारोबारी बैठक में एआई, कृषि प्रौद्योगिकी, क्वांटम और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर जोर दिया गया।

यह व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत और अमेरिकी प्रशांत उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने के प्रयासों के तहत इसी सप्ताह भारत का दौरा करेगा। प्रमुख उद्योग विशेषज्ञों ने भारत में निवेश के अवसरों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

तनाव बढ़ने से सोने की लंबी छलांग

नई दिल्ली, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय बाजार तनाव का असर एक बार फिर सोने की कीमतों की तेजी के रूप में पर साफ दिख रहा है। सोमवार 26 जनवरी 2026 को सोने ने वैश्विक सर्राफा बाजार में जोरदार उछाल दर्ज किया। वायदा सोने का भाव उछाल कर 5111 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया।

फरवरी डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 2.01 पर्सेंट की बढ़त के साथ 5,079.30 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करते नजर आए। एमसीएक्स के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार, 24 जनवरी को सोना 0.05 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 1,55,963 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

बीते रुझानों पर नजर डालें तो सोना निवेशकों के लिए लंबे समय से भरोसेमंद साबित हुआ है। हालांकि, भारत में गणतंत्र दिवस की छुट्टी के चलते कमोडिटी बाजार बंद रहा। वैश्विक स्तर पर सोने और कीमती धातुओं की कीमतों को प्रभावित करने वाले कई बड़े कारक सामने आए हैं।

1979 के बाद की सबसे बड़ी तेजी

साल 2025 में सोने ने 1979 के बाद की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की थी, जब कीमतों में 75 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया। वहीं, 2026 की शुरुआत से ही सोना मजबूत रफ्तार में है और महीने भर में ही करीब 17 पर्सेंट की बढ़त दिखा चुका है। बीते 20 सालों की बात करें तो सोने की कीमतों में करीब 1,500 फीसदी का इजाफा हुआ है, जो इसे बाजार में डर और अनिश्चितता का सबसे बड़ा पैमाना बनाता है।

रिलायंस ने जनवरी में रूसी तेल से दूरी बनाई

बेतुल (गोवा), एजेंसी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जनवरी में अब तक रूस से एक भी बैरल तेल नहीं खरीदा है। दूसरी ओर, सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों ने रूस से अपनी आयात मात्रा बढ़ा दी है, क्योंकि इस देश से मिलने वाली छूट अब लगभग सात डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। यह छूट 2025 के मध्य में मिलने वाली छूट के स्तर से लगभग तीन गुना अधिक है।

रिलायंस ने 2025 में रूस से प्रतिदिन लगभग छह लाख बैरल तेल खरीदा। उस वक्त रिलायंस रूस से तेल खरीदने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। हालांकि, उसने जनवरी के पहले तीन हफ्तों में रूस से कच्चे तेल की कोई खरीद नहीं की है। जलयानों की निगरानी करने वाले आंकड़ों और उद्योग के सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की है।

सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जनवरी में औसतन 4,70,000 बैरल प्रतिदिन की खरीदारी की, जो इसका अब तक का उच्चतम स्तर है।

दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा 4,27,000 बीपीडी था। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस महीने 1,64,000 बीपीडी तेल खरीदा, जो दिसंबर के 1,43,000 बीपीडी से अधिक है। रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट समर्थित नयारा एनर्जी ने इस महीने लगभग 4,69,000 बीपीडी तेल खरीदा।

यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण अन्य आपूर्तिकर्ताओं से कटे होने की वजह से नयारा पूरी तरह रूसी तेल पर निर्भर है। जनवरी के पहले तीन हफ्तों में रूसी तेल का कुल भारतीय आयात थोड़ा घटकर 11 लाख बीपीडी रह गया, जो दिसंबर में 12 लाख बीपीडी था। यह नवंबर के 18.4 लाख बीपीडी के मुकाबले काफी कम है। यह गिरावट रूस के दो सबसे बड़े तेल निर्यातकों - रोसनेफ्ट और लुकोइल पर 21 नवंबर से लागू हुए अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव को दर्शाती है।

07 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंची छूट, पिछले साले के मुकाबले तीन गुना हुई छूट

- इंडियन ऑयल ने 4,70,000 बैरल खरीदा, जो अब तक का उच्चतम स्तर है

'जीएसटी कटौती पर टिप्पणी नहीं'

नई दिल्ली, एजेंसी। उपभोक्ताओं का झुकाव अभी भी मुख्य रूप से एसयूवी खरीदने की ओर है और यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि जीएसटी कटौती के बाद छोटी कारों की मांग में जो तेजी देखी गई है, वह आगे भी बरकरार रहेगी या नहीं। टायर निर्माता कंपनी सिएट लिमिटेड के एमडी और सीईओ अर्नब बनर्जी ने यह बात कही।

उन्होंने बताया कि हालांकि जीएसटी कटौती ने बाजार को एक गति दी है, लेकिन कंपनी चालू वित्त वर्ष के लिए दहाई अंकों की वृद्धि के अपने पुराने अनुमान पर ही कायम है। कंपनी विशेष रूप से कृषि और दोपहिया टायरों के लिए ग्रामीण बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

यात्री कार खंड में जीएसटी कटौती के प्रभाव और छोटी कारों की मांग जारी रहने के सवाल पर बनर्जी ने कहा कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना समय से पहले होगा क्योंकि कुल मिलाकर ग्राहकों का रुझान अभी भी एसयूवी की तरफ बना हुआ है।

एसयूवी की बिक्री सबसे आगे रही

पिछले कुछ वर्षों में यात्री कार श्रेणी में एसयूवी की बिक्री सबसे आगे रही है, जबकि किफायती न होने के कारण छोटी कारों की बिक्री में गिरावट देखी गई थी। साल 2025 में भी भारत में बिकने वाले कुल यात्री वाहनों में एसयूवी की हिस्सेदारी 2024 के 53.8 प्रतिशत से बढ़कर 55.8 प्रतिशत हो गई, हालांकि जीएसटी कटौती के बाद छोटी कारों में भी सुधार के कुछ संकेत दिखे हैं। बनर्जी ने कहा कि हमें अभी एक और तिमाही तक इंतजार करना होगा ताकि यह देखा जा सके कि वाहन निर्माता जिस ढांचागत बदलाव को महसूस कर रहे हैं, क्या वह पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो छोटे आकार के टायरों की मांग फिर से बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि पुराने टायरों को बदलकर नया टायर लगाने वाले बाजार में ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच होने के कारण कंपनी को लाभ होगा।

Jawahar / Modi Style
JACKETS
SUITS • BLAZERS
ALSO AVAILABLE LONG COATS
upto 60% off
Formal • Casual • Party wear
By Economy Sales: 9212758425
ARROW | raymond | PARK AVENUE | LOUIS PHILIPPE
• PUNCHKUIAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.)
• GURUGRAM 306, City Center, Sector 29 (Near Hotel Pllazio)
• WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)
• NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP
• LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

हिन्दुस्तान नियुक्तियां

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

(रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न CPSE)

आरवीएनएल निम्नलिखित पदों के लिए तत्काल समायोजन पर आवेदन आमंत्रित करता है।

सामान्य योग्यता एवं अनुभव (दोनों पदों के लिए) : बी.टेक (सिविल) या समकक्ष, 25 वर्ष कुल पोस्ट–क्वालिफिकेशन अनुभव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में।

पदों की संख्या: 02 (प्रत्येक पद के लिए 01) । स्थान: पूरे भारत में । आयु: ≤ 57 वर्ष । वेतन (IDA) : E–9 ₹1,50,000 – ₹3,00,000 + भत्ते

रिक्ति सूचना	पद	क्षेत्र–विशेष अनुभव
2026/RVNL/09-CIVIL	कार्यकारी निदेशक (सिविल)	हाईवे / सड़क / एक्सप्रेसवे
2026/RVNL/10-CIVIL	कार्यकारी निदेशक (सिविल)	मेट्रो / अर्बन रेल / मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

आवेदन खुलने की तिथि: 24.01.2026 अंतिम तिथि: 13.02.2026
आवेदन का तरीका: उम्मीदवारों को सही चैनल के माध्यम से आवेदन करना आवश्यक है।
आवेदन की एडवांस कॉपी PDF फॉर्मेट में ई–मेल के माध्यम से भेजी जा सकती है।
विस्तृत योग्यता, शर्तें, आवेदन प्रपत्र और निर्देशों के लिए देखें: www.rvnl.org → Career → Jobs

आत्मा राम सनातन धर्म महाविद्यालय
(दिल्ली विश्वविद्यालय)
धौला कुआँ, नई दिल्ली - 110021

विज्ञापन सं. एआरएसडी/003/टी/2025-26 दिनांक: 27.01.2026

महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों/विभागों में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग पे-मैट्रिक्स के शैक्षणिक पे-लेवल 10, जिसमें 57,700/- रुपये के तर्कसंगत एंट्री-पे के साथ नियमानुसार सामान्य भत्ते शामिल हैं, के साथ सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से वेब-लिंक https://colrec.uod.ac.in पर दिए गए निर्धारित आवेदन फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 16.02.2026 या रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से दो सप्ताह तक, जो भी बाद में हो, है। दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवार को आवेदन फॉर्म भरने में किसी तरह की सहायता की जरूरत होने पर महाविद्यालय में स्थापित हेल्प-डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

क्रमांक	विषय	पदों की संख्या	सामान्य वर्ग (UR)	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जन जाति (ST)	अन्यपिछड़ा वर्ग (OBC)	आर्थिक रूप से कम जोर वर्ग (EWS)	#पीडब्ल्यूबीडी (अ.दृ./ दृ.बा./ वि.अ.दृ.) PWBD (LV/VI/SLD)
1	वाणिज्य	06	01	01	01	02	01	
2	अंग्रेजी	03	–	01	–	01	–	01 (दृ.बा)
3	हिन्दी	05	02	02	–	01	–	
4	इतिहास	01	–	–	–	01	–	–
5	गणित	08	02	01	01	01	02	01 (वि.अ.दृ)
6	फिजिकल एजुकेशन	01	01					
7	भौतिकी	04	01	–	–	02	01	
8	राजनीति विज्ञान	02	01	–	01	–	–	–
9	संस्कृत	01	01	–	–	–	–	
	कुल	31	09	05	03	08	04	02

#दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवार किसी भी श्रेणी के, यानि अ.र./अ.जा./अ.जन./अ. पि. वर्ग/ आ. क. वर्ग, के आवेदन कर सकते हैं।

इस्तेमाल किए गए संक्षिप्त रूप –
अ.र.(UR)- अनारक्षित, अ.पि. वर्ग (OBC)- अन्य पिछड़ा वर्ग, अ.जा. (SC)-अनुसूचित जाति, अ.जन. (ST)-अनुसूचित जनजाति, आ.क.वर्ग (EWS)- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पीडब्ल्यूबीडी (PwBD)- बेंचमार्क विकलांगता वाला व्यक्ति, अ.दृ.(LV)- कम दृष्टि, दृ.बा. (VI)- दृष्टि बाधित जिसमें दृष्टिबाधिता और अल्प-दृष्टि शामिल है, वि.अ.दृ. (SLD)- विशिष्ट अधिगम अक्षमता।

महत्वपूर्ण बिंदु
योग्यता, प्रकाशन, अनुभव, स्क्रीनिंग संबंधी दिशानिर्देश तथा निर्देशात्मक प्रारूप (प्रोफोर्मा) इत्यादि इस विज्ञापन के साथ महाविद्यालय की वेबसाइट www.arsdcollege.ac.in पर उपलब्ध है। आवेदन फॉर्म को भरने से पहले आवेदक इन विवरणों को ठीक से पढ़ लें। कोई भी संयोजन/ शुद्धिपत्र केवल महाविद्यालय की वेबसाइट पर ही सूचित किया जाएगा। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी कि वे महाविद्यालय की वेबसाइट www.arsdcollege.ac.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

ऑनलाइन आवेदन का लिंक 27.01.2026 से एक्टिव हो जाएगा।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16.02.2026 या रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से दो सप्ताह तक, जो भी बाद में हो, है।
प्राचार्य

संपादकीय जागरण

मंगलवार, 27 जनवरी, 2026 : माघ शुक्ल - 9 वि. 2082

इच्छाओं पर विवेक का अंकुश ही उचित है

यूजीसी के नए नियम

इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से लागू किए गए नए नियम इस कारण निशाने पर हैं कि वे बदले की कार्रवाई का जरिया बन सकते हैं। इसकी बड़ी वजह नए नियमों में भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित न किया जाना तो है ही, झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न करने का प्रविधान भी है। चूंकि इन नियमों को लेकर हो रहे विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है और विरोध करने वालों में सत्तारूढ़ भाजपा के नेता भी हैं, इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इन पर नए सिरे से विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। इसी के साथ इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और इसके तहत यूजीसी के नए नियमों को सामान्य बनाम अन्य के रूप में रेखांकित करने की कोशिश की जा रही है। इस क्रम में कुछ भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों के अनुसार सभी शिक्षा संस्थानों को समानता अवसर केंद्र बनाने होंगे, जिनमें एससी-एसटी के साथ ओबीसी वर्ग के छात्र, कर्मचारी और शिक्षक भी अपने खिलाफ जातिगत आधार पर हो रहे भेदभाव की शिकायत कर सकते हैं। पहले के नियमों में केवल एससी-एसटी वर्ग के छात्र ही शामिल थे।

यूजीसी के नए नियमों के तहत नस्ल, पंथ, क्षेत्र, जेंडर, दिव्यांगता आदि के आधार पर भी किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। विरोधियों का तर्क है कि इन आधारों पर तो किसी भी वर्ग के छात्र, कर्मचारी या शिक्षक के खिलाफ भेदभाव हो सकता है। चूंकि यह तर्क निराधार नहीं, इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि नए नियम केवल एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के लिए ही नहीं हैं। आखिर नए नियमों में यह प्रविधान शामिल करने में क्या कठिनाई है कि किसी भी वर्ग का छात्र, कर्मचारी या शिक्षक अपने खिलाफ भेदभाव की शिकायत कर सकता है? ऐसे किसी प्रविधान के न होने से यह ध्वनित हो रहा है कि भेदभाव तो केवल सामान्य वर्ग के लोग ही करते हैं। क्या इस धारणा को सही कहा जा सकता है? यूजीसी के नए नियमों को लेकर यह भ्रम भी दूर किया जाए कि समानता अवसर केंद्रों के सदस्य केवल आरक्षित वर्गों के लोग ही होंगे। इस सबके साथ ही सबसे अधिक आवश्यक यह है कि नए नियमों में झूठी शिकायत करने वालों को हतोत्साहित या फिर आवश्यक हो तो दंडित करने के भी उपाय किए जाएं, ताकि ऐसी शिकायतें न की जा सकें। इसकी अनदेखी न की जाए कि ऐसे कई कानून हैं, जिनका दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। इनमें एससी-एसटी उत्पीड़न के साथ दहेज और यौन हिंसा रोधी कानून प्रमुख हैं। यह ठीक नहीं कि समानता कायम करने वाले नियम समानता के ही सिद्धांत की अनदेखी करते दिखें।

आवश्यक कदम जरूरी

अवैध भूजल दोहन के लिए जिम्मेदार पांच अधीक्षण और कार्यकारी अभियंताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इन अधिकारियों ने वर्ष 2021 से 2024 तक अपने पद पर रहते हुए पहाड़गंज क्षेत्र में भूजल दोहन रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए। उनकी लापरवाही के कारण होटल संचालक लगातार अवैध भूजल दोहन करते रहे, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा। एनजीटी के आदेश पर दिल्ली सरकार ने इन जिम्मेदार अभियंताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया है। साथ ही, अवैध भूजल दोहन करने वाले 536 होटलों से 22.46 करोड़ रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी वसूला जा रहा है। अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली सहित एनसीआर के कई क्षेत्रों में धड़ल्ले से अवैध भूजल दोहन हो रहा है।

> भूजल दोहन रोकने के साथ वर्षा जल संचयन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, दिल्ली में हर वर्ष कुल वर्षा का चौथाई हिस्सा ही संरक्षित हो पाता है

भूजल दोहन रोकने के साथ-साथ वर्षा जल संचयन पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। दिल्ली में प्रतिवर्ष औसतन 775 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इसका केवल एक चौथाई हिस्सा ही संरक्षित हो पाता है। शेष पानी नालों में बह जाता है। उचित वर्षा जल संचयन व्यवस्था करके भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है और पेयजल की कमी भी दूर की जा सकती है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम सहित अन्य शहरों में भी भूजल संरक्षण पर ध्यान देना होगा।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या एक गणतंत्र के रूप में भारत की अभी तक की यात्रा संतोषजनक रही है?

आज का सवाल

क्या विश्व कप से पहले सैंजू सैमसन की खराब फार्म भारत के लिए चिंता का विषय है?

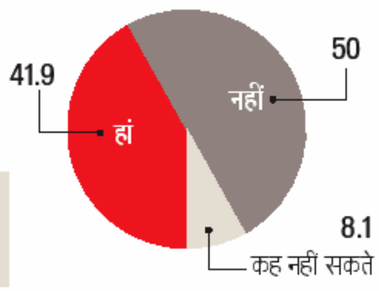

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

विश्व व्यवस्था को लेकर बढ़ती आशंका

विवेक काटजू

भारत के लिए उचित यही होगा कि वह डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित पीस बोर्ड में शामिल न होकर संयुक्त राष्ट्र वाली व्यवस्था को ही समर्थन दे और उसमें सुधारों की पैरवी करता रहे

इस समय अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आकार लेने वाली वैश्विक व्यवस्था के अस्तित्व से जुड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस व्यवस्था का तानाबाना बदल देना चाहते हैं। यह स्थापित वैश्विक व्यवस्था सभी देशों की संप्रभुता और समानता को प्रमुखता देती है। यह शक्ति के दुरुपयोग से देशों की क्षेत्रीय अखंडता से छेड़छाड़ को मान्यता नहीं देती। इसमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास होता है कि कोई भी देश व्यापार में किसी अन्य देश के प्रति भेदभाव न करे या अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। ट्रंप ने भेदभावपूर्ण टैरिफ लगाकर और ईरान में तख्तापलट की समर्थक ताकतों को शह देकर इन स्थापित मूल्यों को तोड़ा है। इससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को राजधानी काराकास से अगवा कर उन्होंने इस दक्षिण अमेरिकी पड़ोसी देश की संप्रुभता का खुला उल्लंघन किया। इसी क्रम में येन-केन प्रकारेण ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की उनकी मंशा डेनमार्क की क्षेत्रीय अखंडता पर आघात करने को आतुर दिखती है।

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के संचालक के तौर पर ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ट्रंप ने हाल में अपने नेतृत्व में जिस शांति बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है, उसे संयुक्त राष्ट्र के उनके संस्करण के रूप में में ही देखा जा रहा है। वैसे तो उनका कहना है कि इन दोनों संस्थाओं की जुगलबंदी काफी कारगर हो सकती है, लेकिन स्थापित संस्थाओं के प्रति ट्रंप का दुराग्रह किसी से छिपा नहीं रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर ट्रंप ने यह कहकर निशाना साधने में संकोच नहीं किया कि ये संस्थाएं अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पाईं। पिछले साल आपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में छिड़ी लड़ाई को रोकने का वे कई बार श्रेय ले चुके हैं, जबकि सच यही है कि पाकिस्तान की गुजारिश पर ही भारत ने संघर्ष विराम किया था। अब ट्रंप चाहते हैं कि उनका पीस बोर्ड हर तनाव और संघर्ष की स्थिति में हस्तक्षेप करे। स्पष्ट है कि वे चाहते हैं कि अमेरिका पूरी तरह से दुनिया पर हावी हो जाए और देशों के बीच संवाद एवं सहभागिता वही निर्धारित करे। इसका अर्थ होगा कि रूस, चीन, भारत और फ्रांस तथा जर्मनी जैसे महत्वपूर्ण देशों की भूमिका सीमित हो जाएगी। यही कारण है कि पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित तमाम देशों ने इससे जुड़ाव को लेकर उदासीनता दिखाई है। सुरक्षा परिषद के

अमेरिकी राष्ट्रपति की नई पहल को लेकर सहयोगी भी दिखा रहे उदासीनता ● फाइल

सदस्यों में ब्रिटेन और फ्रांस इसके चार्टर हस्ताक्षर समारोह में शामिल नहीं हुए। एक अन्य वीटो शक्ति वाले देश रूस ने भी इसमें भाग नहीं लिया तो कई यूरोपीय देश भी उसमें नदारद रहे। अरब के कुछ देश और पाकिस्तान जरूर इसमें शामिल हुए। पाकिस्तान का यह रुख कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए अमेरिका पर निर्भर है। चीन पर निर्भरता के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका को अनदेखा नहीं कर सकता। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के साथ पाकिस्तान के साथ संबंध फिर से पटरी पर आए हैं, जिसमें एक बड़ी भूमिका पाकिस्तान द्वारा आपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप के दावों को मानने की भी है। उसने नोबेल पुरस्कार के लिए भी ट्रंप के नाम की पैरवी की थी।

पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को निशाने पर रखने वाले ट्रंप अब जहां उसे नजदीक ला रहे हैं, वहीं कनाडा जैसे पड़ोसी और निकट सहयोगी उससे छिटक रहे हैं। इसकी टीस बीते दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बातों में सुनाई दी। दावोस में कार्नी ने कहा कि स्थापित वैश्विक व्यवस्था अब टूट गई है। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि हमें पता था कि इस व्यवस्था में आंशिक रूप से खामियां थीं और उसका स्वरूप भी सुविधाजनक था। अमेरिका और चीन में प्रतिस्पर्धा के परिदृश्य में उन्होंने अन्य देशों का आह्वान भी किया कि अगर सभी मिलकर काम करें तो अपनी आवाज दुनिया को सुना सकते हैं। ट्रंप के खैये से कार्नी जैसे पश्चिमी नेता भले ही वैश्विक व्यवस्था की विरूपताओं की ओर ध्यान दिला रहे हों, लेकिन वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों ने हमेशा यह महसूस किया है कि इस व्यवस्था के सिद्धांत और व्यवहार में विसंगतियां हैं। यही कारण है कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही वैश्विक दक्षिण की एकता के लिए काम किया है, ताकि वह अपने नजरिये को सामने रखते हुए एकजुट तरीके से अपने हितों की रक्षा कर सके। भारत ने बार-बार संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की बात की है और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए अपना दावा भी पेश किया है। भारत विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाना चाहता है।

भारत को भी पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता मिला है। भारत ने कहा है कि वह विचार-विमर्श के बाद ही इस संदर्भ में कोई निर्णय करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ पहलुओं की पड़ताल उपयोगी होगी। अगर वह इसमें शामिल होने से इन्कार करता है तो ट्रंप के नाराज होने की आशंका और बढ़ जाएगी, जो पाकिस्तान से संघर्ष समाप्त कराने में अपनी भूमिका को भारत द्वारा नकारे जाने के कारण कुपित हैं। उन्होंने पहले से ही भारत पर ऊंचे टैरिफ लगा रखे हैं, जिन्हें वे और बढ़ा सकते हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। वहीं, इस बोर्ड में शामिल होने के भी अपने जोखिम हैं। किसी बैठक के दौरान अगर ट्रंप कश्मीर को लेकर या भारत-पाक संबंधों पर कोई ऐसी बात कह दें, जिसका भारतीय प्रतिनिधि को वहां खुलकर विरोध करना पड़े तो यह बहुत असहज करने वाली स्थिति होगी। ऐसी स्थिति से बचा ही जाना चाहिए। यह भी तय नहीं है कि ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस बोर्ड का अस्तित्व बचा भी रहेगा या नहीं? इसमें सबसे उचित विकल्प यही रहेगा कि वह इस बोर्ड में शामिल न होकर संयुक्त राष्ट्र को समर्थन दे और उसमें सुधारों की बात को भी आगे बढ़ाता रहे।

(लेखक पूर्व राजनयिक हैं)

response@jagran.com

उदाहरण बनी भारतीय चुनाव प्रणाली

उमेश चतुर्वेदी

विविधता से भरे भारत में पश्चिम जैसा सामाजिक टकराव नहीं है तो एक वजह चुनाव प्रक्रिया में भारतीयों का भरोसा है

चुनावी साक्षरता अभियानों का दिखता असर ● फाइल

पश्चिमी देशों की नजर में लोकतंत्र वही है, जो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई मैग्नाकार्टा की संधि से उपजा। इस लोकतंत्र के नाते पश्चिमी देशों में एक खास तरह का श्रेष्ठताबोध है। ऐसे सोच वाले देशों में चुनाव कराने वाली संस्थाओं के संगठन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ डेमोक्रेटिक एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (आइडीईए) की अध्यक्षता भारत को मिलना मामूली बात नहीं। हाल में दिल्ली में चुनाव आयोग की अध्यक्षता में इस संगठन का सम्मेलन हुआ। इसके जरिये आयोग ने भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों से पश्चिमी देशों को एक तरह से परिचित कराने की कोशिश की। 1995 में 14 देशों द्वारा स्थापित इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या अभी 37 है। अमेरिका और जापान इसके स्थायी पर्यवेक्षक हैं। इस समय दुनिया की आबादी करीब आठ अरब है। इस लिहाज से यह संगठन करीब दो अरब बीस करोड़ पंजीकृत मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसमें अकेले भारत की हिस्सेदारी 99 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। इसके हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। घरेलू मोर्चे पर जिस समय भारतीय चुनाव प्रणाली और मशीनरी सवालों के घेरे में है, उसी वक्त चुनाव आयोग के हाथ इस संस्था की कमान आने का अर्थ है कि आयोग की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ रही है। इस दृष्टि से संगठन की अध्यक्षता भारत के लिए केवल औपचारिक दायित्व नहीं, बल्कि वैचारिक नेतृत्व का भी अवसर है।

आज भारत में मतदाताओं की चुनावों में भागीदारी लगातार बढ़ रही है। यह एक तरह से चुनाव व्यवस्था की सफलता है। चुनावी प्रबंधन में बढ़ता नवाचार, डिजिटल चुनाव प्रबंधन पर जोर, दिव्यांग और दूरस्थ क्षेत्रों के मतदाताओं तक बढ़ती पहुंच-ये सभी चुनाव आयोग के प्रयासों से ही संभव हुए हैं। चुनावी साक्षरता बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग ने बहुत प्रयोग किए हैं। विपक्षी सवालों के बावजूद चुनावों में मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी दिखाता है कि चुनाव आयोग के प्रति लोगों का भरोसा कम नहीं हुआ है। देश में चुनावी पवित्रता बनी हुई है, तो उसकी एक वजह भारत का पारंपरिक लोकतांत्रिक सोच है। दक्षिण भारत में दसवीं सदी के चोल शासकों ने ग्रामीण शासन व्यवस्था के लिए जो तंत्र विकसित किया था, उसे आधुनिक राजनीतिक विज्ञानी भी श्रेष्ठ मानते हैं। मैग्नाकार्टा से पहले कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत बसवेश्वर द्वारा स्थापित अनुभव मंडपम में समाज के हर वर्ग के लोग अपने धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते थे। राजनीतिशास्त्री इसे आधुनिक संसद का प्रारंभिक रूप मानते हैं। दुनिया में बढ़ता ध्रुवीकरण, दुष्प्रचार और साइबर हस्तक्षेप, चुनावों में काले धन का बढ़ता उपयोग तथा युवाओं की घटती रुचि ने आधुनिक लोकतंत्र के समक्ष गंभीर खतरे खड़े कर दिए हैं। जनमत को प्रभावित करने के लिए एआइ का बढ़ता इस्तेमाल कोढ़ में खाज का काम कर रहा है। ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में भारत के अनुभव और उसका सफल चुनावी माडल वैश्विक मंच पर लोकतांत्रिक देशों की चुनाव प्रणालियों के लिए आशा की किरण बन सकता है।

हमारे लोकतंत्र की ताकत केवल चुनाव प्रक्रिया नहीं, बल्कि हर वोट को मिली अहमियत से है। इसी वजह से विविधतापूर्ण समाज, भाषा, धर्म और असमानताओं के बावजूद भारतीय चुनाव प्रणाली शांतिपूर्ण बनी हुई है। बहुलतावादी समाज भारतीय लोकतंत्र की बाधा नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पश्चिमी देशों और ग्लोबल साउथ की लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों की तुलना में भारतीय चुनाव प्रबंधन कहीं अधिक उपलब्धिपूर्ण दिखाई देता है। अमेरिका और यूरोप में न केवल मतदाता भागीदारी लगातार घट रही है, बल्कि अविश्वास और सामाजिक टकराव जैसी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। इसके विपरीत विविधता के बावजूद हमारी व्यवस्था समाधान का शांतिपूर्ण माध्यम बनी हुई है। इसमें महिलाओं और युवा मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया है। आमजन का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति बढ़ता भरोसा भी इसी का प्रतीक है। विविध सामाजिक पहचान, जाति, पंथ और भाषा होने के बावजूद यदि भारत में पश्चिम जैसा सामाजिक टकराव नहीं है, तो इसकी प्रमुख वजह लोकतांत्रिक एवं चुनावी प्रक्रिया में भारतीय मतदाता का अटूट विश्वास है।

भिन्न सामाजिक पहचानों के बीच सामुदायिक संतुलन और सामाजिक सह-अस्तित्व हमारे लोकतंत्र की स्थिरता की गारंटी हैं। इसके पीछे चुनाव आयोग का सोच भी है। इसी सोच के कारण वह लगातार नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। ईवीएम, वीवीपैट, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों द्वारा संचालित तथा थीम आधारित मतदान केंद्र, पोस्टल बैलेट, सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित मतदाता सेवाएं और स्वीप जैसी पहलों को तेजी से व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आइआइटी, आइआइएम जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की सहभागिता यह दर्शाती है कि चुनाव प्रबंधन को केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक अकादमिक और नीति-आधारित अध्ययन क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसके चलते भारतीय लोकतंत्र का भविष्य पश्चिम की तुलना में अधिक व्यापक और स्थायी हुआ है। यही कारण है कि वैश्विक विमर्श में भारतीय चुनाव माडल दुनिया के लिए प्रेरक बन चुका है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

पश्चाताप

जीवन में मनुष्य अनेक निर्णय लेता है और हर निर्णय के अपने परिणाम भी होते हैं। इन्हीं परिणामों के बीच जब कोई भूल या असफलता सामने आती है, तब मन पश्चाताप से भर उठता है। पश्चाताप नकारात्मक न होकर आत्मबोध की अवस्था है, जहां व्यक्ति अपने भीतर झांकता है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब यह पश्चाताप आत्मचिंतन की सीमा लांघकर आत्मग्लानि में बदल जाता है। तब पश्चाताप न तो सुधार का मार्ग खोलता है और न शक्ति देता है, वह केवल मनुष्य को अतीत की बेड़ियों में बांध देता है।

गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं-मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब व्यक्ति अपने बीते निर्णयों और उनके परिणामों में उलझकर बैठ जाता है, तब उसका वर्तमान कमजोर पड़ने लगता है। व्यर्थ का पश्चाताप इसी स्थिति को जन्म देता है, जहां मन अतीत की छाया में जीने लगता है और वर्तमान की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आज का मनुष्य अपनी गलतियों को बार-बार स्मरण कर स्वयं को ही दोषी ठहराता रहता है। यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे उसके आत्मविश्वास को क्षीण और निर्णय क्षमता को कुंद कर देती है। गीता इसके विपरीत जीवन-दृष्टि प्रस्तुत करती है। वह सिखाती है कि भूलों से सीख लेना आवश्यक है, पर उन्हें अपना परिचय बना लेना आत्मघात के समान है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि हर परिणाम उसके वश में नहीं है, तब उसका मन हल्का होता है और चेतना का प्रवाह पुनः सक्रिय हो जाता है।

विवेक से जुड़ा पश्चाताप जीवन को परिष्कृत करता है, जबकि आत्मग्लानि से जन्मा पश्चाताप जीवन की गति रोक देता है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करे, पर उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दे। अतीत से सीख, वर्तमान में सजग कर्म और भविष्य के प्रति आशा ही पश्चाताप का सार्थक रूप है और यही व्यर्थ के पश्चाताप से मुक्ति का मार्ग भी है।

समराज चौहान

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

बदलते विश्व में भारत की नई राह

'विकसित गणतंत्र' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। इसमें बताया गया है कि सभी भारतवासी जीवंत गणतंत्र को शक्तिशाली बना रहे हैं। इसका सीधा संदेश यही है कि देश की प्रगति में हर किसी का योगदान होता है। भारतीय गणतंत्र के 76 वर्ष पूर्ण होना केवल एक मील का पत्थर नहीं, बल्कि एक कठिन वैश्विक भू-राजनीतिक मोड़ पर आत्ममंथन का क्षण भी है। आज जब अमेरिका जैसी महाशक्तियां संरक्षणवाद और ग्रीनलैंड विवाद, व्यापारिक शुल्क जैसी अनिश्चित नीतियों की ओर झुक रही हैं तब 'नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था' के अस्तित्व पर संकट गहरा गया है। ऐसे में भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) और रक्षा सहयोग की पहल एक रणनीतिक अनिवार्यता बन गई है। यूरोपीय नेताओं की गणतंत्र दिवस पर उपस्थिति इसी उभरते ध्रुवीकरण का प्रमाण है। इस समय भारत के लिए चुनौती दोहरी है। बाहरी रूप से उसे रूसी तेल या कार्बन टैक्स जैसे मुद्दों पर अपने हितों की रक्षा करनी है तो दूसरी ओर आंतरिक रूप से 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने हेतु अपनी आर्थिक गति को और तीव्र करना है। डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे में भारत की प्रगति सराहनीय है, लेकिन उसके मार्ग में कई चुनौतियां भी हैं। प्रतिकूल वैश्विक परिवेश में भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कितनी शीघ्रता से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक सुधारों के बीच संतुलन बैठा पाता है। इस समय बैठाया गया संतुलन विकसित भारत की नींव का पत्थर साबित हो सकता है।

अमृतलाल मारू, इंदौर, मप्र

बांग्लादेश क्रिकेट का पतन

टी-20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को आइसीसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। टी-20 विश्वकप में भारत में ना खेलने की जिद बांग्लादेश को महंगा पड़ सकता है। लोग पैरों पर कुल्हाड़ी मारते है लेकिन बांग्लादेश ने खुद कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया है, तो गलत नहीं होगा। भारत में विश्व कप में ना खेलने के कारण बांग्लादेश क्रिकेट आर्थिक रूप से तबाह हो जाएगा। इस फैसले के बाद बांग्लादेश को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आइसीसी और बीसीसीआइ से पंगा लेकर बांग्लादेश क्रिकेट आर्थिक रूप से तबाह हो जाएगा। विश्व कप की धनराशि, स्पांसर धनराशि, प्रसारण धनराशि इन सब का आर्थिक झटके का बांग्लादेश को सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश विश्व क्रिकेट से अलग-थलग पद सकता है। भारत के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों पर भी चोट पहुंच सकती है। आइपीएल से भी पाकिस्तान की तरह बांग्लादेशी क्रिकेटरों को आगे भी खेलने से रोका जा सकता है। बांग्लादेश द्वारा भारत में विश्व कप में ना खेले जाने वाली घटना को बीसीसीआइ इतने आसानी से नहीं भूलेगा। बीसीसीआइ बांग्लादेश को दिए जाने वाले हर तरह के क्रिकेट की मदद को ना सिर्फ रोक सकता है बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट के अस्तित्व पर भी प्रहार कर सकता है, क्योंकि सभी जानते है कि बांग्लादेश में क्रिकेट के विकास में बीसीसीआइ का योगदान कितना महत्वपूर्ण था।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

झूठे जीवन प्रमाण पत्र

11 और 13 जनवरी को दैनिक जागरण में प्रकाशित चित्रकूट कोषागार में मृत पेंशनधारकों के फर्जी जीवन प्रमाण-पत्र बनाकर सरकारी धन की धोखाधड़ी व कई धोखेबाजों को जेल भेजे जाने संबंधी समाचार एक ऐसे कानून-पालक नागरिक के लिए चिंताजनक हैं, जो कड़ी मेहनत से अर्जित आय पर कर अदा करता है। इन्हीं करों से सरकार राजस्व व पूंजीगत व्यय वहन करती है तथा पेंशन का भुगतान करती है। चित्रकूट कोषागार में हुई धोखाधड़ी के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उत्तर प्रदेश के कोषागारों के अभिलेखों की जांच कर ऐसे अन्य धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने के आदेश देने पड़े। कोषागारों एवं बैंकों में जाली जीवन प्रमाण-पत्रों के माध्यम से की गई धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए जांच की आवश्यकता है, इससे सरकारी धन की भारी हानि होती है, जो देश में सैकड़ों करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसका अतिरिक्त कर-भार ईमानदार करदाताओं पर पड़ता है। जीवन प्रमाण एप का उपयोग कागजी जीवन प्रमाण-पत्र की सुविधा के अतिरिक्त स्वैच्छिक है, इसलिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को सभी पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण एप का उपयोग अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि कागजी जीवन प्रमाण-पत्रों की जालसाजी संभव है। जीवन प्रमाण एप में पेंशनभोगी के जीवित होने की पुष्टि अंगुलियों के निशान या आंखों की पुतलियों के माध्यम से की जाती है, जिन्हें जाली नहीं बनाया जा सकता।

डा. एनके धूपर, गाजियाबाद

पोस्ट

समृद्धि का यही सूत्र है कि अगर आपकी आमदनी बढ़े तो खर्चे बढ़ाने के बजाय बचत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

नित्या श्री@Nithya_Shrii

जब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी और देश में पर्यटन गतिविधियां भी ठप पड़ गई थीं तो उसे उबारने के लिए भारत और भारतीय ही सबसे आगे आए। जब अन्य बाजारों ने श्रीलंका से दूरी बढ़ा ली तो भारत ने उसमें भरोसा बनाए रखा। भारत जैसे सच्चे दोस्त को श्रीलंका कभी नहीं भूलेगा। हमारी यही कामना है कि एक गणतंत्र के रूप में भारत निरंतर आगे बढ़ता रहे।

सोनल जयविक्रमा@sonaljay8

शिक्षा संस्थानों में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है और तमाम छात्र इसके दुष्परिणाम झेल चुके हैं, लेकिन इसके समाधान में किसी भी कानून को समावेशी होकर सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? कैंपस में नकारात्मक माहौल बनाने के बजाय यूजीसी की यह अधिसूचना या तो वापस ली जाए या उसमें आवश्यक संशोधन किया जाए।

प्रियंका चतुर्वेदी@priyankac19

जनपथ

मैडम जी यूरोप से लाई बढ़िया डील,
अब पतंग डोनाल्ड की काटो देकर ढील।
काटो देकर ढील बहुत देखी नौटंकी,
ना होगा व्यापार पार्टनर हो जब सनकी।
बना रहे सम्मान भले इनकम हो कम जी,
बस इतना सा ख्याल आप रखना मैडम जी!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 193

एमएसएमई रोजगार सृजित करने का सबसे शक्तिशाली प्लेटफार्म हैं और अगर भारत को समृद्ध बनना है तो इससे ज्यादा प्रभावी कुछ नहीं है। – **जीतन राम मांझी**, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री

ईयू के साथ व्यापार समझौता वार्ता पूरी, घोषणा आज

तीन सप्ताह बाद समझौते का मसौदा होगा सार्वजनिक, कानूनी मशविरे के बाद पहनाया जाएगा अमलीजामा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : 27 देशों वाली यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ चल रही व्यापार समझौता वार्ता पूरी हो गई है। मंगलवार को दोनों पक्ष वार्ता पूरी होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। इस व्यापार समझौते के अमल में आते ही ईयू को निर्यात होने वाली 90 प्रतिशत भारतीय वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ईयू से आने वाली 30 प्रतिशत वस्तुओं को ही पहले साल में शुल्क से मुक्त किया गया है। हालांकि, इस समझौते पर अमल में 10-12 महीने का समय लग सकता है।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि वार्ता पूरी होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के तीन सप्ताह बाद समझौते के मसौदे को सार्वजनिक किया जाएगा। फिर कानूनी मशविरा के बाद दोनों पक्ष व्यापार समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद इस पर अमल की प्रक्रिया शुरू होगी। इस समझौते से दोनों पक्षों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि यूरोपीय काउंसिल व यूरोपीय कमीशन के प्रमुख इन दिनों भारत में हैं।

ईयू से व्यापार समझौते पर कृषि संबंधित आइटम के साथ लेदर फुटवियर, केमिकल, टेक्सटाइल जैसे आइटम पर शुल्क समाप्त होने से इनके निर्यात में खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के संवेदनशील उत्पादों को व्यापार समझौते से दूर रखा है। इसलिए, भारत ने अपने कृषि व डेरी सेक्टर को ईयू के लिए नहीं खोला है। ईयू ने भी भारत के लिए अपने अनाज व मांस बाजार को शुल्क मुक्त नहीं किया है। ईयू सालाना तीन लाख करोड़ डालर का वस्तु आयात करता है जहां भारत को अपना निर्यात बढ़ाने का बड़ा मौका मिलेगा।

व्यापार समझौते में सर्विस सेक्टर को भी शामिल किया गया है और 140 से अधिक प्रकार के सब-सर्विस सेक्टर ईयू ने भारत के प्रोफेशनल्स व अन्य लोगों के लिए खोलने का वादा किया है। भारत ईयू के लिए 102 छोटे-छोटे सर्विस सेक्टर को खोल रहा है।

अमेरिकी शुल्क के बाद माना जा रहा अहम

दोनों पक्षों के बीच पिछले 17 सालों से व्यापार समझौते पर वार्ता चल रही थी जो बीच-बीच में किसी न किसी कारण से टूट जाती थी। वर्ष 2013 में यह वार्ता ईयू की तरफ से आटो सेक्टर में छूट की मांग को लेकर टूट गई थी। इस बार कीमती कारों के शुल्क में ईयू को सीमित छूट दी गई है। ईयू की वाइन भी अब सस्ते दाम पर मिलेंगी। भारतीय वाइन निर्माता को भी अपनी वाइन ईयू के देशों में निर्यात करने का मौका मिलेगा। भारत ईयू में 70 अरब डालर से अधिक का निर्यात करता है और इनमें से 30 अरब डालर के निर्यात पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। इनमें से अधिकतर आइटम कृषि व प्रोसेस्ड फूड या फिर रोजगारपरक सेक्टर से संबंधित है। अमेरिका की तरफ से 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद ईयू के साथ यह व्यापार समझौता काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि कई रोजगारपरक सेक्टर का निर्यात अमेरिका के बाजार में गत सितंबर से प्रभावित होने लगा है।

- दोनों पक्षों के बीच होने वाले समझौते पर अमल में लग सकता है 10-12 महीने का समय
- भारत समझौते के तहत ईयू के लिए 102 छोटे-छोटे सर्विस सेक्टर को खोलेगा

3 लाख करोड़ डालर का वस्तु आयात करता है ईयू प्रतिवर्ष

70 अरब डालर से अधिक का निर्यात करता है भारत ईयू को

ईयू से आयातित कारों पर घट सकता है शुल्क

सूत्रों के हवाले से रायटर के अनुसार, भारत ईयू से आयातित कारों पर शुल्क को 110 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर सकता है। व्यापार समझौते में इसकी घोषणा हो सकती है।

सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार ने 15,000 यूरो (17,739 डालर) से अधिक मूल्य की कुछ कारों पर तुरंत कर कम करने पर सहमति जताई है। समय के साथ इसे और घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा, जिससे फाक्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी यूरोपीय आटोमोबाइल कंपनियों के लिए भारतीय बाजार तक पहुंच आसान हो जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले पांच वर्षों तक टैरिफ में कोई कटौती नहीं होगी।

2025 में शेयर बाजार में रहा युवा निवेशकों का दबदबा

नई दिल्ली, एएनआइ: भले ही महामारी के बाद नए निवेशकों के जुड़ने की रफ्तार में कमी के संकेत मिल रहे हों, लेकिन 2025 में भी इक्विटी मार्केट में युवा निवेशकों का दबदबा रहा। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में जुड़े हर 100 नए निवेशकों में से लगभग 56 निवेशक 30 साल से कम उम्र के थे। इससे इक्विटी मार्केट में युवाओं की लगातार भागीदारी का पता चलता है। 2024 में यह आंकड़ा 54.2 प्रतिशत था और उस समय नए निवेशकों का पंजीकरण अपनी शीर्ष पर था।

2025 के आखिर तक, 30 साल और उससे कम उम्र के निवेशकों का कुल पंजीकरण निवेशक आधार का लगभग 38.7 प्रतिशत था जो 2018 में लगभग 22.7 प्रतिशत से काफी ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं का पंजीकरण बढ़ रहा है, लेकिन निवेशक आबादी थोड़ी उम्रदराज हो गई है, क्योंकि महामारी के बाद बाजार में आए कई निवेशक अब ज्यादा उम्र के ब्रैकेट में चले गए हैं। इस वजह, नए निवेशकों की औसत उम्र लगभग 28 वर्ष पर स्थिर रही है, जो पहली बार निवेशकों की लगातार दिलचस्पी को दिखाता है। युवाओं की हिस्सेदारी के साथ-साथ, रिपोर्ट में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है। एनएसई के व्यक्तिगत निवेशक आधार में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी 2025 में 24.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

- जुड़ने वाले प्रत्येक 100 में से लगभग 56 निवेशक 30 साल से कम उम्र के
- 2022 से लगातार बढ़ रही महिला निवेशकों की हिस्सेदारी, 2025 में यह 24.8% हुई

भारतीय परिवारों ने म्यूचुअल फंड के जरिये इक्विटी में किया निवेश

एनएसई की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में रिकार्ड प्रवाह के बाद इक्विटी मार्केट में व्यक्तिगत निवेशकों की सीधी भागीदारी भले ही कम हो गई है, लेकिन भारतीय परिवारों ने म्यूचुअल फंड के जरिये अपनी बचत को इक्विटी में लगाना जारी रखा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में 1.7 लाख करोड़ रुपये के शुद्ध निवेशक और पिछले पांच सालों में लगातार खरीदारी के बाद व्यक्तिगत निवेशक 2025 में थोड़े नेट सेलर बन गए। साल के दौरान, व्यक्तिगत निवेशकों ने 5,717 करोड़ रुपये निकाले हैं। इसके बावजूद पिछले छह सालों में एनएसई के सेकेंडरी मार्केट में व्यक्तिगत निवेशकों का कुल शुद्ध निवेश 4.5 लाख करोड़ रुपये पर मज़बूत बना रहा।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए रुकेन करें या विजिट करें jagran.com

12 लाख करोड़ रुपये के पार जा सकता है पूंजीगत खर्च

- एसबीआइ ने कहा- कमोडिटीज की कीमतों में तेजी का असर थोक महंगाई पर दिखेगा
- नामिनल जीडीपी अनुमान के आधार पर राजकोषीय घाटा 4.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद

नई दिल्ली, आइएएनएस: एसबीआइ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि आर्थिक बुनियादी कारक मजबूत बने हुए हैं और इसकी वजह से भारत एक अच्छी स्थिति में है। ऐसे में अगले वित्त वर्ष में सरकारी पूंजीगत खर्च 10 प्रतिशत बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये को पार कर सकता है। जरूरी नामिनल (बाजार दरों पर) जीडीपी 10.5-11 प्रतिशत रहने की उम्मीद है और वैश्विक कमोडिटीज की कीमतों में तेजी का असर थोक महंगाई पर दिख सकता है। अगर नामिनल जीडीपी थोड़ी धीमी रहती है तो इससे कर राजस्व को नुकसान हो सकता है। ऐसे में बेहतर खर्च की प्लानिंग करनी होगी।

नामिनल जीडीपी अनुमान के आधार पर अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 4.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। एसबीआइ के मुख्य आर्थिक सलाहकार डा. सौम्य कांति घोष ने अगले वित्त वर्ष में सरकार से उधार लेने की लागत 6.8-7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष में अनुमानित शुद्ध सेंट्रल उधारी 11.7 लाख करोड़ रुपये और 4.60 लाख करोड़ रुपये का रीपेमेंट होना है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि क्योंकि आम सरकारी कर्ज में राज्यों का एक बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए राज्यों के बजट में साफ तौर पर कर्ज से जीएसडीपी को वास्तविक वृद्धि और विकास की जरूरतों के हिसाब से बनाना चाहिए न कि सिर्फ सालाना घाटे के लक्ष्य पर निर्भर रहना चाहिए।

वैश्विक बाजार में पांच हजार डालर प्रति औंस के पार पहुंचा सोना

नई दिल्ली, आइएएनएस: वैश्विक अनिश्चिताओं और सुरक्षित निवेश मांग के बीच वैश्विक बाजारों में सोना और चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। सोमवार को वैश्विक स्तर पर सोना पहली बार पांच हजार डालर के पार जाकर 5,026 डालर प्रति औंस के उच्च स्तर तक पहुंचा। जनवरी 2024 में सोना दो हजार डालर प्रति औंस से थोड़ा ज्यादा था।

चांदी की कीमत भी पहली बार 102 डालर प्रति औंस पर पहुंची है। एक औंस में 28.35 ग्राम वजन होता है। आनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के अनुसार, सुरक्षित निवेश की मांग, केंद्रीय बैंकों की ओर से खरीदारी और आसान वैश्विक मौद्रिक स्थितियों की उम्मीदें सोना-चांदी की कीमतों को समर्थन दे रही हैं। 2026 की पहली तिमाही के बाकी समय में भी कीमती धातुओं का परिदृश्य सकारात्मक बना है।

अमेरिकी शुल्क से प्रभावित रोजगारपरक सेक्टर को बजट में मिल सकती है राहत

- लेदर आइटम, जेम्स व ज्वेलरी, गारमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात हो रहा प्रभावित
- वित्त मंत्रालय ने नुकसान के आकलन के बाद वित्तीय मदद करने का दिया है भरोसा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: अमेरिका की तरफ से पिछले साल अगस्त में भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद रोजगारपरक सेक्टर का निर्यात प्रभावित होता दिख रहा है। इनमें मुख्य रूप से लेदर आइटम, जेम्स व ज्वेलरी, गारमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स शामिल हैं। आगामी एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में इन वस्तुओं के लिए अलग से प्रोत्साहन का एलान किया जा सकता है।

पिछले साल सितंबर से ही इन सेक्टर का अमेरिका में होने वाला निर्यात प्रभावित होने लगा था। तब से ही ये सेक्टर अपने निर्यात प्रोत्साहन के लिए अलग से इंसेंटिव या अन्य आर्थिक मदद की मांग कर रहे थे। वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि पहले ये अपने नुकसान का आकलन करें और फिर उसके हिसाब से सरकार इनके लिए वित्तीय मदद को लेकर कोई कदम उठाएगी।

पिछले साल नवंबर तक अमेरिका व भारत के बीच व्यापार समझौता होने की पूरी उम्मीद दिख रही थी। समझौता होने पर प्रभावित सेक्टर के निर्यात में फिर से तेजी आ जाती। इसलिए, सरकार भी इन सेक्टर को किसी वित्तीय सहायता देने के मामले में इंतजार करो की नीति अपना रही थी। फिलहाल की स्थिति में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर कुछ भी दावा नहीं किया जा सकता है।

वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी भी साफ-साफ कह चुके हैं कि यह समझौता कभी भी हो सकता है, लेकिन समय निर्धारण नहीं किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी स्थिति में सरकार जिन सेक्टर का निर्यात ज्यादा प्रभावित हो रहा है या जिन्हें अब अमेरिका से निर्यात के आर्डर काफी कम या नहीं मिल रहे हैं, उनके निर्यात प्रोत्साहन को लेकर अलग से मदद दे सकती है। कई ऐसे निर्यातक हैं, जिनका निर्यात कारोबार सिर्फ अमेरिका के बाजार पर निर्भर करता है। उन्होंने सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे रखा है। अगर उनके निर्यात आर्डर में कटौती होती है तो उन्हें अपना उत्पादन कम करना होगा, जिससे रोजगार भी प्रभावित होगा।

जनवरी में चार प्रतिशत से ज्यादा लुढ़के सेंसेक्स-निफ्टी

नई दिल्ली, प्रेट्र : शेयर बाजारों के लिहाज से कैलेंडर वर्ष 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। विदेशी फंडों की लगातार निकासी, रुपये में कमजोरी, कारपोरेट आय में सुस्ती, भूराजनीतिक जोखिम और टैरिफ संबंधी नई चिंताओं के कारण पहले महीने में दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी चार प्रतिशत से ज्यादा लुढ़क चुके हैं। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड के रिसर्च प्रमुख संतोष मीना का कहना है कि ऐतिहासिक रूप से जनवरी में बजट से पहले ऐसे रुझानों में तेज गिरावट देखी गई है, जिसमें गणतंत्र दिवस के बाद सुधार होता है। बाजार के प्रतिभागियों को इस बार भी इसी तरह के उलटफेर की उम्मीद है। जनवरी 2025 में भी बीएसई सेंसेक्स 638.44 अंक या 0.81 प्रतिशत गिर चुका था। इसके पहले जनवरी 2024, 2023, 2022, 2021 और 2020 में भी बीएसई बेंचमार्क में गिरावट आई थी।

राष्ट्रीय जागरण

एक नजर में

गाजा में अंतिम इजरायली बंधक का शव मिला

यरुशलम: गाजा में अंतिम इजरायली बंधक रान जिविली का शव मिल गया है। बंधक के शव की तलाश में इजरायली सैनिकों ने सोमवार को गाजा सिटी के तुफाह स्थित कब्रगाह में खोदाई की थी। इजरायली सैनिकों ने यह कार्रवाई हमास की ओर से यह बयान आने के बाद की...कि बंधक के अवशेषों की तलाश में वह विफल रहा है। हमास ने कहा कि युद्धविराम समझौते के तहत बंधक के अवशेषों की तलाश में उसने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया। इस बीच गाजा में इजरायली सैनिकों की फायरिंग में दो फलस्तीनियों की मौत की सूचना है। (एपी)

अश्लील तस्वीरों को लेकर ग्रोक के खिलाफ जांच शुरू

ब्रसेल्स: एलन मस्क की कंपनी एक्स पर यूरोपीय संघ द्वारा अवैध सामग्री के प्रसार की जांच की जा रही है। यह जांच कंपनी के 'ग्रोक' द्वारा अश्लील तस्वीरों के प्रसार को लेकर भारी विरोध के बाद शुरू हुई है। 27 देशों के इस समूह की कार्यकारी शाखा, यूरोपीय आयोग ने सोमवार को कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या एक्स ने ग्रोक की कार्यप्रणाली से संबंधित जोखिमों का आकलन और निवारण करके यूजर्स की सुरक्षा की है। यह जांच ब्रिटिश मीडिया नियामक आफकाम द्वारा ग्रोक द्वारा यौन रूप से अंतरंग डीपफेक तस्वीरें बनाने की आशंकाओं पर जांच शुरू करने के दो सप्ताह बाद और इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया द्वारा चैटबाट को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने के बाद शुरू हुई है। (रायटर)

रतलाम में बंदूक की दुकान में धमाका, फैली दहशत

रतलाम: मध्य प्रदेश में रतलाम शहर के व्यस्त चांदनी चौक क्षेत्र में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक आर्म्स दुकान में जोरदार धमाका हो गया। धमाके के बाद दुकान में आग लग गई, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। झुलसने के बाद एक व्यक्ति का मदद मांगते हुए वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुकान में वेल्डिंग का कार्य चल रहा था, इसी दौरान निकली चिंगारी बारूद पर जा गिरी, जिससे विस्फोट हो गया। (नईदुनिया प्रतिनिधि)

जयपुर और लुधियाना में ईडी ने 1986 करोड़ की संपति की अटैच

जासं, जयपुर: ईडी ने पंजाब के लुधियाना और राजस्थान के जयपुर में 1986.48 करोड़ रुपये की 37 अचल संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच किया है। यह कार्रवाई मैसर्स एग्रोटेक कार्पोरेशन लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों की ओर से चलाई जा रही कलेक्टिव निवेश योजना से जुड़े वित्तीय अनियमितता की जांच के सिलसिले में पीएमएलए के नियमों के तहत की गई। कंपनी द्वारा खेती की जमीन की बिक्री और विकास की आड़ में लाखों निवेशकों से 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई थी।

सीबीआइ ने साल 2014 में दिल्ली में मामला दर्ज किया था। कंपनी मालिक निर्मल सिंह भंगू ने लोगों को जाल में फंसाकर ठगी की थी। पंजाब के 10 लाख से अधिक व राजस्थान में लाखों लोग ठगी का निशाना बने। सीबीआइ जांच में सामने आया कि लोगों को कैश पेमेंट व किस्तों के जरिए निवेश करने के लिए तैयार किया गया। जांच के दौरान भंगू का निधन हो गया। सीबीआइ ने भंगू की पत्नी प्रेम कौर, बेटी बरिंदर, सुखविंदर और दामाद गुरप्रताप एवं सहयोगी प्रतीक के खिलाफ वारंट जारी किए।

म्यांमार के गृहयुद्ध में घातक मोड़, आसमान से मौत बरसा रही सेना

- सरकार विरोधी ताकतों पर हमलों के लिए कर रही पैरामोटर एवं जायरोकाप्टर का इस्तेमाल
- फरवरी 2021 में तख्तापलट के बाद से जारी हिंसा में अबतक 7,700 नागरिक मारे जा चुके

बैंकाक, एपी : म्यांमार के गृहयुद्ध में अब एक नया और घातक मोड़ आ गया है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार की सैन्य सरकार (जुंटा) अब आम नागरिकों और सरकार विरोधी ताकतों पर आसमान से हमला करने की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 'पैरामोटर' और 'जायरोकाप्टर' जैसे कम तकनीक वाले फ्लाइंग मशीनों (उड़ने वाले यंत्रों) का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। मानवाधिकार संगठन 'फोर्टिफाई राइट्स' ने अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है कि सेना इन मशीनों के जरिए आसमान से मौत बरसा रही है।

पैरामोटर दरअसल एक पैराग्लाइडर होता है जिसमें पीछे की ओर एक प्रोपेलर लगा होता है, जबकि जायरोकाप्टर एक छोटा, एक या दो सीटों वाला विमान होता है जिसमें हेलीकाप्टर की तरह घूमने वाले ब्लेड होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार की सेना इन उड़ने वाली मशीनों का उपयोग मोर्टार गोले गिराने के लिए कर रही है। फोर्टिफाई राइट्स के सदस्य चिट सेंग ने बताया कि सेना ने नागरिकों को मारने के लिए यह नया और सस्ता तरीका खोज लिया है। आंकड़ों की बात करें तो दिसंबर 2024 से 11 जनवरी, 2026 के बीच नागरिकों पर पैरामोटर और जायरोकाप्टर से लगभग 304 हमले दर्ज किए गए हैं। सबसे घातक हमला पिछले साल अक्टूबर में सगाइंग क्षेत्र में हुआ था, जहां एक पैरामोटर ने मोमबत्ती जुलूस निकाल रहे प्रदर्शनकारियों पर दो गोले गिराए थे। इसमें 24 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह, सगाइंग में ही अस्पताल पर जायरोकाप्टर से हमला किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सक व दो अन्य स्टाफ सदस्यों की जान चली गई। फरवरी 2021 में तख्तापलट के बाद से म्यांमार में जारी हिंसा में अब तक 7,700 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं। हालांकि, सेना हमेशा इन दावों को खारिज करती आई है कि वह नागरिकों को निशाना बना रही है।

हाई कोर्ट के जज की टिप्पणियों पर बीसीआइ ने सीजेआइ को लिखा पत्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआइ) ने प्रमुख न्यायाधीश सूर्यकांत को एक पत्र लिखकर केरल हाई कोर्ट के एकल जज द्वारा केरल बार काउंसिल चुनाव के संबंध में की गई 'बिना आधार और लापरवाह' टिप्पणियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

बीसीआइ के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने पत्र में कहा कि ये टिप्पणियां नामांकन शुल्क को चुनौती देने के दौरान की गईं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायालयों को चुनाव से संबंधित याचिकाओं पर विचार करने से रोका गया है। 'बीसीआइ अक्सर न्यायिक प्रणाली के कुछ हिस्सों में अनियमितताओं के प्रति गहन रूप से जागरूक रहती है। बीसीआइ के अध्यक्ष ने प्रमुख न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे उचित सलाह या निर्देश जारी करने पर विचार करें और आग्रह किया कि चुनाव से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विशेष तंत्र तक सीमित रहें। यदि ऐसे हमले जारी रहते हैं, तो अधिवक्ता अपने प्रतिनिधि निकायों से कानूनी सामूहिक विरोध और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकारों की रक्षा के लिए है : जस्टिस भुइयां

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के लिए किया गया है। इसका गठन मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली कार्यकारी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए नहीं किया गया है।

गोवा में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-आन-रिकार्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक पैनल चर्चा में जस्टिस भुइयां ने सभी न्यायालयों में कानून के समान पालन सुनिश्चित करने के लिए अदालत के एक स्वर में बोलने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि देश सफेद कालर अपराधियों को प्रत्यर्पित करने में हिचकिचाएं नहीं। उन्होंने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का गठन कार्यकारी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए नहीं किया गया है, जो स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है।'' उन्होंने कहा कि विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन कानून के मूलभूत सिद्धांतों पर भिन्नता नहीं होनी चाहिए। धारणाएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन जब हम कानून के सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में विचारों की विविधता नहीं हो सकती। जस्टिस भुइयां ने कहा कि जांच एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी चाहिए और जब वे राजनीतिक पक्ष बदलते हैं, तो अपराधियों को लक्षित करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा ''भीतर से'' है, इस पर जोर देते हुए जस्टिस भुइयां ने केंद्र के सुझाव पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के कालेजियम के निर्णय पर निराशा व्यक्त की।

जस्टिस उज्जल भुइयां ●

कथ्य, विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन कानून के मूलभूत सिद्धांतों पर भिन्नता नहीं होनी चाहिए

मां-बेटी समेत बच्चे को बनाया हवस का शिकार

जासं, मोगा : पंजाब के मोगा के सिटी साउथ क्षेत्र में रहने वाली एक महिला, उसकी 10 वर्षीय बच्ची और चार साल के बच्चे को हवस का शिकार बनाया गया। तीनों को मोगा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह मोगा में किराये के मकान में रहती है। रविवार रात उसका पति घर पर नहीं था। इस दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस गया और उनके मुंह पर रुमाल लगाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद महिला, उसकी बच्ची व बच्चे को हवस का शिकार बनाया।

बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना का जवान घायल

जासं, राजौरी : जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के निकट सोमवार शाम को हुए बारूदी सुरंग विस्फोट में एक जवान घायल हो गया। राजौरी के केरी सेक्टर में सेना की एक टुकड़ी अग्रिम क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान यह हादसा हुआ। घायल जवान की पहचान केरल निवासी अग्निवीर सिजिल जे के रूप में हुई है। अन्य जवानों ने घायल साथी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घायल जवान की हालत स्थिर बताई जा रही है।

जागरण विशेष

सेना के 'डिटेक्टर' बनेंगे विटाल और हेक्साकाप्टर ड्रोन

इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से मिले टास्क के तहत तैयार किए ड्रोन, अब पेटेंट कराएगा विभाग

आशीष चौरसिया ● जागरण

ग्रेटर नोएडा: दुर्गम जंगलों में छिपे संदिग्धों, आतंकियों की तलाश में सेना के जवानों को अब परेशानी नहीं होगी। सर्च आपरेशन में ड्रोन उनके मददगार होंगे, ऐसे स्थानों से 25 किमी दूर बैठकर भी सेना के जवान ड्रोन के जरिये वहां जानकारी जुटा सकेंगे। अगर जवान मौके पर मौजूद हैं तो ड्रोन से जानकारी मिलने पर निशाना भी बना सकेंगे। पिंपरी चिंचवड़ कालेज आफ इंजीनियरिंग पुणे की मेंवरिक इंडिया टीम ने प्राब्लम स्टेटमेंट के तहत विटाल और हेक्साकाप्टर ड्रोन को तैयार किया है। इसे हाल ही में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित हुए सात दिवसीय निडर कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया था। टीम का नेतृत्व कर रहे रितिक लिपाटे के अनुसार भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्राब्लम स्टेटमेंट के तहत विटाल और हेक्साकाप्टर दो ड्रोन तैयार किए हैं। इसमें से विटाल ड्रोन जंगलों में छिपे दुश्मनों को कैमरे में लगे सेंसर की मदद से स्कैन कर डिटेक्ट करेगा। ड्रोन के कैमरे में थर्मल सेंसर का उपयोग किया गया है, जिसे मशीन लर्निंग के माध्यम से तैयार किया गया है। इसकी मदद से किसी भी दुर्गम क्षेत्र के व्यक्ति को स्कैन करने के साथ ही डिटेक्ट कर सकेगा और अपने साथी हेक्साकाप्टर ड्रोन को मैसेज भेजकर अलर्ट करेगा और लाइव वीडियो इमेज भेजकर अधिकारियों को जंगली इलाकों में छिपे संदिग्धों की संख्या के साथ ही उनके पास मौजूद सामग्री तक डिटेक्ट कर अपडेट करेगा। यह ड्रोन उनकी आवाज को भी रिकार्ड करने में सक्षम है। साथ ही अपने साथी ड्रोन हेक्साकाप्टर को हमला करने के लिए मैसेज करेगा और उनके ऊपर हमला करने में सक्षम होगा।

ड्रोन को 25 किमी दूर से किया जा सकता है संचालित: टीम के सदस्यों ने बताया कि यह दोनों ड्रोन 25 किमी दूरी से बैठकर संचालित किए जा सकते हैं और इनकी उड़ान भरने की 60 से 100 मीटर ऊंचाई तक की क्षमता है। यदि यह ड्रोन किसी चीज से टकराकर गिर जाते हैं, तब भी उनमें रिकार्ड किए गए वीडियो और आडियो सुरक्षित रहेंगे। इनमें रिकार्ड किए जाने वाले वीडियो और आडियो लाइव ही संचालित किए जाने वाले स्थान के कर्मचारी के पास पहुंच जाएंगे। इससे उन साक्ष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

मेंवरिक इंडिया टीम के सदस्य विटाल और हेक्साकाप्टर ड्रोन को प्रदर्शित करते हुए ● जागरण

पुरस्कार सम्मान समारोह में टीम होगी सम्मानित

टीम में अंशुल, दर्शन, मांशी, केदार कुलकर्णी, सम्मीद वोहरा, निमिषा, आर्यन शामिल थे। इन्होंने बताया कि इन ड्रोन में हिंदी-अंग्रेजी, उर्दू समेत सभी भाषाओं को समझने की क्षमता है। इनका उपयोग आपातकाल में लैंडस्लाइड वाले स्थानों पर भी किया जा सकता है। यह टीम जीबीयू में आयोजित हुए निडर कार्यक्रम में विजेता घोषित हुई थी। टीम को दिल्ली में फरवरी में एक कार्यक्रम में चार लाख रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ही इन ड्रोन को पेटेंट और उपयोग के लिए तैयार कराएगा।

राजस्थान में दो सड़क हादसों में छह की मौत

जासं, जयपुर: राजस्थान में रविवार देर रात दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में छह लोगों की मौत हो गई। इनमें एक हादसा बालोतरा जिले में भारतमाला एक्सप्रेस वे पर हुआ। यहां एक मिनी ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मारते हुए पैदल चल रहे छह लोगों को कुचल दिया। इनमें तीन की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी दुर्घटना श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में हुई, जहां एक ट्रैक्टर ट्राली ने पिता-पुत्र सहित तीन लोगों को कुचल दिया। दो बाइक में आमने-सामने की टक्कर के बाद दोनों पर मौजूद सवार सड़क पर गिर गए। तभी वहां से गुजर रही ट्रैक्टर ट्राली उन्हें रौंदते हुए हुए आगे बढ़ गई। इसमें एक पिता-पुत्र और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। उधर, राजस्थान में डीडवाना जिले के छोटी खाटू गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के बाद लौट रही पिकअप पलटने से 31 छात्र घायल हो गए। इनमें कई को उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

चिंतन

कर्तव्य पथ पर दिखी बदलते भारत की सशक्त झलक

भारत ने 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गौरव, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना के साथ मनाया। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड केवल एक औपचारिक सैन्य आयोजन नहीं रही, बल्कि यह नए भारत की सोच, सामर्थ्य, समावेशिता और वैश्विक दृष्टि का भव्य प्रदर्शन बनकर सामने आई। इस वर्ष की परेड कई ऐतिहासिक बदलावों और पहली बार हुए प्रयोगों के कारण विशेष रूप से यादगार रही। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह की सबसे बड़ी विशेषता रही पहली बार दो मुख्य अतिथियों की उपस्थिति। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन का शामिल होना भारत और यूरोप के बीच मजबूत होते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों का स्पष्ट संकेत है। यह दर्शाता है कि भारत अब केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक नीतियों, सुरक्षा और कूटनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश बन चुका है। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में महिला नेतृत्व ने इतिहास रच दिया। पहली बार सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व एक महिला कमांडेंट द्वारा किया गया। यह दृश्य केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि यह संदेश देता है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था में महिलाएं अब निर्णायक और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में आगे बढ़ रही हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल लैंगिक समानता का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक सोच में आए सकारात्मक बदलाव को भी दर्शाती है। इस वर्ष की परेड का एक प्रमुख आकर्षण रहा सेना के युद्ध मॉडल और ऑपरेशन 'सिंदूर' का लाइव प्रदर्शन। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर, अर्जुन मेन बैटल टैंक और स्वदेशी सैन्य प्लेटफॉर्मों की शृंखला ने 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को और मजबूत किया। राफेल, सुखोई, मिग-29 और जगुआर सहित 29 एयरक्राफ्ट्स ने सिंदूर, वज्रांग, अर्जन और प्रहार जैसे फॉर्मेशन बनाकर आकाश में भारत की सामरिक क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। यह दृश्य न केवल सैन्य शक्ति का प्रतीक था, बल्कि देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति, आत्मविश्वास और गर्व की भावना को भी सुदृढ़ करने वाला रहा। झांकियों के माध्यम से विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक विरासत और विकास योजनाओं को प्रस्तुत किया। इन झांकियों में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना स्पष्ट रूप से झलकती नजर आई। एनिमल कंटिंजेंट की भागीदारी ने परंपरा और आधुनिकता के संतुलन को दर्शाते हुए परेड को और भी विशिष्ट बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा तिरंगा फहराना, राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाना, ये सभी क्षण देश की सैन्य वीरता, बलिदान और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर, 77वें गणतंत्र दिवस की परेड केवल अतीत की उपलब्धियों का उत्सव नहीं थी, बल्कि यह भविष्य की दिशा का स्पष्ट संकेत भी थी। यह परेड बताती है कि भारत आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम, सैन्य रूप से सशक्त, लैंगिक रूप से समावेशी और वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा राष्ट्र है। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित यह शौर्य वास्तव में नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जो अपनी परंपराओं पर गर्व करता है और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

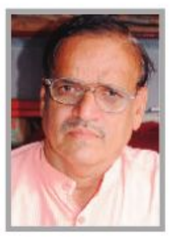

प्रदूषण

प्रमोद भार्गव

कोयला उत्पादन में कमी लाने की जरूरत

> नवंबर 2021 में ग्लासगो में हुए वैश्विक सम्मेलन में तय हुआ था कि 2030 तक विकसित देश और 2040 तक विकासशील देश ऊर्जा उत्पादन में कोयले का प्रयोग बंद कर देंगे। यानी 2040 के बाद थर्मल पावर अर्थात ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले से बिजली का उत्पादन पूरी तरह बंद हो जाएगा। तब भारत-चीन ने पूरी तरह कोयले पर बिजली उत्पादन पर असहमति जताई थी, लेकिन 40 देशों ने कोयले से पल्ला झाड़ लेने का भरोसा दिया था। 20 देशों ने विश्वास जताया था कि 2022 के अंत तक कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्रों को बंद कर दिए जाएंगे। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन बदलते हालातों में हमें जिंदा रहना है तो जिंदगी जीने की शैली को भी बदलना होगा।

दिल्ली समेत भारत वायु प्रदूषण चरम पर पहुंच जाने के कारण चर्चा में है। सड़कों पर बढ़ते वाहन तो प्रदूषण के बड़े कारण हैं ही, कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्र भी वायु प्रदूषण फैलाने के बड़े कारक बन रहे हैं। बावजूद इन संयंत्रों को राहत दी जा रही है। साथ ही कोयला खदान खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाना भी यह दर्शाता है कि बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन की जरूरत बनी रहेगी। ताप विद्युत संयंत्रों के लिए फ्लू एंड गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) लगाने की तिथि निर्धारित कर दी गई थी। किंतु अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, जबकि रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) की नई रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश के करीब 78 प्रतिशत ताप बिजली संयंत्रों में सल्फर डाईऑक्साइड (एसओ-2) को नियंत्रित करने की प्रणाली नहीं है। इस कारण वायु प्रदूषण फैलाने में इनकी बड़ी भूमिका सामने आ रही है। देश में इलेक्ट्रिक उपकरणों और अब इलेक्ट्रिक कारों सहित अन्य वाहनों की आमद ने बिजली की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए विद्युत संयंत्रों की न केवल जरूरत को रेखांकित किया है, अपितु यह भी संकेत मिल रहे हैं कि इन संयंत्रों की संख्या भविष्य में बढ़ाई जा सकती है। साफ है, इसी अनुपात में कोयले का उत्पादन भी बढ़ाना जरूरी हो जाएगा। इस आशंका की पुष्टी इस तथ्य से होती है कि केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार कोयला उत्खनन से जुड़े कोलियरी नियंत्रण नियम 2004 में एक अहम संशोधन करते हुए नई खदानों को खोलने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इस नियम की संहिता 9 को संशोधित किया गया है। साफ है, नए संयंत्र खोलने की बाधा को दूर कर दिया है।

वर्ष 2015 में जारी की गई अधिसूचना के बाद सरकारी क्षेत्र की एनटीपीसी एकमात्र ऐसी कंपनी है, जिसने अपने संयंत्रों में एफजीडी लगाने का काम किया है। इसके बाद से परिणाम बेहद सकारात्मक रहे है। एसओ-2 उत्सर्जन में कमी पाई गई है। एनटीपीसी ने जिन 20,000 मेगावाट क्षमता में एफजीडी को लगाया है, वहां औसतन 70 प्रतिशत तक एसओ-2 उत्सर्जन में कमी आई है, जबकि निजी कंपनियों ने इसे पूरी तरह अनदेखा किया हुआ है। इन कंपनियों में रिलाइंस, टाटा पावर, अडानी और टोरेंट पावर शामिल हैं। इन कंपनियों ने तर्क दिया है कि एफजीडी लगाने में करीब डेढ़ लाख करोड़ का खर्च संभव है। अतएव एफजीडी को स्थापित किया जाता है तो बिजली महंगी होगी, जिसका भार उपभोक्ता को उठाना होगा। महंगी बिजली का भार उपभोक्ता पर पड़े यह केंद्र सरकार भी नहीं चाहती, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में मतदाता प्रभावित हो सकते हैं? इसलिए सरकार ने सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस फार्मूले को अमल में लाकर कंपनियों को राहत देने के लक्ष्य से जुलाई 2025 में बदले नियम के अनुसार तय कर दिया कि जो संयंत्र घनी आबादी या प्रदूषित क्षेत्र से 10 किमी दूर है, उन सभी ताप विद्युत संयंत्रों को एफजीडी लगाने की जरूरत नहीं है। यानी एक बड़ी अड़चन को दूरी के बहाने दूर कर दिया। भारत में बढ़ते शहरीकरण के चलते ऊर्जा, स्टील और सीमेंट उद्योगों की मांग बढ़ती जाने के कारण, उसी अनुपात में कोयले की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। साल 2024-25 में

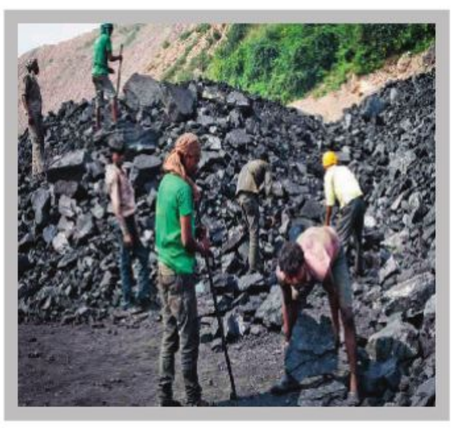

बिजली उत्पादन हेतु कोयले की मांग 94 करोड़ टन पर पहुंच गई थी। एक अनुमान के मुताबिक भारत के ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की मांग 3-4 प्रतिशत की दर से अगले पांच सालों तक बढ़ती दिखाई देगी। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के बढ़ते उपयोग से कोयले से उत्सर्जित बिजली उत्पादन में हिस्सेदारी 2025 की तुलना में 70 प्रतिशत से घटकर 2030 तक 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। भारत में सौर्य ऊर्जा का उत्पादन उम्मीद से कहीं अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि घरों में सौर्य ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में उपभोक्ता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। दरअसल, ब्रिटेन में हुई पहली औद्योगिक क्रांति में कोयले का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1500 ईंसवीं में बड़ी मात्रा में कोयले के उत्खनन की शुरूआत हुई थी। इसके बाद जिन देशों में भी कारखाने लगे, उनमें लकड़ी और कोयले का प्रयोग लंबे समय तक होता रहा। दुनिया की रेलें भी कोयले से ही लंबे समय तक चलती रही हैं। भोजन पकाने, ठंड से बचने और उजाले के उपाय भी लकड़ी जलाकर किए जाते रहे हैं। धुएं के बड़ी मात्रा में उत्सर्जन और धरती के तापमान में वृद्धि की शुरूआत औद्योगिक क्रांति की बुनियाद रखने के साथ ही आरंभ हो गई थी। इसके बाद जब इन दुष्प्रभावों का अनुभव पर्यावरणविदों ने किया तो 14 जून 1992 में रियो डी जनेरियो में पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप जापान के क्योटो शहर में 16 फरवरी 2005 को पृथ्वी के बढ़ते तापमान के जरिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय संधि अस्तित्व में आई। इस संधि में शामिल देशों ने ग्रीन हाउस अर्थात मानव उत्सर्जित गैसों को कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। दुनिया के वैज्ञानियों ने एकमत होकर कहा कि मानव निर्मित गैस सीओ-2 के उत्सर्जन से धरती का तापमान बढ़ रहा है, जो जीवाश्म ईंधन का पर्याय है। 192 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। बावजूद अभी तक इसके सार्थक परिणाम सामने नहीं आए है। रूस-यूक्रेन और इजराइल-हमास के बीच चले युद्धों ने भी इस संकट को बढ़ाने का काम किया है।

नवंबर 2021 में ग्लासगो में हुए वैश्विक सम्मेलन में तय हुआ था कि 2030 तक विकसित देश और 2040 तक विकासशील देश ऊर्जा उत्पादन में कोयले का प्रयोग बंद कर देंगे। यानी 2040 के बाद थर्मल पावर अर्थात ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले से बिजली का उत्पादन पूरी तरह बंद हो जाएगा। तब भारत-चीन ने पूरी तरह कोयले पर बिजली उत्पादन पर असहमति जताई थी, लेकिन 40 देशों ने कोयले से पल्ला झाड़ लेने का भरोसा दिया था। 20 देशों ने विश्वास जताया था कि 2022 के अंत तक कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्रों को बंद कर दिए जाएंगे। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन बदलते हालातों में हमें जिंदा रहना है तो जिंदगी जीने की शैली को भी बदलना होगा। हर हाल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। यदि तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है तो कार्बन उत्सर्जन में 43 प्रतिशत कमी लानी होगी। आईपीसीसी ने 1850-1900 की अवधि को पूर्व औद्योगिक वर्ष के रूप में रेखांकित किया हुआ है। इसे ही बढ़ते औसत वैश्विक तापमान की तुलना के आधार के रूप में लिया जाता है। गोया, कार्बन उत्सर्जन की दर नहीं घटी और तापमान में 1.5 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो असमय अकाल, सूखा, बाढ़ और जंगल में आग की घटनाओं का सामना निरंतर करते रहना पड़ेगा। समुद्र और अंतरिक्ष का तापमान भी इससे बढ़ेगा। विनाशकारी परमाणु हथियारों का प्रयोग और उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की प्रक्रिया भी खगोलीय तापमान बढ़ाने का काम कर रही है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

नमन

विशाल तिवारी

एक अंग्रेज जो हमेशा भारत का बन कर रह गया

भारत के सबसे प्रिय और सम्मानित विदेशी पत्रकारों में से एक सर मार्क टली का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जाना न केवल बीबीसी के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए एक युग का अंत है। जैसे कोई पितामह विदा हो गया हो, जिसकी आवाज दशकों तक लाखों भारतीयों के कानों में गूंजती रही। टली का जीवन भारत से इतना गहराई से जुड़ा था कि वे एक अंग्रेज होते हुए भी भारत का बनकर रह गए। 24 अक्टूबर 1935 को कोलकाता (तब कलकत्ता) में जन्मे, उनका बचपन ब्रिटिश परिवार की छत्रछाया में बीता, लेकिन भारत की मिट्टी ने उन्हें हमेशा खींचा। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान दार्जिलिंग में पढ़ाई, फिर ब्रिटेन में बोर्डिंग स्कूल और कैमब्रिज में धर्मशास्त्र की पढ़ाई वे पादरी बनना चाहते थे, लेकिन नियति ने उन्हें पत्रकारिता की ओर मोड़ा। 1964 में बीबीसी में शामिल होने के बाद 1965 में वे भारत लौट आए और यहीं बस गए। बीबीसी के भारत ब्यूरो चीफ के रूप में उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, बाबरी मस्जिद विध्वंस, आपातकाल जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को कवर किया।

आपातकाल में उन्हें भारत से निकाला गया, लेकिन वे वापस लौटे। उनकी आवाज वो शांत, संतुलित, विनम्र अंग्रेजी बीबीसी हिंदी सेवा और वर्ल्ड सर्विस के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंची। लोग सरकारी रेडियो पर भरोसा न करने के दौर में बीबीसी को सत्य की आवाज़ मानते थे, और उस आवाज में मार्क टली थे। विनम्रता उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। वे कहते थे, मुझे तो ज्यादा मालूम नहीं, आप बताइए...। भले ही विषय पर उनकी पकड़ गहरी हो। झारखंड के संतालों-मुंडाओं से लेकर केरल के आदिवासियों तक, उत्तर प्रदेश के निषादों से बिहार के मुसहरों तक भारत की विविधता को वे बराबर समझते थे। उनकी किताब 'नो फुल स्टॉप इन इंडिया' हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो भारत को समझना चाहता है। इसमें वे एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री के हवाले से लिखते हैंः भारत के बारे में जो सही कहा जा सकता है, उसका विपरीत भी सत्य है। यही उनकी समझ की गहराई थी – वे भारत को जटिल, विरोधाभासी लेकिन खूबसूरत मानते थे। भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्म श्री और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 2002 में ब्रिटेन की महारानी ने उन्हें नाइट की उपाधि दी। हिंदी पाठकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि उनकी कुछ रचनाएं हिंदी में भी उपलब्ध हैं। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित उनकी प्रमुख किताब 'धीमी वाली फास्ट पैसेंजर' है, जो उनकी अंग्रेजी किताब 'अपकंट्री टेल्स' का हिंदी अनुवाद है। प्रभात सिंह द्वारा अनूदित यह कहानी संग्रह 2023 में प्रकाशित हुआ और पूर्वांचल की कस्बाई जिंदगी, छोटे शहरों की कहानियों और भारतीय समाज की बारीकियों को मार्मिक ढंग से उकेरता है। यह उनकी दूसरी कथाकृति है, जो पचास से अधिक वर्षों के भारतीय अनुभव से निकली। भारतीयों से अधिक भारत की समझ रखने वाले वे बीबीसी की पहचान थे। जैसे वकीलों के लिए राम जेठमलानी, उद्यमियों में टाटा, वैसे पत्रकारों में मार्क टली उपमा दी जाती थी। बीबीसी का वह बेबाक स्वर थे, जो भारत की धमनियों में दशकों तक गूंजता रहा। बचपन की वे रातें याद हैं, जब रेडियो पर उनका नाम आता तो घर में सन्नाटा छा जाता। पत्रकारिता सत्य की आग है, तपाती है जलाती है, लेकिन मार्क टली ने इसे कभी हथियार नहीं बनने दिया। 1964 में वे भारत आए एक परदेसी बनकर। जल्दी ही अपने हो गए। बीबीसी दिल्ली प्रमुख बनकर उन्होंने अंधेरे में दीया जलाया। इमरजेंसी के काले दिनों में प्रेस पर ताले लगे, लेकिन टली की आवाज़ लंदन से भारत पहुंचती रही। वह निर्भीकता नहीं, नैतिक विद्रोह था। सोचिए, एक अंग्रेज जो आजादी के बाद के घावों को इतनी गहराई से देखे कि अपनी संस्था के खिलाफ भी खड़ा हो जाए। आज की पत्रकारिता में ऐसा कौन है? सोशल मीडिया की चमक में सब खो गए हैं। टली की पत्रकारिता में जनता की संवेदना थी। नक्सल गलियों में घूमे जहां इंतजामिया का पैर नहीं पहुंचता। पंजाब का दर्द उकेरा, कश्मीर की पीड़ा शब्दों में उतारी। भोपाल गैस त्रासदी पर उनकी रिपोर्टिंग मानवता का रोना है। कारखानों के धुएं में घुसकर मांओं की पीड़ा सुनी, जिनके बच्चे हमेशा सो गए। यह सूखी खबरें नहीं, जीवंत चित्र थे। जैसे कवि कविता को सांस देता है, वैसे टली ने खबरों को जीवन दिया। उनकी किताबें शब्द नहीं, भारत की आत्मा के दर्पण हैं। हर पंक्ति में सतही पत्रकारिता के खिलाफ विद्रोह। वे कहते थे, भारत समझना है तो उसके लोगों के बीच जियो। और वे जिए।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सबके मूल में वही एक भगवान

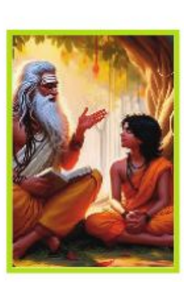

संकलित

दर्शन

एक समय की बात है उद्दालक नाम के एक महान ऋषि थे। उनका 12 साल का एक बेटा था, श्वेतकेतु। श्वेतकेतु अपना ज़्यादातर समय दोस्तों के साथ खेलने और मस्ती करने में बिताता था। उसके पिताजी को उसकी शिक्षा की बहुत चिंता थी इसलिए उन्होंने श्वेतकेतु को एक अच्छे और योग्य गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। कुछ समय पश्चात श्वेतकेतु अपनी शिक्षा पूरी करके अपने घर वापस लौट आया। उसके पिताजी को यह महसूस हुआ कि श्वेतकेतु को अपने ज्ञान का बहुत घमंड हो गया है। वह जानते थे कि इतना अहंकार उसके लिए ठीक नहीं है, यह उसे जीवन के सच तक नहीं पहुँचने देगा। उसे समझाने के लिए एक दिन उन्होंने ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, "बेटा, क्या तुम्हें वह ज्ञान मिला है जिससे न सुनाई देने वाला भी सुनाई दे, न सोचे जाने वाला भी सोचा जाए और जिसे नहीं जाना जा सकता उसे भी जाना जा सके।" श्वेतकेतु के पास अपने पिताजी के इन सवालों का जवाब नहीं था। उसके पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, "इस मिट्टी को देखो, जब कुम्हार इससे घड़ा बनाता है तो इसका रूप और आकार बदल जाता है पर असल में वो घड़ा होता तो मिट्टी ही है। इसी तरह इस संसार की सारी चीजे उसी एक भगवान के अलग-अलग रूप, रंग और आकार हैं। सबके मूल में वही एक भगवान हैं। जिस तरह मिट्टी के बिना घड़ा नहीं हो सकता उसी तरह भगवान के बिना ना तो यह संसार हो सकता है और ना ही इस संसार की कोई चीज। तुम भी भगवान का ही एक रूप हो, श्वेतकेतु।

लोग दोहराव से थक जाते हैं

संकलित

प्रेरणा

कुछ लोग विशेष लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि जिज्ञासा पाने के लिए काम करते हैं। इन विषयों की खोज में यानि अनुभव की तलाश में, उन्हें हमेशा नई जानकारी प्राप्त करने में खुशी मिलती है। इस तरह की खोज सिर्फ मनुष्य मे ही नहीं, जानवर में भी होता है। लोग दोहराव से थक जाते हैं और नई जानकारी चाहते हैं। यह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में दिखाई पड़ता है। यह उनके व्यवहार और अभिव्यक्ति जैसे मुस्कुराहट और बड़बड़ाहट के माध्यम से दिखाया जाता है। उनके मकसद पूरा न होने पर वे परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम हमेशा रोमांनचिक अनुभवों की खोज मे लगे रहते हैं। कुछ लोग विशेष लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि जिज्ञासा पाने के लिए काम करते है। इन विषयों की खोज में यानि अनुभव की तलाश में, नई जानकारी प्राप्त करने में खुशी मिलता है। इस तरह की खोज सिर्फ मनुष्य मे ही नहीं, जानवर मे भी होता है। लोग दोहराव से थक जाते हैं और नई जानकारी चाहते हैं। यह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में दिखाई पड़ता है। यह उनके व्यवहार और अभिव्यक्ति जैसे मुस्कुराहट और बडबडाहट के माध्यम से दिखाया जाता है। उनके मकसद पूरा न होने पर वे परेशान हो जाते हैं। इसलिए लोगों का स्वभाव है कि वे हमेशा नई और रोमान्चिक अनुभवों की खोज में लगे रहते हैं।

सारा संसार

वृन्दावन, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक व ऐतिहासिक नगर है। वृन्दावन भगवान श्रीकृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण की कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केन्द्र माना जाता है। यहां विशाल संख्या में श्री कृष्ण और राधा रानी के मन्दिर हैं। बांके विहारी जी का मंदिर, श्री गरुड़ गोविंद जी का मंदिर व राधावल्लभ लाल जी का, ठा.श्री पर्यावरण बिहारी जी का मंदिर बड़े प्राचीन हैं।

आज की पाती

बढ़ता प्रदूषण खतरनाक

देश में लगातार बढ़ता जा रहा प्रदूषण बेहद खतरनाक है। इसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह हमारे पर्यावरण, स्वास्थ्य, और जीवन को खतरे में डाल रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण हमें श्वसन संबंधी समस्याएं हो रही हैं, और यह हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। जल प्रदूषण के कारण हमारे जल स्रोत दूषित हो रहे हैं और यह हमारे स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है। ध्वनि प्रदूषण के कारण हमें तनाव, नींद की कमी, और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या से निजात दिलवाएं। *-युग धनखड़, रोहतक*

ट्रेंड

सेना की ताकत

यह गणतंत्र दिवस हम सभी को एकता को मजबूत करने, समावेशिता को बढ़ावा देने और हमारे प्यारे गणतंत्र की प्रगति और समृद्धि के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करे। हमारी सेना का शौर्य और ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है।
- सी पी राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति

प्रतिबद्धता दोहराने का दिन

हम भारतीय अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि हम अपने गौरवशाली गणराज्य के नागरिक के रूप में गर्व के साथ रह रहे हैं। आज का दिन राष्ट्रध्वज, संवैधानिक मूल्यों और देश के प्राचीन एवं शाश्वत आध्यात्मिक सार की निरंतर रक्षा एवं संवर्धन की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है।
-दत्तात्रेय होसबाले, आरएसएस के सरकार्यवाह

दूरदर्शी प्रशासक बिंद्रा

आईएस बिंद्रा दूरदर्शी प्रशासक थे, जिनके नेतृत्व ने विश्व क्रिकेट में भारत की भूमिका को फिर से परिभाषित करने में मदद की। उनके कारण ही आज भी खिलाड़ियों, प्रशासकों और स्वयं खेल की सेवा कर रहे है।
- मिथुन मन्हास, बीसीसीआई अध्यक्ष

ख्वाबों से भी ऊपर सम्मान

मैं पद्मश्री को गहरी कृतज्ञता और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। यह सम्मान मेरे सबसे ऊंचे ख्वाबों से भी ऊपर है। यह सम्मान केवल मेरे मार्गदर्शकों के आशीर्वाद, शुभचिंतकों की शुभकामनाओं और जनता के प्यार और प्रोत्साहन के कारण मिला है।
- आर. माधवन, अभिनेता

करंट अफेयर

कटरा और श्रीनगर के बीच विशेष आरक्षित ट्रेनें चलेंगी

हाल ही में हुई भारी बर्फबारी से सड़क और हवाई यातायात बाधित होने के कारण, उत्तरी रेलवे के जम्मू मंडल ने फंसे हुए यात्रियों को राहत प्रदान करने के लिए अगले सप्ताह एसएमवीडी कटरा से श्रीनगर के बीच विशेष आरक्षित ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने बताया कि 27 और 28 जनवरी को श्री माता वैष्णो देवी (एसएमवीडी) कटरा और श्रीनगर के बीच विशेष आरक्षित ट्रेन चलाने का निर्णय मंडल रेल प्रबंधक (जम्मू) विवेक कुमार के निर्देशों के तहत लिया गया। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा और 27 और 28 जनवरी को वंदे भारत ट्रेनों के न चलने को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई गई।

शुक्रवार को बनिहाल सेक्टर में भारी बर्फबारी के कारण पिछले दो दिनों से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद रहने के बाद इसे रविवार को आंशिक रूप से खोल दिया गया। वहीं, बर्फ से ढके कश्मीर में हवाई सेवाएं भी बाधित रहीं। मौसम विभाग ने कश्मीर के अधिकांश हिस्सों और जम्मू के ऊंचे इलाकों में 26 जनवरी से 27 जनवरी की शाम तक बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। अधिकारियों ने बताया कि विशेष आरक्षित ट्रेन 27 जनवरी को सुबह 8:10 बजे एसएमवीडी कटरा से रवाना होगी और सुबह 11 बजे श्रीनगर पहुंचेगी।

ऑफ बीट

पंचकर्म व पारंपरिक उपचार की चाह में गोवा आ रहे विदेशी पर्यटक

पंचकर्म जैसे आयुर्वेद आधारित उपचार पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां आजमाने के इच्छुक विदेशी पर्यटकों के लिए भारत की यात्रा को साधारण छुट्टियों से कहीं आगे कायाकल्प एवं आरोग्य हासिल करने के अवसर में तब्दील कर रहे हैं, और गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) इस मामले में एक अग्रणी केंद्र के रूप में उभर रहा है। एआईआईए में उपलब्ध सबसे लोकप्रिय पारंपरिक उपचार पद्धतियों में पंचकर्म शामिल है, जो संस्थान के चिकित्सकों की मानें तो जटिल बीमारियों में भी आशाजनक परिणाम दिखा रहा है। रूस की 63 वर्षीय नतालिया उन विदेशी पर्यटकों में शामिल हैं, जिनका कहना है कि भारत में छुट्टियां मनाते समय आयुर्वेद आधारित उपचार पद्धति आजमाने के फैसले से उनकी यात्रा के अनुभव में एक शानदार आयाम जुड़ गया। नतालिया के मुताबिक, वह पिछले सात-आठ साल से कमर दर्द, गर्दन में दर्द और जोड़ों में दर्द की शिकायत के साथ-साथ 'रेटिनल एट्रोफी' की समस्या से जूझ रही हैं, जिससे उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है। एआईआईए में पंचकर्म थेरेपी हासिल करने के बाद मुझे अपनी स्थिति में काफी सुधार महसूस हो रहा है।

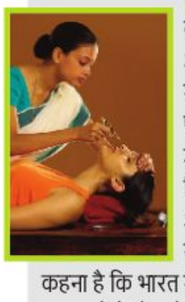

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड,
रोहतक-124001 फोनः 9253681019-20
ई-मेल : haribhoomi@gmail.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

खबर संक्षेप

इंडिगो ने 16 एयरपोर्ट्स पर 717 फ्लाइट स्लॉट्स छोड़े

नई दिल्ली। कल की बड़ी खबर इंडिगो से जुड़ी रही। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने भारत के अलग-अलग डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर अपने 717 स्लॉट्स सरेंडर कर दिए हैं। वहीं देश की सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट का वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 26.8% बढ़कर 1,729.44 करोड़ रुपए रहा।

अदाणी विदेशी कंपनी के साथ विमान बनाएंगे

नई दिल्ली। अदाणी समूह और ब्राजील की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर अगले सप्ताह भारत में नागरिक विमानों के लिए एक 'फाइनल असेंबली लाइन' (विमानों को जोड़ने और तैयार करने की इकाई) स्थापित करने की योजना की घोषणा करेंगे। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक है। एयरलाइंस द्वारा बेड़े का विस्तार करने और नए हवाई अड्डों के निर्माण के कारण हवाई यातायात की मांग लगातार बढ़ रही है।

रूस से कच्चे तेल की खरीदारी के लिए लगाया 25% टैरिफ

ट्रंप के टैरिफ से भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित, कई सेक्टर पर पड़ा असर

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली:

अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इसमें 25% रूस से कच्चे तेल की खरीदारी के लिए लगाया गया है। इससे भारत का एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा मार रत्न एवं आभूषण सेक्टर पर पड़ी है। साथ ही कई दूसरे सेक्टर्स का एक्सपोर्ट भी प्रभावित हुआ है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है लेकिन दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत भी फिलहाल अटकी हुई है। जानिए किस सेक्टर को कितना नुकसान हुआ है।

मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक नवंबर, 2024 से नंवबर, 2025 के बीच अमेरिका को पर्ल्स, गोल्ड सिल्वर, जेम्स, जूलरी और कॉइन्स के एक्सपोर्ट में 161 मिलियन डॉलर की गिरावट आई है। इसी तरह आयरन एंड स्टील का एक्सपोर्ट इस दौरान 44 मिलियन डॉलर गिर गया है। फिश और अन्य सीफूड में एक साल के दौरान 35 फीसदी गिरावट आई है।

अमेरिका को एक्सपोर्ट इसी तरह प्लास्टिक के उत्पादों का एक्सपोर्ट नवंबर, 2024 से नवंबर 2025 के बीच 27 मिलियन डॉलर कम हुआ है। इस दौरान बिल्डिंग मटीरियल्स के एक्सपोर्ट में 23 मिलियन डॉलर की कमी आई है जबकि नेचुरल गम और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स का एक्सपोर्ट 18 मिलियन डॉलर गिर गया है। इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स और ट्रीटेड फैबरिक्स का एक्सपोर्ट भी 13 मिलियन डॉलर कम हुआ है।

अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर बातचीत फिलहाल रुकी हुई है। अमेरिका ने भारतीय सामान पर सबसे ज्यादा 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। इसमें 25 फीसदी का टैरिफ रूस से कच्चे तेल का आयात करने के लिए लगाया गया है। जानिए इससे किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है?

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा से पहले सिएटल में बैठक

सिएटल/न्यूयार्क। वाशिंगटन राज्य से अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा से पहले, सिएटल में आयोजित एक कारोबारी बैठक में एआई, कृषि प्रौद्योगिकी, क्वांटम और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर जोर दिया गया। यह व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत और अमेरिकी प्रशांत उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने के प्रयासों के तहत इसी सप्ताह भारत का दौरा करेगा। सिएटल स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने मोंटाना वर्ल्ड अफेयर्स काउंसिल और प्रौद्योगिकी कंपनी जोहो के साथ साझेदारी में शनिवार को बेल हार्बर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 'इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस फोरम' के दूसरे संस्करण की मेजबानी की। इस मंच में सिएटल क्षेत्र की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सिएटल दूतावास ने कहा, ''कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), फोटोनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, कृषि-प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और उच्च शिक्षा के प्रमुख उद्योग विशेषज्ञों ने भारत में इन क्षेत्रों में निवेश के अवसरों और संभावनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

इस सप्ताह भी रहेगा उतार-चढ़ाव अच्छे पोर्टफोलियो में करें निवेश

एजेंसी ▶▶| मुंबई

देश में 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश के मौके पर आज भारतीय शेयर बाजार में कोई कामकाज नहीं हुआ।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही पूरे दिन के लिए बंद रहेंगे। इक्विटी सेगमेंट के साथ-साथ डेरिवेटिव और एसएलबी सेगमेंट में भी छुट्टी रहेगी। अब बाजार मंगलवार 27 जनवरी को खुलेगा। शेयर बाजार के साथ-साथ देश का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज भी बंद रहा। सुबह और शाम, दोनों ही सत्रों (मॉर्निंग और इवनिंग सेशन) में ट्रेडिंग नहीं होगी। आमतौर पर कुछ छुट्टियों पर शाम का सत्र खुला रहता है, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग स्थगित रखी गई है। करेंसी और डेट मार्केट में भी कारोबार नहीं हुआ। करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डेट प्रॉमिसरी नोट्स (EDP) मार्केट में भी आज कोई हलचल नहीं होगी। आरबीआई के कैलेंडर के मुताबिक, बैंकिंग सेक्टर में भी नेशनल हॉलिडे है, जिसके कारण इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में भी कामकाज

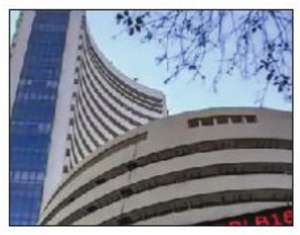

मंगलवार को बाजार की नजर इन फैक्टर्स पर रहेगी

जब मंगलवार को बाजार खुलेगा, तो निवेशकों की नजर रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडाणी ग्रुप के शेयरों और हाल ही में आए तिमाही नतीजों पर रहेगी। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट के संकेत और क्रूड ऑयल की कीमतें भी बाजार की दिशा तय करेंगी। बजट सत्र के नजदीक होने के कारण भी बाजार में अगले हफ्ते उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इससे पहले शेयर मार्केट में शुक्रवार यानी 23 जनवरी को गिरावट रही थी।

बंद रहेगा। गणतंत्र दिवस साल की पहली बड़ी छुट्टी है। इसके बाद आने वाले महीनों में होली (03 मार्च) और गुड फ्राइडे (3 अप्रैल) जैसे मौकों पर भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग बंद रहेगी। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पोर्टफोलियो और पेंडिंग ऑर्डर्स को इन छुट्टियों के कैलेंडर के हिसाब से ही मैनेज करें।

छोटी कारों की मांग में तेजी बनी रहेगी या नहीं, यह कहना अभी जल्दबाजी : एमडी

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

उपभोक्ताओं का झुकाव अभी भी मुख्य रूप से एसयूवी खरीदने की ओर है और यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि जीएसटी कटौती के बाद छोटी कारों की मांग में जो तेजी देखी गई है, वह आगे भी बरकरार रहेगी या नहीं।

टायर निर्माता कंपनी सिएट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अर्नब बनर्जी ने यह बात कही। उन्होंने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में बताया कि हालांकि जीएसटी कटौती ने बाजार को एक गति दी है, लेकिन कंपनी चालू वित्त वर्ष के लिए दहाई अंकों की वृद्धि के अपने पुराने अनुमान पर ही कायम है। कंपनी विशेष रूप से कृषि और दोपहिया टायरों के लिए

ग्रामीण बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यात्री कार खंड में जीएसटी कटौती के प्रभाव और छोटी कारों की मांग जारी रहने के सवाल पर बनर्जी ने कहा कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना समय से पहले होगा क्योंकि कुल मिलाकर ग्राहकों का रुझान अभी भी एसयूवी की तरफ बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में यात्री कार श्रेणी में एसयूवी की बिक्री सबसे आगे रही है, जबकि किफायती न होने के कारण छोटी कारों की बिक्री में गिरावट देखी गई थी। साल 2025 में भी भारत में बिकने वाले कुल यात्री वाहनों में एसयूवी की हिस्सेदारी 2024 के 53.8 प्रतिशत से बढ़कर 55.8 प्रतिशत हो गई, हालांकि जीएसटी कटौती के बाद छोटी कारों में भी सुधार के कुछ संकेत दिखे हैं। बनर्जी ने कहा कि हमें अभी एक और तिमाही तक इंतजार करना होगा ताकि यह देखा जा सके कि वाहन निर्माता जिस ढांचागत बदलाव को महसूस कर रहे हैं, क्या वह पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो छोटे आकार के टायरों की मांग फिर से बढ़ेगी।

उन्होंने आगे कहा कि पुराने टायरों को बदलकर नया टायर लगाने वाले बाजार में ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच होने के कारण कंपनी को लाभ होगा। आने वाली तिमाही में गर्मियों का सत्र शुरू हो जाएगा और मार्च से जून का समय आमतौर पर कंपनी के लिए बेहतर कारोबार वाला होता है।

अमेरिका से अफ्रीका तक भारतीय बाइक्स की धूम

नई दिल्ली। साल 2025 भारतीय मोटरसाइकिलों के लिए बहुत अच्छा रहा। भारत से मोटरसाइकिलों का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 27% बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। 2025 में कुल 43 लाख मोटरसाइकिलों का निर्यात हुआ, जो महामारी के बाद सबसे ज्यादा है। साल 2025 में, कुल मोटरसाइकिल निर्यात में बजाज ऑटो का हिस्सा 43% और टीवीएस मोटर का हिस्सा 29% रहा। यानी, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर करीब 72% निर्यात किया। बजाज की मोटरसाइकिलों का निर्यात 2024 में 16 लाख यूनिट से बढ़कर 2025 में 19 लाख यूनिट हो गया।

बॉट्स और एआई से की 734 करोड़ रुपये की हेराफेरी!

- ऑनलाइन गेमिंग ऐप विंजो पर ईडी का शिकंजा

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

ऑनलाइन गेमिंग ऐप विंजो की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को कहा कि उसने विंजो और इसके प्रमोटर्स के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी द्वारा गेम के एल्गोरिदम में हेरफेर करने के लिए 'बॉट्स' और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किए जाने के कारण यूजर्स ने 734 करोड़ रुपये गंवा दिए। आधिकारिक बयान के अनुसार, ईडी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने 23 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए निर्दिष्ट स्थानीय अदालत में शिकायत दायर की। विनजो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके निदेशक - पवन नंदा और सौम्या सिंह राठौर - तथा इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां, जिनमें विदेश स्थित कंपनियां भी शामिल हैं, जैसे विनजो यूएस इंक, विनजो एसजी प्राइवेट लिमिटेड और जेडओ प्राइवेट लिमिटेड, को आरोपपत्र में आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। ईडी ने बताया कि विनजो अपने मोबाइल ऐप्लिकेशन के माध्यम से 100 से अधिक गेम संचालित करता था और दावा किया जाता था कि इसके लगभग 25 करोड़ उपयोगकर्ता थे, जिनमें से अधिकतर छोटे शहरों से थे। हालांकि, कंपनी का दावा है कि जांच में पाया गया कि अधिकांश आरएमजी (रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम) में हेरफेर किया गया था। गेम कोडबेस, थर्ड-पार्टी डेवलपर समझौतों और आंतरिक संचार के विश्लेषण से पता चलता है कि दिसंबर 2023 तक, आरएमजी में बॉट्स, एआई और एल्गोरिदम प्रोफाइल 'एम्बेडेड' किए गए थे। आरोपपत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी द्वारा अपराध से अर्जित रकम को अमेरिका और सिंगापुर में बनाई गई फर्जी कंपनियों के माध्यम से धनशोधन किया गया था। ईडी ने पिछले साल विनजो और इसके प्रमोटर्स के परिसरों पर छापेमारी की थी और नंदा और राठौर को गिरफ्तार किया था। राठौर फिलहाल जमानत पर है।

कैसे की हेराफेरी?

केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में भारत में रियल मनी गेमिंग ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्रीय एजेंसी ने कहा, 'रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) सेवाएं प्रदान करने के लिए, कंपनी उपयोगकर्ताओं से सट्टेबाजी की राशि का एक निश्चित प्रतिशत कमीशन के रूप में वसूलती थी। कंपनी ने अपने उपयोगकर्ताओं को यह भी आश्वासन दिया था कि उसका गेमिंग प्लेटफॉर्म किसी भी बॉट (कंप्यूटर-नियंत्रित पात्र) से मुक्त है, पारदर्शी और सुरक्षित है।'

डबल पेनल्टी खत्म करने जैसे प्रस्तावों पर नजर

- पति-पत्नी को संयुक्त टैक्स रिटर्न का विकल्प देने पर विचार संभव

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

आम बजट में मध्यम वर्ग और टैक्स पेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। पति-पत्नी को संयुक्त रूप से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का विकल्प देने पर विचार हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया है कि शादीशुदा जोड़ों को अलग-अलग रिटर्न के बजाय एक रिटर्न की सुविधा मिले, जिसमें टैक्स स्लैब और छूट संयुक्त रूप से लागू हों। हालांकि यदि पति-पत्नी दोनों वर्किंग है तो अलग-अलग रिटर्न फाइल करने का विकल्प भी होगा। संयुक्त रिटर्न फाइल करने पर वे तब विचार कर सकते हैं जब उन्हें इसका फायदा मिल रहा हो। सुझाव के पीछे

एलपीजी के मर्जर-डिमर्जर पर टैक्स राहत संभव

कारोबार को आसान बनाने की दिशा में सरकार लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पुनर्गठन पर टैक्स न लगाने पर भी विचार कर सकती है। कंपनियों की तरह एलपीजी के मर्जर या डिमर्जर को टैक्स न्यूट्रल बनाने से स्टार्टअप्स और छोटे कारोबार को फायदा मिलने की उम्मीद है।

तर्क यह है कि भारत में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जहां आय का मुख्य स्रोत केवल एक व्यक्ति है। मौजूदा व्यक्तिगत टैक्स स्लैब के चलते इन परिवारों को सीमित छूट का ही फायदा मिल पाता है। संयुक्त टैक्स सिस्टम लागू होने से पति-पत्नी की आय जोड़कर टैक्स गणना हो सकेगी, जिससे टैक्स स्लैब और छूट बढ़ सकती है। अमेरिका जैसे देशों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। इसके साथ ही बजट में आयकर कानून के तहत कुछ मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव आ सकता है। सुझाव है कि टैक्स पेयर्स चार्टर की भावना के अनुरूप टैक्स-पेयर को ईमानदार माना जाए और आपराधिक कार्रवाई केवल उन्हीं मामलों में हो, जहां आय छिपाने, गलत रिपोर्टिंग या जानबूझकर नाजायज फायदा लेने के स्पष्ट सबूत हों। जन विश्वास एक्ट के तहत पहले ही कुछ मामलों में आपराधिक धाराएं हटाई जा चुकी हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम तुरंत खत्म होने की संभावना कम है, लेकिन सरकार लॉन्ग टर्म फेज आउट को लेकर संकेत दे सकती है। बजट में सनसेट क्लॉज जैसी व्यवस्था का इशारा मिल सकता है। इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने पर जोर रह सकता है। एक गलती पर दो-दो जुर्माना लगाने की व्यवस्था खत्म करने का संकेत भी है। फिलहाल गलत रिपोर्टिंग या गलत एंट्री पर अलग-अलग धाराओं में 200 प्रतिशत तक टैक्स पेनल्टी लग जाती है। सुझाव है कि पेनल्टी को गलती की गंभीरता के अनुसार तर्कसंगत बनाया जाए। आगे ऐसे मामलों में राहत मिल सकती है, जहां टैक्स कटा लेकिन समय पर जमा नहीं हो पाया।

मेनबोर्ड से शैडोफैक्स की 28 जनवरी को लिस्टिंग होगी

मुंबई। शेयर बाजार में इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट काफी व्यस्त रहने वाला है। निवेशकों के पास एक साथ कई कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाने का मौका होगा।

इस हफ्ते एसएमई सेगमेंट में 5 नए आईपीओ कुल 226 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने वाले हैं। साथ ही 5 कंपनियां लिस्ट होने वाली हैं, जिनमें सिर्फ शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज मेनबोर्ड से है। बाजार में हल्की तेजी की उम्मीद है, लेकिन ग्रे मार्केट में शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज को कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा। पिछले कुछ समय से आईपीओ मार्केट में दिख रही तेजी इस हफ्ते भी जारी रहने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लिक्विडिटी और निवेशकों के उत्साह के चलते इन इश्यूज को अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। स्टील फाइबर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी कस्तूरी मेटल कम्पोजिट का आईपीओ 27 को खुलेगा।

अब आधार में फिंगरप्रिंट की जगह चेहरे से होगी पहचान

- हर महीने 100 करोड़ ऑथेंटिकेशन का टारगेट
- एआई और क्वांटम तकनीक से सुरक्षा बढ़ेगी

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

सरकार ने आधार के तकनीकी ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। 'आधार विजन 2032' दस्तावेज तैयार हो गया है। इसमें एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों को अपनाने की सिफारिश की गई है। मकसद आधार को तेज, सुरक्षित और फ्रॉड-फ्री बनाना है। नई व्यवस्था में फिंगरप्रिंट की जगह फेशियल रिकग्निशन प्राथमिक माध्यम होगा। आधार के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा कि विजन 2032 का लक्ष्य है, लेकिन तैयारी उससे आगे की तकनीक को ध्यान में रखकर हो रही है। एआई

और क्वांटम कंप्यूटिंग से तकनीकी परिदृश्य तेजी से बदल रहा है।

तीन प्रमुख बदलाव : रोज लगभग 9 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन होते हैं। इसमें करीब 1 करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए होते हैं। सरकार का लक्ष्य हर महीने 100 करोड़ ऑथेंटिकेशन फेस रिकग्निशन से करना है। एआई सिस्टम से समय-समय पर फेशियल रिकग्निशन अपडेट होगा और बार-बार बायोमैट्रिक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार दिसंबर तक 5 करोड़ बच्चों और किशोरों का बायोमैट्रिक अपडेट कर चुकी है।

भारत और ईयू में ट्रेड डील पर बैठक आज

नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार यूरोपियन यूनियन (ईयू) के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) का ऐलान मंगलवार को भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में होगा। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए ईयू के शीर्ष नेता दिल्ली में हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के लिए फायदेमंद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे दोनों पक्षों के बिजनेस और लोगों की तरक्की होगी। सूत्रों के मुताबिक, इस समझौते से कृषि, डेयरी और पर्यावरण से जुड़े कुछ मुद्दों को अलग रखा गया है। गणतंत्र दिवस समारोह और इंडिया-ईयू समिट के लिए यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा रविवार को नई दिल्ली पहुंचे। काउंसिल ने कहा, 'मंगलवार को इंडिया-ईयू समिट के लिए प्रेजिडेंट कोस्टा नई दिल्ली पहुंचे।

बजट 2026-27: सीमा शुल्क में बदलाव, विशेष रियायतों की उम्मीद

टीडीएस सरलीकरण प्रमुख उम्मीदों में शामिल

- वित्त मंत्री सीतारमण एक फरवरी को नौवां बजट पेश करेंगी

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लोकसभा में लगातार अपना नौवां बजट पेश करेंगी। इस बार बजट से उम्मीद की जा रही है कि वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सीमा शुल्क ढांचे में जीएसटी की तर्ज पर बड़े बदलाव और कई अन्य सुधार देखने को मिल सकते हैं।

बजट में कर्ज और जीडीपी के अनुपात को कम करने पर भी ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि अब भारत का राजकोषीय प्रबंधन केवल

घाटे को संभालने के बजाय कर्ज के बोझ को कम करने की दिशा में बढ़ रहा है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए, जिन्हें पिछले साल 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट और बाद में जीएसटी दरों में कटौती से बड़ी राहत मिली थी, इस बार मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि एक अप्रैल से लागू होने वाले नए और सरल आयकर अधिनियम 2025 के बारे में बजट में स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए कुछ नए प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं, ताकि अधिक लोग पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई व्यवस्था को अपनाएं। इसके साथ ही टीडीएस की विभिन्न श्रेणियों और दरों को कम करके उन्हें और सरल बनाया जा सकता है। सीमा शुल्क व्यवस्था में सुधार के तहत दरों को कम करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया जा सकता है। साथ ही विवादों में फंसे लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये को सुलझाने के लिए एक माफी योजना भी लाई जा सकती है। रक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन' के तहत केंद्र और राज्यों की भागीदारी वाली एक नई योजना के लिए भी बजट का प्रावधान किया जा सकता है।

8वें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद

सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद है, जिसे एक जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। राज्यों को मिलने वाले करों के हिस्से में भी 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ोतरी हो सकती है। एमएसएमई क्षेत्र और रत्न-आभूषण तथा चमड़ा जैसे उद्योगों के लिए विशेष रियायतों की उम्मीद है। इसके अलावा लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के लिए भी बजट में फंड दिया जा सकता है।

बेहद सस्ती होने वाली है मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू!

नई दिल्ली। फॉक्सवैगन, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी कारों की कीमत में आने वाले दिनों में कमी हो सकती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत यूरोपीय संघ (EU) से आने वाली कारों पर लगने वाले टैक्स को काफी कम करने की योजना बना रहा है। अभी यह टैक्स 110% तक है, जिसे घटाकर 40% किया जा सकता है। यह भारत के बड़े कार बाजार को खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सूत्रों के मुताबिक भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा मंगलवार को हो सकती है।

मोदी सरकार ने यूरोपीय संघ के 27 देशों से आने वाली कुछ खास कारों पर तुरंत टैरिफ कम करने पर सहमति जताई है। इनमें वे कारें होंगी जिनकी कीमत 15,000 यूरो से ज्यादा है। दो सूत्रों ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी है। समय के साथ यह टैक्स और कम होकर 10% तक घट जाएगा।

भारत-चीन ने सोने की खरीद बढ़ा निकाला डॉलर का दिवाला

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के लिए बड़ा अहम बदलाव आया है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में भारत की हिस्सेदारी घटकर पिछले पांच वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। इस गिरावट का कारण आवश्यकता और रणनीतिक दोनों है।

रुपये का अवमूल्यन हुआ है, जिसके चलते पिछले वर्ष भारत का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। दूसरा कारण विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना में रणनीतिक बदलाव करना और अमेरिकी परिसंपत्तियों पर निर्भरता कम करना है।

अमेरिकी बॉन्ड बाजार पर निर्भरता घटी

वास्तव में, दुनिया भर की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं विश्व के सबसे बड़े

अमेरिकी बॉन्ड बाजार पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं। पिछले सप्ताह जारी अमेरिकी सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के दीर्घकालिक अमेरिकी ऋण घटकर लगभग 174 अरब डॉलर रह गए हैं। यह 2023 में दर्ज किए गए उच्चतम स्तर से 26% की भारी गिरावट है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, ट्रेजरी बॉन्ड अब देश के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग एक तिहाई हिस्सा हैं, जो एक साल पहले लगभग 40% थे।

Get Exclusive Access to My Private Channel

✅ One-Time Entry Fee Only. No Monthly Fees. Lifetime Validity.

♦ **Indian Newspaper**

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) Financial Express
7) Live Mint
8) Hindustan Times
9) Business Standard

♦ **International Newspapers channel**

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ **Magazine Channel**

National & International
[Genaral & Exam related]

♦ **English Editorials**

[National + International Editorials]

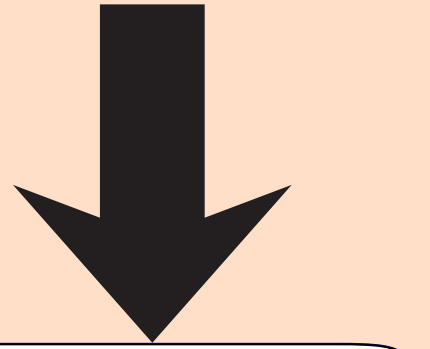

Click here to join

सहयोग की राह

बदलते दौर में भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत अपनी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने की राह पर आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में अब भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक समझौता होने वाला है, जिसकी घोषणा द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में किए जाने की संभावना है। इसके तहत रक्षा क्षेत्र, समुद्री सुरक्षा एवं आतंक के खिलाफ साझा मोर्चेबंदी, भारतीय और यूरोपीय नागरिकों की आसान आवाजाही तथा वस्त्र उद्योग एवं प्रौद्योगिकी जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। यह समझौता इसलिए भी अहम होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि इससे अमेरिका की शुल्क नीति के प्रभाव से निपटने के लिए भारत और यूरोपीय देशों के बीच साझा एवं व्यापक दृष्टिकोण विकसित होगा। अनुमान है कि इस समझौते से दो अरब लोगों का एक ऐसा बाजार बनेगा, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक चौथाई हिस्सा होगा। इससे न केवल भारत के निर्यात को गति मिलेगी, बल्कि यहां के पेशेवरों के लिए यूरोपीय देशों में रोजगार पाने का रास्ता भी सुगम हो जाएगा।

इसमें दोराय नहीं कि अमेरिका की ओर से भारत पर पचास फीसद शुल्क लगाए जाने के बाद देश का निर्यात कारोबार प्रभावित हुआ है। नतीजतन, भारत अपने उत्पादों के लिए दुनिया के विभिन्न देशों में वैकल्पिक बाजार तलाशने के हर संभव प्रयास में जुटा है। हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार एवं व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले ब्रिटेन और ओमान के साथ व्यापार समझौते किए गए थे। यूरोपीय संघ के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पहली बार वर्ष 2007 में शुरू की थी, लेकिन कुछ मसलों पर आपसी सहमति न बनने के कारण वर्ष 2013 में बातचीत स्थगित कर दी गई थी। जून, 2022 में वार्ता को फिर से आगे बढ़ाया गया, जो निर्णायक रही। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े जानकारों का मानना है कि यह ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में गुणात्मक बदलाव लाएगा।

माना जा रहा है कि शिखर सम्मेलन में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी देने के अलावा दोनों पक्ष रक्षा ढांचागत समझौता और एक रणनीतिक एजंडा भी प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि भारत और यूरोपीय संघ वर्ष 2004 से रणनीतिक साझेदार रहे हैं। प्रस्तावित सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी दोनों पक्षों के बीच सहयोग को और गहरा करने में सहायक होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आपसी तालमेल बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय संघ के 'सेफ' (सिक्योरिटी एक्शन फार यूरोप) कार्यक्रम में भागीदारी के रास्ते खुलेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक समझौते से देश के वस्त्र निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे बड़ा परिधान बाजार है। वर्तमान में भारत इस क्षेत्र में 4.5 अरब डालर से अधिक मूल्य के परिधानों का निर्यात करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का कुल वस्तु व्यापार लगभग 136 अरब अमेरिकी डालर का था, जिसमें निर्यात की हिस्सेदारी करीब 76 अरब अमेरिकी डालर थी। अब बहु-प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगने से निश्चित रूप से द्विपक्षीय व्यापार को एक नई दिशा मिलेगी और भारत के निर्यात कारोबार पर अमेरिकी शुल्क के प्रभाव को कम करने में भी काफी मदद मिलेगी।

नाहक विवाद

देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि किसी मसले पर असहमति या विवाद की स्थिति है, तो उसे संवाद और सौहार्द के सहारे हल किया जाए और सहमति की हर संभावना को मजबूत किया जाए। मगर विडंबना यह है कि कई बार कुछ मुद्दों को इस हद तक संवेदनशील स्वरूप दे दिया जाता है कि उसके बाद विवाद नाहक ही जटिल होता चला जाता है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी ने चेन्नई में रविवार को 'भाषा शहीद दिवस' मनाया और इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन ने हिंदी भाषा पर बहस को एक बार फिर हवा दे दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि 'न तब, न अभी, न ही कभी हिंदी को यहां जगह मिलेगी।' इस मसले पर अतीत में कैसे मत-विरोध रहे हैं और कैसे यह एक समय हिंसक आंदोलन का कारण बना था, यह जानते हुए भी अगर आज एक बार फिर उसी तेवर में विवाद को तूल दिया जाता है, तो इसे किस रूप में देखा जाएगा? संवाद के बजाय आक्रामकता का सहारा लेकर किस समस्या का स्थायी हल निकाला जा सकता है?

देश की संघीय भावना विविधता के सौंदर्य से ही शक्ति ग्रहण करती है। अलग-अलग भाषाएं इसका एक सबसे अहम हिस्सा हैं। हिंदी को देश को जोड़ने वाली एक भाषा की सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी के तौर पर देखा जाता है, तो इसके अपने आधार हैं। मगर इसमें कहीं भी तमिल या देश की किसी भी अन्य भाषा की अहमियत की अनदेखी करने या खुद को उन पर थोपे जाने का आग्रह नहीं है। हैरानी की बात यह है कि किसी भाषा को नुकसान पहुंचाए बिना कभी सिर्फ हिंदी पढ़ाने की बात की जाती है, तो उसे थोपने के तौर पर देख लिया जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का यही मानना है कि केंद्र सरकार राज्य में हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। उनकी इस बात से शायद ही किसी को असहमति होगी कि तमिलनाडु अपनी भाषा से जीवनधारा की तरह प्यार करता है। मगर क्या किसी भी भाषा से प्यार को दूसरी भाषा के खिलाफ संघर्ष या टकराव का कारण बनना चाहिए? इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि भाषा के मसले पर इस तरह मोर्चा खोलना किसी भी भाषा का कितना हित सुनिश्चित करेगा!

गंभीर जल संकट के मुहाने पर दुनिया

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की एक रपट के मुताबिक, जल के अत्यधिक दोहन, सिमटते भूजल स्रोतों, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया अब 'वैश्विक जल दिवालियापन' की स्थिति में कदम रख चुकी है। अगर समय रहते स्थिति नहीं संभाली, तो परिणाम भयावह हो सकते हैं।

अमरपाल सिंह वर्मा

दुनिया में बढ़ता जल संकट चिंता का विषय बना हुआ है। अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़े जाने की भविष्यवाणियां तक की जा चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान के शोधकर्ताओं की हाल में आई एक रपट इन चिंताओं को और गंभीर रूप दे रही है। इसमें कहा गया है कि पिछले कई दशकों के दौरान जल के अत्यधिक दोहन, सिमटते भूजल स्रोतों, भूमि क्षरण, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से उपजी बाधाओं की वजह से दुनिया अब जल संकट की अवस्था से आगे बढ़कर 'वैश्विक जल दिवालियापन' की स्थिति में कदम रख चुकी है। जब कोई इंसान दिवालिया होता है, तो उसके पास पैसा नहीं बचता, घर तक गिरवी हो जाता है और विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। बड़ा सवाल यह है कि अगर दुनिया पानी के लिहाज से दिवालिया हो गई, तो क्या होगा? रपट में शोधकर्ताओं ने जो कुछ कहा है, उसका मतलब यह नहीं कि दुनिया से पानी अचानक खत्म हो जाएगा, बल्कि जिस ढंग से जल का अंधाधुंध दोहन और प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे जल व्यवस्था की रीढ़ टूटनी शुरू हो गई है।

समूचे विश्व में बहुत पहले से जल संकट की चर्चा होती रही है, मगर इसे एक ऐसे झटके की तरह देखा जाता रहा है, जिससे समय के साथ उबरा जा सकता है। अगर जल संकट के बारे में चेतावनी दी जाती रही है, तो यह भरोसा भी दिलाया जाता रहा है कि फिर से अच्छी बरसात होगी, जल का स्तर सुधर जाएगा और हालात पुनः सामान्य हो जाएंगे। मगर नई रपट ने इस भरोसे पर सवालिया निशान लगा दिया है। रपट में साफ कहा गया है कि विश्व की जल आपूर्ति प्रणाली कई जगहों पर पतन के दौर में पहुंच चुकी है। अनेक क्षेत्रों में पानी की कमी अब स्थायी स्वरूप लेती जा रही है। यह स्थिति केवल पानी की कमी की नहीं, बल्कि व्यवस्था के टूटने की ओर संकेत करती है। ऐसे में अब हमें पानी के बारे में अपने सोचने का ढंग बदलना होगा।

अब तक जल संकट को एक अस्थायी समस्या माना जाता रहा है। अकाल पड़े, परेशानियां आईं, मगर कुछ साल बाद हालात सुधर गए। किसी साल वर्षा कम हुई, लेकिन अगले मानसून में भरपाई हो गई। जब ऐसा चल रहा था, तो नीतियों का निर्धारण भी इसी अनुरूप होता रहा। कभी जल की बूंद-बूंद को सहेजने वाले समाज ने भी लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। कई जगहों पर जलस्रोत इतने कमजोर हो चुके हैं कि उन्हें पहले जैसी स्थिति में लौटने में दशकों लग सकते हैं और कई मामलों में शायद लौटना संभव ही न हो पाए। हम दिवालियापन को व्यक्ति के आर्थिक रूप से कंगाल होने के संदर्भ में ही समझते आए हैं। जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से दिवालिया होता है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि दुनिया से पैसा खत्म हो गया है। पैसा रहता है लेकिन उस व्यक्ति की आमदनी, खर्च और कर्ज के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी तरह दुनिया में पानी मौजूद है, लेकिन उसकी उपलब्धता, उसके उपयोग और

उसके पुनर्भरण के बीच संतुलन तेजी से टूट रहा है। हम भू-गर्भ से जितना पानी निकाल रहे हैं, उतना पुनर्भरण नहीं कर रहे हैं। यानी जल खाता खाली हो रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के शोधकर्ताओं ने रपट में जो कुछ कहा है, उसके अनुसार इस असंतुलन की जड़ें दशकों पुरानी हैं। भूजल के अंधाधुंध दोहन, नदियों को गंदे नालों में बदल दिए जाने, वनों की कटाई, मिट्टी के क्षरण और जलवायु परिवर्तन ने मिलकर पानी की प्राकृतिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। जब पानी प्रदूषित हो जाता है, तो वह मौजूद होते हुए भी उपयोग के लायक नहीं रहता। जब भूजल जरूरत से ज्यादा निकाला जाता है, तो वह वापस भरने से पहले ही खत्म हो जाता है। धीरे-धीरे यह स्थिति एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाती है, जहां से लौटना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह बात भी सच है कि इस संकट का असर सब पर बराबर नहीं पड़ता। जिस प्रकार आर्थिक दिवालियापन में सबसे पहले गरीब तबके टूटते हैं, वैसे ही जल संकट और जल दिवालियापन का सबसे बड़ा बोझ भी कमजोर वर्गों पर पड़ना स्वाभाविक है। छोटे किसानों, आदिवासियों, शहरी गरीब बस्तियों, महिलाओं और युवाओं के जीवन पर सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत जिन संपन्न एवं शक्तिशाली वर्गों ने सबसे ज्यादा पानी का दोहन किया होता है, उसके लाभ तो अक्सर उन्हीं तक सीमित रहते हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम दूसरों को भुगतने पड़ते हैं।

> **भारत के संदर्भ में देखें तो संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी और भी गहरी चिंता पैदा करने वाली है। दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हमारे देश में है, पर उसके हिस्से में उपलब्ध मीठा पानी सीमित है। इसके बावजूद भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जो सबसे ज्यादा भूजल दोहन कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। कुएं सूख रहे हैं, हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा और हर साल गहरे नलकूप खोदे जा रहे हैं। हमारी नदियों की हालत भी सबके सामने है। कई नदियां मृत कही जाने लगी हैं, तो कई अब वर्षाकाल तक सीमित हो गई हैं। शहरों में तालाब और झीलें या तो पाट दी गई हैं या गंदे पानी का भंडार बन चुकी हैं।**

भारत के संदर्भ में देखें, तो संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी और भी गहरी चिंता पैदा करने वाली है। दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हमारे देश में है, पर उसके हिस्से में उपलब्ध मीठा पानी सीमित है। इसके बावजूद भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जो सबसे ज्यादा भूजल दोहन कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। कुएं सूख रहे हैं, हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा और हर साल गहरे नलकूप खोदे जा रहे हैं। हमारी नदियों की हालत भी सबके सामने है। कई नदियां मृत कही जाने लगी हैं, तो कई अब वर्षाकाल तक सीमित हो गई हैं। शहरों में तालाब और झीलें या तो पाट दी गई हैं या गंदे पानी का भंडार बन चुकी हैं। वर्षा जल व्यर्थ बह जाता है, उसे सहेजने के उपाय नहीं हो रहे। तमाम मुश्किलों के बावजूद यह तय है कि हमारे यहां पानी मौजूद है, मगर हम उसका प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं।

जाहिर है, भारत में भी जल संकट प्राकृतिक से अधिक नीतिगत है। ऐसे उद्योगों की स्थापना पर चिंता व्यक्त की जा रही है, जिनमें जल खपत अत्यधिक होती है। खेती में ज्यादा सिंचाई की जरूरत वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाना भी एक बड़ा कारण है। सस्ती या मुफ्त बिजली देने के निर्णयों ने भूजल दोहन को और बढ़ा दिया है। औद्योगिक और शहरी प्रदूषण ने उपलब्ध जल को अनुपयोगी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अगर हम जल संकट से पार पाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले यह मानना होगा कि पानी असीमित नहीं है। भूजल को निजी संपत्ति मानने की सोच में बदलाव लाना होगा। भूगर्भ में मौजूद पानी सामूहिक धरोहर है और उसकी रक्षा करना भी सामूहिक जिम्मेदारी है। जल संकट और खेती के बीच गहरा संबंध है। हमें खेती में फसलों के चयन को पानी की उपलब्धता से जोड़ना होगा। शहरों और गांवों में जल की बचत को औपचारिकता भर से ऊपर उठकर और जरूरत बनाकर काम करना होगा। गंदे पानी को बहाने की जगह उसे साफ करके पुनः उपयोग में लाने के काम को बढ़ावा देना होगा। मगर बड़ा सवाल यह है कि यह सब करेगा कौन? केवल सरकारों पर जिम्मेदारी डाल कर इस संकट से नहीं उबरा जा सकता। इसके लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि जल है तो कल है।

मेहनतकश की पुकार

एकता कानूनगो बक्षी

हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग 'वैश्विक' हो चुका हैं। उसका जन्म अपने देश में होता है, बच्चों का जन्म किसी और देश में; नौकरी वे किसी और देश के लिए करते हैं। काम की भाषा अलग, व्यवहार की भाषा अलग और आत्मीयता-स्नेह की भाषा और भी अलग है। हमारी भोजन की थाली तो हमेशा से अपने देश के विभिन्न व्यंजनों के स्वाद की विविधताओं से सराबोर रही है और अब लंबे समय से लगभग हर देश के पारंपरिक भोजन का जायका ले रहे हैं। रोजमर्रा के छोटे-बड़े सामान्य सामान, बेशकीमती जूते, पहनावे, गाड़ियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हैं या स्वदेशी, इसे चिह्नित करना कठिन होता जा रहा है। ढेर सारे विकल्प, विविधताएं जीवन का आम हिस्सा बन चुकी हैं।

जब सामान्य दिनों के संघर्षों में कमी आने लगती है, नए-नए अनुभवों से हम गुजरते हैं, दुनिया की सैर करते हैं, तो अपने देश के लिए सपने भी देखने लगते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा देश, हमारा शहर भी इतना ही विकसित और सुंदर हो जाए। यह गलत भी नहीं है। हम एक दूसरे से जब सीखते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। पर एक बहुत बड़ा तबका हमारे ही समाज का ऐसा है, जिसे हमारी सभी सुविधाओं से लैस कालोनियां ही किसी अलग दुनिया का हिस्सा लगने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है, वह गरीब बस्ती के लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है। महामारी का असर मलिन बस्तियों में ज्यादा होता है, गरीब मजदूर आदमी दूषित पानी से बीमार क्यों होने लगता है। दवा पीकर क्यों बच्चे अधिक बीमार हो जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में गरीब लोगों के नवजात को चूहे क्यों कुतर जाते हैं? क्या इस पर हम गंभीरता से कभी सोच पाए हैं?

गरीब व्यक्ति जब किसी मध्यवर्गीय या संभ्रांत कहे जाने वाली कालोनी में जाता है और वहां की व्यवस्था- साफ पानी, सुरक्षा, बच्चों के खेलने के पार्क और स्वच्छता को देखता है, तब वह भी एक सपना देखने लगता है कि उसकी गलियों तक भी विकास की हवा पहुंचे। वह संपन्न मध्यवर्गीय परिवार या व्यक्ति की तरह वैश्विक नहीं हुआ है, उसके पास ढेर सारे विकल्प मौजूद नहीं हैं। उसका और उसके पूरे परिवार का जीवन इसी देश में गुजरने वाला है। इसीलिए उसका अधिकार इस देश के ऊपर अधिक है। वह यहां का स्थायी नागरिक है। उसकी जरूरतें, सपने, उम्मीदें सबसे पहली प्राथमिकता में होना चाहिए।

हम सब मनुष्य हैं, उसके बाद भी हम सबकी जरूरतें और संघर्ष कितने अलग हैं। ऐसे में हम सबके भीतर संवेदनशील मन का होना बेहद जरूरी हो जाता है। जगमगाती रोशनी, गगनचुंबी इमारतों को सराहते हुए हमारे चित्त में यह भी रहना चाहिए कि हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, कहीं कोई छूट तो नहीं रहा। विकास के क्रम में सबसे पहला अधिकार उन लोगों का आना चाहिए, जिनकी मूलभूत जरूरतें अभी तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। विकास होते हुए महसूस हम कर सकते हैं जब हमारी असमानताओं की खाई कम होने लगे। मूलभूत जरूरतें, जैसे साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और सुरक्षा की गुणवत्ता सभी नागरिकों के लिए समान हो।

कुछ लोगों को अलग तरह का पानी, अलग शिक्षा, स्वास्थ्य- इस तरह की असमानता से हम कभी भी प्रगतिशील और मजबूत समाज नहीं बना सकेंगे। एक तबका हमेशा पिछड़ा रहेगा। एक गली हमेशा मलिन बनी रहेगी। मूलभूत जरूरतों को लेकर किसी भी तरह की भिन्नता को हटाना होगा। अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति, दोनों को ही समान गुणवत्ता की मूलभूत सुविधाएं एक समान प्राप्त होनी चाहिए। विकास के लिए सबसे पहले ईमानदार कोशिश की जरूरत होती है और ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो जमीन से जुड़े हुए हों, जिनका उद्देश्य व्यापक हो और स्वार्थ से परे हो। किसी भी तरह का विकास एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरता है। हमें खुद के भीतर की खूबियों और कमियों से अवगत होना होता है।

जब हम खुद को केंद्र में रखकर संघर्ष करते हैं, तब हमारी नींव मजबूत बनती है, हर सफलता को हम अपनी पहले की स्थिति को देखकर समझते हैं, न कि किसी विकसित देश को अपना आदर्श मानकर आनन-फानन उसकी तरह बन जाने का प्रयास करने लगते हैं। ऊपरी साज-सजावट की जगमगाहट जरूर हमें चकित करती है, पर उसके कारण पड़ा दबाव मूलभूत ढांचे की स्थिति को और भी जर्जर कर देता है। विकास की शुरुआत भव्य आलीशान इमारतों से नहीं होती है, उसकी शुरुआत के लिए तंग गलियों में जाना होता है। फिर उसमें कितना ही समय लगे, पर वह परिवर्तन स्थायित्व लिए होता है।

विकसित देशों को देखकर उनकी तरह बनने का सपना देखना, दूसरों से सीखना, समझना, विविधताओं को अपनाना बहुत अच्छी बात है। पर उसके साथ जुड़ी एक लंबी प्रक्रिया को भी समझना, जिसमें बुनियादी काम किए गए हों, जनभागीदारी से निर्णय लिए गए हों, प्रगतिशील और व्यापक सोच के साथ सबके हित को ध्यान में रखते हुए रूपरेखा बनाई गई हो, जो निश्चित करती हो कि यह एक समान और सबकी पहुंच सुनिश्चित करने वाले विकास को बढ़ावा देने में सक्षम रहेगी। विकास की ओर पहला कदम उन दबी हुई, बिलखती आवाजों को सुनना और उसे मजबूती देना होना चाहिए, जिसके होने से देश सांस लेता है। मेहनतकश लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, उनके सपनों को प्राथमिकता देने से ही देश की नींव मजबूत हो सकती है। मजबूत नींव पर हर सपने को पूरा किया जा सकता है।

दुनिया मेरे आगे

> **हम सब मनुष्य हैं, उसके बाद भी हम सबकी जरूरतें और संघर्ष कितने अलग हैं। ऐसे में हम सबके भीतर संवेदनशील मन का होना बेहद जरूरी हो जाता है। जगमगाती रोशनी, गगनचुंबी इमारतों को सराहते हुए हमारे चित्त में यह भी रहना चाहिए कि हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, कहीं कोई छूट तो नहीं रहा।**

संवेदना की जगह

बीते दिनों नोएडा में कार डूबने से एक युवक की असमय मृत्यु ही नहीं हुई, बल्कि यह वर्तमान समय के नैतिक पतन का संकेत भी है। सत्ताईस वर्षीय होनहार नौजवान की मौत उसके असहाय पिता की आंखों के सामने हो जाना और वहां बचाव कर्मियों का मूकदर्शक बने खड़े रहना, व्यवस्था पर कठोर प्रश्न खड़े करता है। ये लोग कोई एआइ नियंत्रित रोबोट नहीं थे, बल्कि हाड़-मांस से बने वही जीवित इंसान थे, जिनका पेशा ही संकट में फंसे लोगों की जान बचाने का है। आज समस्या संसाधनों की नहीं, संवेदनाओं और साहस की कमी की है। वीरता का अर्थ केवल पदकों या सुर्खियों में आना नहीं होता, बल्कि जोखिम उठा कर सही समय पर उचित कदम उठाना होता है। यदि कोई बचाव कर्मी आपात स्थिति में भी निर्जीव बना रहे, तो उसे उस पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को न केवल जवाबदेह ठहराया जाना जरूरी है, बल्कि बचाव दलों से उनकी छंटनी, प्रशिक्षण और मूल्यांकन भी अनिवार्य है। वरना हम ऐसे समाज में बदल जाएंगे, जहां तकनीक तो उन्नत होगी, लेकिन इंसान भीतर से संवेदनहीन।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

संतोष का पैमाना

हम भौतिक सुख-सुविधाओं के पीछे इस कदर भागते हैं कि जीवन का असली आनंद भूल जाते हैं। सच्चा सुख अधिक पाने की होड़ में नहीं, बल्कि कम में भी पूर्णता खोजने में है। मनुष्य का मन ऐसी छलनी की तरह है, जिसे संसार की वस्तुओं से कभी नहीं भरा जा सकता। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है, जिससे मन सदैव अशांत रहता है। सच्चा वैभव बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं और जो हमारे पास है, उसका सम्मान करना सीखते हैं, तभी हमें मानसिक शांति मिलती है। हमारे पास मौजूद अनमोल उपहार जैसे स्वास्थ्य, समय और परिवार अक्सर हमारी उपेक्षा का शिकार होते हैं। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि वर्तमान के प्रति एक गहरा आभार है। यदि मन संतुलित हो, तो एक साधारण भोजन भी अमृत के समान और एक छोटी सी कुटिया भी स्वर्ग जैसी लग सकती है।

– समीक्षा मिश्रा, जम्मू

गरिमा के प्रतिकूल

'दायित्व का बोझ और शिक्षक की गरिमा' (आलेख, 23 जनवरी) पढ़ा। एक समय था जब शिक्षक स्कूलों में जाते थे, तो उन्हें सिर्फ बच्चों को पढ़ाना होता था। मगर अब शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा दूसरे कार्यों में लगा दिया जाता है। यह उनकी गरिमा के प्रतिकूल है। कई बार तो महीनों निर्वाचन कार्य के कारण वे स्कूल नहीं जा पाते। कुछ समय पहले बड़ी संख्या शिक्षकों को मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में लगा दिया गया। बच्चे बगैर शिक्षकों के कक्षा में बैठे रहे। बात जब सरकारी स्कूलों की होती है, तो कहा जाता है कि बच्चे पढ़ाई में काफी पीछे हैं और तो और यह भी कहा जाता है कि शिक्षक ठीक से पढ़ाते नहीं। मगर इस ओर ध्यान कम ही जाता है कि शिक्षकों को कितने कार्यों में लगा दिया गया है। इससे उनकी कार्यक्षमता पर असर पड़ता है और वे पठन-पाठन ठीक से नहीं करवा पाते। सरकारी शिक्षा में जो नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें कम करना होगा।

– साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर

सुधार का रास्ता

वैश्विक स्तर पर अस्थिरता के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में नजर आती है। हालांकि, आर्थिक गति को निरंतर बनाए रखने के लिए केवल संभावनाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए ठोस नीतिगत सुधारों और घरेलू मोर्चे पर सक्रियता जरूरी है। विकास की दर स्थिर रखने के लिए उपाय करने होंगे। बाहरी आर्थिक उतार-चढ़ाव से बचने के लिए देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ाना होगा। रोजगार सृजन के साथ युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना विकास की प्राथमिकता में होना चाहिए। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रख कर ही लंबी अवधि की स्थिरता हासिल की जा सकती है। अब समय 'नई पीढ़ी के सुधारों' का है, जिनमें मुख्य रूप से आम नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। वहीं बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ कारोबार सुगमता बढ़ानी होगी।

– प्रसिद्ध यादव, फुलवारी, पटना

लोककला

गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर नई दिल्ली में छऊ नृत्य प्रस्तुत करता लोक कलाकारों का समूह।

बोल

अबू धाबी में रूस और अमेरिका के साथ दो दिनों की त्रिपक्षीय वार्ता युद्ध समाप्त करने के संभावित मापदंडों पर चर्चा के साथ समाप्त हुई। सभी पक्ष वार्ता पर अपने नेताओं के साथ आगे के कदमों का समन्वय करने पर सहमत हुए।
- व्लोदिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति

बोल

शांति समझौते तक पहुंचने के लिए, कीव को पूर्व के उन क्षेत्रों से अपनी सेना वापस बुलानी होगी, जिन्हें रूस ने कब्जा करके अपनी सीमा में शामिल होने का दावा किया है, लेकिन पूरी तरह से अपने अधिकार में नहीं लिया है।
- व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति

सम-सामयिक

जापान : आव्रजकों का स्वागत, भारतीय बन गए पहली पसंद

जनसत्ता संवाद

जापान धीरे-धीरे आबादी घटने के दबाव में विदेशी श्रमिकों को अपना रहा है। यहां गंभीर बहस हो रही है कि विदेशी श्रमिकों और निवासियों को कितनी संख्या में और कितनी तेजी से स्वीकार किया जाए। जापान धीरे-धीरे एक आव्रजन देश बनने के प्रयोग कर रहा है। भारतीय पहली पसंद बन रहे हैं।

आज भी देश की कुल आबादी में विदेशी निवासियों की हिस्सेदारी लगभग तीन फीसद ही है, जो यूरोप या उत्तरी अमेरिका के मुकाबले काफी कम है। जापानी मीडिया में प्रकाशित संपादकीय और विचार लेख अब केवल आर्थिक जरूरतों पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सुरक्षा और जनसंख्या घटने के दौर में जापानी होने के अर्थ जैसे सवालों पर भी चर्चा कर रहे हैं। विदेशी श्रमिक और निवासी अब कई प्रतीकात्मक सीमाएं पार कर चुके हैं। क्योतो शिम्बुन के मुताबिक, विदेशी श्रमिकों की संख्या अब 20 लाख से अधिक हो चुकी है और कुल विदेशी निवासी 32 लाख से ऊपर हैं।

मुख्यधारा का मीडिया भी अब मानने लगा है कि आव्रजन जापानी समाज का हिस्सा बन चुका है। माइनिची शिंबुन के संपादकीय में बताया गया कि विदेशी निवासियों की संख्या लगभग 34 लाख यानी कुल आबादी का करीब 2.7 फीसद है। ये लोग अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं हैं। छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी श्रमिक, माता-पिता और पड़ोसी के रूप में रह रहे हैं।

इस बदलते परिदृश्य में भारतीय कहां हैं? जापान में भारतीय समुदाय की संख्या चीनी, वियतनामी या फिलिपीनी समुदायों की तुलना में कम है लेकिन इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जापान में भारतीय दूतावास के अनुसार, वहां 50,000 से अधिक भारतीय रहते हैं। इनमें से कई आइटी, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, वित्त और वैज्ञानिक शोध से जुड़े हैं। एक नया वर्ग सेवा क्षेत्र, विनिर्माण और आतिथ्य उद्योग में काम कर रहा है। नीतिगत स्तर पर भारत और जापान ने पहले ही ठोस ढांचे तैयार कर लिए हैं। वर्ष 2017 का तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को जापानी कंपनियों में काम के दौरान कौशल सीखने का अवसर देता है। वहीं 2021 का समझौता भारतीय श्रमिकों को 14 क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। आने वाले वर्षों में भारत-जापान सहयोग में मानव संसाधन और श्रमिक आवाजाही भी रक्षा, तकनीक और बुनियादी ढांचे के साथ अहम हो सकती है।

आने वाले वर्षों में भारत-जापान सहयोग में मानव संसाधन और श्रमिक आवाजाही भी रक्षा, तकनीक और बुनियादी ढांचे जैसे पारंपरिक मुद्दों के साथ एक अहम स्तंभ बनकर उभर सकती है।

अध्येताओं के लिए जापान की आव्रजन बहस- और उसमें भारतीय श्रमिकों की उभरती भूमिका-एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। हिंद-प्रशांत रणनीति को आकार देने में भारत-जापान सहयोग में मानव संसाधन का विषय अहम होगा। निप्पोन डाट काम ने गुनमा, टोक्यो के शिंजुकु और कोच्चि जैसे क्षेत्रों के उदाहरण दिए हैं, जहां कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। विदेशियों के खिलाफ नफरत भड़काने वाली भाषा से बचने और राजनीति से ऊपर उठकर साथ रहने की नीतियों पर जोर है। यह बहस भारत-जापान सहयोग की आवश्यकता दिखाती है, जहां भाषा प्रशिक्षण, पारदर्शी भर्ती, श्रमिक अधिकार और कौशल मान्यता सुनिश्चित करना जरूरी है।

डर भी है

जापान के प्रतिबंध समर्थकों को डर है कि अगर विदेशी निवासियों की संख्या तेजी से बढ़ी तो सामाजिक दबाव, अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिम बढ़ सकते हैं। साकेई शिम्बुन में छपे एक लेख में सवाल उठाया गया कि विदेशी आबादी का उपयुक्त अनुपात क्या होना चाहिए और अगर यह 10 फीसद तक पहुंच गया तो क्या होगा। प्रेजिडेंट आनलाइन ने अगले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में श्रमिकों को स्वीकार करने की योजनाओं को मतदाताओं की स्पष्ट सहमति के बिना 'पिछले दरवाजे से आव्रजन नीति' बताया।

शोध

हर साल खोजी जा रही हैं 16,000 से ज्यादा प्रजातियां

जनसत्ता संवाद

वैज्ञानिक अध्ययन में पता चला है कि हर साल औसतन 16,000 से अधिक नई प्रजातियां सामने आ रही हैं, जिनमें 10,000 से अधिक जानवर (ज्यादातर कीट और अन्य आर्थ्रोपाड), 2,500 पौधे और 2,000 फफूंद शामिल हैं। यूनिवर्सिटी आफ एरिजोना के शोधकर्ताओं का कहना है कि पौधों, फफूंद (फंगी), मकड़ियों, मछलियों और उभयचरों जैसे कई जीव समूहों में जैव-विविधता हमारी सोच से कहीं अधिक समृद्ध है।

वैज्ञानिकों ने वर्ष 2015 से 2020 के बीच, हर साल औसतन 16,000 से अधिक नई प्रजातियों की खोज की है। इनमें 10,000 से ज्यादा जानवर (ज्यादातर कीट और अन्य आर्थ्रोपाड), 2,500 पौधे और 2,000 फफूंद शामिल हैं। अनुमान है कि भविष्य में मछलियों की 1,15,000 और उभयचरों की 41,000 प्रजातियां सामने आ सकती हैं, जबकि अभी तक मछलियों की महज 42,000, जबकि उभयचरों की 9,000 प्रजातियों की ही खोज हुई है। पौधों की प्रजातियां पांच लाख से भी अधिक हो सकती हैं।

अभी तक वैज्ञानिक करीब 11 लाख कीट प्रजातियों की पहचान कर पाए हैं, जबकि इनकी असल संख्या करीब 60 लाख हो सकती है। करीब तीन सौ साल पहले, स्वीडन के प्रकृतिवादी कार्ल लिनियस ने हर जीव को पहचानने और उसे नाम देने का प्रयास शुरू किया था। आज उन्हें आधुनिक टैक्सोनामी का जनक माना जाता है। अपने जीवनकाल में उन्होंने पौधों और जानवरों की 10,000 से अधिक प्रजातियों का वर्णन किया। वैज्ञानिक उसी खोज को नई गति दे रहे हैं।

यूनिवर्सिटी आफ एरिजोना में किए गए अध्ययन में सामने आया है कि वैज्ञानिक हर साल औसतन 16,000 से अधिक नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। यह अब तक की सबसे तेज रफ्तार है। शोधकर्ताओं का कहना है कि पौधों, फफूंद (फंगी), मकड़ियों, मछलियों और उभयचरों जैसे कई जीव समूहों में जैव-विविधता हमारी सोच से कहीं अधिक समृद्ध है। इस अध्ययन के नतीजे अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'साइंस एडवांसेज' में प्रकाशित हुए हैं।

(फाइल फोटो)

अध्ययन के वरिष्ठ लेखक प्रोफेसर जान वाइंस के मुताबिक, 'कुछ वैज्ञानिक मानते थे कि नई प्रजातियों की खोज धीमी पड़ गई है और शायद अब सामने लाने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन हमारे शोध के नतीजे इसके बिलकुल उलट हैं, आज हम पहले से कहीं तेजी से नई प्रजातियां खोज रहे हैं और जीवन की विविधता से जुड़े रहस्य उजागर कर रहे हैं।'

अपने अध्ययन में वैज्ञानिकों ने करीब 20 लाख ज्ञात प्रजातियों का विश्लेषण किया है। नई प्रजातियों की खोज की रफ्तार, विलुप्त होने की रफ्तार से कहीं ज्यादा है। अक्तूबर 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक हर साल करीब 10 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। वाइंस का कहना है, 'अगर कोई एलियन हमसे पूछे कि धरती पर कितनी प्रजातियां हैं, तो हमारे पास इसका पक्का जवाब नहीं होगा।' उनके मुताबिक अभी हम करीब 25 लाख प्रजातियों को जानते हैं, लेकिन असल संख्या करोड़ों, शायद अरबों में भी हो सकती है।

अभी तक वैज्ञानिक करीब 11 लाख कीट प्रजातियों की पहचान कर पाए हैं। कीट प्रजातियों की कुल संख्या दो करोड़ के आसपास भी हो सकती है। फिलहाल ज्यादातर नई प्रजातियां बाहरी बनावट के आधार पर पहचानी जाती हैं। लेकिन जैसे-जैसे डीएनए और आणविक तकनीक बेहतर होंगी, वैसे-वैसे छिपी हुई (क्रिप्टिक) प्रजातियां भी सामने आएंगी, ऐसे जीव जो दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन आनुवंशिक रूप से अलग हो सकते हैं।

नई प्रजातियों की खोज सिर्फ ज्ञान बढ़ाने तक सीमित नहीं है। कई नई प्रजातियां दवाओं और तकनीक के लिए खजाना साबित हो सकती हैं। वजन घटाने की लोकप्रिय दवाओं में इस्तेमाल होने वाला जीएलपी-1 हार्मोन गिला मांस्टर नामक छिपकली से प्रेरित है।

विश्व परिक्रमा

इंडोनेशिया : सुलावेसी में मानव इतिहास की सबसे पुरानी गुफा

जनसत्ता संवाद

इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पाए गए गुफा चित्र मानवता की अब तक की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कला हैं। यह खोज यूरोप में पाए जाने वाले फ्रांस और स्पेन के प्रसिद्ध गुफा चित्रों से हजारों साल पहले की कला का सबूत देती है। 'नेचर' जर्नल में प्रकाशित इस शोध में बताया गया है कि पूर्वी इंडोनेशिया में रहने वाले लोग अब तक सोचे गए समय से कहीं पहले पत्थर पर चित्र बना रहे थे। ये कलाकार संभवतः उस आबादी का हिस्सा थे जो बाद में आस्ट्रेलिया और पापुआ के आदिवासी पूर्वजों के तौर पर विकसित हुईं।

सुलावेसी की चूना-पत्थर की गुफाओं में लाल रंग के हाथ से बनाए गए स्टेंसिल पाए गए हैं, जो पत्थर पर दबा कर रखे गए हाथ पर रंग को फूंककर डालते हुए बनाए गए थे। यूरेनियम के सूक्ष्म विश्लेषण से चित्रों के बनने का समय कम से कम 67,800 वर्ष पुराना पाया गया, जिससे यह पूरी दुनिया की अब तक की सबसे पुरानी, सुरक्षित रूप से जांची गई गुफा कला बन गई। यह क्षेत्रीय चित्रों से 15,000 वर्ष और फ्रांस के सबसे पुराने गुफा चित्रों से 30,000 वर्ष पुराना है।

इससे पहले सुलावेसी में पक्षी जैसे सिर वाले मानव चित्र और अन्य पशु-संरचना वाले चित्र भी पाए गए थे, जो कम से कम 48,000 वर्ष पुराने थे। पत्थरों की इन गुफाओं में चित्रकला एक लंबी अवधि तक जारी रही, करीब 20,000 वर्ष पहले आखिरी हिम युग तक।

शोध से यह भी संकेत मिलता है कि इन चित्रों को बनाने वाले लोग संभवतः उस आबादी का हिस्सा थे, जिन्होंने समुद्र पार किया, आस्ट्रेलिया और न्यू गिनी पहुंचे तथा बस गए। इन लोगों को आधुनिक आदिवासी आस्ट्रेलियाई लोगों के पूर्वज के तौर पर जाना जाता है।

जानें-समझें

भारत और यूरोपीय संघ

वैश्विक कूटनीतिक मंच पर नई धमक

जनसत्ता संवाद

भारत-यूरोपीय संघ के रिश्ते एक नए रणनीतिक दौर में प्रवेश कर गए हैं। अमेरिका में ट्रंप के शासन में संबंधों और नीतियों को लेकर अनिश्चितताओं से यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों को नई दिशा मिली है। भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें दंडात्मक शुल्क और रूस से तेल खरीद के संबंध में दबाव शामिल हैं।

यूरोपीय संघ और भारत इस बात को मानते हैं कि रणनीतिक स्वायत्तता महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि गठबंधन सुरक्षा की गारंटी नहीं देते हैं। ऐसे में इस साल 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय संघ के नेताओं की यात्रा पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हैं। ईयू के नेताओं की यात्रा में मुक्त व्यापार समझौते से वस्त्र, दवा, रसायन, वाहन और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नए मौके सृजित होंगे।

मजबूत संबंधों की कवायद

भारत-यूरोपीय संघ के संबंध मुख्य रूप से आकस्मिक रहे हैं, जो अक्सर रूस और चीन से संबंधित चर्चाओं से प्रभावित होते रहे हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यूरोपीय संघ-भारत साझेदारी एक लचीले और व्यावहारिक संबंध माडल का उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। यह साझेदारी रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देती है, जिससे रूस के गैस, चीनी बाजारों और अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर निर्भरता कम हो सके। भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। यह साझेदारी भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप है, जो रक्षा क्षेत्र में सह-उत्पादन के अवसर प्रदान करती है। यूरोपीय संघ ने भारत के साथ जापान और दक्षिण कोरिया के साथ ही समान सुरक्षा व रक्षा साझेदारी का प्रस्ताव रखा है।

सटीक अवसर

भारत और यूरोपीय संघ - दोनों ही इस अवसर का लाभ उठाकर और आंतरिक नौकरशाही चुनौतियों पर काबू पाकर एक लचीली, न्यायसंगत और संप्रभु बहुध्रुवीय व्यवस्था स्थापित करके बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने की स्थिति में हैं। द्विपक्षीय संबंध 1962 से चले आ रहे हैं, जब भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय (जो कि यूरोपीय संघ का पूर्ववर्ती संगठन था) के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक बन गया था। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लिस्बन में पहला भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।

महत्त्व, उम्मीद और भरोसा

इस बार के शिखर सम्मेलन में तीन प्रमुख परिणाम अपेक्षित हैं - व्यापार, सुरक्षा और रक्षा तथा आवागमन पर समझौते। पिछले साल फरवरी में आयुक्तों के संघ के दौरे के बाद से, भारत और यूरोपीय संघ ने संबंधों को गति देने के लिए एक महत्त्वाकांक्षी और रणनीतिक रोडमैप पर काम किया है। इसे एक ठोस आधार प्रदान करने के लिए, यूरोपीय संघ ने पिछले साल सितंबर में अपना रणनीतिक एजंडा दस्तावेज जारी किया। भारत का यूरोपीय संघ के लिए महत्त्व है। एक अरब से अधिक कामकाजी आयु वर्ग के लोगों और 31 वर्ष की औसत आयु के साथ, भारत 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है।

व्यापार और निवेश

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यूरोपीय संघ के साथ भारत का कुल वस्तु व्यापार लगभग 136 अरब अमेरिकी डालर का था, जिसमें निर्यात लगभग 76 अरब अमेरिकी डालर और आयात 60 अरब अमेरिकी डालर था। भारत में लगभग 6,000 यूरोपीय कंपनियां कार्यरत हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से 30 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। पांच वर्षों में भारत में यूरोपीय संघ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोगुना हो गया है, और भारतीय कंपनियां लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) में निवेश सहित विभिन्न माध्यमों से यूरोपीय संघ में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही हैं।

(फाइल फोटो)

दुनिया पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, इसलिए ईयू-भारत रक्षा सहयोग को और गहरा करना स्वाभाविक कदम है। हम व्यापार, सुरक्षा और तकनीक पर साथ काम करने वाले हैं। गणतंत्र दिवस में शामिल होने का न्योता बड़ा सम्मान है और यह सच्चे भरोसे को दिखाता है। भारत अब सिर्फ एक भागीदार नहीं रहा, बड़ा रणनीतिक सहयोगी भी है। - *काजा कल्लास, उपाध्यक्ष, यूरोपीय संघ*

यूरोपीय संघ भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है। दोनों पक्ष एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, बल्कि विकास के महत्त्वपूर्ण अवसरों को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत और यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं, इसलिए यह भारतीय निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों के लिए बड़ा मौका होगा। - *भास्वती मुखर्जी, भारत की पूर्व राजदूत, नीदरलैंड*

सुरक्षा और रक्षा

भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ इस तरह की साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा देश होगा - एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया अन्य दो देश हैं। गतिशीलता साझेदारी समझौता कुशल भारतीय प्रतिभाओं के लिए यूरोपीय संघ के साथ जुड़ने के नए गतिशीलता मार्ग तैयार करेगा। यूरोपीय संघ में भारतीय प्रवासी समुदाय में लगभग 13 लाख लोग शामिल हैं, जिनमें 884,718 अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) और 478,206 भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआइओ) शामिल हैं। यूरोप के मुख्य भूभाग में सबसे बड़े भारतीय समुदाय जर्मनी (260,864), नीदरलैंड (228,787) और इटली (206,503) में हैं। 2024 में, भारतीय नागरिकों को यूरोपीय संघ में निवास करने की सबसे अधिक अनुमति प्राप्त हुई।

व्यक्तित्व

नंदिनी : महिला लीग में लगातार तीन विकेट लेकर रचा इतिहास

जनसत्ता संवाद

क्रिकेट की महिला प्रीमियर लीग में नंदिनी शर्मा ने इतिहास रच दिया। वह दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से लगातार तीन विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गईं। इसके साथ ही उन्होंने पांच विकेट भी चटकाए। नंदिनी से पहले इसी वोंग (मुंबई इंडियंस), ग्रेस हैरिस (यूपी वारियर्स) और दीप्ति शर्मा (यूपी वारियर्स) के नाम यह कीर्तिमान दर्ज है।

डब्ल्यूपीएल के एक मैच में पांच विकेट लेने वाली वह सातवीं गेंदबाज और भारत की दूसरी गेंदबाज बन चुकी है। उनसे पहले आशा शोभना ने यूपी वारियर्स के लिए पांच विकेट झटके थे।

चंडीगढ़ में जन्मीं नंदिनी 2025 की सीनियर विमेंस टी20 ट्राफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों में शामिल थी। इसी को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 20 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा था। नंदिनी का यह पहला सत्र है। उन्होंने खुद को एक उभरती हुई तेज गेंदबाज के रूप में स्थापित किया है। गुजरात जाइंट्स के खिलाफ हैट्रिक लेकर नंदिनी ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। उन्होंने यह सफलता गुजरात जाइंट्स की पारी के 20वें ओवर में नंदिनी ने कनिका आहूजा, राजेश्वरी गायकवाड़ और रेणुका सिंह को आउट कर हासिल की। हालांकि, नंदिनी के शानदार गेंदबाजी के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स वह मुकाबला हार गई थी।

नंदिनी शर्मा चंडीगढ़ की एक प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उन्होंने चंडीगढ़ महिला टीम का प्रतिनिधित्व किया है और उत्तरी क्षेत्रीय महिला टीम की ओर से अंतर क्षेत्रीय मुकाबले भी खेले हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए हैट्रिक लेने के बाद उन्होंने इसका श्रेय टीम की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा को दिया। दिल्ली कैपिटल्स की तेज गेंदबाज ने बताया कि जेमिमा और शेफाली ने लगातार उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, 'मैं बस अपने लक्ष्य पर गेंदबाजी करने पर ध्यान दे रही थी। शेफाली और जेमिमा हर गेंद से पहले मुझसे बात कर रही थीं और हमारी योजना बिल्कुल साफ थी, स्टंप्स पर हमला करना। मुझे लगातार तीन विकेटों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन टीम लगातार कह रही थी कि विकेट मिलेंगे।'

नंदिनी ने इस टूर्नामेंट के पहले मैच में भी शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने तीन ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 26 रन देकर दो विकेट चटकाए थे, जिसमें गुनालन कामलिनी और निकोला कैरी के अहम विकेट शामिल थे। नंदिनी ने यही लय गुजरात जाइंट्स के खिलाफ भी बरकरार रखी। डब्ल्यूपीएल 2026 में नंदिनी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी हैं।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

आदिवासी हक्कांवर ‘सुधारणे’ची काट!

‘**वनहक्क कायदा**– अंमलबजावणीची सद्य:स्थिती’ हा माधव गाडगीळ आणि विजय एदलाबादकर यांचा लेख (रविवार विशेष, २५ जानेवारी) वाचला. वनहक्क कायदा हा मुळातच वर्षानुवर्षं जंगलात वनजमिनी कसणाऱ्या आदिवासींवर झालेला ऐतिहासिक अन्याय मान्य करून त्यांना सन्मानपूर्वक न्याय मिळवून देण्यासाठी २००६ मध्ये संसदेने मंजूर केला, पण विद्यमान केंद्र सरकारने ‘वनसंवर्धन सुधारणा कायदा २०२३’ करून पूर्वीच्या वनहक्क २००६ कायद्याला अधिक कमजोर करून अधिकचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. नव्या कायद्याने वनसंवर्धन व आदिवासींच्या सहजीवनाकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करून जंगलावर आधिक कठोर सरकारी नियंत्रण आणि त्यांचे बाजारीकरण करण्याचा घाट घालणे सोपे झाले आहे. ग्रामसभांचा अंतिम अधिकार नाकारणारी ‘सुधारणा’ वन संवर्धन कायद्यात असली तरी ती वनहक्क कायद्याच्याच मुळावर येणार. ग्राम वनांचे व्यवस्थापन खासगी व्यक्ती /संस्थाकडे जाण्याची मुभा देऊन, राखीव वनांच्या नावाखाली आदिवासी/वननिवासींना वनहक्क २००६ कायद्यान्वये मिळालेले जमिनीचे पट्टे सरकार काढून घेऊ शकते. या २०२३ च्या कायद्याचा भंग करणाऱ्याला शिक्षेची तरतूद असल्याने वन हक्कांसाठी अथवा त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी लढणाऱ्यांचा छळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘उत्पादक वने’ ही संज्ञा कायद्यात असून त्याद्वारे जंगलाचे बाजारीकरण करून भांडवलदार व व्यापाऱ्यांकडे सोपवण्याचे धोरण आपल्या सरकारने स्वीकारल्याचे स्पष्ट दिसते. वन विभागाला- पर्यायाने शासनाला अमर्याद अधिकार देऊन, आदिवासींचे अधिकार काढून घेतले जात आहेत, विकासाच्या नावाखाली त्यांच्या जगण्याचा आधारही नष्ट केला जात आहे तर दुसरीकडे भांडवली बाजारपेठेची भूक भागवण्यासाठी जंगले खासगी मालकीच्या हाती दिली जात आहेत. केवळ कायदे करून आदिवासींना न्याय मिळणार नाही तर त्या कायद्याचा उद्देशही शुद्ध असला पाहिजे आणि त्या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली तरच या वंचित घटकांना न्याय मिळू शकेल

■ **डॉ. बी. बी. घुगे,** बीड

लिहिणारे लिहितात, वाचणारे वाचतात; पण...

‘**वनहक्क कायदा**-अंमलबजावणीची सद्य:स्थिती’ हा लेख वाचला. आदिवासींच्या संरक्षण व कल्याणासाठी आखल्या जाणाऱ्या योजना, केले जाणारे कायदे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची होणारी गत या नेहमीच्या अनुभवापेक्षा आदिवासी वनहक्क कायद्याचा अनुभव काही वेगळा नाही. वास्तविक हा एक अतिशय महत्त्वाचा कायदा लागू करण्यात येऊन सुमारे दोन दशके लोटली पण या कायद्यातून किती प्रश्न सुटले हे सांगणे फार कठीण आहे. कोणतही सरकार आदिवासी भागात जाऊन जाहीर केलेल्या योजनांची किती प्रमाणात अंमलबजावणी झाली याची माहिती घ्यायला तयार नाही. आणि सरकारी नोकर वर्ग त्या दुर्गम भागात नोकरी करण्यासाठी उदासीन असतो. असेच घडत राहिले तर शेवटच्या घटकाचा विकास कसा साधला जाईल? रानावनात राहणाऱ्या आदिवासी समाजाचा विकास करायचा असेल तर त्यांना कायदा आणि योजनेची परिपूर्ण माहिती दिली गेली पाहिजे. त्यासाठी शिक्षण महत्त्वाचे आहे. आजही आदिवासी दुर्गम भागात शिक्षण दुरापास्तच. जागरूकतेचा अभाव, भाषेची समस्या आपल्या हक्काबद्दल अपुरी समज ही परिस्थिती महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि ओरिसामधील काही अपवाद वगळता देशभरात असून त्यावर सरकारने काम करण्याची गरज आहे. नाही तर, आदिवासी विकासाबद्दल लिहिणारे लिहितात, वाचणारे वाचतात- एवढेच सुरू आहे.

■ **अमोल आढळकर,** नांदगाव (नाशिक)

व्यवस्थाभ्रष्टतेमुळे संविधानालाच धक्का

छगन भुजबळ दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातून दोषमुक्त झाल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- २४ जाने.) वाचले. हा निकाल बैलगाडीभर भ्रष्टाचाराचे पुरावे असणाऱ्या नेत्यांना चपराक देणारा ठरावा. भाजपची सत्ता केंद्र व राज्यात येण्यापूर्वी २०१० मधील २जी स्पेक्ट्रम घोटाळा व २०१२ मध्ये कॅगचा कोळसा घोटाळ्यासंबंधित अहवाल या दोन्हीप्रकरणी देशाचे १.७६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढला गेला होता हे विशेष. या प्रकरणांचे पुढे काय झाले, न्यायालयांत ती कितपत टिकली हे सर्वश्रुत आहे. अजित पवारांवरही ७० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होता. राज्यकर्त्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करा, माध्यमांत पेरलेल्या मंडळींच्या मार्फत वातावरणनिर्मिती करा व संधी मिळताच सत्ता हस्तगत करा असे पेव मध्यंतरी फुटले होते. परंतु सत्ता हाती येताच तत्कालीन कायद्यांना / नियमांना नवे रूप असे मिळाले की, पुढील काळात राज्यकर्त्यांना भ्रष्टाचारापासून अभय मिळावे. नवनवीन रस्त्यांच्या, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचे खर्च किती पटींनी व कसे वाढतात ही याची बोलकी उदाहरणे ठरावीत. अधिकाधिक प्रदेश ‘सत्ताक्रांत’ करण्याच्या नादात, संपूर्ण व्यवस्थाच भ्रष्ट होते आहे व त्याने देशाच्या मूळ संविधानालाच धक्का बसतो आहे, याचा विसर पडलेल्या राजकीय समुदायास, प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने राज्यघटनेचे पालन करण्याची सुबुद्धी यावी एवढीच अपेक्षा.

■ **शैलेश न. पुरोहित,** मुलुंड पूर्व (मुंबई)

‘कायद्याच्या राज्या’साठी चिंतेचे कारण?

‘**उच्च न्यायालये** कायद्याच्या राज्याचे प्रथम संरक्षक, सरन्यायाधीशांकडून कर्तव्याची आठवण’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २५ जाने.) व सोबतचा इतर तपशील वाचला. न्यायमूर्तीपद भूषवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीबद्दल मनात सन्मानाचीच भावना असूनही असा प्रश्न पडला की, सरन्यायाधीशांनी अशी कर्तव्याची आठवण का करून दिली असावी? उच्च न्यायालये कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरत आहेत का? की त्यांचा रोख खासकरून व्यवस्थात्मक अपयशाबाबत सावध व सक्रिय असण्यावर असून उच्च न्यायालयांकडून त्याबाबतीत कुठेतरी कसूर होत आहे अशी त्यांची भावना असावी? व्यवस्थात्मक अपयश जाणवत असेल तर ते त्यांच्याच (उच्च न्यायालयांच्याच) पातळीवर रोखले जाऊ शकते असे त्यांना म्हणायचे असावे. तसे असेल तर तशी कर्तव्याची आठवण करून देणे उचितच; पण उच्च न्यायालयांच्या पातळीवर अशा घटना परिणामकारकरीत्या रोखल्या जात नसतील तर ते कायद्याच्या राज्यासाठी चिंतेचे कारण होत नाही का?

■ **श्रीकृष्ण साठे,** नाशिक

बॉलीवूडच्या ‘निवडक मौना’ची सवय...

‘**रेहमानचा इशारा...** बॉलीवूडचे मौन’ हा लेख (रविवार विशेष- २५ जानेवारी) वाचला. कुठल्याच धार्मिक सीमारेषा चित्रपटसृष्टीत उमटू नयेत, तिथे सर्व दिशांना मुक्तपणे संचार करू शकणारी निखळ कलात्मक अभिव्यक्ती आणि मनोरंजन यांनाच स्थान असावे अशी मनापासूनची इच्छा असणारा एक मोठा प्रेक्षकवर्ग आहे. रेहमानने व्यक्त केलेली चिंता त्यांनाही जाणवत असेल. परंतु त्या वर्गाला बॉलीवूडच्या ‘निवडक मौना’ची आजवर चांगलीच सवय झालेली आहे. जगातल्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यातल्या नेमक्या कुठल्या गोष्टींवर बॉलीवूड भरभरून बोलते आणि अगदी स्वत:च्या अंगणात घडणाऱ्या कुठल्या गोष्टींवर सूचक मौन बाळगते हे त्या वर्गाने अनेक वर्षे अनुभवले आहे. बॉलीवूडमध्ये ‘आयडेंटिटीज’ कशा तऱ्हेने जोपासल्या जातात हेही त्या जाणकार प्रेक्षकवर्गाला अजिबात नवीन नाही. कोणत्या व्यक्तिरेखा वर्षानुवर्षे कायम साध्या सोज्वळ दाखवल्या जायच्या व कोणत्या कायम खलनायकी थाटाच्याच असायच्या हेही अजिबात लपून राहिलेले नाही. चांगल्यावाईट प्रवृत्तीचे लोक सगळीकडेच असतात याची पूर्ण जाणीव असणाऱ्या त्या प्रेक्षकवर्गाला तेव्हा तेही खटकत होतेच. इतकेच काय, पण बॉलीवूडमधील नक्की कोणाला, कधी व कुठल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर ‘पद्मश्री’ वगैरे पुरस्कार मिळत आलेले आहेत हेही त्यांना चांगलेच समजत होते.

■ **प्रसाद दीक्षित,** ठाणे

वघळ येईपर्यंत वरपूवरपू खायचे...

‘**मरणनगरीतले जिणे**’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. जगण्यासाठी शहरे आहेत का? सुरक्षा, सुविधा सगळ्यांचा बोजवारा उडाला आहे. नेतेमंडळी रोज नवनवीन देशांचे दौरे करतात कारण काय? उद्योगधंदे, कारखाने चालू व्हावे पण एक तरुण चार माणसांचेही पोट भरू शकत नाही ही शोकांतिका! इंजिनीअरलाही वीस हजार रुपये महिना.. मग गरिबांची अवस्था काय असेल! सगळ्यात सुखी राजकारणी आणि सरकारी नोकर..कुणीही मरो, कुणी जगो- यांचा काही संबंध नाही. यांच्यातल्याच वरिष्ठांशी राजकारणी लोकांनी सौदेबाजी करून टक्के ठरवायचे आणि दोन्ही व्यवस्थेने वरपूवरपू खायचे- कोपराला वघळ येईपर्यंत... दुर्दैव अजून काय!

■ **ॲड.मंगल कांगणे दराडे,** कल्याण

अजूनही काळरात्र आहे...

मुळशी धरणविरोधी सत्याग्रह १९२१ पासून सुरू झाला आणि १९२४ मध्ये लयाला गेला; तोवर धरण पूर्ण होत आले, जमिनी गेल्या... हे कशामुळे घडले?

चित्ततोष खांडेकर
नदी विषयक संशोधक अभ्यासक
chittatoshresearch@gmail.com

नदीकारण

विकासाचे शिल्प म्हणून उभे राहिलेले ते मोठे धरण. त्या धरणाने गिळंकृत केलेली गावांची जमीन, त्यातही मागे उरलेले सीतापर्वत बेट. या बेटावर एकच मंदिर आणि राहणारे कोण? तर फक्त मंदिराचा पुजारी आणि त्याचे कुटुंब. पावसात नदीची पातळी वाढली की बेट पाण्यात जाणार हे निश्चित. निसर्ग, जंगलातील प्राणी धरणामुळे पुरात नदीचे वाढते पाणी या साऱ्याशी झुंज देत ते कुटुंब जीवन-मरणाच्या लढाईत कसेबसे वाचते. पण संकटांची मालिका या कुटुंबासमोर उभीच असते- ती मात्र संपत नाही!’ सीतापर्वत नावाच्या कुठल्याशा बेटाची ही काल्पनिक कथा, ‘द्वीपा’ या कन्नड चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेली. पण ही फक्त कथा नसून, पुण्याहून काही कोसांवर असणाऱ्या मुळशी खोऱ्यातील धरणग्रस्तांच्या पिढ्यानपिढ्यांची शोकांतिकाच होय. या शोकांतिकेचा पूर्वार्ध आजच्या लेखात.

मुळशीचे धरण पुणेकरांसाठी सुंदर पिकनिक स्पॉट झाला आहे. खरेतर तो स्पॉट, आंबेमोहोर भाताने सोनपिवळ्या झालेल्या सुजलाम सुफलाम प्रदेशाचे भकास स्मशान आहे. हा सुंदर पिकनिक स्पॉट अनेक गावे, त्यांच्या जमिनी आणि त्या जमिनी पिकवणाऱ्या मावळ्यांचे हुंकार दडपणाऱ्या एका व्यवस्थेचे प्रतीक आहे. देश स्वतंत्र झाला तरीही व्यवस्था आजही मुळशीच्या धरणग्रस्तांवर दडपशाही करते आहे. पण मुळशी खोऱ्याची अशी दुरवस्था का झाली?

शंभरएक वर्षांपूर्वी मुळा आणि निळा या दोन नद्यांचे पाणी कोकणाच्या दिशेने वळवून एक धरण बांधण्याची योजना इंग्रज सरकारने आणली. त्यातून होणारी वीजनिर्मिती अख्ख्या मुंबईला प्रकाशमान करणार होती. या धरणाचा प्रकल्प टाटा कंपनीला देण्यात आला. आता असे काही धरण आहे, याची पुणे काँग्रेसमधील नेत्यांना फार कल्पना आणि महत्त्व नव्हते. त्या धरणाची कुणकुण विनायकराव भुस्कुटे नावाच्या एका पत्रकाराला लागली. टाटा कंपनी वैध मार्गाने मुळशीतील शेतकऱ्यांची जमीन बळकावत असल्याची बातमी १९२० सालच्या ‘केसरी’च्या एका अंकात वाचून हा पत्रकार खाडकन जागा झाला. ‘मुळशी खोऱ्यात नक्की काय चाललंय’ हे पाहायला तडक निघाला. सर्व बाजूने डोंगरदऱ्यांनी नटलेला, शिवरायांच्या पदस्पर्शाचा इतिहास लाभलेला निसर्गरम्य परिसर पूर्ण पाण्याखाली जाणार हे त्याच्या लक्षात आले. मुळा नदीच्या काठी वसलेली असंख्य गावे तिथे भातशेती करत होती. ज्योतीरूपकेश्वराचे संपन्न देवस्थानही या प्रदेशात होते. हे सारेच पाण्याखाली जाणार होते. याशिवाय हा प्रकल्प बांधण्यासाठी ज्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते, तीही इंग्रज सरकार आणि टाटा कंपनीने केली नव्हती. त्या काळात पुनर्वसनाचे कायदे नव्हते. धरणात ज्यांच्या जमिनी जाणार त्यांना केवळ आर्थिक मोबदला देण्याची तरतूद होती. पण मोबदला कुणाला मिळणार? तर जमीनदारांना, सावकारांना आणि बँकेत खाती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना. बहुतांश शेतकरी, खोऱ्यातील ’मावळे’ यातील कोणत्याच गटात बसत नव्हते. हा निधी मिळाला तरी, मुंबई- पुण्यासारख्या शहरी जीवनात तो कितपत कामी येणार? मुख्य म्हणजे पैशाची कितीही मोठी रक्कम कसलेल्या काळ्या आईची आणि भाताच्या पिकाची भरपाई करू शकते का? पण यातला कुठलाच विचार सरकार किंवा टाटा कंपनीच्या खिजगणतीतही नव्हता. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांच्या नुकसानाची दाहकता पुण्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांनाही जाणवत नव्हती.

ती फक्त भुस्कुटेंना समजली. या धरणाची सगळी माहिती घेऊन ते पुण्यात आले. या धरणाविरोधात काँग्रेसने सरकारशी लढावे असा त्यांचा आग्रह होता. काँग्रेसचे राजकीय पाठबळ मिळाले तर हे धरण थांबू शकते, शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचू शकतात हे त्यांना माहीत होते. काँग्रेसच्या राजकारणात तेव्हा महात्मा गांधींचा उदय झाला होता. त्यांची असहकार चळवळ देशभर पसरत होती. गांधींच्या सत्याग्रहाच्या अहिंसक मार्गाने इंग्रजांना जेरीस आणले होते. तेव्हा या धरणाविरोधात सत्याग्रहच करावा अशी जनभावना तयार झाली. पण हा सत्याग्रह काही सहज झाला नाही.

सत्याग्रहाला काँग्रेसचे नेते न. चिं. केळकर यांनीच विरोध केला. धरणविरोधी सत्याग्रह करण्याऐवजी जास्तीतजास्त मोबदला शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी त्यांची धारणा होती. त्यांचा विरोध धरणाच्या प्रश्नाला नव्हता, तर सत्याग्रहाला होता. सत्याग्रह गांधीजींनी काँग्रेसमध्ये रूढ केले. न. चिं. केळकर टिळकांचे अनुयायी आणि त्यांच्यानंतरचे महाराष्ट्र काँग्रेसमधील मोठे नेते. त्यामुळे काँग्रेसमधील टिळक समर्थक नेते, त्यांचे कमी होत चाललेले अस्तित्व, विरोधात गांधी आणि त्यांच्या अनुयायांचा उदय या काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षाची त्यांच्या भूमिकेला किनार होती. त्यापुढे धरणप्रश्नाला काय किंमत? केळकरांनी विरोध केला असला तरी काँग्रेसमधील शंकरराव देव, शिवरामपंत परांजपे आणि इतर नेत्यांनी भुस्कुटेंना पाठिंबा दिला. या सत्याग्रहाबाबत १९२०-२१ मध्ये लोकांशी चर्चा केल्यानंतर १९२१च्या रामनवमीला मुळशीच्या सत्याग्रहाची सुरुवात झाली.

धरणाचे बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी जाऊन अहिंसक मार्गाने ते काम थांबवणे, हा सत्याग्रहींचा रोजचा शिरस्ता होता. त्याला पांडुरंग सदाशिव बापट यांचे करारी नेतृत्व मिळाले. त्यांनी फक्त सत्याग्रहाचे नेतृत्वच केले नाही, तर राज्यभर फिरून रान पेटवले. मुळशीच्या मावळ्यांना मदत करायला राज्यभरातून सत्याग्रही नदीखोऱ्यात आले. परिणामी काँग्रेसच्या वसई सभेत महात्मा गांधींनीदेखील या सत्याग्रहाची दखल घेतली. पण त्यांचे पाय कधीही सक्रियपणे या सत्याग्रहाकडे

वळलेच नाहीत. गांधींशी बापटांचे सत्याग्रहाच्या मार्गाबद्दल मतभेद होते. शिवाय या सत्याग्रहासाठी जनमत पूर्णपणे तयार नाही अशी भूमिका नंतरच्या काळात गांधीजींनी घेतली. आता गांधीजींनी या सत्याग्रहापासून राखलेले अंतर हे बापटांशी असलेल्या मतभेदांमुळे होते, की टाटांशी असलेल्या संबंधामुळे? हे त्यांनाच माहीत. पण गांधीजींची भूमिका सत्याग्रहाच्या मुळावर आली. धरण थांबवण्यासाठी फक्त मुळशीत नाही तर राज्यभरात कलेक्टर कचेऱ्यांसमोर सत्याग्रह करावा अशी बापटांची इच्छा होती. पण काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारणामुळे ही कल्पना हाणून पाडण्यात आली.

या सत्याग्रहाला फक्त काँग्रेसमधूनच अंतर्गत विरोध होता, असे नाही. नुकत्याच आकार घेऊ लागलेल्या ब्राह्मणेतर चळवळीतील पुढाऱ्यांनीही या सत्याग्रहाच्या ब्राह्मण नेतृत्वावर अनेक आसूड ओढले. हा सत्याग्रह धरण थांबवण्यासाठी नसून ब्राह्मण सावकारांना जास्तीतजास्त मोबदला मिळावा म्हणून होत आहे असा त्यांचा रोख होता. पण नेतृत्वाला विरोध करण्याऐवजी ब्राह्मणेतर पुढारीच अठरापगड जातीच्या मावळ्यांसोबत आले असते तर इतिहास काही वेगळाच झाला असता. कारण सत्याग्रहाचे नेतृत्व करणारे पांडुरंग बापट यांना अटक झाली आणि ते सात वर्षे तुरुंगात गेले. सत्याग्रहाचे सेनानायक म्हणून ते ‘सेनापती’ बापट झाले. पण धरणामुळे मुळशी खोऱ्यातील मावळ्यांना लागलेली घरघर आजही संपलेली नाही. शंभर वर्षांनंतरही त्यांची होरपळ सुरूच आहे. या विरोधामुळे सत्याग्रहात जातीय फूट मात्र पडली.

या सत्याग्रहाला तिसरा खोडा घातला तो सावकारांनी आणि मुळशीतील मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांनी. पहिले दीड वर्षं सत्याग्रहाला पाठिंबा देणारे सावकार नंतर मात्र मोबदला घेऊन मोकळे झाले. जातीच्या आधारेच सत्याग्रहात उभी फूट पडल्यामुळे आणि टाटा कंपनीच्या प्रयत्नांमुळे अनेक मावळेही सत्याग्रहापासून दूर होऊ लागले. ज्या धरणाविरोधात संपूर्ण मुळशी तालुका एकत्र आला होता, तो दोन वर्षांहून अधिक काळ एकत्र राहिला नाही. त्यामुळे सत्याग्रहाला मिळणारा पाठिंबा १९२२ नंतर कमी होऊ लागला. शिवाय विनायक भुस्कुटे आणि पांडुरंग बापट या दोघांनाही सरकारने वारंवार अटक करून सत्याग्रहाची धार कमकुवत केली. त्यामुळे १९२१मध्ये सुरू झालेल्या या सत्याग्रहाला १९२४मध्ये पूर्णविराम मिळाला. तोपर्यंत धरणाचे कामही होत आले होते. मावळ्यांच्या जमिनी गेल्याच होत्या. पुढे धरण पूर्ण झाले आणि मुळशीतील गावेच्या गावे पाण्याखाली गेली. अन्नपाण्याविना शेकडो मावळे देशोधडीला लागले.

अपयशाची सोनेरी किनार...

पण हा सत्याग्रह पूर्णपणे अयशस्वी झाला का? तर नाही. मुळशीच्या सत्याग्रहामुळे धरणाच्या कायदेशीर बाबी कंपनीला पूर्ण कराव्या लागल्या. शिवाय धरण झाल्यावर जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या विकासाची आणि काही प्रमाणात पुनर्वसनाची जबाबदारी घेऊ असेही कंपनीला लिहून द्यावे लागले. मुळशीच्या चळवळीत टाटा कंपनीचे सर्वस्व पणाला लागले. त्यामुळे पुन्हा धरणाचे काम हाती घ्यायचे का? हाही विचार टाटा कंपनी करायला लागली. त्याच काळात कोयना धरणाचा प्रकल्पही टाटा कंपनीला देण्यात आला होता. पण मुळशीच्या सत्याग्रहापासून धडा घेऊन कोयना खोऱ्यात टाटा कंपनीला प्रचंड विरोध झाला. त्यामुळे कोयनेचा प्रकल्प टाटा कंपनीकडून काढून घेण्यात आला. तो प्रकल्प इंग्रजांना १९२९मध्ये बंदच करावा लागला. मुळशीचा सत्याग्रह तीन वर्षांत संपला. हा सत्याग्रह फसला तो काँग्रेस, ब्राह्मणेतर पक्ष यांनी मावळ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा वैयक्तिक हितसंबंधांना तसेच सावकार आणि राजकारणाला जास्त महत्त्व दिल्यामुळेच.

सत्याग्रह संपला, पण नदीकारण मात्र संपले नाही. मुळशीचे धरणविरोधी नदीकारण १९२४ पासून आजपर्यंत सुरूच आहे. धरणामुळे देशोधडीला लागलेल्या आणि खोऱ्यात मागे राहिलेल्या मावळ्यांवर काळरात्र आली. तीन पिढ्या उलटल्यावर त्यांची काळरात्र सुरूच आहे. सत्याग्रह फसून धरण झाले, पण धरणामुळे काय झाले? मावळ्यांची होरपळ कशी झाली? याची उत्तरे लेखाच्या उत्तरार्धात शोधू.

कुतूहल

कुकरमध्ये पदार्थ लवकर का शिजतो?

दररोजच्या स्वयंपाकात आपण प्रेशर कुकरचा वापर सहज करतो. डाळ, भात, कडधान्यं काहीही शिजवायचं म्हटलं की, कुकर हवाच! कुकरमध्ये अन्न लवकर का शिजतं? पातेल्यातही अन्न शिजतं, पण कुकरपेक्षा लवकर...? नक्कीच नाही.

अन्न शिजतं म्हणजे काय होतं? अन्न शिजतं म्हणजे अन्नामधल्या रेणूंमधले बंध सैल होतात. अन्नातली प्रथिनं, कर्बोदकं आणि तंतू मऊ होतात. उदाहरणार्थ, उष्णतेमुळे तांदळाच्या दाण्यात पाणी लवकर शोषलं जातं. त्यामुळे दाणा फुगतो आणि मऊ होतो. डाळ शिजताना डाळीतल्या प्रथिनांच्या साखळ्या तुटतात. अन्नातल्या रेणूंच्या साखळ्या तोडण्यासाठी अन्नाला लागणारी ऊर्जा आपण उष्णतेच्या रूपात अन्नाला देतो. साहजिकच पदार्थाला जितकं जास्त तापमान मिळेल, तितक्या लवकर तो पदार्थ शिजेल.

उघड्या पातेल्यात आणि प्रेशर कुकरमध्ये अन्न शिजणं जरी सारखं वाटत असलं तरी दोघांमध्ये वाफेचा दाब, तापमान आणि त्यामुळे अन्नपदार्थावर होणारा उष्णतेचा परिणाम यांत बराच फरक आहे.

हवाबंद कुकरमध्ये आतली वाफ बाहेर जाऊ शकत नाही. उकळत्या पाण्याची वाफ कुकरच्या आतल्या भागात अडकून पडते. कुकरच्या आत झाकणाखाली जसजशी वाफ वाढू लागते, तसतसा अन्नावर वाफेचा दाब वाढतो. या वाफेच्या दाबावर मात करून उकळण्यासाठी, पाण्याला अधिक उष्णता लागते. सर्वसाधारणत: पाणी १०० डिग्री सेंटिग्रेडला उकळतं. पण कुकरमध्ये ते साधारण १२० डिग्री सेंटिग्रेडला उकळतं. या अधिक तापमान असलेल्या पाण्याची वाफ अन्नात पटकन शिरते. या अतितप्त वाफेमुळे अन्नाला जास्त आणि सगळीकडे सारखी उष्णता मिळते; त्यामुळे ते लवकर शिजतं. उष्णता आत अडकल्यानं बाहेरून थेट उष्णता देणं बंद केलं तरीही काही काळ आत अन्न शिजत राहतं!

वाफेचा दाब मर्यादेपेक्षा वाढला तर कुकर फुटूही शकेल इतकी शक्ती या वाफेत असते, म्हणूनच अतिरिक्त वाफ काढून टाकण्यासाठी कुकरमध्ये शिटी, व्हॉल्व्ह आणि गास्केट (कुकरची रिंग) अशा व्यवस्था असतात. कुकरमधला दाब प्रमाणाबाहेर वाढतो तेव्हा शिटी उचलली जाते आणि अतिरिक्त वाफ बाहेर फेकली जाते. उघड्या पातेल्यात अन्न शिजवताना मात्र तयार होणारा वाफेचा दाब, पातेल्याच्या आसपास असलेल्या हवेच्या दाबाच्या तुलनेनं फारसा जास्त नसतो. वाफ कोंडली न गेल्यामुळे दाब वाढतही नाही; त्यामुळे कुकरमध्ये दिसून येतो तसा परिणाम इथं होत नाही. पाणी उकळलं तरी त्याची उष्णता अन्न लवकर शिजण्याइतपत नसते. थोडक्यात सांगायचं तर, पारंपरिक पद्धतीच्या तुलनेत प्रेशर कुकरमध्ये अन्न ७० टक्के वेळात शिजतं! आणि हो... वाफेचा योग्य तो वापर केल्यामुळे इंधनही वाचतं!

– **चारुशीला सतीश जुईकर**
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

‘**पुसा बासमती-१**’ ही तांदळाची जात बहुतेकांना माहीत असते. मधुमेह रुग्णांसाठी उपयुक्त अशी सुधारित सांबा मसुरी हा तांदळाचा वाण उपलब्ध आहे, हेही काही जणांना माहीत असेल... पण या दोन्ही वाणांचे उत्पादन ज्या डॉ. इब्राहीमअली अबूबकर (ई.ए.) सिद्दीक यांच्या संशोधनामुळे साध्य झाले, त्यांचे नाव आणि कर्तृत्व मात्र फार कमी जणांना ठाऊक असते. भारतमातेच्या या सुपुत्राचे निधन २२ जानेवारी रोजी झाले.

कृषी संशोधनासाठी त्यांना पद्मश्री (२०११) आणि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार (१९९५) यांसह अनेक पुरस्कार मिळाले होते. ते मूळचे तमिळनाडूचे. तिरुचिरापल्लीतून वनस्पतिशास्त्राची पदवी घेऊन दिल्लीतील राष्ट्रीय कृषी संशोधन संस्था अर्थात पुसा इन्स्टिट्यूटमध्ये १९६४ साली पुढील शिक्षणासाठी आले. इथेच भारतरत्न कृषिज्ञ एम. एस स्वामिनाथन यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी पेशीजननशास्त्राचा (सायटोजेनेटिक्स) अभ्यास करून पीएच.डी. मिळवली. पुढे हरित क्रांती घडवण्यात त्यांचाही वाटा होताच पण पुसा बासमती हा आखूड रोपाचा वाण तयार होण्याचे श्रेय त्यांना मिळण्यासाठी १९८९ उजाडले. मधल्या काळात फिलिपाइन्सची आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संस्था आणि हैदराबादच्या संस्थेत त्यांनी अनेक तरुण कृषी संशोधक घडवले. ‘पुसा बासमती’च्याच अन्य सुधारित वाणांच्या संशोधनाचे ते मार्गदर्शक ठरले. या कामाचे कौतुक खुद्द स्वामिनाथन यांनीही केले होते- ‘भारताच्या पूर्व किनारपट्टीच्या भागात बासमतीसह अन्य सुधारित वाण रुजवून तेथील तांदूळ उत्पादन वाढवण्याचे श्रेय सिद्दीक यांचे’ असे ते म्हणाले होते.

डॉ. ई.ए. सिद्दीक

पण सिद्दीक यांचे कार्य अर्थातच व्यापक होते. त्यांनी संशोधित केलेले वाण इजिप्तमध्येही लाभदायक ठरल्याने त्या देशाचा सर्वोच्च कृषी पुरस्कार त्यांना मिळाला होता. तांदळाचे रोप उंच असल्यास तग धरण्याची त्याची क्षमता कमी असते आणि विशेषत: बंगालच्या उपसागरालगतच्या राज्यांना वादळवाऱ्यांचा फटका १९७०च्या दशकातही वेळीअवेळी बसत असे. आखूड उंचीचे वाण संकरित करून या संकटावर सिद्दीक यांनी मात केली. दिल्लीच्या कृषी संशोधन संस्थेचे उप महासंचालक म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर ते हैदराबादेत राहू लागले. ‘राइस रीसर्च इंडिया’ या उपक्रमाचे प्रमुख म्हणून २००० ते २००५ पर्यंत ते कार्यरत होते, शिवाय कृषी विषयाचे ‘राष्ट्रीय प्राध्यापक’ ही जबाबदारी त्यानंतरही त्यांच्याकडे होती. सरकारदरबारी समित्यांवर वर्णी लावून घेण्यापेक्षा कृषी संशोधनाच्या क्षेत्रातच डॉ. सिद्दीक नेहमी अधिक रमत.

सिद्दीक यांच्या पत्नी फातिमुथु या लेखिका. या दाम्पत्याने स्वकमाईतून विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती न्यास स्थापतानाच, ‘कोणत्याही जातीच्या, धर्माच्या गरजू व हुषार विद्यार्थ्यांसाठी’ हे ध्येय ठेवले. त्यांचे पुत्र आणि आता फिलिपाइन्सच्या आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्थेत उच्चपदी असलेले डॉ. जौहर अली यांनी त्यापुढले पाऊल उचलून, हैदराबादच्या कृषी विद्यापीठातील उत्कृष्ट संशोधकासाठी दर दोन वर्षांनी ५० हजार रुपये रोख व मानपत्र अशा स्वरूपाचा ‘डॉ. ई. ए. सिद्दीक संशोधन पुरस्कार’ काही वर्षांपूर्वीच सुरू केला.

राजवाडे विचारविश्व

विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांचे धाडस

‘**निबंधमाला**’ **१८७४** च्या जानेवारी महिन्यात सुरू झाली, तर शेवटचा अंक ३० एप्रिल १८८२ रोजी प्रकाशित झाला, तो विष्णुशास्त्र्यांच्या अकाली झालेल्या निधनाच्या बातमीसह झाला. तो ‘माले’चा चौऱ्याऐंशीवा अंक होता. सात वर्षांच्या अवधीत त्यांनी सुमारे २८०० पृष्ठांचा मजकूर लिहून वाचकांसमोर ठेवला. त्यांनी एकहाती, एकटाकी लेखन करून ‘माले’च्या माध्यमातून जी कामगिरी बजावली, तिचे चिकित्सक मूल्यमापन करता येणे शक्य आहे; महाराष्ट्राच्या वैचारिक जडणघडणीचा व्यापक आढावा घेत असताना ते आवश्यकही आहे. तथापि, सध्या आपण राजवाड्यांवरील त्यांच्या प्रभावाच्या मर्यादित संदर्भातच विष्णुशास्त्र्यांच्या लेखनाची माहिती करून घेतली, तरी ते पुरेसे ठरणार आहे.

त्या दृष्टीने फक्त दोनच निबंधांचा थोडासा तपशीलवार परिचय करून घेऊ या. पहिला आहे- ‘इतिहास’ हा पहिल्या वर्षीच सहाव्या, सातव्या आणि आठव्या अशा तीन अंकांमध्ये मिळून प्रसिद्ध झालेला एकूण ४७ पानांचा निबंध.

‘इति ह-आस’ हे तीन शब्द ज्याचे घटकावयव आहेत, त्या इतिहास विषयावर भारतात प्राचीन काळी फारशी ग्रंथनिर्मिती झाली नव्हती, ग्रीक किंवा रोमन लोकांमध्ये जसे सप्रमाण लिहिण्याची प्रवृत्ती विकसित झाली, तशी ती भारतात झाली नव्हती... ही वस्तुस्थिती विष्णुशास्त्र्यांनी आपल्या या निबंधात आपणहून प्रारंभीच मांडली होती. देशाच्या अनुल्लंघ्य राहिलेल्या चतु:सीमा, प्रवृत्तीमार्गापेक्षा निवृत्तीमार्गाकडे जास्त कललेली जनसामान्यांची मानसिकता वगैरे कारणे देऊन थोडासा बचाव त्यांनी केला होता, परंतु पाठोपाठ ‘राजतरंगिणी’ या काश्मीरच्या इतिहासावरील कल्हणाच्या ग्रंथाचा, काशिराज नावाच्या पंडिताने नबाबाच्या सांगण्यावरून फारशी भाषेत लिहिलेल्या पानपतच्या लढाईच्या बखरीचा दाखलाही दिला होता. हिरॉडट्स हा आद्य ग्रीक इतिहासकार, त्यानंतरच्या थुसिडिडीज, सॉक्रेटिसशिष्य जिनोफन वगैरेंबद्दलची रंजक माहिती विष्णुशास्त्र्यांनी दिली होती.

अर्थात असे केवळ माहितीपूर्ण विवेचन करून विष्णुशास्त्री थांबले नाहीत, तर मिल-मेकॉले-मॉरिस वगैरे तत्कालीन इंग्रज इतिहासकारांवर कडाडून टीका करण्याचे वैचारिक धाडसही त्यांनी दाखवले.

‘‘जेम्स मिलने ‘हिंदुस्थानचा इतिहास’ लिहिला; पण कसा, तर इंग्लंडमध्ये बसून; ज्याचा इतिहास लिहावयाचा आहे, तो देश सात-आठ हजार कोस दूर; तेथील लोक काळे का गोरे कधी पाहिलेलेही नाहीत; इथल्या भाषांचे ज्ञान अजिबात नाही. येथील स्थितीबद्दल इतर कुणी लिहून ठेवलेले असेल, तर त्यामधले हिंदूंविरुद्ध जे असेल ते घ्यायचे, प्रशंसेचा मजकूर आढळला तर तो गाळायचा आणि स्वत:चे लेखन म्हणून सर्वत्र मिरवायचे... हा प्रकार मूर्खपणाचा व लज्जास्पद आहे’’- हे विष्णुशास्त्र्यांनी त्या निबंधात विस्ताराने लिहिले होते.

‘मॉरिसने हिंदुस्थानच्या इतिहासाबद्दल लिहिलेल्या पुस्तकात शिवशाहीवर जेमतेम दोनअडीच पाने मजकूर आणि त्यात या विद्वान इतिहासकाराने शंभर चुका केल्या आहेत. शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक दहा वर्षे अगोदर ओढला आहे, अफझुलखानास तीन वर्षे उशिराने मारवला आहे, संभाजीची हत्या वगैरे गोष्टी शिवाजी जिवंत असतानाच घडवल्या आहेत!’ विष्णुशास्त्र्यांनी या शब्दांत त्या मान्यवर इतिहासकाराचे वस्त्रहरण करण्याचे ‘औद्धत्य’ त्या निबंधात दाखवले होते.

आणि मेकॉलेच्या वॉरन हेस्टिंग्जवरील निबंधातले अत्यंत प्रक्षोभक उद्धरण देऊन विष्णुशास्त्र्यांनी आपल्या निबंधात राष्ट्रीय स्वाभिमानाला केलेले आर्त आवाहन म्हणजे तर तत्कालीन ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने ‘राजद्रोह’च होता. मेकॉलेने त्या निबंधात लिहिले होते, ‘शहाण्या व्यापाऱ्यांना या देशातल्या संपत्तीबद्दल भ्रम होता. हिंदुस्थानात हिऱ्यांची जोती, रत्नांचे खांब, सोन्याचे वाडे आहेत, अशा वेड्या कल्पना त्यांच्या मनात घोळत. पण खरोखर हा सगळा भ्रम होता. युरोपात पोर्तुगाल देश किंवा त्याहूनही आयर्लंड देश भिकारी समजतात; पण हिंदुस्थान तर आयर्लंडहूनही भिकारी आहे!’

‘हिंदुस्थान आणि भिकारी?’ या शब्दांत विष्णुशास्त्र्यांनी केलेली मेकॉलेवर टीका पुढील लेखांकात...

– **आनंद हर्डीकर**
anand47.hardikar@gmail.com

प्रजासत्ताकाचा खोकला

‘आयात शुल्कांपेक्षा पर्यावरणाची काळजी करा’ असे भारतास सुनावणाऱ्या जागतिक नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थवेत्त्यांची गणना राष्ट्रविरोधकांत करण्यापेक्षा आत्मचिंतन बरे...

विचारधारेच्या उजवीकडे असणाऱ्यांस स्वतःसमोरील अडचणींचे खापर फोडण्यासाठी कोणी अन्य हवा असतो. डावीकडच्यांस स्वतःच्या बुद्धिसामर्थ्याचा गर्व असतो. तथापि तशा चिकित्सक बुद्धिसामर्थ्याअभावी उजवीकडीलांस असणारा गंड ते आपल्या मर्यादांसाठी अन्यांवर खापर फोडून भरून काढतात. जसे की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. अमेरिकेसमोरील संकटांसाठी ते कधी चीन, कधी मेक्सिको तर कधी स्वदेशातील ‘वोक’ म्हणजे डावे आदींस जबाबदार धरतात. आपल्याकडेही देशासमोरील आव्हानांसाठी कधी पं. जवाहरलाल नेहरू, कधी पाकिस्तान, कधी काँग्रेस वा कधी ‘अर्बन नक्षल’ जबाबदार धरले जातात ते याच मानसिकतेमुळे. आपल्या धोरणांतही काही खोट असू शकते हे अशा सत्ताधीशांच्या गावी नसते आणि अशांच्या मागे धावणाऱ्यांची नैतिकताही तितकी प्रामाणिक नसते. त्यामुळे अशी विचारधारा असणाऱ्यांस सतत ‘बाह्य शत्रू’ शोधावा लागतो. ते मुबलक मिळत राहतात. त्यामुळे बाह्य घटकांस दोष देता देता आतील सुधारणांची गरज नेहमीच अपूर्ण राहते. प्रजासत्ताक दिन हा अशा आत्मचिंतनासाठी रास्त मुहूर्त. कारण देश स्वतंत्र होत असतानाच धर्म/ जात/ पंथ/ वर्ण/ लिंग यावर कोणताही भेदाभेद न करता सर्व नागरिकांस एकसमान मताधिकार देणाऱ्या प्रजासत्ताकाची आखणी करणारा हा एकमेव देश. अन्य देशांत स्त्रिया, कृष्णवर्णीय आदींस समान मताधिकारांसाठी संघर्ष करावा लागला. भारतात तसे झाले नाही. ही पुण्याई पं. नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची. त्यामुळे २६ जानेवारी ही या सर्वांच्या विचारकर्तृत्वाची पुण्यतिथी. ती साजरी करताना सद्यःस्थितीत या ‘आतील आव्हानांची’ दखल घेणे इष्ट.

अर्थवेत्त्या गीता गोपीनाथ या अशा महत्त्वाच्या ‘आतील’ आव्हानांची जाणीव करून देतात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या त्या माजी मुख्य अर्थवेत्त्या. परत भारतीय वंशाच्या. खरे तर कोणतीही कथित भारतीय व्यक्ती परदेशी संस्था/ कंपन्यांत उच्चपदी गेली की आपल्यातील अजागळांस कोण आनंद होतो. गोपीनाथ यास अपवाद. कारण त्या सत्य कथन करतात. त्यामुळे सर्व सत्यकथनींस ज्याप्रमाणे भारत-विरोधी गटांत कोंबले जाते त्याचप्रमाणे गोपीनाथ यांचीही गणना त्यात होते. आताही तसेच झाले. व्यापारी/ उद्योजक/ राजकारणी यांच्या दावोस येथे भरणाऱ्या वार्षिक उरूसात गोपीनाथ यांनी भारतातील पर्यावरण दुर्लक्षावर कमालीचे खरे, आणि म्हणून कटू ठरणारे, भाष्य केले. अमेरिकेकडून लादल्या गेलेल्या/ जाणाऱ्या व्यापार निर्बंधांपेक्षा भारतीय शहरांतील अत्यंत भिकार दर्जाची हवा हे मोठे संकट आहे, असे त्या म्हणाल्या. म्हणजे ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर लादलेले अतिरिक्त आयात शुल्क वगैरे मुद्दे ठीक. पण खरी समस्या आहे ती आपल्या देशातील ढासळते पर्यावरण, असे त्यांचे म्हणणे. ‘‘पर्यावरण रक्षण हा मुद्दा पर्यावरणवाद्यांवर सोडण्यासारखा नाही. ढासळते पर्यावरण हे आव्हान आर्थिक आहे’’, अशा अर्थाचे त्यांचे विधान हे किमान वैचारिक क्षमता शाबूत असणाऱ्यांस नाकारता न येणारे सत्य. ते अधोरेखित करताना गोपीनाथ आकडेवारी सादर करतात. खराब हवेमुळे

...ते केल्यास दोन प्रमुख ‘आतील आव्हाने’ उघड होतात...

नागरिकांचे संकटात येणारे आरोग्य, त्यामुळे त्यांस रोजगारादी कर्तव्यांपासून घ्यावी लागणारी सुटी, त्यातून वाया जाणारे श्रम, आरोग्य रक्षणार्थ होणारा वैद्यकीय खर्च यामुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर गंभीर परिणाम कसा होतो हे त्या सोदाहरण स्पष्ट करतात. जागतिक बँकेच्या पाहणी अहवालानुसार खराब हवेमुळे जगभरातील नागरिकांचा केवळ औषधपाण्यावर वर्षभरात ५ लाख ७० हजार कोटी डॉलर (सुमारे ५२ लाख २५ हजार कोटी रुपये) इतका प्रचंड खर्च होतो. ही रक्कम सकल जागतिक उत्पन्नाच्या ४.८ टक्के इतकी आहे. म्हणजे जगाचे उत्पन्न इतक्या टक्क्यांनी कमी होते. भारतात दरवर्षी १७ लाख लोकांचा मृत्यू केवळ पर्यावरणीय कारणांमुळे होतो. हे प्रमाण देशातील एकूण मृत्यूंच्या १८ टक्के इतके आहे. केवळ खराब हवेमुळे होणाऱ्या आजारांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेस दरवर्षी १५,००० कोटी डॉलर्सचा फटका बसतो. या प्रदूषण-निर्मित व्याधींमुळे एकंदरच समाजाच्या उत्पादकतेवर परिणाम होतो. यामुळे आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा १.७ टक्के इतका मोठा टवका यात निघून जातो. मुदलात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार तो केवढा! त्यात हे प्रदूषणनिर्मित आजार. म्हणजे तोळामासा प्रकृती असलेल्यास ढाळ लागावी, तसे हे.

सबब गोपीनाथ यांनी मांडलेली अभ्यासपूर्ण निरीक्षणे अत्यंत रास्त आणि म्हणून विचारप्रवृत्त करणारी आहेत. हे प्रदूषणाचे संकट ना ट्रम्प यांनी निर्मिले ना त्यास पं. नेहरू, मुसलमान वा अर्बन नक्षल जबाबदार. हे पूर्णपणे सरकार न-नियंत्रित संकट. ते अधिक गहिरे होते कारण पर्यावरणविषयक प्रश्न निर्माण करणाऱ्यांस सर्रास विकास-विरोधी ठरवले जाते म्हणून. वस्तुतः पर्यावरण आणि विकास हे मुद्दे परस्पर विरोधी आहेत ही मांडणीच मुळी अयोग्य. सर्वसाधारण अनुभव असा की विचारधारेच्या उजवीकडे असलेल्यांची धारणा अशी असते. विकसित जगाकडे नजर टाकल्यास ती किती चुकीची आहे हे कळावे. आज जे विकसित गटात आहेत त्यांनी तिसऱ्या जगातील पर्यावरणीय अज्ञानाचा फायदा अनेकदा उठवला, हे सत्य. यात आपलाही समावेश होतो. पण या देशांनी आधीही आणि नंतरही आपापल्या देशांतील पर्यावरण उत्तम राखले. याचा अर्थ आपण जर विकसित देशांतील समावेशाचे स्वप्न पाहत असू तर आपणास पर्यावरण रक्षणास प्राधान्य द्यावे लागेल. या स्तंभात याही आधी अनेकदा उल्लेख केल्यानुसार भारताच्या राजधानीतील हवेचा दर्जा आणि अन्य महत्त्वाच्या जागतिक शहरांतील हवेचा दर्जा यांची तुलनाच होऊ शकत नाही, इतके आपण मागास आहोत. म्हणजे ज्या वेळी दिल्लीतील हवा ४०० निर्देशांकापर्यंत विषारी होत होती त्या वेळी लंडनमधील हवेचा निर्देशांक एक होता. किमान आरोग्यासाठी हा निर्देशांक ५० पेक्षा कमी हवा. तेव्हा गोपीनाथ यांच्या म्हणण्यातील गांभीर्य ओळखण्याऐवजी त्यांना आपण भारतविरोधी गटात ढकलणार असू तर त्यामुळे होणारे नुकसान भारतीयांचे असेल. गोपीनाथ यांचे ते नसेल. त्या तशाही भारतीय रहिवासी नाहीत. तेव्हा त्यांचे प्रतिपादन ‘गाढवापुढे वाचली गीता...’ असे व्यर्थ जाऊ देणे आपल्यासाठी अनर्थकारी आहे हे लक्षात घेणे शहाणपणाचे.

या इतके दुसरे ‘आतील’ आव्हान म्हणजे आपल्या शहरांतील हवेइतकीच सतत ढासळत जात असलेली आपली शैक्षणिक गुणवत्ता. परिस्थिती अशी की आपली हवा अधिक भिकार की शिक्षण; असा प्रश्न पडावा. ‘आयआयटी’, ‘आयआयएम’ आदी नेहरूकालीन संस्थांचा अपवाद केल्यास आपले शिक्षण हे अशिक्षणच अधिक. आधुनिक तंत्रज्ञानात ‘सेवा’ क्षेत्रातील कारकुनांचा पुरवठा अव्याहत सुरू राहील याबाबत आपली शिक्षण व्यवस्था कमालीची जागरूक आहे. गुणवत्तेचा चुकूनही संशय येऊ नये याबाबत शिक्षण व्यवस्था घेत असलेली खबरदारी खरोखरच कौतुकास्पद. त्यातही आपला दुजाभाव असा की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जे काही कर्तृत्ववान निपजतात ते एकतर आयआयटी, आयआयएमचे स्नातक तरी असतात किंवा दक्षिणी राज्यांतील तरी निघतात. गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, अडोब, आयबीएम, शनेल इत्यादींचे आजचे उच्चपदस्थ हे दक्षिणी राज्यांतील आहेत, हे वास्तव. आपले उत्तरदेशीय धर्मक्षेत्री आनंद मानत असताना दक्षिणी देशीयांनी उत्तम शिक्षण व्यवस्थेच्या सुदृढतेवर लक्ष दिले आणि त्याच वेळी आपापल्या मंदिरांचे पावित्र्यही जपले. म्हणून विकासगतीबाबत आपली दक्षिणी राज्ये चीन वा दक्षिण कोरिया यांच्याशी स्पर्धा करतात आणि त्याच वेळी उत्तरदेशीय कशाचा अभिमान बाळगतात हे आपण पाहतोच आहोत.

या असंतुलनासाठीही ना ट्रम्प जबाबदार ना पुरोगामी. आजच्या २६ जानेवारीच्या उत्सवी सोहळ्यात प्रजासत्ताकासमोरील या खऱ्या खोकल्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये इतकेच.

लाल किल्ला

महापालिका निवडणुकांतील ‘प्रॉक्सी वॉर’

महेश सरलष्कर
mahesh.sarlashkar@expressindia.com

दिल्लीमध्ये मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम आणि शिंदे गटाचे नेते राहुल शेवाळे यांच्यात झालेल्या चर्चेला फारसा अर्थ नव्हता. महापौरपद अडीच-अडीच वर्षे हवे असल्याची भाषा शिंदे करत असले तरी मुंबई महापालिकेचा ताबा भाजपकडे आणि ठाणे व कल्याण-डोंबिवलीचा हक्क शिंदेंकडे अशी विभागणी अटळ...

महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांच्या निकालांनंतर रंगलेले राजकीय नाट्य अॅगाथा ख्रिस्तीच्या रहस्यमय कादंबरीतील गुंतागुंतीच्या, लोकांची उत्कंठा वाढवणाऱ्या, स्तरांवर-स्तर चढत जाणाऱ्या कथानकासारखे झालेले आहे. अशा कादंबऱ्यांत प्रत्येकजण दुसऱ्यावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत असतो. नेमके तसेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या होताना दिसत आहे. महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने छोट्या-मोठ्या अनेक लढाया लढल्या जात आहेत. त्या पक्षीय स्तरावर आहेत, पक्षाअंतर्गत आहेत. त्यातील एक लढाई मुंबई महापालिकेत, दुसरी कल्याण-डोंबिवलीमध्ये, तर तिसरी दिल्लीतून लढली जात आहे. यामध्ये पुन्हा भाजपअंतर्गत संघर्ष होत आहे, दुसरा संघर्ष शिंदे गट आणि भाजपमध्ये रंगलेला आहे. तिसरा शिंदे आणि ठाकरे गटांत सुरू आहे. या लढायांमध्ये मनसे वगैरे गट आपापल्या पोळ्या भाजून घेत आहेत. यात भाजपच्या नेतृत्वाला म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आनंद इतकाच आहे की, राज्यातील महापालिकांमध्ये भाजपने यश मिळवलेले आहे. त्यांचा हा आनंद जाहीर भाषणातून व्यक्त झालेला आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कमालीचे अस्वस्थ आहेत कारण त्यांना दिल्लीकरांनी २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘तुम्हालाच मुख्यमंत्री करू’ असे आश्वासन दिले होते हे खरे असेल तर, ते पूर्ण झालेले नाही. शिंदेंना त्याचा जाब दिल्लीकरांना विचारता येत नाही. त्यामुळे त्यांची धुसफुस सुरू आहे. त्याचा राग ते संधी मिळेल तिथे काढतात. त्यांना त्यातून एकप्रकारे दबावही निर्माण करायचा असतो. खरेतर शिंदेंना मुंबई महापालिकेचे महापौरपद हवेच असे नाही. त्यांचे खरे लक्ष्य कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर वगैरे महापालिकांची सत्ता कायम ठेवण्याकडे लागलेले आहे. ठाण्यात त्यांची एकहाती सत्ता आहेच. अंबरनाथ नगरपालिकेत नगराध्यक्ष भाजपचा झाला असला तरी, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार नगरसेवक फोडून उपनगराध्यक्ष आणि विषय समिती ताब्यात ठेवण्यात शिंदे गटाला यश आले. अंबरनाथ आणि या दोन महापालिका कल्याण-डोंबिवली लोकसभा मतदारसंघात येतात. इथून शिंदेंचे पुत्र श्रीकांत निवडून येतात. इथे सत्तेवर पकड मिळाली तरच श्रीकांत शिंदेंचे राजकीय अस्तित्व टिकेल नाहीतर भाजप शिंदे गटावर मात करेल. तसे प्रयत्न झालेही होते. पण दिल्लीकरांच्या दबावामुळे ते अपयशी ठरले. ठाणे जिल्ह्यासाठी शिंदे मुंबई महापालिकेचा वापर करत आहेत. तिथे त्यांना महापौर, स्थायी समिती आणि बेस्ट समितीचे अध्यक्षपद नको असे नव्हे, पण ते मिळाले नाही तरी त्यांचे काही बिघडणार नाही. शिंदेंनी रिझॉर्ट राजकारण करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण दिल्लीकरांनी कल्याण-डोंबिवलीमध्ये तुम्हाला हवे ते करा, आम्ही मध्ये येणार नाही असे आश्वासन दिल्यामुळे शिंदेंचे मुंबईतील नगरसेवक हॉटेलमधून घरी गेले. दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांकडील प्रदेश भाजप नेत्यांच्या बैठकीत शिंदेंना काय करायचे ते करू द्या, तुम्ही बाजूला राहा, असे सांगितले गेल्याचे समजते. पण फडणवीस, चव्हाण काय करतील याचा नेम नाही, त्यामुळे शिंदेंच्या मनातील धाकधूक कायम आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या अवतीभोवती दोन-तीन लढाया लढल्या जात आहेत. मुंबई महापालिकेत निदान बेस्ट समितीचे अध्यक्षपद तरी द्या, अशी शिंदे गटाची मागणी असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिंदे गटाला महापौर व स्थायी समिती द्यायला तयार नाहीत. तसे करायचे तर भाजपला ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीमध्ये महापौर आणि स्थायी समिती द्यावी लागेल. हे शिंदेंना मान्य होणार नाही. दिल्लीमध्ये मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम आणि शिंदे गटाचे नेते राहुल शेवाळे यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेला फारसा अर्थ नव्हता. दुय्यम दर्जाच्या समितीच्या अध्यक्षपदावर चर्चा करून काही मिळत नसते. शिंदे गटाने अडीच-अडीच वर्षे महापौरपद मागितले असले तरी, शिंदे व फडणवीस यांच्या चर्चेमध्ये वा पुढे जाऊन दिल्लीकरांच्या अखेरच्या शब्दानंतर मुंबई महापालिकेचा ताबा भाजपकडे आणि ठाणे व कल्याण-डोंबिवलीचा हक्क शिंदेंकडे अशी विभागणी होईल. कल्याण-डोंबिवलीमध्ये शिंदे गटाच्या नेत्यांची पळवापळव किंवा मुंबईमध्ये ७० जागादेखील द्यायची तयारी न दाखवणे यातून फडणवीसांनी शिंदेंना घेरण्याची रणनीती स्पष्ट झाली होती. शहांनी २० जागा वाढवून दिल्या म्हणून शिंदेंना ९० जागा लढवता आल्या. पैकी ६० हरल्या, त्यातून ठाकरे गटाचा फायदा आणि भाजपचे नुकसान झाले. या शिंदे वि. फडणवीस लढाईत फडणवीस आक्रमक भूमिका घेत आहेत.

मात्र दिल्लीकर शिंदेंकडे उपयुक्ततेच्या नजरेने पाहतात. विधानसभा निवडणुकीतील यशानंतर भाजपला शिंदे गटाची गरज उरलेली नाही. तरीही, शिंदे गट हा ठाकरे गटाचे जितके नुकसान करेल तितके चांगले हा हिशेब लावून शिंदे गटाला दिल्लीतून जिवंत ठेवले जात आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर ठाकरे आणखी कमकुवत झाले; पण ते पुरते संपलेले नाहीत. फडणवीस जसे ठाकरेंचा शिंदेंविरोधात वापर करताना दिसतात, तसे दिल्लीकर शिंदेंचा ठाकरेंविरोधात आणि फडणवीस यांना नियंत्रित करण्यासाठीही वापर करतात. ठाकरेंचा फार विस्तार होईल असे भाजपला वाटत नाही. पण, त्यांना शिंदे गटाचाही फार विस्तार होऊ द्यायचा नाही. विधानसभा निवडणूक आणि त्यानंतर आता महापालिका निवडणुकांमधून भाजपने एकप्रकारे ‘एकला चलो रे’चा नारा दिला आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांमध्ये अजित पवारांचा धुव्वा उडवून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुसक्याच आवळलेल्या आहेत. शिंदे गटाला महापालिकांमध्ये ३००हून अधिक जागा मिळाल्या असल्यामुळे शिंदेंची ताकद टिकून राहिली आहे, ती वाढू न देण्याची दक्षता भाजपला घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे दिल्लीकर शिंदेंबाबत आवश्यक तिथे जुळवून घेताना दिसतात. त्याचाच भाग म्हणून शिंदेंना मोदी-शहांकडे प्रवेश मिळतो, हे दोन्ही नेते ठाकरेंचे नाक कापण्याच्या हेतूने शिंदेंना भेटीसाठी वेळ देतात. त्यामुळे दिल्लीकरांचा आपल्याला आशीर्वाद आहे असे चित्र निर्माण करण्यात शिंदे कमालीचे यशस्वी झालेले आहेत. मोदी-शहांचा वरदहस्त असल्यामुळे आपण राज्यात कधीही मुख्यमंत्री होऊ शकतो, असे शिंदे आपल्या नेत्यांना भासवत आहेत. हे चित्र कायम ठेवण्यात शिंदे जोपर्यंत यशस्वी होतात, तोपर्यंत शिंदेसेनाही कायम राहील. त्यानंतर शिंदे गटाची शकले होण्यास फार वेळ लागणार नाही. हे सर्वस्वी दिल्लीकरांवर अवलंबून आहे.

या सगळ्या राजकीय मारामारीमध्ये एक निर्णायक वळण येणे बाकी आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षाची लढाई प्रलंबित आहे, त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये या प्रकरणावर अंतिम निकाल लावू असे सांगितले असले तरी, खटल्यांच्या सुनावणीला न्यायालयाने वेळ दिलेला नाही. शिवसेना हे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणाच्या मालकीचे याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. या सुनावणीची तारीख चार आठवड्यांमध्ये ठरेल. पण, लगेच सुनावणी होईल असे सांगता येत नाही. ती कितीही लांबणीवर पडू शकते. प्रत्यक्ष राजकारण आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रक्रिया यामध्ये थेट कोणताही संबंध नसतो हे खरे, पण दिल्लीकरांच्या मनात काय आहे याची चाचपणी करता येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी होऊन शिंदे गटाला दिलासा मिळाला तर दिल्लीकरांचे आशीर्वाद नजीकच्या भविष्यात तरी शिंदेंच्या पाठीशी असतील. निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूने लागला तर दिल्लीकरांसाठी शिंदेंची उपयुक्तता संपून जाईल. मग, शिंदेंना मुख्यमंत्रीच काय, स्वतःचा पक्ष एकत्र ठेवणेही कठीण होऊन जाईल. शिवसेना हे पक्षनाव ठाकरेंना पुन्हा बहाल होईल. धनुष्य-बाण हे निवडणूक चिन्ह मिळालेच पाहिजे असा ठाकरेंचा आग्रह नसेल. त्यामुळे शिवसेना या नावावर ठाकरेंचा आनंद मानून घेईल. नव्या जोमाने पक्षाची बांधणी करण्यासाठी ते प्रवृत्त होऊ शकतील. मग, शिंदेंना स्वतःला राजकीयदृष्ट्या वाचवण्यासाठी पक्ष भाजपमध्ये विलीन करावा लागेल. दहाव्या अनुसूचीप्रमाणे हाच मार्ग कायदेशीरपणे योग्य ठरतो. शिंदेंना दिल्लीकरांनी विलीन करून घेतले तर राज्यात वेगळी राजकीय गणिते मांडली जातील. पण हे सारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असेल. तोपर्यंत महायुतीतील दोन्ही पक्षांतील लढाई अटीतटीने लढली जाईल. आत्ता तरी मुंबई महापालिकेत शिंदेंच्या काही हाती लागण्याची शक्यता नाही. त्यांच्यासाठी ठाणे व कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील सत्ता भाजपने सोडलेली आहे. शिंदे गटाला त्यावरच समाधान मानावे लागेल.

विश्लेषण

‘काझीरंगा’तील उन्नत महामार्गाने प्राण्यांना काय फरक पडेल?

मनीषा देवणे
manisha. devne@expressindia. com

पावसाळ्यात काझीरंगातील प्राणी सुरक्षित उंच भागाकडे जातात. ते महामार्गावर येऊ नयेत, अशी काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानातील नव्या उन्नत महामार्गाची रचना असणार आहे...

हा प्रस्तावित प्रकल्प नेमका काय?

काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाच्या मध्यभागातून जाणारा चारपदरी महामार्ग आणि आसाममधील पहिली उन्नत (एलिव्हेटेड) वन्यजीव मार्गिका (कॉरिडॉर) उभारली जात आहे. १८ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. सुमारे ६,९५० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात सध्याच्या दोनपदरी राष्ट्रीय महामार्ग-७१५ चे चारपदरीकरण होणार आहे. यामध्ये काही भाग उड्डाणपूल स्वरूपात असून, गेंडे, हत्ती आणि वाघ यांसारख्या प्राण्यांच्या पारंपरिक स्थलांतर मार्गांचा विचार करून रचना करण्यात आली आहे.

वन्यजीव संवर्धनासाठी तो उपयुक्त कसा?

पावसाळ्यात ब्रह्मपुत्रा नदीला पूर येतो तेव्हा काझीरंगातील प्राणी सुरक्षित उंच भागाकडे, विशेषतः कार्बी आंगलाँग टेकड्यांकडे स्थलांतर करतात. या वेळी त्यांना महामार्ग ओलांडावा लागतो आणि अपघातांची शक्यता वाढते. उन्नत कॉरिडॉरमुळे वाहतूक वरून जाईल आणि प्राण्यांची हालचाल खाली सुरू राहील, त्यामुळे अपघात कमी होतील आणि नैसर्गिक स्थलांतर मार्ग अबाधित राहतील, अशा पद्धतीने या महामार्गाची आणि उन्नत मार्गिकेची रचना करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वन्यजीवांसाठी अनुकूल उपाय’ करण्यास सांगितल्यामुळे हा मार्ग आखण्यात आला.

काझीरंगाकडेच लक्ष का?

भारताच्या आसाम राज्यात काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आणि व्याघ्र संरक्षित अभयारण्य आहे. या उद्यानातील एकशिंगी गेंड्यांची संख्या जगातील एकूण एकशिंगी गेंड्यांच्या संख्येच्या दोन-तृतीयांश आहे. येथे सुमारे अडीच हजारांवर एकशिंगी गेंड्यांचा अधिवास आहे. १९८५ मध्ये या उद्यानाला जागतिक वारसास्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले होते. एकशिंगी गेंड्यांव्यतिरिक्त येथे बंगाल टायगर, हत्ती, गवेदेखील आहेत. हे उद्यान ब्रह्मपुत्रा नदीकिनारी स्थित आहे. येथे उगवणाऱ्या उंच गवत व दलदलीमुळे एकशिंगी गेंड्यांना नैसर्गिक अधिवास मिळतो. २००६ मध्ये काझीरंगा व्याघ्र संरक्षित भाग म्हणून घोषित करण्यात आला.

शिकारीचे गुन्हे किती?

काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हे एकशिंगी गेंड्याचे घर म्हटले जाते. पण या एकशिंगी गेंड्यांची शिकारही मोठ्या प्रमाणावर होते. याविषयी या कॉरिडॉर भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भाष्य केले. ते म्हणाले की एक काळ असा होता जेव्हा गेंड्यांची शिकार ही मोठी चिंतेची बाब होती; २०१३ आणि २०१४ मध्ये डझनभर एकशिंगी गेंडे मारले गेले होते. केंद्र सरकारने वन विभागास आधुनिक संसाधने पुरवली, पाळत ठेवणारी यंत्रणा वाढवली आणि ‘वन दुर्गा’ योजनेद्वारे महिलांचा सहभाग वाढवला. परिणामी २०२५ मध्ये गेंड्यांच्या शिकारीची एकही घटना नोंदवली गेली नाही.

वाहनांसाठी कितपत फायदा?

हा ८६ किमी लांबीचा प्रकल्प कालियाबोर ते नुमालीगड दरम्यान राबवला जात आहे. यामध्ये ३० किमी विद्यमान महामार्गाचे रुंदीकरण, २१ किमी बायपास, ३५ किमी उन्नत वन्यजीव कॉरिडॉर यांचा समावेश आहे. यामुळे गुवाहाटी, नागाव, गोलाघाट, जोरहाट आणि नुमालीगड यांसारख्या शहरांमधील संपर्क सुधारेल. तसेच काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान व काकोचांग धबधबा यांसारख्या पर्यटनस्थळांपर्यंत पोहोचणे सुलभ होईल.

मग पर्यावरणतज्ज्ञांचा आक्षेप काय?

या महामार्गासाठी काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाच्या मुख्य क्षेत्रातील सुमारे २० हेक्टर जंगल आणि पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रातील ३६४ हेक्टर जमीन वापरली जाणार आहे. त्यामुळे उद्यान दोन भागांत विभागले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

काही पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, बांधकाम काळात प्राण्यांवर ताण येऊ शकतो आणि त्यांच्या नैसर्गिक हालचालींवर परिणाम होऊ शकतो. स्थानिक पर्यावरणतज्ज्ञ प्रसांतकुमार सैकिया यांनी युनेस्कोकडेही हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. मात्र, राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने (NBWL) काही अटींसह या प्रकल्पाला आधीच मान्यता दिली आहे आणि योग्य प्राणी मार्ग रचना अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानातून जाणाऱ्या चारपदरी महामार्ग आणि उन्नत वन्यजीव कॉरिडॉर प्रकल्पाकडे केवळ पायाभूत सुविधांचा विस्तार म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. देशातील सर्वात संवेदनशील वन्यजीव अधिवासांपैकी एका ठिकाणी राबवला जाणारा हा प्रकल्प विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यांच्यातील नाजूक समतोलाची परीक्षा ठरणार आहे.

अन्वयार्थ

‘ईडी’ विश्वासार्ह कशी ठरणार?

सक्तवसुली संचालनालय म्हणजे ‘ईडी’चे नाव घेतल्यावर भल्याभल्यांना धडकी भरते. ईडीने तपास सुरू केला हे नुसते कानावर पडले तरी सत्ताधारी पक्षाला शरण जाणारे राजकारणी बघायला मिळाले. एवढा ईडीचा दबदबा. कारण स्पष्टच- ते म्हणजे भ्रष्टाचार किंवा आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासात ईडीला देण्यात आलेले अमर्याद अधिकार. भ्रष्टाचारविरोधी किंवा अवैध पैसे प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) २००२ पासूनचा, त्यातील कलम ५० नुसार ईडीचे अधिकार कोणालाही चौकशीसाठी बोलावणे, देशात कुठेही छापे घालणे व साहित्य जप्त करणे आणि वॉरंटशिवाय कोणालाही ताब्यात घेणे असे अमर्याद आहेत. तसेच या कायद्यान्वये जामीन मिळणे महाकठीण. ईडीने अटक केल्यावर किमान वर्ष- दोन वर्षे तुरुंगात राहावे लागते. याचीच साऱ्यांना भीती. ईडीचा एवढा धाक असला तरी १ जानेवारी २०१५ ते ३० जून २०२५ या दहा वर्षांत ईडीने दाखल केलेल्या एकूण ५,९८२ गुन्ह्यांपैकी न्यायालयाने शिक्षा ठोठावलेल्या गुन्ह्यांची संख्या आहे फक्त आठ आणि शिक्षा सुनावली गेलेल्या व्यक्ती १५. याचाच अर्थ ईडीने दाखल केलेले गुन्हे आणि गेल्या दहा वर्षांत शिक्षा झालेली प्रकरणे याची तुलना केली असता गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण एक टक्काही नाही! ही आकडेवारी सरकारनेच संसदेत प्रश्नोत्तरात सादर केली असली तरी ईडीच्या संचालकांच्या म्हणण्यानुसार अलीकडच्या काळात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण ९४ टक्के आहे. आता केंद्रीय वित्तीय राज्यमंत्र्यांनी संसदेत दिलेली माहिती खरी की ईडीच्या संचालकांची आकडेवारी योग्य हा पुन्हा कळीचा मुद्दा. पण ईडीने कितीही दावे केले तरीही गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण फारच अत्यल्प असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच ईडीची कानउघाडणी केली होती. संसदेतील सरकारची माहिती वा सर्वोच्च न्यायालयाने दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याबद्दल केलेली विचारणा यावरून ईडीची कामगिरी फार काही समाधानकारक दिसत नाही.

ईडीने मोठा गाजावाजा करून अटक केलेल्या छगन भुजबळ यांना विशेष न्यायालयाने दोषमुक्त केले हा या यंत्रणेला बसलेला आणखी मोठा धक्का. नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन ही वास्तू उभारण्यासाठी ठेकेदाराला काम देण्याच्या बदल्यात भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांनी लाच घेतल्याचा ठपका ठेवून ईडीने भुजबळांना अटक केली होती. सुमारे दोन वर्षे भुजबळांचा मुक्काम ऑर्थर रोड कारागृहात होता. भुजबळ म्हणजे ‘भ्रष्टाचाराचे महामेरू’ असाच जणू काही प्रचार भाजपच्या मंडळींनी केला. भुजबळांच्या कर्वे नावाच्या जुन्या सहकाऱ्याला हाताशी धरून भाजपने आकांडतांडव केले होते. तेच भुजबळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मांडीला मांडी लावून मंत्रिमंडळात बसू लागले. तेव्हा भाजप नेत्यांना भुजबळ ‘स्वच्छ’ वाटू लागले. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या ‘आरे’ ला ‘कारे’ करण्यासाठी भाजपने भुजबळांचा पुरेपूर वापर करून घेतला. महाराष्ट्र सदनाचे काम खासगी ठेकेदाराला देण्याचा निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीचा होता, तो आपला वैयक्तिक निर्णय नव्हता, असे भुजबळ तेव्हा ओरडून सांगत होते. पण त्यांची तेव्हा कोणीही दखल घेतली नाही. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना सूचक इशारा देण्यासाठी तेव्हाच्या भाजप-शिवसेना सरकारने भुजबळांना तुरुंगात डांबले. भाजपचा डाव यशस्वी झाला होता. कारण लगेचच नारायण राणे यांनी अटकेच्या भीतीने भाजपमध्ये कोलांटउडी मारली. नंतर तर भाजपमध्ये प्रवेशाची रांगच लागली. आता भुजबळ सुटले. मध्यंतरी ईडीने अनधिकृत बांधकामांसाठी चौरस फुटाला पैसे घेणारे वसई - विरारचे तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त अनिल पवार यांना अटक केली. पण तांत्रिक कारणावर या पवारांना लगेच जामीन मंजूर झाला. कोट्यवधी रुपयांची माया जमा केल्याचा आरोप असलेले आयुक्त लगेच सुटले हेही ईडीचे अपशयच, पण यातूनही राजकारणास यश येते की कसे हे पाहावे लागेल.

गेल्या दहा वर्षांत यच्चयावत् विरोधी पक्षांतील नेत्यांच्या विरोधात ईडीने गुन्हे दाखल केले वा अटक केली. विधानसभेची निवडणूक लवकरच होत असलेल्या तमिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्येच ईडी अलीकडे अधिक सक्रिय झाल्याचे बघायला मिळते. केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधात ईडीचा वापर केला जातो या विरोधकांच्या आरोपांमध्ये तथ्यही आढळते. हसन मुश्रीफ, प्रताप सरनाईक या मंत्र्यांच्या विरोधातील ईडीच्या चौकशीचे पुढे काय झाले? भुजबळ सुटले, आणखी काही सुटतील. कारवाईचा बागुलबुवा उभा करायचा पण शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प. हे सारे ईडीचे अपयशच. सरकारी यंत्रणांवरील जनसामान्यांचा विश्वास डळमळीत होतो तो अशा धरसोड कारभारामुळे.

जोखीम घेतल्याशिवाय परतावा मिळवणे शक्य नाही. गुंतवणूक करताना जोखीम आणि परतावा यांचा संतुलन साधणे महत्वाचे आहे. आपल्या जोखीम सहनशीलतेनुसार गुंतवणूक करा आणि आपल्या पोर्टफोलिओचे विविधीकरण करा.
-रॉबर्ट डी. अर्नोट , अमेरिकी गुंतवणूकदार

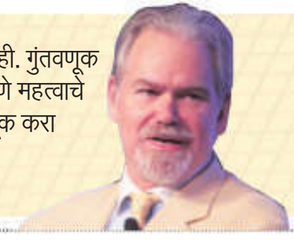

निसटून जाई संधीचा क्षण...

फंडभान

वसंत माधव कुळकर्णी

रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२५ पासून रेपोदरात कपात करण्यास सुरुवात केली. मागील वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात १.५० टक्के कपात केली आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये चलनवाढीचा दर १.३३ टक्के होता, जो भारताच्या दीर्घकालीन सरासरी महागाई दराच्या तुलनेत बराच खाली आहे.

चांगल्या पावसामुळे आलेल्या भरघोस पिकांमुळे अन्नधान्य चलनवाढ उणे २.७१ टक्क्यांवर घसरली आहे. रिझर्व्ह बँकेचा महागाई दराचा उर्वरित आर्थिक वर्ष २०२६ साठीचा अंदाज ४.२४ टक्क्यांचा असून २०२७ मध्ये महागाईच्या दरात थोडीशी घसरण होऊन ४.०९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. वस्तू आणि सेवादरांतील (जीएसटी) कपातीनंतर कमी झालेल्या किंमती सामान्य होऊ लागलेल्या दिसत आहेत. मध्यम-मुदतीत (आर्थिक वर्ष २०२८ पर्यंत) महागाईचा दर ४ टक्क्यांच्या वर जाणार नाही. सध्याच्या या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेचे धोरण वृद्धीला प्राधान्य देणारे आहे. या परिस्थितीत व्याजदरांबाबत रिझर्व्ह बँकेचा दृष्टिकोन स्पष्ट नाही. रिझर्व्ह बँकेचा सध्याचा महागाई दर आणि रेपोदर यांच्यात ३.५० टक्के आणि भविष्यातील महागाईचा अंदाजित दर आणि रेपोदर यांच्यात १ ते ०.७५ टक्के इतका फरक आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक पुढील २४ ते ३० महिने रेपोदर बहुधा स्थिर राखेल, असा अंदाज आहे. जर अर्थव्यवस्थेत समाधानकारक वृद्धी दिसली नाही तर कदाचित व्याजदरात कपात होईल किंवा महागाई वाढली तर व्याजदर वाढवावे लागतील.

'डायनॅमिक बाँड फंड' म्हणजे काय?

'डायनॅमिक बाँड' फंड म्हणजे गुंतवणुकीसाठी कायम खुला असलेला (ओपन-एंडेड) रोखे गुंतवणूक करणारा फंड. हा फंड विविध कालावधींसाठीच्या कंपन्यांनी (कॉर्पोरेट) आणि सरकारने विकलेल्या विविध पत राखणाऱ्या रोख्यांत गुंतवणूक करतात. 'डायनॅमिक बाँड फंडां'चे मुख्य उद्दिष्ट वाढत्या आणि घसरत्या व्याज चक्राच्या दोन्ही परिस्थितींमध्ये इष्टतम 'ड्युरेशन' (उर्वरित कालावधी) राखून परतावा मिळविणे आहे. 'डायनॅमिक बाँड फंडां'मध्ये उर्वरित मुदतीबाबत भांडवली बाजार नियामक 'सेबी'ने निधी व्यवस्थापकांना कोणतीही मर्यादा घातलेली नाही. निधी व्यवस्थापक व्याजदरांतील बदलांनुसार कोणत्याही मुदतीच्या रोख्यांत गुंतवणूक करू शकतात.

'आयटीआय डायनॅमिक बाँड फंड'

'आयटीआय डायनॅमिक बाँड' फंडाची सुरुवात १४ जुलै २०२१ रोजी झाली. सुरुवातीपासून विक्रांत मेहता हे फंडाचे निधी व्यवस्थापक होते. ते जिओ ब्लॅकरॉक म्युच्युअल फंडात दाखल झाल्यावर अल्प कालावधीसाठी फंडाच्या व्यवस्थापनाची सूत्रे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी राजेश भाटिया यांच्याकडे होती. लौकिक बागवे यांची फंड घराण्याने जानेवारी २०२५ मध्ये रोखे गुंतवणुकीचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केल्यापासून फंड व्यवस्थापनाची सूत्रे त्यांच्याकडे आली आहेत. लौकिक बागवे यांना एकूण २५ वर्षांचा रोखे व्यवस्थापनाचा अनुभव आहे. 'आयटीआय म्युच्युअल फंडा'त दखल होण्याआधी ते १७ वर्षे 'डीएसपी म्युच्युअल फंडा'त निधी व्यवस्थापक होते. मागील दहा वर्षांची त्यांची कामगिरी सोबतच्या कोष्टकात दिली आहे.

कॅलेंडर वर्ष	फंड गट सरासरी	निधी व्यवस्थापकाने मिळविलेला परतावा
२०१६	६.५५	९.०४
२०१७	८.११	९.९३
२०१८	०.५६	४.१२
२०१९	७.५७	७.९१
२०२०	८.६७	१२.९३
२०२१	८.०२	८.९३
२०२२	२.६८	५.३६
२०२३	८.८०	१२.३५
२०२४	९.५७	१२.०१
२०१५	७.५७	७.९१

*फंड प्रभाव : इक्वल वेट

विस्तृत बाजारापेक्षा सरस परतावा मिळविण्याचा त्यांचा लौकिक आहे. 'डायनॅमिक बाँड फंड'मध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी निधी व्यवस्थापकाचे कौशल्य लक्षात घेणे गरजेचे असते. 'डायनॅमिक बाँड फंडां'च्या कामगिरीमध्ये निधी व्यवस्थापकाचे कौशल्य खूप महत्त्वाचे असते. बाजाराचा (व्याजदराचा) अंदाज बांधून वेगाने 'डयुरेशन' वाढविणे किंवा कमी करणे यावर फंडाचा परतावा ठरतो. वेगवेगळ्या कालावधीसाठी केलेले मालमत्तेचे वाटप आणि निवड ही निधी व्यवस्थापकाचे व्याजदरातील हालचालींबद्दलच्या अंदाज बांधण्याच्या कौशल्यावर अवलंबून असते आणि जर व्याजदरातील बदलांची त्यांची अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेशी सुसंगत नसेल त्याचा फंडावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. निधी व्यवस्थापकाची व्याजदर आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजाबाबत निधी व्यवस्थापकाची वेगवेगळ्या व्याजदर आवर्तनात कामगिरी तपासणे महत्त्वाचे आहे. लौकिक बागवे यांची वरील दहा वर्षांची कामगिरी त्यांचे व्याजदराबाबत अंदाज बांधण्याचे कौशल्य उत्तम असल्याचे ही आकडेवारी ग्वाही देते.

'आयटीआय डायनॅमिक बाँड फंड' गुंतवणुकीसाठी मुदतीचा अप्रतिबंधित गुंतवणूक दृष्टिकोन वापरतो. 'डायनॅमिक बाँड फंड' गटात सध्या सर्वात कमी 'मॉडिफाइड डयुरेशन' आणि 'ॲव्हरेज मॅच्युरिटी' राखलेला फंड आहे. या पोर्टफोलिओमध्ये अगदी अल्प-मुदतीच्या रोख्यांपासून ते ४०-५० वर्षांच्या दीर्घ-मुदतीच्या रोख्यांचा समावेश आहे. फंडाच्या गुंतवणुकीत सर्वात दीर्घ मुदत असलेला रोख ६.९० जीओआय २०६५ हा २०६५ मध्ये मुदतपूर्ती असलेला रोखा आहे. 'आयटीआय डायनॅमिक बाँड' फंडाचे पत विवरण (क्रेडिट प्रोफाइल) अत्यंत आकर्षक आहे. फंडाची लवचीक कार्यपद्धती तीन प्राथमिक नियमांनुसार चालते, ते म्हणजे व्याजदर घसरत असताना कालावधीचे फायदे मिळवणे, कमी व्याजदराच्या परिस्थितीत व्याजाच्या दारातून उत्पन्नातून व्याजाचे उत्पन्न मिळवणे आणि सरकारी सिक्युरिटीज (जी-सेक), राज्य विकास कर्ज (एसडीएल) आणि उत्तम पत असलेले रोखे धारण करणे.

'आयटीआय डायनॅमिक बाँड' फंडानी मागील साडेचार वर्षांमध्ये परताव्यात सातत्य राखले आहे. फंडाच्या सुरुवातीपासून तीन वर्षांच्या 'रोलिंग रिटर्न्स'वरून असे दिसून येते की, फंडाने ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वेळा ७.१० टक्के सरासरी वार्षिक परतावा मिळविला आहे, मागील या कालावधीत फंडाचा परतावा ५.५ टक्के आणि ७.६७ टक्के दरम्यान राहिला आहे.

गुंतवणुकीच्या वेगाने बदलत्या जगात, अनेक गुंतवणूकदारांना परताव्याच्या मागे धावण्याचा मोह आवरत नाही. एखादी कंपनी किंवा फंड किंवा मालमत्ता प्रकार (जसे सध्या सोने चांदी), चांगला परतावा देत असला की, त्या मालमत्ता प्रकार किंवा फंडात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतात. बाजारात वेळ साधता येत नाही. मालमत्ता विभाजन हा गुंतवणुकीत यश मिळविण्याची पहिली पायरी आहे. ही पायरी चुकविली तर गुंतवणूकदार अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात फिरत राहतात. शिस्त, उद्देश आणि भावनिक द्विधा स्थिती यामुळे हा निर्णय (त्या वेळी अव्वल परतावा देणाऱ्या मालमत्ता वर्गात गुंतवणूक करणे) योग्य ठरेलच याची खात्री देता येत नाही. मालमत्ता विभाजन सतत संतुलित करणे, हा योग्य मार्ग असतो. तिथेच खऱ्या अर्थाने दीर्घकालीन संपत्तीची निर्मिती होते.

या फंडाच्या कामागिरीकडे पाहताना कवी अनिलांच्या ओळी आठवतात.

निसटुनी जाई संधीचा क्षण
सदा असा संकोच नडे...

हा फंडाकडे मोठा 'एयूएम' नाही परिचित नाममुद्रा नाही. मॉर्निंग स्टार रेटिंग 'सिंगल स्टार' असूनही या फंडाची शिफारस केवळ नवीन निधी व्यवास्थापक आणि त्या व्यवस्थापकाच्या 'लौकिका'वर विसंबून केली आहे. म्युच्युअल फंड संशोधनासाठी वापरत असलेल्या प्रणालीने या फंडाचा शोध लागला. या फंडात गुंतवणूक करण्यास संकोच करण्याचे कारण नाही. हा फंड पुढील तीन वर्षांत वार्षिक ७.२५ ते ७.७५ टक्के दरम्यान परतावा देईल, अशी आशा बाळगायला वाव आहे.

shreeyachebaba@gmail.com

'सिबिल' सूत्र

भूषण पडकील

मज्जा सुटीची, चिंता 'सिबिल'ची!

सुटीचे दिवस म्हणजे बहुतांशवेळा आनंद, प्रवास, कुटुंबासोबतचा वेळ आणि थोडीशी उधळपट्टी. या काळात तुम्ही विमान तिकिटे बुक करणे, नवीन 'गॅजेट्स' घेणे, आपल्या प्रियजनांसाठी खरेदी करणे किंवा एखाद्या छोट्या सहलीची योजना आखणे असे अनेक खर्च करता. साहजिकच, या कालावधीत नेहमीपेक्षा खर्च वाढतो. अलीकडच्या काळात या खर्चाचा मोठा भाग 'क्रेडिट कार्ड', 'नो कॉस्ट ईएमआय', 'बाय नाऊ पे लेटर' असे पर्याय किंवा अल्पकालीन वैयक्तिक कर्जे या माध्यमातून खर्च भागवला जातो. या पर्यायांमुळे खर्च करणे अधिक सुलभ आणि लवचीक होते. त्याचवेळी त्यांचा तुमच्या पत गुणवत्तेवर अर्थात 'क्रेडिट प्रोफाइल'वर ठसा उमटतो. याच वेळी तुमचा 'सिबिल स्कोअर' महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

मुळात, तुमचा 'सिबिल स्कोअर' हा तुमच्या 'क्रेडिट' माहितीचा तीन अंकी संख्यात्मक सारांश असतो. तुम्ही कर्ज कसे घेता, किती वेळा कर्ज घेता, 'क्रेडिट कार्ड'चा वापर करता, किती प्रमाणात वापर करता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्ही त्याची परतफेड किती नियमितपणे करता, हे तो दर्शवतो. सुटीच्या काळातल्या जास्त खर्चाच्या कालावधीत, तुम्ही 'क्रेडिट कार्ड' अर्थात खर्च कसे हाताळता यानुसार हा 'स्कोअर' सकारात्मक किंवा नकारात्मक पद्धतीने प्रभावित होऊ शकतो.

सुटीतील खर्चाचा 'क्रेडिट कार्ड'च्या आरोग्यावर परिणाम

सुटीतील खर्च सहसा एका व्यवहारापुरता मर्यादित नसतो. अनेक वेळा 'कार्ड स्वाइप', मोठ्या तिकीट खरेदीसाठी 'ईएमआय' आणि कधी कधी रोख प्रवाह सांभाळण्यासाठी घेतलेले अल्पकालीन कर्ज यामुळे तुमचा 'क्रेडिट कार्ड' वापर लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो. 'क्रेडिट युटिलायझेशन' म्हणजे तुमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या एकूण

'सिबिल स्कोअर' हा तुमच्या आर्थिक वर्तनाचा आरसा असतो. याबद्दल 'ट्रान्सयुनियन सिबिल'चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूषण पडकील यांनी 'लोकसत्ता'ला सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यांची विशेष मुलाखत पाहण्यासाठी क्यूआर कोड स्कॅन करा.

'क्रेडिट'पैकी म्हणजे तुम्हाला दिलेल्या अल्पकालीन कर्जाच्या किती टक्के कर्ज वापरत आहात. जेव्हा हा वापर अचानक वाढतो, म्हणजेच 'क्रेडिट कार्ड'च्या मर्यादेचा मोठा भाग वापरला जातो, जरी 'क्रेडिट कार्ड'च्या माध्यमातून वापरलेले पैसे तुम्ही वेळेत भरणा करत असले तरी वित्तपुरवठादारांना तुम्ही ते 'क्रेडिट कार्ड' जास्त वापरत असल्याने अधिक जोखमीचे संकेत देतात.

सुटीतील काळात धावपळीत देय तारखा चुकण्याची शक्यतादेखील वाढते. प्रवास, गडबडीची दिनचर्या आणि वाढलेली देयके यामध्ये 'क्रेडिट कार्ड' किंवा 'ईएमआय' हप्ता चुकू शकतो. अगदी एकच उशिरा किंवा चुकलेले देयकसुद्धा 'सिबिल स्कोअर'वर लक्षणीय परिणाम करू शकते. याचे कारण परतफेडीचा इतिहास हा त्यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे.

कर्जाची सोय आणि शिस्त यांचा समतोल

'क्रेडिट कार्ड' म्हणजेच अल्पकालीन कर्ज विचारपूर्वक योग्य नियोजनासह वापरल्यास सुटीतील खर्चासाठी 'क्रेडिट कार्ड'चा वापर हा शहाणपणाचा आर्थिक निर्णय ठरू शकतो. यामुळे वाढीव खर्च करता येतो, रोख प्रवाह अधिक चांगल्याप्रकारे व्यवस्थापित करता येतो. अनेक बक्षिसे म्हणजेच 'रिवॉर्ड' किंवा सवलतींचा लाभ मिळतो. मात्र, हा काळ नैसर्गिकरीत्या जास्त आणि कधी कधी अनियोजित खर्चाला प्रोत्साहन देणारा असल्याने शिस्त पाळणे अत्यावश्यक ठरते.

उदाहरणार्थ, 'ईएमआय'मुळे मासिक खर्च कमी वाटू शकतो, पण एकाच वेळी अनेक 'ईएमआय' सुरू असतील तर एकूण रक्कम झपाट्याने वाढू शकते. यामुळे सुटीनंतरच्या महिन्यांत तुमचे महिन्याचे अंदाजपत्रक ताणले जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे, 'क्रेडिट कार्ड'वर केवळ किमान देय रक्कम भरणे तात्काळ दिलासा देऊ शकते, मात्र त्यामुळे व्याजाचा खर्च वाढतो आणि परतफेडीचा कालावधी लांबतो.

क्रेडिट कार्डच्या आरोग्याच्या दृष्टीने, प्रसंगापेक्षा सातत्य अधिक महत्त्वाचे असते. वित्तपुरवठादार सणासुदीचा हेतू पाहत नाहीत, ते वापरण्याची पद्धत अर्थात 'पॅटर्न' पाहतात. नियमित आणि वेळेवर देयक, सुयोग्य प्रमाणात 'क्रेडिट युटिलायझेशन' आणि नियंत्रित कर्ज यामुळे कर्ज फेडीच्या क्षमतेवर विश्वास निर्माण होतो.

सणासुदीपलीकडील परिणाम

सणासुदीच्या दिवसातील सोहळे संपले तरी तेव्हा केलेल्या खर्चाचे परिणाम थांबत नाहीत. या काळातील 'क्रेडिट' वर्तन तुमच्या दीर्घकालीन खर्चाच्या इतिहासाचा भाग बनते. गृहकर्जासाठी अर्ज करणे, चांगले व्याजदर मिळवणे किंवा अधिक कर्जाची मर्यादा मिळवणे अशा भविष्यातील महत्त्वाच्या आर्थिक टप्प्यांसाठी सक्षम 'सिबिल स्कोअर' उपयुक्त ठरतो. याउलट, खर्च जास्त असतानाच्या काळात सतत जास्त खर्च आणि परतफेडीचा ताण असल्यास 'क्रेडिट स्कोअर' हळूहळू कमकुवत होऊ शकतो. कालांतराने, यामुळे सर्वाधिक गरजेच्या वेळी परवडणाऱ्या किमतीत कर्ज मिळणे अवघड होऊ शकते.

सुट्यांमध्ये 'सिबिल स्कोअर' सुरक्षित ठेवण्यासाठीचे सोपे मार्ग

सणासुदीच्या काळात 'क्रेडिट कार्ड' आरोग्य जपणे म्हणजे उत्सवावर मर्यादा घालणे नव्हे, तर आधीच नियोजन करणे होय. खर्चाचा आराखडा ठरवणे, 'क्रेडिट कार्ड' वापरावर लक्ष ठेवणे आणि खरेदी टप्प्याटप्प्याने करणे. यामुळे 'क्रेडिट युटिलायझेशन'मध्ये अचानक वाढ होण्यापासून बचाव करता येतो. 'क्रेडिट कार्ड'ची थकबाकी पूर्ण भरणे आणि 'ईएमआय' वेळेवर भरल्यास 'सिबिल स्कोअर' सुरक्षित राहण्यास मोठी मदत होते.

वेळोवेळी 'क्रेडिट' अहवाल तपासणेदेखील उपयुक्त ठरते. अहवाल तपासल्याने चुका ओळखता येतात, परतफेडीचा मागोवा घेता येतो आणि अलीकडील व्यवहारांचा 'क्रेडिट स्कोअर'वर कसा परिणाम झाला आहे, हे समजते. जागरूकता ही अनेकदा चांगल्या आर्थिक निर्णयांची पहिली पायरी असते.

सध्याच्या खर्च आणि भविष्यातील उद्दिष्टांमधील समतोल राखणे सुटीचा काळ आनंदाचा असावा, नंतर आर्थिक तणाव निर्माण करणारा नव्हे. जेव्हा 'क्रेडिट'कडे अल्पकालीन सोयीऐवजी दीर्घकालीन आर्थिक जबाबदारी म्हणून पाहता, तेव्हा खर्चाचे निर्णय अधिक मोजूनमापून आणि विचारपूर्वक होतात. तुमचा 'सिबिल स्कोअर' हा केवळ एक आकडा नसून तो एवढ्या काळात निर्माण केलेल्या आर्थिक सवयींचे प्रतिबिंब आहे. जास्त खर्चाच्या काळात कर्ज किती जबाबदारीने हाताळता याचाही यामध्ये समावेश असतो.

सणासुदीच्या काळात शिस्तबद्ध, सजग आणि जागरूक आर्थिक वर्तन ठेवल्यास, आजच्या गरजा पूर्ण करताना तडजोड न करता उद्याची आर्थिक लवचीकता कायम राखू शकता. म्हणजेच भविष्यात आर्थिक ताण येत नाही. विचारपूर्वक कर्ज घेणे, वेळेवर परतफेड आणि सुज्ञपणे कर्जाचा वापर यामुळे सणोत्सवाचा मनमुराद आनंद घेऊ शकता आणि भविष्यासाठीही सज्ज राहू शकता.

लेखक 'ट्रान्सयुनियन सिबिल'चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आहेत.

कर-समाधान

प्रवीण देशपांडे

अर्थसंकल्प २०२६ : आशा आणि अपेक्षा

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये (११ जानेवारी, २०२५ पर्यंत) सुमारे २०.६४ लाख कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष कर जमा झाला होता आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात (११ जानेवारी, २०२६ पर्यंत) २१.४९ लाख कोटी रुपये इतका प्रत्यक्ष कर जमा झाला. या वर्षी एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन मागील वर्षाच्या तुलनेने ४.१४ टक्क्यांनी वाढले. निव्वळ प्रत्यक्ष कर (करपरतावा वजा जाता) मागील वर्षी १६.८८ लाख कोटी रुपये होते आणि या वर्षी १८.३७ लाख कोटी रुपये आहे, म्हणजेच मागील वर्षाच्या तुलनेत ८.८२ टक्के अधिक आहे. केंद्र सरकारला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १२.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

तसेच विवरणपत्र दाखल करणाऱ्या करदात्यांची संख्यादेखील वाढत आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ९.१८ कोटी विवरणपत्र दाखल करण्यात आले हीच संख्या २०१३-१४ मध्ये ३.८० कोटी इतकी होती.

प्राप्तिकर कायद्यात वेळोवेळी झालेल्या सुधारणांमध्ये करचोरीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने विविध तरतुदी आणण्यात आल्या. तसेच मोठ्या रकमेची माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे वेळोवेळी विविध माध्यमांतून उपलब्ध होते, ज्या करदात्यांनी असे व्यवहार केले आहेत आणि अशी माहिती विवरणपत्रात दाखविली नाही किंवा विवरणपत्र दाखल केले नाही अशा लोकांना प्राप्तिकर खात्याकडून नोटीस दिली जाते आणि त्यांना विवरणपत्र दाखल करण्याची संधी दिली जाते. त्यामुळे विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता संसदेत सादर होणार आहे. मागील वर्षी नवीन करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या करदात्यांना, वजावटी न घेता, १२ लाख रुपयांपर्यंत नियमित उत्पन्नावर आणि पगारदार करदात्यांना ७५,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट मिळून १२,७५,००० रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही, अशी सवलत दिली गेली. तसेच दीर्घकालीन भांडवली नफ्यासाठी कराचा दर १२.५ टक्के करण्यात आला. त्यामुळे यात अजून सवलती मिळतील अशी आशा वाटत नाही.

या अर्थसंकल्पात ज्या सुधारणा होतील त्या नवीन प्राप्तिकर कायदा, २०२५ मध्ये सुचविल्या जातील. सद्य परिस्थितीनुसार कायद्यात बदल केले जातात. मागील काही महिन्यांपासून काही देशांमध्ये युद्धाचे सावट आहे, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारात केलेली विक्री, डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील नीचांकी घसरण, सोन्या-चांदीचे गगनाला भिडलेले भाव, शेअर बाजारात झालेली पडझड या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा अर्थसंकल्प सादर करणे, हे एक आव्हान आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या दृष्टीने, तरतुदींमध्ये सुसूत्रता, सुलभता आणण्यासाठी काही बदल आवश्यक आहेत. या अर्थसंकल्पात खालील सुधारणा अपेक्षित आहेत.

१ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर : प्राप्तिकर कायद्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढला आहे. करदात्याला विवरणपत्रात भरावी लागणारी ठरावीक माहिती ही 'प्री-फील्ड' अर्थात आधीच त्या प्रणालीमध्ये भरून येते. याची व्याप्ती आता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. जेणेकरून करदात्याला विवरणपत्र दाखल करणे सोपे होईल.

२ विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत- मागील वर्षी विवरणपत्र दाखल करण्याची ३१ जुलै, २०२५ ही मुदत (ज्या करदात्यांना लेखापरीक्षण लागू नाही) वाढवून १६ सप्टेंबर, २०२५ आणि कंपनी आणि ज्या करदात्यांना लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू आहेत त्यांच्यासाठी ३१ ऑक्टोबर, २०२५ ही मुदत वाढवून १० डिसेंबर, २०२५ केली गेली. परंतु सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर, २०२५ हीच होती. त्यामुळे सुधारित विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. फॉर्म १६/१६ए किंवा इतर माहिती मिळण्यास विलंब होतो या कारणांमुळे ३१ जुलै या तारखेपूर्वी विवरणपत्र दाखल करणे अवघड होऊन जाते. ही मुदत १ महिन्यानी वाढविणे गरजेचे आहे.

३ पती आणि पत्नीच्या एकत्रित उत्पन्नावर कर : भारतात पती आणि पत्नीच्या उत्पन्नावर स्वतंत्रपणे कर आकारला जातो. काही वेळेला या तरतुदीचा जाणता-अजाणता दुरुपयोग केला जातो. उदा. ज्याचे उत्पन्न कमी आहे किंवा उत्पन्न नाही त्याच्या नावाने आपले उत्पन्न दाखवून कर वाचवायचा. याला आळा घालण्यासाठी 'क्लबिंग'च्या तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यात आणल्या गेल्या, जेणेकरून पती/पत्नीने मोबदल्याशिवाय उत्पन्न किंवा मालमत्ता आपल्या पती/पत्नीला हस्तांतरित केल्यास त्यावरील उत्पन्नावर, हस्तांतर करणाऱ्याला कर भरावा लागेल. जर्मनी, अमेरिका, फ्रान्स, स्वित्झर्लंडसारख्या देशांत पती आणि पत्नीच्या एकत्रित उत्पन्नावर कर आकारला जातो. भारतातसुद्धा अशा तरतुदी कायद्यात आणण्याची शक्यता आहे. यामुळे उत्पन्नाच्या 'क्लबिंग'च्या तरतुदी राहणार नाहीत आणि सुलभता येईल.

४ वैद्यकीय खर्चाची वजावट : जुन्या करप्रणालीनुसार ज्येष्ठ नागरिकांना वैद्यकीय खर्च आणि 'मेडिक्लेम' हफ्त्याची वाढीव वजावट मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांना नवीन करप्रणालीनुसार कोणताही अतिरिक्त फायदा मिळत नाही. नवीन करप्रणालीमध्ये करदात्याला (करदाता ज्येष्ठ नागरिक असला तरी) वैद्यकीय खर्चाची किंवा 'मेडिक्लेम' हफ्त्याची वजावट मिळत नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे नवीन करप्रणालीनुसार अशा खर्चाची वजावट मिळाल्यास त्यांना मदत होईल.

५ शैक्षणिक आणि वैद्यकीय कारणासाठी भारताबाहेर पैसे पाठविल्यास 'टीसीएस' : सध्याच्या तरतुदीनुसार १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक निधी एका वर्षात शैक्षणिक (कर्ज न घेता) किंवा वैद्यकीय खर्चासाठी पाठविल्यास त्यावर ५ टक्के 'टीसीएस' द्यावा लागतो. हे दोन्ही खर्च आता वाढले आहेत. त्याचा परिणाम थेट रोकड सुलभतेवर होतो. त्यामुळे १० लाख रुपयांची किमान रक्कम वाढविणे अपेक्षित आहे.

६ राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) : नवीन करप्रणालीनुसार नोकरदार करदात्यांना कलम '८० सीसीडी'(२) नुसार मूळ वेतनाच्या १४ टक्क्यांपर्यंत कंपनीने केलेल्या योगदानाची वजावट मिळते. या निवृत्तिवेतन योजनेला चालना देण्यासाठी इतर करदात्यांनी केलेल्या योगदानावर कलम '८० सीसीडी(१बी)' नुसार १ लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळावी.

७ अनिवासी भारतीयांकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी : दिवसेंदिवस अनिवासी भारतीयांची संख्या वाढत आहे. अनिवासी भारतीयांकडून मालमत्ता खरेदी केल्यास करदात्याला उद्गम कर कापावा लागतो, त्यासाठी किमान रकमेची मर्यादा नाही. तसेच ३० टक्के (अधिक शैक्षणिक कर) पर्यंत कर कापला जातो. मालमत्ता खरेदी करणाऱ्याला 'टॅक्स डिडक्शन अकाऊंट नंबर' घ्यावा लागतो आणि त्याचे विवरणपत्रसुद्धा दाखल करावे लागते. ही तरतूद फक्त अनिवासी भारतीयांकडून मालमत्ता खरेदी केली तरच लागू होते. निवासी भारतीयाकडून मालमत्ता खरेदी केल्यास मालमत्ता खरेदी करणाऱ्याला १ टक्का उद्गम करासाठी 'टॅक्स डिडक्शन अकाऊंट नंबर' घेणे गरजेचे नाही, तो उद्गम कर त्याच्या पॅनवर भरू शकतो. अनिवासी भारतीयांसाठीसुद्धा ही सोपी पद्धत लागू व्हावी अशी अपेक्षा आहे.

मागील वर्षात नवीन करप्रणालीअंतर्गत दिलेल्या भरघोस सवलती आणि नवीन प्राप्तिकर कायदा, २०२५ या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्यात, करदात्यांसाठी नवीन काय आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता सर्वांच्या मनात आहे.

लेखक सनदी लेखापाल आहेत.
pravindeshpande1966@gmail.com

अमर उजाला

प्रवाह

77 साल बेमिसाल

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

नई दिल्ली ■ सोमवार, 26 जनवरी 2026

आज के डिजिटल गणतंत्र में, डिजिटल साक्षरता पारंपरिक साक्षरता की तरह ही महत्वपूर्ण है। - निकी वर्ड

नई चुनौतियों के बीच

आज जब भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तब यह अवसर सिर्फ संविधान को स्मरण करने का नहीं, बल्कि उसके जीवंत स्वरूप के मूल्यांकन का भी है। दुनिया भर के गणतंत्रों में जो स्थितियां बन रही हैं, उस संदर्भ में हमारा लोकतंत्र बाकियों की तुलना में अधिक मजबूत नजर आता है। जाहिर है कि हममें कोई तो शक्ति निहित है, जिसकी बदौलत न तो बाहरी दबाव और न ही आंतरिक चुनौतियां इसे विचलित कर पा रही हैं। हमारे गणतंत्र की वास्तविक स्थिति समझनी हो, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे तथाकथित घोषित गणतंत्रों की ओर देखना ही पर्याप्त है, जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं बार-बार सैन्य या राजनीतिक हस्तक्षेप का शिकार होती रही हैं। दूसरी तरफ, वेनेजुएला और यूक्रेन जैसे देश हैं, जहां चुनाव तो होते हैं, लेकिन वैश्विक शक्तियां अपने हितों के अनुसार उन्हें दबाए रखती हैं। इसके उलट, भारत में कुछ बात तो है कि उस पर कोई हाथ तक नहीं डाल पाता। यह 'कुछ बात' हमारी संस्थागत परिपक्वता, सांविधानिक निरंतरता और नागरिकों की लोकतांत्रिक चेतना का सम्मिलित परिणाम है। हालांकि गणतंत्र की मजबूती केवल चुनावों से नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन की सुरक्षा और सम्मान से भी मापी जाती है। ग्रेटर नोएडा में हाल ही में युवा पेशेवर के साथ हुआ हादसा संविधान की भावना पर ही प्रश्नचिह्न लगाता है। इसी पृष्ठभूमि में हाल ही में सरकार ने पुराने श्रम कानूनों की जगह चार नई श्रम संहिताएं लागू करने की घोषणा की है, जिसे स्वतंत्रता के बाद श्रमिकों के लिए सबसे बड़े और प्रगतिशील सुधारों में से एक माना जा रहा है। यह गणतंत्र दिवस हमें संघीय ढांचे की चुनौतियों पर सोचने के लिए भी बाध्य करता है। दक्षिण के राज्यों में राज्यपाल और निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के बीच बढ़ते टकराव ने सांविधानिक मर्यादाओं पर बहस को और तेज कर दिया है। दोनों को ही समझना होगा कि हमारा गणतंत्र तभी मजबूत रहेगा, जब केंद्र और राज्य, दोनों एक-दूसरे के अधिकारों और सीमाओं का सम्मान करेंगे। गणतंत्र की मजबूती का एक और पैमाना हमारी वैश्विक भूमिका भी है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच

होने वाले मुक्त व्यापार समझौते को लेकर यूरोपीय देशों का संघ जिस तरह से उत्साहित है, वह वैश्विक पटल पर भारतीय बाजारों की ताकत को ही दर्शाता है। आज जब दुनिया भर के लोकतंत्रों पर अविश्वास बढ़ रहा है, चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और संस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं, हमारा गणतंत्र एक अपवाद की तरह दिखता है।

डाटा का लोकतंत्र

तकनीक अपने आप में न तो लोकतांत्रिक है और न ही अधिनायकवादी। यह इस बात पर निर्भर है कि इसे कौन नियंत्रित करता है व इसे कैसे विनियमित किया जाता है। लोकतंत्र पर खतरा सिर्फ तकनीक की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए आ सकता है कि लोगों में जागरूकता का विकास उसी रफ्तार से नहीं हुआ है।

लोकतंत्र का विकास हमेशा तकनीकी विकास के साथ हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस ने राजनीतिक जागरूकता का विस्तार किया, रेडियो ने जनमत को आकार दिया और टेलीविजन ने चुनावी अभियानों का स्वरूप बदल दिया। आज कहीं ज्यादा ताकतवर तकनीकी काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), साइबरस्पेस और सोशल मीडिया मिलकर यह तय कर रहे हैं कि लोकतंत्र कैसे काम करते हैं, मुकाबला करते हैं और टूटते हैं। जो व्यवस्था कभी सार्वजनिक बहस और सामूहिक फैसले पर आधारित थी, वह अब तेजी से एल्गोरिदम, डाटा प्रवाह और अनदेखे डिजिटल हस्तक्षेप से प्रभावित हो रही है।

अमित दुबे
लेखक एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ

आधुनिक लोकतंत्र अब डाटा नामक एक नई नींव पर काम करता है। हर सर्च क्वेरी, सोशल मीडिया इंटरैक्शन, लोकेशन पिंग और एप परमिशन से उपयोगकर्ताओं के व्यवहार से जुड़ी जानकारी मिलती है। एआई के साथ मिलकर, यह डाटा लोगों की राय को समझने और प्रभावित करने में अभूतपूर्व सटीकता प्रदान करता है। वैश्विक अनुमानों के अनुसार, आज इस्तेमाल होने वाली 70 प्रतिशत से अधिक राजनीतिक सामग्री को एल्गोरिदम द्वारा क्यूरेट किया जाता है, न कि जानबूझकर चुना जाता है। मतदाता एक ही शहर या घर में होने पर भी एक जैसी जानकारी नहीं देख पाते हैं। इसके बजाय, उन्हें वही दिखाया जाता है, जो एल्गोरिदम को लगता है कि जुड़ाव, भावना या विश्वास को मजबूत करेगा। नतीजतन एक खंडित सार्वजनिक वातावरण तैयार होता है, जहां नागरिक साझा सूचना आधार साझा नहीं करते, जो लोकतांत्रिक विमर्श के लिए जरूरी शर्त है। पारंपरिक राजनीतिक संदेश सार्वजनिक और बहस योग्य होता था। डिजिटल मनुहार निजी, व्यक्तिगत और अक्सर अदृश्य होती है।

एआई सिस्टम व्यक्तित्व की खूबियों, डर, आर्थिक तनाव, पहचान के संकेतों और भावनात्मक प्रतिक्रिया का विश्लेषण करके आदत के अनुसार राजनीतिक आख्यान तैयार करते हैं। ये संदेश सोशल मीडिया फीड, मैसेजिंग

प्लेटफॉर्म और छोटे वीडियो के जरिये चुनिंदा लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। सामूहिक प्रचार के विपरीत, इन संदेशों का पता लगाना मुश्किल होता है, इन्हें सार्वजनिक रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती और ये अक्सर कानूनी एवं नैतिक निगरानी से बच निकलते हैं। असल में, चुनाव अब सिर्फ सार्वजनिक रैलियों या टेलीविजन बहसों में नहीं लड़े जाते, बल्कि व्यक्तिगत डिजिटल पारिस्थितिकी के अंदर लड़े जाते हैं। एआई से निर्मित सामग्रियों ने एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है: भरोसे का खत्म होना। डीपफेक वीडियो, सिंथेटिक ऑडियो और छेड़छाड़ की गई तस्वीरें अब सार्वजनिक हस्तियों को ऐसी बातें कहते या ऐसे काम करते हुए दिखा सकती हैं, जो कभी हुई ही नहीं थीं। हालांकि तत्काल चिंता गलत जानकारी फैलाने को लेकर है, लेकिन इसका दीर्घकालीन खतरा ज्यादा गंभीर है। जब नागरिक यह फर्क नहीं कर पाते कि क्या असली है और क्या मनगढ़ंत, तो लोकतांत्रिक जवाबदेही खत्म हो जाती है।

उतना ही खतरनाक इसका उल्टा मामला है: असली सबूतों को भी नकली बताकर खारिज किया जा सकता है, जिससे हमेशा के लिए अनिश्चितता पैदा हो जाती है। जब सच्चाई पर मोलभाव होने लगता है, तो लोकतंत्र काम नहीं कर सकता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब सबसे प्रभावशाली राजनीतिक बिचौलियों के तौर पर काम करते हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों के बगैर, जो पारंपरिक रूप से मीडिया संस्थानों से जुड़ी होती हैं। उनके एल्गोरिदम सटीकता से ज्यादा भावना, संदर्भ से ज्यादा टकराव और सत्यापन (वेरिफिकेशन) से ज्यादा वायरल होने को प्राथमिकता देते हैं। अध्ययनों से लगातार यह स्पष्ट होता है कि गलत या गुमराह करने वाली जानकारी, सत्यापित तथ्य की तुलना में काफी तेजी से फैलती है, खासकर जब यह डर, गुस्सा या पहचान पर आधारित प्रतिक्रिया पैदा करती है। इसके प्रलोभन की संरचना स्पष्ट है-जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, उतनी कमाई होगी और आक्रोश जुड़ाव को बढ़ाता है। लोकतांत्रिक स्थिरता अक्सर इसका शिकार होती है। बड़े पैमाने पर डाटा लीक अब सिर्फ वित्तीय नुकसान तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। चोरी किए गए पर्सनल डाटा का इस्तेमाल मतदाताओं की प्रोफाइल बनाने, मतदान कम करने, खास समुदायों पर निशाना साधने एवं जानी-मानी हस्तियों को ब्लैकमेल करने के लिए हथियार के तौर पर किया जा सकता है। कई मामलों में, नागरिकों को पता ही नहीं चलता कि उनके डाटा का इस्तेमाल राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किया गया है। यह अदृश्य हेरफेर सहमति को कमजोर करता है, जो लोकतंत्र की नैतिक नींव है। अगर इसे निर्बाध छोड़ दिया जाए, तो एआई, डाटा के गलत इस्तेमाल और सोशल मीडिया हेरफेर से नागरिक एक ही तरह के वैचारिक भंवर में फंस जाएंगे, जहां कोई साझा सच्चाई नहीं होगी। इससे चुनावों की वैधता का संकट उत्पन्न होगा और व्यापक अविश्वास के कारण निष्पक्ष चुनावी नतीजों पर भी सवाल उठाए जाएंगे। इसके अलावा, इससे डिजिटल तानाशाही शुरू होगी, जहां निगरानी, सेंसरशिप और नियंत्रण को सही ठहराने के लिए अराजकता का इस्तेमाल किया जाता है।

विडंबना यह है कि डिजिटल आजादी का गलत इस्तेमाल खुद आजादी के खिलाफ सबसे मजबूत तर्क बन सकता है। इसका समाधान सेंसरशिप या टेक्नोलॉजिकल रोलबैक में नहीं है। यह लोकतांत्रिक अनुकूलन में है। इसके लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं- मजबूत डाटा सुरक्षा और पारदर्शी कानून, एआई निर्मित राजनीतिक सामग्रियों का अनिवार्य खुलासा, एल्गोरिदमिक सिस्टम का स्वतंत्र ऑडिट, बड़े पैमाने पर डिजिटल और मीडिया साक्षरता कार्यक्रम और लोकतांत्रिक बुनियादी ढांचे के रूप में एआई तथा साइबरस्पेस का नैतिक शासन स्थापित करना। सबसे जरूरी बात यह है कि नागरिकों को सिर्फ उपयोगकर्ता या उपभोक्ताओं के तौर पर नहीं, बल्कि डिजिटल क्षेत्र में हितधारकों के तौर पर माना जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी अपने आप में न तो लोकतांत्रिक है और न ही अधिनायकवादी। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन नियंत्रित करता है, इसे कैसे विनियमित किया जाता है, और समाज इसकी ताकत को कितनी अच्छी तरह समझता है। लोकतंत्र सिर्फ एआई या सोशल मीडिया की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए खतरे में है, क्योंकि प्रौद्योगिकी की तरह संस्थान, कानून और लोगों में जागरूकता का विकास उसी रफ्तार से नहीं हुआ है। लोकतंत्र का भविष्य सिर्फ मतदान केंद्रों पर ही तय नहीं होगा, बल्कि डाटा सेंटर, कोड रिपॉजिटरी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी तय होगा। लोकतंत्र इस बदलाव में बचेगा या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि समाज कितनी जल्दी यह पहचानता है कि साइबरस्पेस अब सिर्फ संचार साधन नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। और हर सत्ता क्षेत्र की तरह, इसमें भी जवाबदेही की जरूरत होती है।

edit@amarujala.com

समाज

तभी तो पूरी होगी भारत की कहानी

सिनेमा को सिर्फ समाज का आईना नहीं होना चाहिए। इसे एक हथौड़ा होना चाहिए आकार देने के लिए, सवाल उठाने के लिए, जहां सहानुभूति नहीं है, वहां उसे बनाने के लिए।

हम देखते हैं कि हिंदी सिनेमा से गांव गायब हो रहे हैं? देश का एक बड़ा हिस्सा अब ग्रामीण भारत में रहता है, लेकिन हम उन किरदारों के बारे में बात नहीं करते। अगर वे होते भी हैं, तो ज्यादातर स्टीरियोटाइप होते हैं। तो एक मकसद यह भी था कि वहां की कहानी के बारे में बात की जाए। हमारी भारतीय फिल्मों में कोई भी हाशिये पर पड़े लोगों या अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा है। हमारी कहानियां सिर्फ हमारी 15 फीसदी आबादी तक ही सीमित हैं... शहर खलनायक नहीं है, लेकिन यह हमें खलनायक बना देता है।

जब हम हाशिये पर पड़ी पहचानों की बात करते हैं, चाहे वे नस्लीय अल्पसंख्यक हों, या धार्मिक, या जाति, या यौन अल्पसंख्यक, या फिर प्रवासी, हम हमेशा उनके बारे में आंकड़ों में बात करते हैं।

आंकड़ा जरूरी है, लेकिन यह उन्हें अमानवीय भी बनाता है, क्योंकि जब शहरी भारत के लोग या दुनिया भर के शहरी इलाकों के लोग इनके बारे में बात करते हैं, तो वे खोखली सहानुभूति दिखाते हैं, जिसमें जवाबदेही की कमी होती है। हम सच में यह जानना नहीं चाहते कि उनके साथ क्या होता है। मानवीय पहलू इस फिल्म (होमबाउंड) को बनाने की असली वजहों में से एक था, और पीछे मुड़कर देखने के लिए भी। इसमें मैंने अपने बचपन से बहुत कुछ लिया है। मैं एक बड़े चॉल वाले घर में पला-बढ़ा हूं। मेरे बहुत सारे अनुभव, यहां तक कि 35 वर्षों तक खुद को छिपाने और पूरी तरह से सामने न आने की शर्म, मैंने इस फिल्म में डाली है।

वीरज घेवाण

मुझे भी अपनी शर्म को उस तरह से सामने लाने में डर लग रहा था। उस लिहाज से, यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी काफी राहत देने वाला था। मुझे यह फिल्म बनाने में डर लग रहा था कि इसका विरोध होगा। जब मैंने काम शुरू किया, तो एहसास हुआ कि इस फिल्म को देखने का तरीका यह होगा कि नारेबाजी, राजनीतिक दिखावे और उपदेश से दूर रहा जाए। दोस्ती का जरिया इतना शक्तिशाली है कि जब आप ऐसा करते हैं, तो यह विरोध का एक तरीका होता है। मुझे लगा कि इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि सेंसर बोर्ड दोस्ती को कैसे सेंसर करेगा? मेरी फिल्म व्यवस्था-विरोधी नहीं है; यह इन्सानियत के लिए है। यह लोगों में हमदर्दी जगाने की एक विनम्र अपील भी है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से दुनिया चल रही है, उसमें बहुत नफरत है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम अपने दुश्मनों के सामने बैठें और उन्हें हमदर्दी दिखाएं। सिनेमा को सिर्फ समाज का आईना नहीं होना चाहिए। इसे एक हथौड़ा होना चाहिए—आकार देने के लिए, सवाल उठाने के लिए, और जहां सहानुभूति नहीं है, वहां उसे बनाने के लिए। हमारी खाने की आदतें, धर्म और जाति, या विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन सबसे जरूरी है एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति और इन्सानियत। ऐसा सिर्फ उनके लिए नहीं होना चाहिए, जो हमारे जैसे दिखते हैं या हमारे जैसी बात करते हैं, बल्कि उनके लिए भी होना चाहिए, जो हमसे अलग हैं। हमें इन्सानियत को कम नहीं समझना चाहिए।

यह सही समय है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा फिल्में नहीं आई हैं, खासकर हाशिये पर पड़े लोगों की, जो अपने समुदाय के बारे में बात करती हों।

(विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित)

मैं किसी देश या समुदाय की प्रगति को इस बात से मापता हूं कि महिलाओं ने कितनी प्रगति की है।
-डॉ. बीआर आंबेडकर

सुधार का संकल्प घर से शुरू हो

चिंतन की वास्तविक क्रांति तभी धरातल पर उतर सकती है, जब सुधार का हर संकल्प पहले 'अपने घर से' शुरू हो। लोकतांत्रिक ढांचे में 'व्यक्तिगत इच्छा' सर्वोपरि तो होती है, लेकिन वह 'सामाजिक इच्छा' यानी राज्य की मर्यादाओं से बंधी होती है।

जीवन धारा

लोकतंत्र केवल नियमों या प्रशासनिक बदलावों का नाम नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के हृदय परिवर्तन की मांग करता है। इसकी नींव समाज में रचे-बसे उस 'भाईचारे' पर टिकी है, जो इसे महज एक राजनीतिक व्यवस्था से ऊपर उठाकर एक जीवंत मानवीय स्वरूप प्रदान करती है। वास्तव में, यह वह उत्कृष्ट कला व विज्ञान है, जो समाज के हर वर्ग के शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संसाधनों को 'सर्वजन हिताय (सबकी भलाई)' के महान उद्देश्य के लिए एकजुट कर देता है।

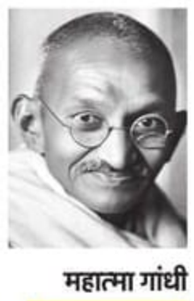

महात्मा गांधी

यही कारण है कि एक अनुशासित और प्रबुद्ध लोकतंत्र को दुनिया की सबसे सुंदर रचना माना जाता है। इसके विपरीत, यदि यही व्यवस्था पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों की जकड़न में फंस जाए, तो यह अराजकता की ओर बढ़ते हुए स्वयं के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर लेती है। इस विनाश से बचने का एकमात्र मार्ग स्वतंत्र चिंतन है, जहां हर पुरुष और महिला को अपने विवेक से सोचना सिखाया जाता है। हालांकि, चिंतन की यह वास्तविक क्रांति तभी धरातल पर उतर सकती है, जब सुधार का हर संकल्प पहले 'अपने घर से' शुरू हो। लोकतांत्रिक ढांचे में 'व्यक्तिगत इच्छा' सर्वोपरि तो होती है, लेकिन वह 'सामाजिक इच्छा' यानी राज्य की मर्यादाओं से बंधी होती है। स्वतंत्रता की असली परीक्षा भी यही है कि एक व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक तब तक है, जब तक उसकी गतिविधियों से किसी दूसरे के जीवन या संपत्ति को कोई आंच न आए। इस मर्यादा को आत्मसात करने वाला व्यक्ति ही 'जन्मजात लोकतंत्रवादी' कहलाता है, क्योंकि वह नियमों और कानूनों का पालन किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी सहज इच्छा से करता है।

लोकतंत्र का सच्चा सिपाही बनने की पहली शर्त 'निःस्वार्थ' होना है, क्योंकि यह पूरी व्यवस्था केवल आपसी 'विश्वास' के नाजुक धागों पर टिकी होती है। भारत के संदर्भ में देखें, तो इस लोकतांत्रिक भावना की सबसे बुनियादी इकाई हमारा 'गांव' है। लेकिन यहां एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि यदि बहुसंख्यक आबादी स्वार्थी और अविश्वसनीय हो जाए, तो 'पंचायत राज' का आदर्श भला कैसे सफल होगा?

जब मैंने अंतरिक्ष से भारत को देखा

अंतरिक्ष स्टेशन से हम जितनी बार भी भारत के ऊपर से गुजरे, हमने देखा शानदार हिमालय। खूबसूरत रंगों की वह लहर देख हम सभी मंत्रमुग्ध थे। मैंने सोचा यही है महान भारत। यही घर है मेरा।

सुनीता विलियम्स
भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री

भारत अद्भुत देश है! अंतरिक्ष से देखने पर यह अद्भुत दिखता है। अमेरिकी अंतरिक्ष स्टेशन से हम जितनी बार भी हिमालय के ऊपर से गुजरे, तो मेरे साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने इसकी शानदार तस्वीरें लीं, जो बेहद अद्भुत हैं! अंतरिक्ष से दिखने वाले भारत के नजारे देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो जाती हूं-पश्चिम में मछली पकड़ने वाले बेड़ों से लेकर उत्तर में शानदार हिमालय तक, यह मेरे लिए घर जैसा ही है। मैंने पहले भी हिमालय को एक लहर की तरह बताया है, जो साफ तौर पर तब बनी, जब प्लेटें टकराईं और फिर, जैसे-जैसे यह भारत में नीचे आती है, इसके कई-कई रंग होते हैं। मुझे लगता है कि जब आप पूरब से गुजरात और मुंबई की तरफ जाते हैं, और (आप) वहां तट के पास मछली पकड़ने वाले जहाजों का बेड़ा देखते हैं, तो यह आपको एक तरह से इशारा देता है कि हम भारत आ गए हैं। मुझे लगता है कि पूरे भारत को लेकर मेरी धारणा यह थी कि यह रोशनी का एक नेटवर्क है, जो बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक फैला हुआ है, और रात एवं दिन में भी देखने में बहुत शानदार लगता है, खासकर हिमालय की वजह से, जो भारत में नीचे की ओर जाते हुए सबसे आगे है।

मुझे खुशी है कि मुझे भारत यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि यह एक महान देश है और एक शानदार लोकतंत्र है। मेरे पिता भारत में पैदा हुए थे, इसलिए अपने 'पिता के देश' की यात्रा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बहुत दिन से इस यात्रा की उम्मीद कर रही थी। भारत अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्षयान भेजने वाले देशों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है और मैं इसका हिस्सा बनना चाहूंगी और भारत की मदद करना चाहूंगी। इस समय मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अंतरिक्ष की होड़ चल रही है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम चांद पर वापस जाना चाहते हैं, ताकि वहां काम करने के नियमों और तरीकों के बारे में बातचीत शुरू कर सकें, कि हम वास्तव में चांद पर कैसे काम करेंगे, खासतौर पर दूसरे देशों के साथ मिलकर । लेकिन यह भी सुनिश्चित करना है कि यह काम अंटार्कटिका की तरह ही उत्पादक और लोकतांत्रिक तरीके से हो। मेरा मतलब है, यह उसी तरह की चीज है।

मुझे लगता है कि जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं, तो सबसे पहली चीजों में से एक जो आप करते हैं, वह यह कि हम सब अपना घर ढूंढना चाहते हैं, जैसे हमारा अपना घर। मैं मैसाचुसेट्स में पली-बढ़ी हूं। मेरे पिता भारत से हैं। मेरी मां स्लोवेनिया से हैं। इसलिए मैं जाहिर है कि उन जगहों को ढूंढ रही हूं, जिन्हें मैं अपना घर कह सकूं। मुझे लगता है कि हर कोई ऐसा करता है, या हो सकता है कि मैं गलत कह रही हूं। और यही आपका पहला मकसद है-इस ग्रह को एक ग्रह के तौर पर देखना। हमारा ग्रह जिंदा है।

कुछ लोगों को लगता है कि वहां सिर्फ चट्टानें हैं। लेकिन यह हिल रहा है। मैं वे खास हलचलें तो नहीं देख पाई, लेकिन मैं वातावरण को देख सकती थी। मैं पारस्परिक क्रिया को देख सकती थी। मैं मौसम देख सकती थी। मैं समुद्र के रंगों में बदलाव देख सकती थी, जैसे कि शैवाल के

खिलने से, या उत्तरी गोलार्ध में या अंटार्कटिका के पास बर्फ बनने को देख सकती थी। आप यह सब देख सकते हैं। हवा और पानी जुड़े हुए हैं। और फिर आप खुद अपने बारे में सोचते हैं। मेरे लिए, यह ऐसा था, ओह, हे भगवान, मैं जितने भी लोगों को जानती हूं, वे सब वहां हैं। हर जानवर, हर पौधा, हम जो कुछ भी जानते हैं, वे सब वहां है। और हम सब इस एक चीज पर हैं, जिसे वे हमारे सौर मंडल में एक छोटा-सा अंतरिक्षयान कहते हैं। यह हमारे बीच किसी भी तरह के मतभेदों के बारे में सोच को बदल देता है। यह सच में आपको ऐसा महसूस कराता है कि हम सब एक हैं, और हम सभी को शायद थोड़ा और करीब तथा मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी धारणा यह है कि लोग अच्छे होते हैं। लोग भले होते हैं। लेकिन हम जिंदगी की उलझनों में कभी-कभी यह भूल जाते हैं। क्योंकि हम इस या उस बात पर, धर्म, राजनीति, वगैरह-वगैरह पर बहस करने लगते हैं। लेकिन हम सब इन्सान हैं और हम एक-दूसरे की परवाह करते हैं। यह अंतरिक्ष में मेरी सीखी हुई सबसे बड़ी सीखों में से एक है।

(विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित)

एजुकेशन & कॅरिअर

जो कठिनाइयों से भागता है, सफलता हमेशा उससे दूर रहती है।

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

यंत्र इंडिया लिमिटेड में आवेदन आमंत्रित

अप्रेंटिसशिप के लिए करें आवेदन

3979 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 03 मार्च, 2026
योग्यताएं : दसवीं व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : recruit-gov.com

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ■ 394 पद

अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य उम्मीदवार करें अप्लाई
आवेदन की अंतिम तिथि
10 फरवरी, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 24 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें
apprenticeshipindia.gov.in

नाबार्ड में आवेदन आमंत्रित ■ 162 पद

डेवलपमेंट असिस्टेंट के पदों पर नौकरी के मौके
आवेदन की अंतिम तिथि
03 फरवरी, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 35 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें
nabard.org

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ■ 804 पद

प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि : 25 फरवरी, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : sso.rajasthan.gov.in

एचपीएससी ने जारी किया विज्ञापन ■ 50 पद

असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती
आवेदन की अंतिम तिथि
12 फरवरी, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 42 वर्ष
यहां आवेदन करें
hpsc.gov.in

केंद्रीय रेशम बोर्ड में रिक्तियां ■ 28 पद

साइंटिस्ट-बी के पदों पर रोजगार के अवसर
आवेदन की अंतिम तिथि
18 फरवरी, 2026
योग्यताएं
बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
csb.gov.in

यहां भी रोजगार के अवसर ...

- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओडिशा : वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पदों पर रिक्तियां।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 31 जनवरी, 2026
- hal-india.co.in
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली : उप महानिदेशक का पद खाली।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 31 जनवरी, 2026
- beeindia.gov.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

आपके मन में कौन-सी भावनाएं प्रबल हैं

सोशल मीडिया के दौर में आप अपनी भाषा-बोली को लेकर झिझक तो महसूस नहीं करते?

डॉ. निशांत जैन
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के सदस्य

फ्रांसीसी विचारक बर्क ने कभी लिखा था- "मुझे बता दीजिए कि युवाओं के मन में कौन-सी भावनाएं सर्वाधिक प्रबल हैं, मैं बता दूंगा कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसा होगा।" बुढ़ाती दुनिया में भारतीय गणतंत्र की तरुणाई को पूरी दुनिया हसरत भरी निगाहों से देख रही है। इंडस्ट्री, बाजार, मीडिया और अकादमिक जगत, ये सभी भारत के युवा मन की थाह लेने की पुरजोर कोशिश में हैं। हर ओर बस भारतीय युवाओं की चर्चा है और उनकी सोच को डिकोड करने का जतन जारी है।

■ **डिजिटल डिटॉक्स की ओर**

सर्वे बताते हैं कि भारतीय युवा खासकर जेन-जी अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बेहद सजग है। यह युवा अपनी सेहत के लिए गैर-हानिकारक विकल्प अपना रहा है। सोशल मीडिया के दीवानेपन के दौर में भी खुद की निजता बनाए रखने की समझ ही है कि आज का युवा स्क्रीन टाइम और स्क्रॉलिंग के व्यूह को तोड़कर 'डिजिटल डिटॉक्स' जैसी अवधारणाओं की ओर बढ़ रहा है। योग और आयुर्वेद के प्रति आकर्षण असाधारण तरीके से बढ़ा है। वीकेंड पर 'भजन क्लबिंग', ऑफिस ब्रेक में मेडिटेशन, तीर्थों की सोलो ट्रिप ब्लॉगिंग और अपने गांव, कस्बे, शहर की लोक कला की समझ जैसी प्रवृत्तियां, भारतीय युवाओं की सांस्कृतिक सजगता और परिपक्वता की एक नई कहानी गढ़ रही हैं।

■ **अपनी भाषा का आत्मविश्वास**

इस परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण संकेत युवाओं की भाषा-संबंधी चेतना में भी दिखाई देता है। मातृभाषा में सोचने और अभिव्यक्त करने की आजादी को वह किसी झिझक के साथ नहीं, बल्कि वैचारिक स्वाभिमान व आत्मविश्वास के साथ अपनाता है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कंटेंट, स्टार्टअप, पॉडकास्ट और रचनात्मक प्रयोग इस बदलाव के स्पष्ट संकेत हैं। भाषा के प्रति सजगता और सरोकार का आलम यह है कि अपनी भाषा और बोली को लेकर जो झिझक कभी मिलेनियल्स ने महसूस की होगी, वह जेन-जी के लिए एक समझ से बाहर की बात है।

■ **संस्कृति का सवाल**

संस्कृति के प्रश्न पर भी आज का युवा एक संतुलित दृष्टि के साथ खड़ा है। वह संस्कृति को बोझिल परंपरा नहीं, बल्कि निरंतरता के रूप में देखता है, उस पर गर्व करता है और भाषायी-सांस्कृतिक चेतना को जमीनी स्तर पर जीवंत बनाए रखता है। लोक संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति बढ़ती रुचि इस बात का प्रमाण है कि परंपरा और आधुनिकता के बीच टकराव नहीं, बल्कि संवाद संभव भी है और साध्य भी। वेद के मंत्र- 'आ नो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः' और 'संगच्छध्वं संवदध्वं' भारतीय युवा चेतना के प्रेरक सूत्र बने रहेंगे, ऐसा विश्वास है।

खुद को परखें

1. भारत में, एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ) राष्ट्रीय पुरस्कार का संचालन किस संगठन द्वारा किया जाता है?
   (a) नीति आयोग
   (b) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
   (c) भारतीय रिजर्व बैंक
   (d) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
2. भारत में किस राज्य में खारे पानी के मगरमच्छों की प्राकृतिक आवास में सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है?
   (a) गुजरात (b) महाराष्ट्र
   (c) केरल (d) ओडिशा
3. आईएनएस सुदर्शनी का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया था?
   (a) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
   (b) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
   (c) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
   (d) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

उत्तर-1.b, 2.d, 3.c

आईएएसएच पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप 2026-27

फेलोशिप प्रोग्राम

एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन ह्यूमैनिटीज (आईएएस ह्यूमैनिटीज) द्वारा आईएएसएच पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह उन छात्रों के लिए है, जिन्होंने हाल ही में (2023-2026 के बीच) पीएचडी पूरी की हो। यह फेलोशिप पोस्ट-डॉक्टोरल शोधकर्ताओं को अपनी विशेषज्ञता और कौशल बढ़ाने का मौका देती है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार पहले किसी विश्वविद्यालय में स्थायी पद पर नहीं होने चाहिए और आईएएस ह्यूमैनिटीज में फेलोशिप नहीं पाए हों। केवल कला, मानविकी या सामाजिक विज्ञान में शोध विषय वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवार को 20,000 पाउंड तक छात्रवृत्ति और अन्य लाभ मिलेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल, 2026 निर्धारित की गई है। योग्य आवेदक आधिकारिक लिंक tinyurl.com/57a58cnk पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

हमदान इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवॉर्ड-2026

आवेदन आमंत्रित

हमदान इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवॉर्ड (एचआईपीए)-2026 के लिए दुनिया भर के 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

■ **प्रतियोगिता की श्रेणियां**

इस प्रतियोगिता को परिवार, एआई के माध्यम से सपने, खेल फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो (कहानी सुनाना) और जनरल (ब्लैक एंड व्हाइट तथा रंगीन) श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

■ **पुरस्कार**

इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को 20,000 डॉलर से लेकर 2,00,000 डॉलर तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसमें ग्रैंड प्राइज, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, कंटेंट क्रिएटर और फोटोग्राफी एप्रिसिएशन अवॉर्ड भी शामिल हैं।

■ **यहां आवेदन करें**

इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक प्रतिभागी अपनी योग्यताओं की जांच करते हुए आधिकारिक लिंक hipa.ae/award/family-hipa-award-2026 पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

एग्जाम अलर्ट | हफ्ते की परीक्षाएं

एनटीए जेईई मेन परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :**
  28-29 जनवरी, 2026
- परीक्षा तीन पेपर के लिए होगी। पेपर-I में गणित, भौतिकी व रसायन से 75 अंकों के प्रश्न, पेपर-2 ए में गणित, एप्टीट्यूड व ड्राइंग से 77 अंकों के प्रश्न व पेपर-2 बी में गणित, एप्टीट्यूड व प्लानिंग से 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक पेपर के लिए 3-3 घंटे का समय निर्धारित है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें**
  tinyurl.com/5x3defp3

बीपीएससी स्पेशल स्कूल टीचर परीक्षा (कक्षा 6-8)

- **परीक्षा की तिथि :**
  29 जनवरी, 2026
- इस परीक्षा के भाग-I में भाषा (अंग्रेजी एवं हिंदी/उर्दू/बांग्ला) से व भाग-II में सामान्य जागरूकता आदि से व भाग-III में चयनित विषय से 150 अंकों के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि ढाई घंटे है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें**
  bpsconline.bihar.gov.in

सामान्य ज्ञान

एएससी अर्जुन

- **क्या है**
  यह इन्सानों जैसे हाव-भाव और क्षमता रखने वाला एक रोबोट है, जिसे स्टेशन पर विभिन्न कामों में इस्तेमाल किया जाएगा।
- **चर्चा में क्यों**
  हाल ही में, भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर 'एएससी अर्जुन' नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया है।
- **विशेषताएं**
  यह रोबोट भीड़ के समय आरपीएफ के साथ मिलकर स्टेशन पर काम करेगा। स्वदेशी तकनीक से बना यह रोबोट फेस रिकग्निशन, रियल-टाइम अलर्ट, बहुभाषी घोषणाएं और सेमी-ऑटोनॉमस नेविगेशन जैसी सुविधाओं से लैस है।
- **24 घंटे करता कार्य**
  यह रोबोट रेलवे प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे गश्त और निगरानी कर सकता है, जिससे मैनपावर का बेहतर उपयोग हो सके। इसमें आग और धुएं का पता लगाने की सुविधा है और यह यात्रियों से संवाद कर जानकारी व मदद भी देता है।

रोशनी यहां है

इस बार : रामचंद्र अग्रवाल
क्यों : छोटी दुकान से शुरुआत कर बनाया हजारों करोड़ का कारोबार

एक समय छोटी-सी दुकान से कारोबार शुरू करने वाले रामचंद्र अग्रवाल ने पहले विशाल मेगा मार्ट की नींव रखी और बाद में परिस्थितियों के कारण इसे बेच दिया। इसके बाद उन्होंने वी2 रिटेल की शुरुआत की, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक खड़ा किया। आज वी2 रिटेल का बाजार पूंजीकरण लगभग 6,530 करोड़ रुपये है।

बैसाखियों पर काटी जिंदगी, जेब में उधार के पैसे, बनाया हजारों करोड़ का साम्राज्य

भारतीय रिटेल जगत में कुछ नाम ऐसे हैं, जो केवल ब्रांड नहीं, बल्कि संघर्ष और संकल्प की पहचान बन जाते हैं। विशाल मेगा मार्ट भी ऐसा ही एक नाम है, जिसने मध्यमवर्गीय परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों को किफायती दामों पर पूरा कर अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन इस चमकते ब्रांड के पीछे एक कहानी छिपी है। इस कहानी के नायक हैं रामचंद्र अग्रवाल। एक ऐसे उद्यमी, जिन्होंने न तो किसी बड़ी डिग्री का सहारा लिया और न ही किसी मजबूत आर्थिक या सामाजिक समर्थन का। महज चार साल की उम्र में पोलियो से प्रभावित होने के बावजूद रामचंद्र अग्रवाल ने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। बैसाखियों के सहारे चलते हुए उन्होंने एक छोटी गारमेंट शॉप से शुरुआत की और विशाल मेगा मार्ट जैसा बड़ा ब्रांड खड़ा किया। कुछ गलत फैसलों के कारण यह कारोबार बेचना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने अनुभव और हौसले से उन्होंने वी2 रिटेल की नई शुरुआत की, जो आज देशभर में 150 से अधिक स्टोर के साथ तेजी से बढ़ता रिटेल ब्रांड है। उनकी कहानी साबित करती है कि असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत होती है।

बचपन में पोलियो ने रोकी चाल

रामचंद्र अग्रवाल का जन्म 1965 में कोलकाता के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। 650 वर्ग फीट के घर में उनके परिवार के 20 लोग रहते थे और घर की आर्थिक हालत कमजोर थी। कई बार घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता था। चार साल की उम्र के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे वे जीवन भर के लिए विकलांग हो गए और उन्हें चलने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। इसके बावजूद उनके भीतर कुछ अलग करने की चाह हमेशा बनी रही। 17 साल की उम्र से उन्होंने डायरी लिखनी शुरू की, जिसमें वे अपनी जिंदगी और समाज को बेहतर बनाने के सपने और योजनाएं लिखते थे। उन्हें समझ आ गया था कि इन सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपने खर्च निकालने लगे। कॉमर्स में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और साथ ही एक पार्ट-टाइम नौकरी भी की, जहां 300 रुपये महीने की सैलरी मिलती थी। जल्द ही उन्होंने नौकरी छोड़कर उधार लेकर फोटोकॉपी और सॉफ्ट ड्रिंक की दुकानें शुरू कीं। भले ही ये सफल न रहीं, लेकिन यहीं से उनके उद्यमी सफर की शुरुआत हुई।

बाजार में बनाई मजबूत साख

उन्होंने कोलकाता में छोटी रेडीमेड कपड़ों की दुकान विशाल गारमेंट्स से शुरुआत की और इसे 15 वर्षों तक सफलतापूर्वक चलाया। कुछ सालों में इसका नाम कोलकाता में लोकप्रिय होने लगा। उन्होंने स्थानीय व्यवसायों और दुकानों को कपड़े बेचकर बाजार में अपनी मजबूत साख बनाई। इसके बाद फैब्रिक के व्यवसाय में भी उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। रामचंद्र अग्रवाल ने महसूस कर लिया था कि आने वाले समय में मल्टीस्टोर्स का दौर आएगा, जहां राशन से लेकर कपड़े और सब्जी-भाजी, सब कुछ एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने वर्ष 2001-02 में दिल्ली में विशाल मेगा मार्ट की शुरुआत की। उन्होंने खास ध्यान रखा कि कीमतें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए किफायती हों।

जब बेचनी पड़ी कंपनी

2007-08 तक विशाल मेगा मार्ट के 18 राज्यों में 50 से ज्यादा स्टोर खुल चुके थे। उन्होंने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू की, यानी कपड़े अपनी फैक्टरी में बनाकर अपने ही स्टोर्स में बेचे, जिससे मुनाफा बढ़ने लगा। लेकिन तेजी से बढ़ाने की यह कोशिश उनके लिए भारी पड़ गई। एक के बाद एक स्टोर और फैक्टरियां खुलती गईं, जिसके लिए बाजार से बहुत ज्यादा कर्ज लेना पड़ा। इसी बीच वैश्विक मंदी आई और विशाल मेगा मार्ट भारी घाटे में चला गया। कंपनी को करीब 750 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। हालात इतने खराब हो गए कि रामचंद्र अग्रवाल को दिवालियापन के लिए आवेदन करना पड़ा। मजबूरी में उन्हें 'विशाल' ब्रांड, जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपये मानी जाती थी, सिर्फ 70 करोड़ रुपये में श्रीराम ग्रुप और टीपीजी कैपिटल को बेचना पड़ा।

वी2 रिटेल के साथ वापसी

जब विशाल का कारोबार खत्म माना जा रहा था, तब रामचंद्र अग्रवाल ने बची पूंजी और 10 करोड़ रुपये के कर्ज से वी2 रिटेल लिमिटेड की शुरुआत की। पिछली गलतियों से सीख लेकर उन्होंने कारोबार को अनुशासित और आम ग्राहकों पर केंद्रित बनाया। आज वी2 रिटेल भारत के सबसे तेजी से बढ़ते रिटेल ब्रांड्स में से एक है। वी2 रिटेल अब एक सूचीबद्ध कंपनी है और 2025 तक इसका बाजार पूंजीकरण लगभग 6,530 करोड़ रुपये है। विशाल मेगा मार्ट को बेचने की मजबूरी के बावजूद, रामचंद्र अग्रवाल ने एक और सफल रिटेल चेन खड़ी करके अपनी व्यावसायिक समझ साबित की।

युवाओं को सीख

- शरीर की कमजोरी सपनों को नहीं रोक सकती, अगर इरादे मजबूत हों।
- असफलता अंत नहीं होती, बल्कि दोबारा खड़े होने का सबसे मजबूत आधार बनती है।
- छोटी शुरुआत भी बड़े इतिहास रच सकती है, जब मेहनत और धैर्य साथ हों।
- जो गिरने के बाद उठने का साहस रखता है, वही सच्चा विजेता होता है।

26 जनवरी, 1950 आज का दिन

भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके बाद देश एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य बन गया था। संविधान को तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था।

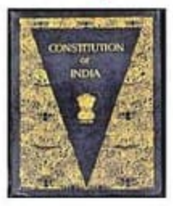

- **1837 :** मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका का 26वां राज्य बना था।
- **1942 :** द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में पहला अमेरिकी अभियान बल आयरलैंड पहुंचा था।
- **1958 :** अमेरिकी हास्य कलाकार एलेन डीजेनेरेस का जन्म हुआ था।
- **2020 :** अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी।
कल : शिशिर ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, दक्षिण गोले।
राहुकाल : दिन में 15.00 से 16.30 तक

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2082, 07 माघ मास शक 1947, माघ मास 14 प्रविष्टे, 07 सावान हिजरी 1447, माघ शुक्ल पक्ष नवमी 19.05 तक उपरांत दशमी, भरणी नक्षत्र 11.08 तक उपरांत कृतिका नक्षत्र, शुक्ल योग 27.12 तक उपरांत ब्रह्म योग, बालव करण 08.11 तक उपरांत कौलव करण, चंद्रमा वृष राशि में 16.42 बजे।

■ सूर्योदय : 07.16
■ सूर्यास्त : 17.52
(भारतीय मानक समयानुसार)

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : आत्मबल बना रहेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विकास की नई योजना बन सकती है।

वृष : पारिवारिक मामलों में सहनशीलता बनाए रखें। अचानक व्यय से परेशानी होगी। ऋण लेने से बचें।

मिथुन : दिनमान अनुकूल रहेगा। नई योजना बन सकती है। अटका कार्य बनेगा। अचानक यात्रा संभव है।

कर्क : मानसिक तनाव से बचें। सहोदरों से निराशा होगी। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। घर में शांति रखें।

सिंह : नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। संतान से सुख मिलेगा। नई व्यावसायिक साझेदारी हो सकती है।

कन्या : कार्यक्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। राजकाज में अनुकूलता रहेगी। मेहनत के चलते सेहत का ध्यान रखें।

तुला : सकारात्मक सोच बनाए रखें। नूतन संपर्क उन्नति में सहायक रहेंगे। आर्थिक स्थिति यथावत रहेगी।

वृश्चिक : आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रहेगी। विरोधी पक्ष से पूर्ण सावधानी बरतें। परिवार में आनंद बना रहेगा।

धनु : पठन-पाठन में मन लगेगा। शुभचिंतकों से मेल मुलाकात हो सकती है। संतान पक्ष से कुछ चिंता रहेगी।

मकर : धैर्य बनाए रखें। संतान पक्ष से शुभ सूचना मिल सकती है। नई नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है।

कुंभ : लोकप्रियता में वृद्धि होगी। मित्रों का समागम रहेगा। आमोद-प्रमोद के अवसर मिल सकते हैं।

मीन : अटके कार्य में सफलता मिल सकती है। आर्थिक लाभ हो सकता है। कला, साहित्य में रुचि बढ़ेगी।

जन्मदिन

रवि तेजा, अभिनेता

इस वर्ष मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राजनीतिक संबंध सहायक रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से वर्ष अनुकूल रहेगा। विकास के नए अवसर मिलेंगे। भू-संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। वर्ष मध्य में अविवाहितों के विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। उच्चस्तरीय परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

सुडोकू

1	6			8				
	4		6		3	2	1	
	9		1					6
		4	8	2	1			
7	8						2	5
			3	7	5	9		
8					7		6	
	7	1	9		8		3	
				1			9	7

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

1	6	2	7	8	4	3	5	9
5	4	7	6	9	3	2	1	8
3	9	8	1	5	2	7	4	6
9	5	4	8	2	1	6	7	3
7	8	3	4	6	9	1	2	5
2	1	6	3	7	5	9	8	4
8	2	9	5	3	7	4	6	1
6	7	1	9	4	8	5	3	2
4	3	5	2	1	6	8	9	7

डेली हेल्थ कैप्सूल

सेहतमंद है मिक्स वेजीटेबल सूप

मिक्स वेजीटेबल सूप का सेवन करने से शरीर को गरमाहट मिलती है। साथ ही इससे कमजोरी भी दूर होती है।

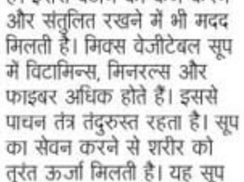

इन दिनों बाजार में तरह-तरह की सब्जियां मिलती हैं। आप गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च और पालक का सूप बनाकर सेवन कर सकते हैं। इससे सेहत को कई लाभ मिलते हैं। इस सूप में विटामिन सी और ए भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर को गरमाहट देने के साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करते हैं। अक्सर ठंड

में ज्यादा खाने से वजन बढ़ने की समस्या हो जाती है। ऐसे में मिक्स वेजीटेबल सूप एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सूप का सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। इससे आप ओवरईटिंग करने से बचे रहते हैं। इससे वजन को कम करने और संतुलित रखने में भी मदद मिलती है। मिक्स वेजीटेबल सूप में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर अधिक होते हैं। इससे पाचन तंत्र तंदुरुस्त रहता है। सूप का सेवन करने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। यह सूप पाचन से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार है। नियमित रूप से यह सूप पीने से गैस, कब्ज और अपच से बचाव होता है। इस सूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है, जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

मिक्स वेजीटेबल सूप बनाते समय नमक और मक्खन की मात्रा कम ही रखें। इससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को लाभ मिलेगा। लोगों को बाजार में मिलने वाले सूप का सेवन करने से बचना चाहिए।
-प्रीता जैन, आहार विशेषज्ञ

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

विश्वविद्यालय और समाज

अभी हम अपना 77वां गणतन्त्र दिवस मना चुके हैं जिसमें भारत के शौर्य से लेकर इसकी शक्ति व प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। निश्चित रूप से हमने आजादी के बाद से चहुंमुखी विकास किया है जिसकी छाप राष्ट्र के हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। परन्तु कोई भी राष्ट्र तभी आगे बढ़ता है जब इसमें रहने वाले लोग जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और सशक्त बनते हैं क्योंकि वही देश मजबूत होता है जिसके लोग मजबूत होते हैं। देशों का निर्माण चूंकि इसमें रहने वाले लोगों से ही होता है अत: यह बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी भी देश के लोगों के बीच आपसी भाईचारा व सौहार्द इस प्रकार हो कि हर किसी के प्रगति करने में किसी प्रकार की कोई सामाजिक व आर्थिक बाधा न हो। इसके लिए सबसे पहली शर्त यह होती है कि उस देश के लोग शिक्षित व स्वस्थ हों । इस बारे में लोकतान्त्रिक व्यवस्था में चुनी गई सरकारों की विशेष भूमिका होती है क्योंकि सरकारी नीतियों से ही किसी भी देश में शिक्षा व स्वास्थ्य की गारंटी तय की जा सकती है। अत: स्वतन्त्र भारत में शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी को पहचानते हुए शिक्षा के प्रचार-प्रसार में विशेष योगदान दिया और निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। भारतीय समाज चूंकि जातिगत व्यवस्था के चलते ऊंच-नीच के भाव से ग्रस्त था अत: ऐसे समाज में शिक्षा का प्रसार करके जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। समाज के सभी वर्गों के समुचित विकास के लिए यह बहुत जरूरी था कि स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक में सामाजिक रूप से अगड़े-पिछड़े व दलित-सवर्ण में बंटे समाज को शिक्षा के माध्यम से एक समान बनाया जाये और सभी अमीर व गरीब विद्यार्थियों के लिए एक समान स्तर की शिक्षा प्रणाली विकसित की जाये। इस काम में हम उस सीमा तक सफल नहीं हो सके जिसकी अपेक्षा स्वतन्त्र भारत के निर्माताओं को थी। इसकी सबसे प्रमुख वजह यह रही कि जमीन तक जड़ें जमाए हुए सामाजिक वर्जनाओं की विसंगतियां हमारे शिक्षण संस्थानों तक में पहुंची जिसके कारण समाज के सदियों से शिक्षा से वंचित लोगों के साथ सम्यक रूप से न्याय नहीं हो सका। इसके लिए स्वतन्त्र भारत की सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों व जन जातियों के लोगों को आरक्षण देकर यह तय किया कि वे जीवन में तरक्की करने से किसी से पीछे न रह पायें। आर्थिक रूप से भी देश की सरकारों ने इस वर्ग के विद्यार्थियों को समर्थन दिया और सुनिश्चित किया कि वे आर्थिक कठिनाइयों के चलते शिक्षा से वंचित न रह सके। मगर इसके लिए यह बहुत जरूरी था कि प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक में छात्रों में आपस में बराबरी का भाव जागृत हो और नई पीढ़ियां ऊंच-नीच की मानसिकता से मुक्त हों। इसे समाप्त करने के लिए ही हमारे संविधान निर्माताओं ने सरकारी नौकरियों में दलित समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जिससे इस समाज के लोग भी देश की शासन व्यवस्था में सक्रिय योगदान देकर एक समानता की मानसिकता को बढ़ावा दे सकें और नई पीढ़ियां जाति के स्थान पर योग्यता का सम्मान कर सकें, परन्तु 1991 से भारत की अर्थव्यवस्था में बाजारवाद के पदार्पण के बाद सबसे बड़ी विसंगति शिक्षा के क्षेत्र में ही उत्पन्न हुई और निजी क्षेत्र में कथित उच्च गुणवत्ता के स्कूल व कालेजों व विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी। इससे शिक्षा के संस्थान दुकानों में तब्दील होने लगे और खासतौर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समाज के धनी वर्ग का आधिपत्य स्थापित होने लगा। मगर 1990 में ही मंडल आयोग के लागू होने की वजह से एक और विसंगति पैदा हुई तथा सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई। इसका असर पूरे समाज पर चहुं दिशा पर पड़ा और स्वतन्त्र भारत में एक बार फिर जातियों के आधार पर इसके नागरिकों की पहचान होने लगी। बाद में मनमोहन सरकार के दौरान मानव संसाधन मन्त्री बने स्व. अर्जुन सिंह ने उच्च शिक्षा में भी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी। लोकतन्त्र में वोट की राजनीति के प्रभावी होने की वजह से इस कदम का समर्थन देश की जातिमूलक राजनैतिक पार्टियों ने तो किया मगर वे यह भूल गईं कि भारतीय संविधान जिस जातिविहीन समाज का आह्वान करता है उस दिशा में यह कदम कितना खतरनाक और शिक्षा के क्षेत्र में विभाजन पैदा करने वाला था। वास्तव में यह कदम उठाकर अर्जुन सिंह ने बाजारवाद के समक्ष हथियार डाल दिये थे और शिक्षा के क्षेत्र को निजी धन्ना सेठों की जागीर बनाये रखने के इन्तजाम बांध दिये थे। बाद में 2012 में विश्वविद्याल अनुदान आयोग की नियमावली में यह संशोधन भी किया गया कि हर उच्च शिक्षण संस्थान में अनुसूचित वर्ग के छात्रों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए स्थापित तन्त्र में पिछड़े वर्गों को भी शामिल किया जायेगा। इससे भारत की उस ऐतिहासिक सच्चाई को नजरअन्दाज किया गया जिसके कारण आज के वर्तमान युग में भी गांवों में दलित समाज के लोगों के साथ भारी भेदभाव किया जाता है। दलित वर्ग के लोगों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक उत्पीड़न कथित पिछड़े समाज की दबंग जातियों के लोगों के द्वारा ही किया जाता रहा है। स्वतन्त्रता के बाद से भारत में जिस प्रकार औद्योगिकरण बढ़ा है उसकी वजह से इसके शहरों में जातिगत भेदभाव को हाशिये पर डाला जाने लगा था क्योंकि महानगरों की भाग-दौड़ भरी जिन्दगी में श्रम की महत्ता को स्थान मिलने लगा था जिसकी वजह से व्यक्ति की पहचान उसकी जाति नहीं बल्कि उसका श्रम व हुनर बनने लगे थे। हमारे विश्वविद्यालयों में भी अगर जाति के आधार पर ही छात्रों के साथ भेदभाव के भाव को आधार बनाया जाता है और दलितों के समकक्ष ही पिछड़े वर्गों को भी रखा जाता है तो इससे समाज में कलुषता को ही और बढ़ावा मिलेगा और विश्वविद्यालय भी जातिवादी राजनीति का अखाड़ा बनते चले जाएंगे। इसका विरोध छात्रों के कुछ समूहों द्वारा किया जा रहा है। इस विरोध को हमें ऐतिहासिक सांस्कृतिक सन्दर्भों में देखना और परखना होगा। पिछड़े वर्ग की अनेक जातियां भारतीय इतिहास में शासक वर्ग तक में रही हैं। अत: इनकी तुलना हम अनुसूचित वर्ग के लोगों के साथ किस प्रकार कर सकते हैं। भारत का संविधान ही जब लोगों में वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकारों पर डालता है तो किस प्रकार हम अपने विश्वविद्यालयों को पिछली सदियों की रूढ़ियों से लाद सकते हैं। जहां तक अनुसूचित वर्गों का सवाल है तो हजारों साल से इन जातियों के लोगों के साथ पशुवत व्यवहार होता रहा है और उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया है। इसलिए उनके साथ पूर्ण न्याय करना भारत की नई पीढ़ियों का भी कर्त्तव्य बनता है।

भारतीय समाज चूंकि जातिगत व्यवस्था के चलते ऊंच-नीच के भाव से ग्रस्त था अत: ऐसे समाज में शिक्षा का प्रसार करके जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। समाज के सभी वर्गों के समुचित विकास के लिए यह बहुत जरूरी था कि स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक में सामाजिक रूप से अगड़े-पिछड़े व दलित-सवर्ण में बंटे समाज को शिक्षा के माध्यम से एक समान बनाया जाये और सभी अमीर व गरीब विद्यार्थियों के लिए एक समान स्तर की शिक्षा प्रणाली विकसित की जाये। इस काम में हम उस सीमा तक सफल नहीं हो सके जिसकी अपेक्षा स्वतन्त्र भारत के निर्माताओं को थी।

नशा मुक्त समाज का करेंगे निर्माण ...

गीता पाढा

"बढ़ते नशे से हो रहा घरों का विनाश है,
आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक अभिशाप है,,
लुट रही जवानी, बुझते सपनों की आस है,
माताओं की सूनी गोद, बहनों का टूट रहा विश्वास है,,
आओ संकल्प लें इस अंधेरे को मिटायेंगे,
और नशामुक्त समाज रचकर इतिहास नया बनाएंगे।।"

विजय दर्डा
संपादक : लोकमत समूह
पूर्व राज्यसभा सांसद

105 मिनट की यात्रा और कई सवाल !

पिछले दिनों यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो नियमित रूप से मेरा कॉलम पढ़ते हैं। उनका एक अहम सवाल था कि देश और प्रदेश में इतनी गतिविधियां हो रही हैं। इतने सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, फिर मैंने इन दिनों अपने कॉलम में विदेशी मसलों को प्राथमिकता क्यों दी है? मैं पाठकों को बताना चाहूंगा कि दुनिया एक-दूसरे से इतनी करीब है कि हर मसले से भारत जुड़ा हुआ है। अपने पाठकों को सहज शब्दों में इन सारी परिस्थितियों से अवगत कराते रहना मेरी जिम्मेदारी है। मैं विषयों को देशी और विदेशी में नहीं बांटता। मैं जो कुछ भी लिखता हूं, समसामयिक लिखता हूं ताकि पाठक सजग रहें। उनके मन में जो सवाल उठ रहे हों, उनके जवाब तलाशे जाएं।

तो फिलहाल चर्चा का विषय यह है कि पिछले सप्ताह यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान केवल 105 मिनट के लिए भारत आए। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की यह अत्यंत छोटी यात्रा थी। प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए अगवानी के लिए मोदी जी एयरपोर्ट गए। वहां से दोनों एक ही कार में पीएम निवास पहुंचे। गुफ्तगू हुई। कुछ डील साइन हुए और नाहयान फिर यूएई निकल गए। स्वाभाविक रूप से हर किसी के मन में यह सवाल उठा कि इस यात्रा का मकसद क्या था? विदेश मंत्रालय ने हमें साइन हुए डील की कुछ जानकारियां दीं लेकिन क्या इस संक्षिप्त यात्रा का मकसद केवल इतना ही था?

यह सवाल उठना लाजिमी है क्योंकि यूएई हाल के वर्षों में कूटनीति का धुरंधर खिलाड़ी बन कर उभरा है, और दूसरी बात कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूटनीति के चाणक्य हैं। मध्य पूर्व के सभी देशों से उन्होंने भारत के रिश्तों में गजब की मिठास घोली है। चाहे यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, ईरान हो या फिर इजराइल। सभी भारत के दोस्त हैं।

यूएई तो इतना करीबी है कि उसने बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर बनाने की इजाजत दी। यह अच्छी बात है कि भारत और यूएई में डिफेंस, स्पेस और स्पेशल इन्वेस्टमेंट पर कई सहमतियां बनी हैं। डील साइन हुए हैं लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारत को यूएई सालाना पांच लाख मीट्रिक टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति करेगा। यानी भारत को एलएनजी आपूर्ति करने वाला वह दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।

मगर ये सारे मुद्दे वो हैं जो सतह पर हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस मुलाकात की गहराई में कौन से मुद्दे रहे होंगे। क्या नाहयान कोई ऐसा संदेश लेकर आए थे जो सिक्योर्ड लाइन पर भी साझा नहीं की जा सकती थी? या फिर विषय ऐसे थे कि जिस पर दोनों नेताओं का आमने-सामने बात करना ही उचित होता? क्या इस बातचीत में ट्रम्प का बोर्ड ऑफ पीस भी शामिल था? ट्रम्प ने यह बोर्ड दुनिया में शांति के लिए बनाया है जिसका सबसे पहला प्रोजेक्ट गाजा का विकास होगा। 60 देशों को इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया है जिसमें भारत भी है। वैसे आपको जानकर हैरत होगी कि जिसे स्थायी सदस्यता चाहिए, उसे एक बिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा। बाकी बातें अभी स्पष्ट नहीं हैं। आपको बता दें कि चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और कई अन्य बड़े देशों ने बोर्ड की साइनिंग सेरेमनी में भाग नहीं लिया। इसे बहिष्कार कहा जा रहा है। जर्मनी, इटली, रूस और तुर्किए जैसे कई देशों ने कुछ भी नहीं कहा है, भारत ने भी चुप्पी साध रखी है लेकिन यूएई ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो क्या दोनों नेताओं के बीच बातचीत में यह मामला भी आया होगा? क्या वे कोई संदेश लेकर आए थे? यह सवाल इसलिए कि मध्य पूर्व की राजनीति या फिर किसी भी उथल-पुथल का सीधा असर भारत पर भी पड़ता है और दूसरी बात है कि भारत एक तरफ इजराइल से बेहतरीन संबंध रखता है और दोनों का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर फिलिस्तीन के समर्थन का स्टैंड भी कायम रखा है।

निश्चित रूप से ट्रम्प चाह रहे होंगे कि भारत बोर्ड में शामिल हो। सवाल है कि दुनिया में शांति के लिए यूनाइटेड नेशन है तो ऐसे बोर्ड की क्या जरूरत?

लोगों की एक जिज्ञासा यह भी है कि यूएई के राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच चर्चा में क्या मध्य पूर्व के अन्य मामले भी रहे होंगे? ऐसा इसलिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब है कि एक पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। इस गठबंधन में तुर्किए भी शामिल होने ही वाला है। खबर तो यह भी आ रही है कि इस गठबंधन में मिस्र और सोमालिया भी शामिल होने को उतावले हैं।

इधर सऊदी अरब और यूएई में यमन, सोमालीलैंड और सूडान में संघर्ष को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। यूएई कतई नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब की स्थिति मजबूत हो। यदि सऊदी के साथ कोई संघर्ष होगा तो कौन उसका साथ देगा? अमेरिका तो सऊदी से भी और यूएई से भी दोस्ती की बात करता है। इसलिए वह किसी के पक्ष में खुलकर नहीं आएगा, इसलिए यूएई का भारत की ओर देखना आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इजराइल, यूएई और भारत के डिफेंस पैक्ट की चर्चा जोर पकड़ रही है। सवाल लाजमी है कि क्या मुलाकात में इस विषय पर भी बात हुई होगी? और क्या चर्चा में ईरान का मुद्दा भी था? मगर फिलहाल इंतजार कीजिए। वक्त सारे सवालों के जवाब जरूर देता है।

> सबके मन में यही सवाल है कि जो कुछ सामने दिख रहा है, केवल उन्हीं पर बात हुई होगी या फिर ये बड़ी गहरी मुलाकात थी। सवालों के जवाब वक्त आने पर ही मिलेंगे

रोहित माहेश्वरी

गरीब बच्चों के स्कूल प्रवेश पर सुप्रीम पहल

हर माता-पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा एक अच्छा स्कूल जाए, अच्छी पढ़ाई करे और जिंदगी में कुछ बन सके, लेकिन जब बात प्राइवेट स्कूलों की आती है, तो अक्सर फीस एक बड़ी रुकावट बन जाती है। अब इस चिंता को सरकार ने दूर करने की पहल की है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब हर प्राइवेट स्कूल में 25 फीसदी सीटें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। यानी अगर आपके पास साधन नहीं हैं, फिर भी आपका बच्चा महंगे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त पढ़ाई कर सकता है। हाल ही में शिक्षा के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम और दूरगामी फैसला सामने आया है।

अदालत ने साफ कहा है कि सच्चा बंधुत्व तभी संभव है, जब समाज के हर वर्ग के बच्चे एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में साथ पढ़ें। इसी सोच को मजबूत करते हुए शीर्ष अदालत ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट और गैर-सरकारी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत मुफ्त सीटें सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में गरीब बच्चों को प्रवेश देना 'एक राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए।'

आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार कानून, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत यह हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। शिक्षा के अधिकार को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, तो इसमें कोई भी स्कूल बच्चे को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता है। हर 60 बच्चों पर कम से कम दो प्रशिक्षित अध्यापकों का होना अनिवार्य है। हर तीन किलोमीटर के अंदर स्कूल होना जरूरी हैं। राईट टू एजुकेशन पर होने वाले खर्चों का 55 प्रतिशत केंद्र और 45 प्रतिशत राज्य सरकार उठाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, देश के स्कूल शिक्षा तंत्र में 24.8 करोड़ से अधिक छात्र नामांकित हैं, और प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर 96.9 फीसदी से ऊपर पहुंच गई है। तल्ख हकीकत यह है कि भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिलने के बाद भी कई राज्यों में आधारभूत ढांचे, जनसंख्या वृद्धि, वित्तीय बाधाओं और प्रशासनिक लापरवाही के कारण प्राथमिक शिक्षा की पहुंच प्रभावित होती रही है।

अदालत की यह टिप्पणी असल में हमारे सामाजिक विवेक को झकझोरने की कोशिश है। कानून का इरादा बिल्कुल नेक है पढ़ाई वह भरोसेमंद टूल है, जिससे जीवन बदला जा सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र का एक बुनियादी सिद्धांत है किसी भी नीति का मूल्यांकन उसके नेक इरादों से नहीं, उसके अंतिम परिणाम से होना चाहिए। शिक्षा में परिणाम का मतलब है वह बच्चा वास्तव में सीख रहा है, क्या वह स्कूल में टिक पा रहा है, और क्या उसकी क्षमताएं उसे भविष्य के प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए तैयार कर रही हैं? समस्या यह है कि हम अक्सर शिक्षा को केवल 'सीट' या 'फीस' की बहस तक सीमित कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि फीस माफ हो गई, तो शिक्षा मुफ्त हो गई। हकीकत में सीखने की कीमत सिर्फ स्कूल की फीस नहीं होती। अर्थशास्त्र में कहें तो हर परिवार को सीखने की लागत चुकानी पड़ती है। इसमें पैसा, समय, मानसिक तनाव और जोखिम सब शामिल हैं।

अदालत ने कहा कि कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला केवल कागजी अधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को स्पष्ट नियम बनाने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से जुड़े इस मामले में याचिकाकर्ता दिनेश बीवाजी अष्टिकर ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को पड़ोस के निजी स्कूल में 25 फीसदी कोटे के तहत दाखिला नहीं मिला। आरटीआई से सामने आया कि सीटें खाली थीं, फिर भी स्कूल ने जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए राहत नहीं दी कि ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वर्षों की देरी के कारण बच्चों को समय पर राहत मिलना संभव नहीं रहा। इसके बावजूद अदालत ने इसे "नज़ीर तय करने वाला" मामला मानते हुए व्यापक दिशा-निर्देश देने का फैसला किया। कोर्ट ने माना कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, भाषा की बाधा, डिजिटल अशिक्षा और जानकारी की कमी के कारण गरीब परिवारों के लिए 25 फीसदी कोटे तक पहुंचना आज भी मुश्किल है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पड़ोस के स्कूलों में दाखिला केवल सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है।

अदालत ने यह याद दिलाया कि निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना कोई अलग कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) और 39 (एफ) में निहित बाल विकास और बंधुत्व के सिद्धांतों को लागू करने का जरिया है। पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा जारी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिनके बच्चों को पड़ोस के एक स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रवेश नहीं मिला था, जबकि सीटें उपलब्ध थीं।

शीर्ष अदालत का कहना था कि आरटीई कानून सभी बच्चों को जाति, वर्ग, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना एक ही स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा देने की बात करता है। इसने कोठारी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसमें कॉमन स्कूल सिस्टम पर जोर दिया गया था, जहां पर समाज के हर वर्ग के बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा मिल सके। संविधान के भाईचारे का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब एक रिक्शा खींचने वाले का बच्चा, एक करोड़पति या सुप्रीम कोर्ट के जज के बच्चे के साथ एक ही स्कूल में पढ़े। शीर्ष अदालत के इस फैसले को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार परिषदों से सलाह लेकर, धारा 12(1)(सी) के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक नियम और कानून तैयार करें और जारी करें। कोर्ट ने आगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियम और कानून जारी करने की जानकारी इकट्ठा करें और 31 मार्च तक कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी।

वास्तव में यह फैसला केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि देशभर के लाखों बच्चों के अधिकार से जुड़ा है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि यदि नियम नहीं बने, तो शिक्षा का अधिकार "कागजी हक" बनकर रह जाएगा। पीठ ने जोर देकर कहा कि सरकार, स्थानीय प्रशासन और स्कूल-तीनों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा सिर्फ प्रक्रिया की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।

क्या होते हैं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर

हर साल जब केंद्र सरकार का आम बजट पेश होता है, तो सबसे ज्यादा चर्चा इनकम टैक्स को लेकर होती है, लेकिन इसके साथ-साथ अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टैक्स) भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये ऐसे कर होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की चीजों की कीमत में जुड़े होते हैं। बजट में जब इन करों में बदलाव होता है, तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब, महंगाई और कारोबार पर पड़ता है। इसलिए बजट को समझने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों को जानना जरूरी है। प्रत्यक्ष कर वे टैक्स होते हैं जो अपनी कमाई पर व्यक्ति या कंपनी सीधे सरकार को चुकाती है। इन करों का बोझ किसी और पर नहीं डाला जा सकता। भारत में प्रत्यक्ष कर की वसूली और नियमों को देखने का काम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) करता है। प्रत्यक्ष कर में आमतौर पर ज्यादा कमाने वालों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है, ताकि समाज में बराबरी बनी रहे। इनकम टैक्स वह कर है जो व्यक्ति या संस्था की कमाई पर लगाया जाता है, जैसे सैलरी, बिजनेस या प्रॉपर्टी से हुई आय।

कॉरपोरेट टैक्स कंपनियों के मुनाफे पर लगता है। कैपिटल गेन टैक्स शेयर, जमीन या सोना बेचकर हुए मुनाफे पर लगाया जाता है। इसके अलावा शेयर बाजार में खरीद-बिक्री पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) लगता है। कुछ खास मामलों में मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (एमएटी) और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स (एएमटी) भी लागू होते हैं। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो हमारी कमाई पर सीधे नहीं लगते, बल्कि सामान और सेवाओं की खरीद पर वसूले जाते हैं। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, तो दुकानदार टैक्स लेकर सरकार को जमा करता है। इसलिए इन्हें अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। आज भारत में सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर जीएसटी है, जिसने पहले के कई टैक्स जैसे वैट और सर्विस टैक्स की जगह ले ली है। जीएसटी लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। इसके अलावा विदेश से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी लगती है। कुछ खास चीजों जैसे पेट्रोल, डीजल, तंबाकू और कोयले पर सेस भी लगाया जाता है। ये सभी टैक्स अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं।

केंद्र सरकार को होने वाली कुल टैक्स कमाई का बड़ा हिस्सा अप्रत्यक्ष करों से आता है। बजट में अगर जीएसटी, कस्टम ड्यूटी या सेस में बदलाव किया जाता है, तो इसका असर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ता है। मोबाइल, कपड़े, दवाइयां या खाने-पीने की चीजें सस्ती या महंगी हो सकती हैं। इससे महंगाई और बाजार का माहौल भी बदल जाता है।

अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है। अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं। जानकारों का कहना है कि अप्रत्यक्ष कर अमीर और गरीब दोनों पर एक जैसा लगता है। ऐसे में गरीब लोगों पर इसका असर ज्यादा पड़ सकता है। इसी वजह से हर बजट में यह बहस होती है कि जरूरी सामान पर टैक्स कम होना चाहिए या नहीं, लग्जरी चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए या नहीं और देसी उद्योगों को बचाने के लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाए या घटाई जाए।

वहीं आगामी आम बजट 2026 में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़े फैसले सरकार की आमदनी, महंगाई, कारोबार और आम लोगों की जेब को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए बजट को सही तरीके से समझने के लिए इन करों की जानकारी होना बेहद जरूरी है।

रिलायंस ने रूसी तेल से दूरी बनाई

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने जमकर की खरीदारी

बेतुल (गोवा), (पंजाब केसरी) : रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने जनवरी में अब तक रूस से एक भी बैरल तेल नहीं खरीदा है।

दूसरी ओर, सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों ने रूस से अपनी आयात मात्रा बढ़ा दी है, क्योंकि इस देश से मिलने वाली छूट अब लगभग सात डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। यह छूट 2025 के मध्य में मिलने वाली छूट के स्तर से लगभग तीन गुना अधिक है।

रिलायंस ने 2025 में रूस से प्रतिदिन लगभग छह लाख बैरल तेल खरीदा। उस वक्त रिलायंस रूस से तेल खरीदने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। हालांकि, उसने जनवरी के पहले तीन हफ्तों में रूस से कच्चे तेल की कोई खरीद नहीं की है। जलयानों की निगरानी करने वाले आंकड़ों और उद्योग के सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की है।

सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने जनवरी में औसतन 4,70,000 बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) की खरीदारी की, जो इसका अब तक का उच्चतम स्तर है। दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा 4,27,000 बीपीडी था। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने इस महीने 1,64,000 बीपीडी तेल खरीदा, जो दिसंबर के 1,43,000 बीपीडी से अधिक है।

रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट समर्थित नयारा एनर्जी ने इस महीने लगभग 4,69,000 बीपीडी तेल खरीदा। यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण अन्य आपूर्तिकर्ताओं से कटे होने की वजह से नयारा पूरी तरह रूसी तेल पर निर्भर है।

जनवरी के पहले तीन हफ्तों में रूसी तेल का कुल भारतीय आयात थोड़ा घटकर 11 लाख बीपीडी रह गया, जो दिसंबर में 12 लाख बीपीडी था। यह नवंबर के 18.4 लाख बीपीडी के मुकाबले काफी कम है। यह गिरावट रूस के दो सबसे बड़े तेल निर्यातकों - रोसनेफ्ट और लुकोइल पर 21 नवंबर से लागू हुए अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव को दर्शाती है।

रेल पटरी पर पतंग पकड़ रहे दो लड़कों की मौत

चंडीगढ़, (पंजाब केसरी): चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में रेल पटरियों पर पतंग पकड़ रहे 10 और 13 साल के दो लड़कों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एक अधिकारी ने बताया कि लड़कों का एक समूह कटी पतंग को पकड़ रहा था और वे अंबाला से जालंधर जा रही ट्रेन को आते हुए नहीं देख सके।यह घटना रविवार शाम चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में बाल्टाना क्षेत्र की हरमिलाप नगर कॉलोनी के पास हुई।अधिकारी नेबताया कि इस घटना में दो लड़कों की मौत हो गई और उनकी उम्र 10 एवं 13 साल थी।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

NEW LAYOUT-674X576 Pawan New

देशभर में बैंक कर्मचारियों की आज हड़ताल, सेवाएं रहेंगी प्रभावित

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): अगर आप 27 जनवरी को किसी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले ये जान लें कि कहीं आपका भी बैंक मंगलवार को बंद तो नहीं है। बैंक कर्मचारियों की यूनियनों ने अपनी लंबे समय से लंबित 5-डे वर्क वीक की मांग को लेकर 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने किया है। ऐसे में देशभर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है।

यूनियनों की मुख्य मांग है कि बैंकों में भी सप्ताह में पांच दिन काम और दो दिन छुट्टी की व्यवस्था लागू की जाए। यूएफबीयू का कहना है कि मार्च 2024 में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ हुए वेतन संशोधन समझौते में सभी शनिवारों को छुट्टी देने पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इसी देरी के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं।

वर्तमान में बैंक कर्मचारियों को

हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को ही छुट्टी मिलती है। इसके अलावा बाकी शनिवारों में बैंकों में कामकाज होता है, जिससे महीने में दो हफ्ते कर्मचारियों को छह दिन काम करना पड़ता है। यूनियनों का कहना है कि यह व्यवस्था अब समय के साथ उचित नहीं रह गई है।

इस हड़ताल में देशभर के सभी प्रमुख सरकारी बैंक शामिल होंगे, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। कई शहरों में पहले से ही बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा।

- यूनियनों की मुख्य मांग है कि बैंकों में भी सप्ताह में पांच दिन काम और दो दिन छुट्टी की व्यवस्था लागू की जाए

बैंक यूनियनों ने साफ किया है कि पांच दिन काम की व्यवस्था लागू होने से काम के घंटे कम नहीं होंगे। यूनियन का कहना है कि कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना करीब 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को तैयार हैं, ताकि कुल साप्ताहिक कार्य समय में कोई कमी न आए। यह प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन पिछले दो वर्षों से इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

यूएफबीयू का तर्क है कि आरबीआई, एलआईसी, स्टॉक एक्सचेंज और अधिकांश सरकारी कार्यालय पहले से ही पांच दिवसीय कार्य सप्ताह का पालन कर रहे हैं। ऐसे में बैंकों में अब भी छह दिन काम की व्यवस्था बनाए रखने का कोई ठोस कारण नहीं है।

यह हड़ताल 26 जनवरी की आधी रात से शुरू होकर 27 जनवरी की आधी रात तक चलेगी। इस दौरान देशभर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहने की संभावना है, जिसमें कैश लेन-देन, चेक क्लीयरेंस और शाखाओं से जुड़े अन्य काम शामिल हैं। यूएफबीयू ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत हड़ताल की सूचना इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए), मुख्य श्रम आयुक्त और वित्तीय सेवा विभाग को पहले ही भेज दी है। यूनियनों के मुताबिक, 7 दिसंबर 2023 को आईबीए और यूएफबीयू के बीच हुए समझौते और 8 मार्च 2024 को जारी संयुक्त नोट के बावजूद अब तक सरकार की अंतिम मंजूरी नहीं मिल पाई है।

यूनियनों ने स्पष्ट किया है कि पांच दिन काम की मांग कोई नई बात नहीं है।

भारत से 40 हजार से अधिक श्रमिक बुलाएगा रूस

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): रूस में कामगारों की भारी कमी को देखते हुए वहां की सरकार भारत से ज्यादा मजदूर और कामगार बुलाने की योजना बना रही है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, इस साल करीब 40,000 भारतीय नागरिक काम के लिए रूस जा सकते हैं।

डीडब्ल्यू.कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल के अंत तक 70,000 से 80,000 भारतीय नागरिक पहले से ही रूस में काम कर रहे थे।

पिछले साल दिसंबर में भारत और रूस के बीच दो अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। इन समझौतों का मकसद भारत के अर्ध-कुशल और कुशल कामगारों को रूस में काम करने के बेहतर अवसर देना है। ये समझौते हैं, एक देश के नागरिकों को दूसरे देश में अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति और अवैध प्रवासन से निपटने में सहयोग।

इन समझौतों से भारतीय कामगारों को रूस में नौकरी मिलने का एक सुरक्षित ढांचा मिलेगा, ताकि उन्हें पहले की तरह धोखाधड़ी या गलत तरीकों का सामना न करना पड़े।

सन फार्मास्यूटिकल और सिप्ला ने अमेरिका से वापस मंगाईं दवाएं

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): भारतीय दवा कंपनियों सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और सिप्ला ने विनिर्माण से जुड़ी समस्याओं के कारण अमेरिका के बाजार से अपनी कुछ दवाएं वापस मंगाई हैं। यह जानकारी अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) की ताजा रिपोर्ट में सामने आई है।

एन्फोर्समेंट रिपोर्ट में अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक ने बताया कि मुंबई मुख्यालय वाली सन फार्मा की अमेरिका स्थित यूनिट एक जेनरिक दवा की हजारों बोतलें वापस मंगा रही है। यह दवा डैंड्रफ (रूसी) और त्वचा की सूजन व खुजली जैसी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होती है।

न्यू जर्सी के प्रिंसटन में स्थित सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इंक ने फ्लुओसिनोलोन एसीटोनाइड टॉपिकल सॉल्यूशन की 24,624 बोतलें वापस मंगाई हैं। जांच में पाया गया कि यह दवा अशुद्धता और गुणवत्ता के तय मानकों पर खरी नहीं उतर रही थी।

कंपनी ने 30 दिसंबर 2025 को अमेरिका में देशभर में क्लास III

रिकॉल शुरू किया। यूएसएफडीए के अनुसार, क्लास III रिकॉल उन मामलों में किया जाता है, जहां दवा के इस्तेमाल से स्वास्थ्य को नुकसान होने की संभावना बहुत कम होती है।

यूएसएफडीए ने यह भी बताया कि सन फार्मा ने क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट यूएसपी नाम की दवा के कुछ बैच भी वापस मंगाए हैं। यह दवा मुंहासों के इलाज में इस्तेमाल होती है।

इस दवा को 26 नवंबर 2025 को वापस मंगाया गया था, क्योंकि जांच में अशुद्धता का स्तर और दवा की मात्रा तय सीमा से बाहर पाई गई थी। इसे भी क्लास III रिकॉल में रखा गया है।

वहीं दूसरी ओर, यूएसएफडीए ने बताया कि सिप्ला की अमेरिका स्थित यूनिट ने भी 15,000 से

- दवा अशुद्धता और गुणवत्ता के तय मानकों पर खरी नहीं उतर रही थी

ज्यादा इंजेक्शन सिरिंज अमेरिकी बाजार से वापस मंगाई हैं।

सिप्ला यूएसए इंक का मुख्यालय न्यू जर्सी के वॉरेन में है। इसने लैनरियोटाइड इंजेक्शन की 15,221 पहले से भरी हुई सिरिंज वापस मंगाई हैं। इन सिरिंज में कण पाए गए हैं।

सिप्ला ने यह रिकॉल 2 जनवरी 2026 को क्लास II रिकॉल के तहत शुरू किया। यूएसएफडीए के अनुसार, क्लास II रिकॉल तब किया जाता है, जब दवा के इस्तेमाल से अस्थायी या ठीक हो सकने वाले स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं, हालांकि गंभीर नुकसान की संभावना कम रहती है।

अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दवा बाजार है। इसलिए वहां काम करने वाली दवा कंपनियों के लिए नियमों का पालन और दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना बेहद जरूरी माना जाता है।

पीएसीएल की 1,986.48 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दिल्ली जोनल कार्यालय–2 ने पीएसीएल लिमिटेड और उससे जुड़ी इकाइयों द्वारा संचालित बहुचर्चित सामूहिक निवेश योजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 1,986.48 करोड़ रुपए की 37 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ये संपत्तियां पंजाब के लुधियाना और राजस्थान के जयपुर में स्थित हैं। ईडी की ओर से सोमवार को जारी एक प्रेस नोट में यह जानकारी दी गई।

ईडी की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट के अनुसार, यह कार्रवाई सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। इस एफआईआर में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। ईडी की जांच में सामने आया है कि आरोपित संस्थाओं और व्यक्तियों ने अवैध सामूहिक निवेश योजना के जरिए देशभर के लाखों निवेशकों से 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि धोखाधड़ी से जुटाई। निवेशकों को कृषि भूमि की बिक्री और विकास के नाम पर कैश डाउन पेमेंट और किस्तों (इंस्टॉलमेंट) के जरिए निवेश के लिए प्रेरित किया गया। उनसे भ्रामक दस्तावेजों, जैसे समझौते, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य कागजात, पर हस्ताक्षर कराए गए।

जांच में यह खुलासा हुआ कि अधिकांश मामलों में निवेशकों को कोई जमीन नहीं दी गई और लगभग 48 हजार करोड़ की राशि आज भी निवेशकों को लौटाई जानी बाकी है। इस घोटाले में कई फ्रंट कंपनियों और रिवर्स सेल ट्रांजैक्शनों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी को छिपाया गया और अवैध लाभ कमाया गया।

ईडी की जांच के अनुसार, निवेशकों से जुटाई गई राशि को विभिन्न संबंधित और असंबंधित कंपनियों के माध्यम से घुमाया गया और अंतत: स्वर्गीय निर्मल सिंह भंगू, उनके परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों और पीएसीएल से जुड़ी संस्थाओं के बैंक खातों में जमा कराया गया।

बीजापुर में कई प्रेशर बमों में विस्फोट, 11 सुरक्षाकर्मी घायल

रायपुर, आशीष शर्मा (पंजाब केसरी): छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए कई प्रेशर बमों में हुए विस्फोट में 11 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान कर्रेगुट्टा पहाड़ियों के जंगलों में प्रेशर बमों में धमाके हुए। उन्होंने बताया कि घायल सुरक्षाकर्मियों में से 10 राज्य पुलिस की इकाई जिला रिजर्व गार्ड के हैं, जबकि एक सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का है।

अधिकारियों ने बताया कि कोबरा बटालियन के घायल जवान की पहचान रुद्रेश सिंह के रूप में हुई है, जो कोबरा 210 वीं बटालियन में उप निरीक्षक है। उन्होंने बताया कि सिंह और डीआरजी के दो जवानों को पैर में चोट लगी है, जबकि तीन अन्य कर्मियों को आंखों में छर्रे लगे हैं।

राष्ट्र की प्रगति में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान : नायब सैनी

गुरुग्राम, कुमार प्रवीण (पंजाब केसरी): मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा' के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए हरियाणा प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार ने पुरानी परिपाटियों को बदलते हुए गरीबों के उत्थान के लिए न केवल नई योजनाएं शुरू की हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हों।

मुख्यमंत्री ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को जिला गुरुग्राम में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे पहले उन्होंने वीर शहीदी स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस, महिला पुलिस, होमगार्ड तथा स्काउट्स सहित विभिन्न टुकड़ियों की परेड का निरीक्षण किया और उन्हें

सलामी ली।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन की शुरुआत अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर तथा संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करते हुए की और कहा कि वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से ओत-प्रोत यह गणतंत्र दिवस हमें देश की एकता, सांस्कृतिक गौरव और स्वावलंबन की भावना का स्मरण कराता है। विविधताओं से भरा हमारा राष्ट्र सदैव एकता के सूत्र में बंधा रहा है, जिसकी झलक वंदे मातरम के 150 वर्षों के गौरवपूर्ण उत्सव में दिखाई देती है। आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हुए भारत आज विश्व मंच पर नई पहचान बना रहा है, जो प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।

गणतंत्र दिवस—अतीत की स्मृति और उज्ज्वल भविष्य का संकल्प : मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल अतीत को स्मरण करने का पर्व ही नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की उस सुनहरी तस्वीर को देखने का भी महापर्व है, जिसे हमने पिछले 11 वर्षों में मिलकर गढ़ा है। उन्होंने कहा कि दशकों तक सरकारें बदलती रहीं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली।

मुख्यमंत्री ने शिप्रा के तट पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज

भोपाल, (मनीष शर्मा): मध्यप्रदेश में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र रक्षकों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत और सिंहस्थ पर केंद्रित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां भी हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभागीय झांकियों को पुरस्कृत भी किया। समारोह में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती सीमा यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, विभिन्न धर्मों के धर्मगुरू, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, छात्र-छात्राएं और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने

शिप्रा तट सुनहरी घाट पर तिरंगा कलर के गुब्बारे खुले आकाश में छोड़ कर राष्ट्रभक्ति और जनसेवा का संदेश दिया। इस अवसर पर मां शिप्रा में 40 से अधिक तिरंगे रंग से सरावोर नाव पर तिरंगा ध्वज लिए होमगार्ड, एसडीईआरएफ के जवान उपस्थित होकर देश भक्ति के गीत गा रहे थे। घाट पर तिरंगे की थीम पर साज-सज्जा की गई साथ ही घाट पर जनजातीय भील कलाकारों द्वारा भगोरिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति हुई। मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज राष्ट्र के जन-गण-मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2028 में सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में होना है।

राष्ट्रीय गौरव के साथ लखनऊ में मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस

लखनऊ (पंजाब केसरी) 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में विधान भवन के सामने मुख्य समारोह का आयोजन किया गया जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रध्वज फहराया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में परेड की सलामी ली। इस अवसर पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई। राष्ट्रध्वज फहराए जाने के बाद राष्ट्रगान गाया गया और पूरे परिसर में देशभक्ति गीत गूंजते रहे। समारोह में भारतीय थल सेना की विभिन्न रेजिमेंटों की टुकड़ियां, उत्तर प्रदेश पुलिस, होमगार्ड, पीएसी की 32वीं एवं 35वीं वाहिनी, महिला पीएसी

बल, प्रांतीय रक्षा दल तथा एनसीसी कैडेटों ने मार्च पास्ट किया। इस वर्ष विशेष रूप से हरियाणा पुलिस का दस्ता भी परेड में शामिल रहा। परेड में शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ के ब्रास बैंड के साथ सेंट जोसेफ कॉलेज, अटल आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा अन्य राजकीय और निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने मार्च किया। सीएमएस अलीगंज की शिक्षित बेटियां'थीम तथा सीएमएस गोमतीनगर के बैंड द्वारा प्रस्तुत'सारे जहां से अच्छा'की धुन को सराहा गया।

खड़गे, राहुल को तीसरी पंक्ति में बैठाने पर कांग्रेस भड़की

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): कांग्रेस ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें तीसरी पंक्ति में बैठाया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पहले राहुल गांधी के साथ तीसरी पंक्ति में बैठे हुए दिखाई दिए। बाद में उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बगल में पहली पंक्ति में बैठा दिया गया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी और खड़गे की तीसरी पंक्ति में बैठने वाली तस्वीर साझा करते हुए 'एक्स' पर कहा, क्या देश में विपक्ष के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी शिष्टाचार,

- बाद में उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बगल में पहली पंक्ति में बैठा दिया गया था

परंपरा और प्रोटोकॉल के मानकों को पूरा करता है? उन्होंने कहा, '' यह बस एक ऐसी सरकार की हताशा को उजागर करता है जो हीन भावना से ग्रस्त है। लोकतंत्र में मतभेद तो बने रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी के साथ किया गया यह बर्ताव अस्वीकार्य है।'' कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने भी 'एक्स' पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, '' यह प्रोटोकॉल और शिष्टाचार का घोर उल्लंघन है!! मौजूदा हालात में इसकी उम्मीद करना बेकार है!!

स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब की बेमिसाल कुर्बानियां दी : मान

होशियारपुर, (पंजाब केसरी) :गणतंत्र दिवस पर होशियारपुर में राष्ट्रीय तिरंगा लहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस अवसर पर पंजाब के संवैधानिक अधिकारों की जोरदार पुष्टि करते हुए अपनी सरकार के शासन रिकॉर्ड का विस्तारपूर्वक विवरण दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब की बेमिसाल कुर्बानियों और देश के अन्नदाता व खड़गभुजा के रूप में इसकी निरंतर भूमिका को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद राज्य को इसकी राजधानी और अलग हाई कोर्ट से गैरकानूनी तरीके से वंचित रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी और इसके पानी के अधिकारों पर पंजाब के दावे को

कमजोर करने की कोशिशें सफल नहीं होंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब अपने हितों की रक्षा के लिए हर रोज कानूनी और संवैधानिक कार्रवाई करता रहेगा। शासन को विरासत और विश्वास से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस की ऐतिहासिक यादगार, श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर का दर्जा दिया है।शासन की दिशा को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने 'युद्ध नशे के विरुद्ध' और 'गैंगस्टरों पर वार' के तहत नशों, गैंगस्टरों और नारको-ड्रोन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, 10 लाख रुपए तक की सार्वव्यापी स्वास्थ्य सुविधा, रिश्वत के बिना 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान करना है।

राजस्थान में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा

जयपुर, (बनवारी कुमावत): जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, गणमान्यजन उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने झंडा फहराने के बाद परेड का निरीक्षण किया और सलामी गारद द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। राज्यपाल श्री बागडे ने इस दौरान गणतंत्र दिवस पर "विकसित भारत- विकसित राजस्थान" के निर्माण में सभी को अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान की महान परंपरा, उसके मूल तत्व और उसके आदर्शों में अटूट आस्था व्यक्त करने का अवसर है।

मुख्यमंत्री को दी सलामी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने

सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री निवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री को कंपनी कमांडर श्री राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में आर.ए.सी. की टुकड़ी ने सलामी दी।

श्री शर्मा ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि हमारा देश दुनिया का सबसे समृद्ध लोकतंत्र है तथा हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।

मेट्रो प्रांगण में ध्वजारोहण

जयपुर मेट्रो प्रांगण में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन बहुत ही हर्षोल्लास व गौरव के साथ आयोजित किया गया। जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निदेशक कम्पनी मामलात् महेश कुमार भुराड़िया द्वारा झंडारोहण किया गया तथा आजादी के शहीदों को नमन करते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यक्रम में सभी निदेशकगण, अधिकारीगण, मेट्रो पुलिस एवं समस्त कार्मिक उपस्थित रहें।

सूचना केन्द्र में फहराया तिरंगा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

राकेश शर्मा ने सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सूचना केन्द्र जयपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक प्रशासन गोरधन लाल शर्मा, प्रभारी सूचना केन्द्र, संयुक्त निदेशक जसराम मीना, राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलोजी के कार्यकारी निदेशक तकनीकी संजय सिंघल सहित सूचना केन्द्र एवं आरकेट के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

शिमला का रिज देश भक्ति के रंग में रंगा

शिमला, (विक्रांत सूद): गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान जब राष्ट्रभक्ति के रंगों में सराबोर था, तब हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग की झांकी ने ना केवल लोगों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि प्रदेश की औद्योगिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत और नवाचार की दिशा को सशक्त स्वर भी दिया। झांकी के केंद्र में रहा, हाल ही में शिमला में आयोजित हिम एमएसएमई उत्सव 2026, जिसने प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नई उड़ान दी। इसका सबसे प्रभावशाली दृश्य था हैंडलूम से निर्मित 4023 हस्तनिर्मित शॉलों का भव्य प्रदर्शन, एक ऐसी उपलब्धि जिसने गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान पाकर हिमाचल के बुनकरों और कारीगरों को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित कर दिया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने झांकी को आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) आर डी नजीम ने कहा कि यह झांकी राज्य की औद्योगिक सोच की स्पष्ट झलक है।

मार्च-2026 तक नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़ : सीएम विष्णुदेव

रायपुर, आशीष शर्मा (पंजाब केसरी): देश के साथ छत्तीसगढ़ ने भी 77 वां गणतंत्र दिवस मनाया। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल रामेन डेका ने तिरंगा फहराया। सीएम विष्णु देव साय बिलासपुर जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। साय बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री हैं।

इस दौरान सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस बल को राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ का पदक मिलेगा। नक्सलवाद अंतिम चरण में है। मार्च 2026 तक प्रदेश नक्सलमुक्त हो जाएगा। सरेंडर नक्सलियों के पुनर्वास, बस्तर कैफे और नियद नेल्ला नार योजन से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य तेज किए जाएंगे।

बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ के पहले

सीएम अजीत जोगी साल 2001 से लेकर 2003 तक गणतंत्र दिवस पर बिलासपुर में ही राष्ट्रीय ध्वज फहराते रहे हैं। वहीं, डिप्टी सीएम अरुण साव बस्तर, डिप्टी सीएम विजय शर्मा सरगुजा जिला मुख्यालय में झंडा फहराया।

जांजगीर चांपा में मंत्री ओपी चौधरी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। दुर्ग साइंस कॉलेज से प्रभात रैली निकली। रैली में प्राचार्य, स्टाफ के साथ एनसीसी कैडेट्स भी शामिल हुए।

राज्यपाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया

राजधानी रायपुर स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल रमेन डेका ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की टुकड़ियों द्वारा आकर्षक परेड प्रस्तुत की गई। इधर दुर्ग में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्ग साइंस कॉलेज से प्रभात रैली निकाली गई। रैली में कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं एनसीसी कैडेट्स ने सहभागिता की। रैली के माध्यम से देशभक्ति और संविधान के मूल्यों का संदेश दिया गया। राज्यभर में विभिन्न शासकीय, शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों द्वारा झंडा फहराने का कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं राष्ट्रभक्ति से जुड़े आयोजन किए गए।

Please Support me by joining My Private Channel

✅ I Give My Earliest Newspapers updates from 5 AM in Private channel with All Editions

♦ **Indian Newspaper**

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) Financial Express
7) Live Mint
8) Hindustan Times
9) Business Standard

♦ **International Newspapers channel**

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ **Magazine Channel**

National & International
[Genaral & Exam related]

♦ **English Editorials**

[National + International Editorials]